Vol. Third Series, XXXVIII—No. 17

Thursday, March 11, 1965
Phalguna 20, 1886 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Eleventh Sessions)

(Vol. XXXVIII contains Nos. 1—10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price: Re. 1·00

CONTENTS

	COLUMNS
No. 17—*Thursday March* 11, 1965/*Phalguna* 20, 1886 (*Saka*)	
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 380 to 386	3605—43
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 387 to 401.	3643—55
Unstarred Questions Nos. 969 to 1024 and 1026 to 1041	3655—3703
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Declaration of emergency in a Manipur sub-division and necessity for calling of troops	3703—05
Papers laid on the Table	3705—06
Messages from Rajya Sabha	3706—07
Re : Point of Propriety	3707—08
Demands for Grants (Railways), 1965-66	3708—3814
Dr. M.S. Aney	3709—13
Shrimati Laxmi Bai	3713—19
Shri Harish Chandra Mathur	3719—25
Shri A.P. Sharma	3726—29
Shri Onkar Lal Berwa	3729—36
Shri D.C. Sharma	3736—42
Shrimati Sahodra Bai Rai	3742—48
Shri C.K. Bhattacharyya	3748—53
Shri Abdul Ghani Goni	3753—56
Shri Basumatari	3756—60
Shri Daljit Singh	3760—66
Shrimati Savitri Nigam	3766—70
Shrimati Subhadra Joshi	3770—76
Shri Bakliwal	3776—81
Shri D.J. Naik	3781—85
Shri Veerappa	3785—87
Shrimati Lakshmikanthamma	3787—91
Dr. Ram Subhag Singh	3791—3810
Motion re : Home Minister's statement on anti-national activities to pro-Peking Communists	3814—3900
Shri P.K. Deo	3821—28
Shri H.N. Mukerjee	3828—38
Shri Vidya Charan Shukla	3839—47
Shri Prakash Vir Shastri	3847—56
Shri Madhu Limaye	3856—62

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	COLUMNS
Shri P. Venkatasubbaiah	3862—66
Shri N.C. Chatterjee .	3866—71
Shri Kappen . . .	3871—75
Shri Hari Vishnu Kamath . .	2875—81
Shri Dinen Bhattacharya . .	3881—85
Shri R.S. Pandey . . .	3885—91
Shri Hukam Chand Kachhavaiya	3891—96
Shri Sarjoo Pandey . .	3896—3900
Shri Nanda . .	3900

LOK SABHA

Thursday, March 11, 1965/Phalguna 20, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली के मीटरों के लिये नकद जमानत

\+

*380. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री श्रोंकार लाल बेरवा :
श्री श्रोंकार सिंह :
श्र मू० ला० वर्मा :
श्री प्रक शवीर शास्त्री :
श्री बृजराज सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हेमराज :
श्री रामानन्द शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री उटिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाजी :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री जेधे :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री माते :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री शिव नारायण :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री प० ह० भील :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री यु० द० सिंह :
श्री लहरी सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के बिजली के मीटर की सरकारी जमानत रद्द करके उनसे नकद जमानत जमा कराने के नोटिस दे दिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) ऐसे नोटिस देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नोटिसों में यह दिया हुआ था कि यदि 24 फरवरी, 1965 तक नकद जमानत जमा नहीं कराई तो उनके मीटर काट दिये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले गजटेड अधिकारियों से, जिनके सम्बन्ध में राजकोष

से बिजली का खर्च नहीं काटा जा सकता, कहा है कि वे बिजली के उन कनेक्शनों के लिये नकद जमानत जमा करें जो कि उनको 26 नवम्बर, 1964 से पहले दिये गये थे। 26 नवम्बर, 1964 के पश्चात सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले गजटेड अधिकारियों को कनेक्शन निर्धारित स्केल में नकद जमानत जमा करने पर दिये जा रहे हैं। यह उन गजटेड अधिकारियों को लागू नहीं होता जो कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और छावनी के क्षेत्रों में रहते हैं।

(ख) प्रभावित अधिकारियों की कुल संख्या लगभग 4500 है।

(ग) नकद जमानत न लेने पर, दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने यह देखा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्वार्टरों को, स्थानान्तरण पर अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्वार्टर बदले जाने पर, खाली किया, किन्तु उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द करने के लिये नहीं कहा। उनमें से बहुत तो अपनी आखिरी अदायगी किये बिना ही क्वार्टर छोड़ गये और परिणामस्वरूप उपक्रम को पैसे वसूल करने में बहुत कठिनाई हुई। और भी, जब एक अधिकारी, दूसरे अधिकारी द्वारा खाली किये गये मकान पर कब्जा करता था, तो नया अलाटी पुराने अलाटी के नाम पर रजिस्टर हुए कनेक्शन से बिजली का प्रयोग करता जाता था और बिल की अदायगी के बारे में झगड़े खड़े हो जाते थे, जो कि काफी देर तक चलते रहते थे।

(घ) नोटिस देने के 15 दिन के बाद बिजली की सप्लाई का कनेक्शन काटा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन नहीं काटा गया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली के अन्दर भिन्न-भिन्न भागों में अलग अलग ढंग से पैसे लिये जाते हैं और हर भाग के अन्दर अलग अलग इसके नियम हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : दिल्ली में एक तो दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग का एरिया है और एक एन० डी० एम० सी० का एरिया है। यह बात सही है कि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पैसे लिये जाते हैं। चूंकि दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को कुछ दिक्कत है इस लिये उन्होंने ऐसा नियम बनाया है। एन० डी० एम० सी० में चूंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसलिये वह दूसरे ढंग से ले रहे हैं। अगर इनको दिक्कत आयेगी तो वह भी ऐसा ही नियम रक्खेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : दिल्ली में जितने भी मीटर लगाये जाते हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा न होने के कारण प्रति वर्ष उनकी चोरी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एक साल में कितने मीटर चोरी जाते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : चोरी होना कोई खास दिल्ली की बात नहीं है। चोरी हर जगह होती है। कितनी चोरियां हुई, यह तो मैं नोटिस मिलने पर ही बतला सकता हूं।

श्री अ० सिं० सहगल : जो नई स्कीम बनाई गई है उसे लागू करने में आपको कितना समय लगेगा, ताकि सब जगह बराबर रेटस हो जायें।

श्री श्यामधर मिश्र : यहां पर रेट्स का कोई सवाल नहीं है। यह मीटरों का सवाल है। दिल्ली एलेक्ट्रिक सप्लाई

अंडरटेकिंग एरिया में गजेटेड आफिसर्स से सरकार की गारेन्टी के बजाय मीटर का पैसा देने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : दिल्ली में अब क्या विशेष बात पैदा हो गई है जिसके कारण सरकारी जमानत रद्द की जा रही है, और नकद पैसा लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्टेटमेंट में समझाया गया है। आपने स्टेटमेंट को देखा नहीं है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि जिनसे 25 फरवरी, 1965 तक जमानत का पैसा मांगा गया था और उन्होंने उसे जमा नहीं किया ऐसे कितने लोगों के मीटर अब तक काटे गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : अभी कोई मीटर काटा नहीं गया है। अभी केवल नोटिस दी गई है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : तो क्या जमानत जमा कराने की तारीख बढ़ाई जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र : इसकी तारीख बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। जब फिर से नोटिस दिया जायेगा तो यह लागू हो जायेगा।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैं इस प्रश्न के मूल में न जाता हुआ यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि इस निर्णय से पूर्व सरकारी कर्मचारियों से बिजली के बारे में कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्टेटमेंट में दिया गया है।

श्री यु० सिं० चौधरी : अब से पहले क्यों नहीं ली जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अब क्यों ली जाती है।

श्री यु० सिं० चौधरी : स्टेटमेंट हमें मिला ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मैं पता कर लेता हूं कि क्यों नहीं मिला। जिन्होंने मांगा होगा उन्हें जरूर मिला होगा।

श्री यशपाल सिंह : अभी लाखों कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। तो सरकार का इससे क्या नुक्सान हो रहा था। जैसे इस वक्त लाखों लोग ले रहे हैं उसी तरह से अगर इन कर्मचारियों को भी इससे एग्जेम्पट कर दिया जाता तो क्या नुक्सान था सरकार का।

अध्यक्ष महोदय : यह सभी बातें स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं।

श्री यशपाल सिंह : इसमें डिटेल्स नहीं हैं हैं।

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): In the DESU area, there are 2,75,000 consumers, and out of that number, cash security is being demanded from the Gazetted government officers residing in the Government quarters, who number about 4,500.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether Government are thinking of finding out some *via media* so as to enable the very-low-paid Government servants to pay the amounts which are sometimes very big?

Dr. K. L. Rao: In the case of the non-gazetted Government servants, there is no cash security. The guarantee is given by the Government Department.

Shrimati Savitri Nigam: My question has not been answered.

Mr. Speaker: The hon. Minister has said that this requirement does not apply to that category.

Shrimati Savitri Nigam: I wanted to know whether the arrears which amount to big sums would be allowed to be paid in instalments?

Mr. Speaker: Let the arrears remain. That is a different question altogether.

Houses for Industrial Workers

+

381. { **Shrimati Savitri Nigam:** **Shri J. B. Singh:** **Shrimati Renu Chakravartty:**

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the proposal to bring forth legislation to make it obligatory on the part of the employers to build houses for industrial workers has been finalised; and

(b) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The question of making it obligatory on the part of employers to build houses for Industrial workers was considered in the Housing Ministers' Conference held at Chandigarh on the 29th and 30th December, 1964. The Conference has recommended that for the time-being additional facilities like grant of 100 per cent financial assistance under the Subsidised Industrial Housing Scheme, relief in income-tax, allotment of land at cost price and release of controlled building materials for workers' housing, may be given to industrial employers, with a view to encouraging them to provide houses in large numbers for their workers. The Conference has also recommended that if despite these additional facilities the employers' response continues to be unsatisfactory, then the Government might consider the question of enacting suitable legislation for making it obligatory for the employers to provide housing for a certain percentage of their workers. These recommendations are under consideration.

Shrimati Savitri Nigam: Have the various departments of Government already taken as cue from these suggestions and formulated adequate plans to house all the government servants?

Shri Mehr Chand Khanna: I am sorry the question is not clear to me.

Mr. Speaker: The question is whether Government as an employer has implemented this recommendation and provided houses for its employees.

Shri Mehr Chand Khanna: This ques- question only relates to private employers. So far as government construction under the public sector is concerned, the scheme provides for the construction of houses up to a certain limit. As far as the private employers are concerned, as I have stated many times before in the House, we are not receiving enough encouraging response from them in the matter of construction of houses for their workers.

Shrimati Savitri Nigam: First of all, my first question has not been clearly answered. There are many industries under the public sector. Has the hon. Minister taken care to see that people employed in these public undertakings have been given this facility of housing and other facilities which he has recommended to the private employers or not? That was my question.

Shri Mehr Chand Khanna: As regards public undertakings under the charge of my Ministry, I have taken adequate care and precaution, and am at one with the questioner, that we should do everything possible for them.

Shrimati Savitri Nigam: My second question is. . . .

Mr. Speaker: No, Madam, Shri Oza.

Shri Oza: Has Government any information about the percentage of employees already getting residential accommodation? Also, what is the percentage contemplated by the Works and Housing Ministry to be provided by the employers?

Shri Mehr Chand Khanna: The percentage is not very high; it is rather small. That is the main reason why we have taken up this question with a view to see that more houses are built for industrial workers.

Shri A. P. Sharma: The hon. Minister said that if the progress is not found satisfactory, he will see that certain steps are taken to make it satisfactory. What are the steps taken so far? How do Government obtain reports from the private employers about the progress made in this direction? What is the latest report?

Shri Mehr Chand Khanna: The latest position is about the same. Previously we were giving 50 per cent loan and 25 per cent subsidy; now our intention is to give 75 per cent loan and 25 per cent subsidy so that the load on an industrialist *vis-a-vis* the industry is reduced to the minimum. If in spite of this encouragement we do not find enough response, then the matter may have to be considered. The Finance Ministry, Planning Commission, Industry Ministry, Commerce Ministry and my Ministry are concerned. It is rather a big question which will have to be considered.

Shri P. R. Chakraverti: In the context of the unambiguous statement of the hon. Minister that more than two thirds of the people are living in shanties and hovels, may I ask whether the private industrialists had pointed out some difficulties which they have to surmount if some facilities are not made available to them?

Shri Mehr Chand Khanna: I think my statement was very clear and encouraging, it is not ambiguous. The position of the private employer is fully known to all of us. If they could save some money, they put it to the advancement of the industry; they are not very keen to divert it to housing.

श्री विभूति मिश्र : मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए जिन चीनी मिल मालिकों को सरकार की तरफ से सबसिडी और लोन दिया गया है उन्होंने उस पैसे को ले कर आज तक मकान नहीं बनाए हैं । क्या सरकार इस की जांच पड़ताल करेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : : दूसरी बात का तो मुझे इल्म नहीं है । लेकिन पहली बात के बारे में मैं ने कहा कि यह किसी कदर दुरुस्त है कि जिस तरह से उन को इन लोगों की सेवा करनी चाहिए थी वह उन्हों ने नहीं की ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के अन्दर क्या कुछ मालिकों के भी प्रतिनिधि थे और यदि थे तो उन्हों ने क्या सुझाव दिये, और क्या सरकार का यह विचार है कि जिन मजदूरों की भविष्य निधि जमा है उन्हें व्यक्तिगत मकान बनाने के लिए लोन दिया जाय ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक इस कानफरेंस का ताल्लुक है हम ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के नुमायन्दों को बलाया था, दो आए थे । उन्हों ने अपनी तकलीफात हमारे सामने जाहिर कीं : जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का और हमारा ताल्लुक है, हम यह चाहते हैं कि जितने भी मकान इन के लिए बन सकते हैं बनाए जाये ।

Shri Indrajit Gupta: Very often the private sector employers put forward the plea, particularly in built-up areas that it is not possible to get land even if they wanted to construct houses and in view of that may I know whether this Housing Ministers' Conference has taken any decision whereby employers who are genuinely interested in building houses may be helped by the Central or State Governments to get the necessary land through acquisition measures?

Shri Mehr Chand Khanna: We have gone into this question and for that very purpose we have also appointed a committee under the chairmanship of Mr. Thacker of the Planning Commission. We want to

tackle this problem from two aspects. If there is difficulty in the matter of acquisition of land we want to see that the procedure is simplified so that land for the construction of houses in the industrial sector can be made available. Secondly, this committee will also examine, where in certain circumstances it has been stated to us that vast lands were acquired by industrialists for industrial purposes of which a large part is still lying unused, whether part of that land could not be diverted for construction of industrial houses.

श्री भागवत झा आजाद : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आवास की जो सुविधायें हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, उन की बहुत कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने जो इस काम के लिए जो अनुदान और कर्ज दिए हैं, यद्यपि वे सीमित हैं, उन का ठीक उपयोग किया गया है या नहीं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : वह तो मैं ने कहा कि जितने मकान उन्हें बनाने चाहिए उतने उन्होंने नहीं बनाए हैं, बहुत थोड़े बनाए हैं। कहीं पर कहते हैं कि जमीन नहीं मिलती है, कहीं कहते हैं कि पानी नहीं मिलता . . .

अध्यक्ष महोदय : जो रुपया दिया गया उस का पूरा उपयोग हुआ या नहीं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह जो चीज हम करते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट्स की मारफत करते हैं। अगर किसी खास योजना या इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो मुझे बतलाया जाये, मैं मालूम कर के बता सकूंगा।

Shri P. Venkatasubbaiah: In view of the fact that there has been a very unsatisfactory progress so far as private sector is concerned in providing accommodation to industrial workers, may I know whether the Government would make it a matter of policy to insist upon a condition precedent to provide accommodation for the industrial workers whenever a licence is issued for a private-sector industry?

Shri Mehr Chand Khanna: That question has been examined, it is fraught with difficulties.

Shri D. C. Sharma: Have any decisions been taken to take action, punitive, financial or social, against those industrialists who did not build houses for any valid reasons?

Shri Shinkre: What does he mean by 'social'?

Mr. Speaker: Whether any action has been taken against those who did not spend the money—that is what he wants to know.

Shri Mehr Chand Khanna: There is no compulsion in a matter of this nature.

शान्तिवन, दिल्ली

\+
*382. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती:
श्री रा० बरुआ :
श्री रामसेवक :
श्री क० गो० सेन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शान्तिवन के विकास के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य मख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). शान्तिवन में दरख्त लगाने और डीयर पार्क बनाने का विचार है। इस योजना को हम दो हिस्सों में चलायेंगे, जो जल्दी की योजना है उस में निचली जमीन को भरा जा रहा है, और

समाधि तक पैदल चलने वालों के लिए रास्त बना दिया गया है और समाधि के चारों तरफ एक जंगला बना दिया जायेगा । जो बड़ी योजना है वह विचाराधीन है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिए कितनी भूमि निर्धारित की गयी है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : भूमि तो इस के लिए वहां बहुत ज्यादा है । मुझे जबानी तो याद नहीं है । लेकिन हमारा इरादा है कि राजघाट से ले कर पुराने किले के दूसरे कोने तक जितनी भी जमीन पड़ी है हम उस को इस तरह इस्तेमाल करें कि उस पर कोई खास मकान वगैरह न बनें, उस जगह को साफ रखें । शायद वह जमीन 70 एकड़, या 100 एकड़ या 150 एकड़ है । मुझे जबानी याद नहीं है, लेकिन काफी जमीन है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह सही है कि जिस जगह का मंत्री जी ने जिक्र किया है वहां गन्दगी बहुत ज्यादा है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है, जहां पर बहुत से लोग बाहर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं । क्या इस गन्दगी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी हां, गन्दगी वहां बहुत ज्यादा थी । हम शान्तिवन के इलाके को भी साफ कर रहे हैं और उस के सामने का जो इलाका है वहां से तमाम झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया गया है, वहां हम चमन बना रहे हैं और जगह को साफ कर रहे हैं और इरादा यही है कि वह एक शानदार और मतबर्रक जगह बन जाये जोकि हिन्दुस्तान की शान के शायां हो ।

Shri Basumatari: May I know whether this plan is under the direct charge of the Minister of Works and Housing or whether any committee has been set up so that they may go into it?

Shri Mehr Chand Khanna: The Ministry which is in charge of this, is the Ministry of Works and Housing. But, as I said just now, a committee has been appointed which would help my Ministry in the matter of development of *Shantivana*.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या शान्तिवन में फलदार पेड़ लगाए जायेंगे, और अगर लगाए जायेंगे तो कितनी भूमि पर, और क्या इन फलों का उपयोग जनता के लिए किया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : दरख्त अभी लगे नहीं और फल खाने के लिए आप उत्सुक हैं ।

श्री यशपाल सिंह : जिन झुग्गी झोंपड़ी वालों को वहां से हटाया जा रहा है उन की सेवा के लिए तो नेहरू ने अपनी लाइफ डेडीकेट कर रखी थी । ये लोग तो उस जगह की शोभा बढ़ा रहे थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण हुआ कि इनको वहां से उजाड़ कर बेघर किया जा रहा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने एक दिन मेरी सराहना की थी कि मैं ने रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा काम किया है । मैं समझता हूं कि वह इस मामले में भी जल्दी ही मेरी सराहना करेंगे क्योंकि मैं उन गरीबों को जल्द बसा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह सरटिफिकेट तो उस वक्त के लिए था ।

श्री यशपाल सिंह : नहीं, अब भी मेरा वही खयाल है ।

Shri D. J. Naik: May I know what would be the cost for developing *Shantivana*?

Shri Mehr Chand Khanna: It is difficult for me to say it at the moment. But the plan is getting ready and we should be able to take a decision in regard to this within the next two or three months. After that, I shall be in a position to indicate the approximate financial implications.

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि शान्तिवन की योजना पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अभी यह बताना मुश्किल है, जब योजना तैयार हो जायगी तो बता सकूंगा ।

श्री अब्दुल गनी गोनी : मैं यह जानन चाहता हूं कि यह जो राजघाट और शान्तिवन को इकट्ठा करने की प्राजेक्ट बनायी जा रही है, इसमें शान्तिवन में एक बहुत बड़ी नरसरी लगाने के बारे में सरकार का क्या खयाल है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सजेशन है ।

श्री रतन लाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि शान्तिवन के विस्तार का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब दूसरी योजना तैयार हो जायगी और लौंग टर्म प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जायगी तब यह बतलाया जा सकेगा । मेरे खयाल में इस में समय तो लगेगा ।

श्री गुलशन : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे आंख से पकड़ने की कोशिश करें, कान से पकड़ने की नहीं ।

श्री गुलशन : अभी मंत्री जी ने बताया कि राजघाट और शान्तिवन को अच्छा बनाने के लिए सौ एकड़ के लगभग जमीन एक्वायर की जा चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस का अन्दाजा लगाया है कि अगर दस प्रधान मंत्री शान्त हो जायें तो उन के लिए कितनी भूमि शान्ति घाट बनाने के लिए होनी चाहिए, सारी दिल्ली होनी चाहिए या बाहर से जमीन एक्वायर की जायेगी ?

Mr. Speaker: I do not allow the question.

Prevention of Pollution of Jamuna Water

\+

*383. Shri Surendra Pal Singh:
Shri R. G. Dubey:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Heda:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two projects have now been finalised to check the inflow of flood waters into the Jamuna river near Wazirabad in order to prevent pollution of the Capital's supply of drinking water; and

(b) if so, the main features thereof and the financial implications of the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The following two projects for the prevention of pollution of Jamuna water are being taken up:—

(1) (a) *Embankment from Tail Regulator to Shah Alam Bridge.*

This work has been taken up by the Delhi Administration recently at an estimated cost of Rs. 3,10,000.00. About 2½ lakhs cft. of earthwork was done upto the middle of February, 1965.

(b) *Excavation in rock of the outfall which joins Jamma 1,400 ft. below Wazirabad.*

This work is to be done by the Karnal Drainage Circle of the Government of Punjab. The work has recently been started. The target for

completion of this work is June, 1965. The estimated cost of this work is Rs. 1,90,500.00.

(2) (a) *Bund along the left bank of Burari Drain on a length of 7,100 ft.*

This work is to be done by the Delhi Administration this year and the estimated cost is Rs. 6,17,700.00. Tenders for the work have already been received and the work is being awarded.

(b) *Regulator at the tail-end of the Burari Drain*

This work is also to be done by the Delhi Administration. The design is being prepared by the Central Water and Power Commission. The estimate is not yet ready.

Shri Surendra Pal Singh: We learn from the statement that in respect of Project No. 1, the work of constructing an embankment from Tail Regulator to Shah Alam Bridge, has been entrusted to the Delhi Adiministration and the excavation in rock of the outfall which joins Jamuna 1,400 ft. below Wazirabad is to be carried out by the Punjab Government. May I know why these two works of one project have been entrusted to two different agencies and what steps have been taken to co-ordinate the work on these two projects so that the work at both the places is completed in time according to schedule?

Shri P. S. Naskar: The work of flood prevention is given to Delhi Administration because item No. 1 falls within the jurisdiction of Delhi Administration. The second work mentioned by the hon. Member falls within the jurisdiction of the Punjab Government. For the flood control and co-ordination the Irrigation Ministry is responsible and it looks after the work of co-ordination.

Shri Surendra Pal Singh: Is it a fact that the services of some foreign experts have been invited by the Government of India to advise them in solving this problem of water pollution; if so, do we take it that our own Public Health Engineers and experts are not competent to handle this problem and we need foreign help?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): No, Sir. We have not taken the services of any foreign expert. There is a Public Health Engineer of the US AID who has been placed here for such consultations as our experts may like to have with him. There may have been some consultations but we have not called for any help from outside.

Shri Surendra Pal Singh: What about Mr. Taylor from U.K. who is coming on the 26th of March for this very purpose?

Dr. Sushila Nayar: The Delhi Municipal Corporation had asked for a labartory on the pattern of the laboratory set up in London. I think the suggestion was made by the hon. Minister, Dr. K. L. Rao, who had seen that laboratory. Assistance was asked for under the Colombo Plan for equipment etc. and so they are sending their expert to have a look round.

Shri R. G. Dubey: May I know whether the Dhassa Bund has any connection with these projects and whether, in that case, it will remain as at present or there will be some changes?

Dr. Sushila Nayar: I am sorry, my hon. colleague Dr. Rao knows more about Dhassa Bund than I do.

Mr. Speaker: Why should she be sorry about it that Dr. Rao knows more about it?

Dr. Sushila Nayar: I am sorry that I cannot answer the question.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): It has nothing to do with it. Dhassa Bund has nothing to do with these projects.

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that time is running against us. . . .

Mr. Speaker: Therefore, she should be very precise with her question.

Shrimati Savitri Nigam: In the statement it has been mentioned that this work is also—Regulator at the tail-end of the Burari Drain—

to be done by the Delhi Administration. The design is being prepared by the Central Water and Power Commission. The estimate is not yet ready. I would like to know whether this regulator will be ready by the end of June or beginning of July which are the worst months as far as pollution of water is concerned?

Dr. K. L. Rao: The works are in good progress. We expect them all to be completed in time before we get the rain water.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : इन दोनों परियोजनाओं की कब तक पूर्ति हो जायेगी ?

Mr. Speaker: When will it be completed?

Dr. K. L. Rao: We expect the work to be completed by the end of June.

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी ने सवाल का जवाब देते हुए जो स्टेटमेंट सभा की मेज़ पर रक्खा है उस के (2) (ए) में लिखा हुआ है कि इस बंद के काम पर तकरीबन 6 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत आयेगी

"Tenders for the work have already been received and the work is being awarded".

अभी मंत्री जी ने कहा कि यह काम जन-जुलाई तक पूरा हो जायेगा तो मेरा कहना है कि यह 6 करोड़ 17 लाख रुपये के काम के लिए टेंडर्स अभी आप के पास आये हैं और यह काम सौंपा जा रहा है, अब सभी लोग और अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि यह कब तक पूरा हो सकेगा इसलिए सरकार साफ साफ कहे कि यह काम कब तक पूरा होने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : अब मिश्र जी, अंदाज उन्होंने जून के आखिर तक का बतलाया है लेकिन हो सकता है कि जुलाई हो जाये ।

श्री विभूति मिश्र : अब जैसे आप को सब को इस बात का ज्ञान है कि इस समय साढ़े ग्यारह बज रहे हैं उसी तरह से जब मंत्री जी के पास टेंडर्स पहुंच चुके हैं और काम सौंपा जा रहा है तो वे इसको मजबूती के साथ कहें कि अमुक समय तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

Shri P. S. Naskar: The hon. Member has made a mistake. It is not work worth Rs. 6 crores and odd. It is work worth Rs. 6 lakhs and odd.

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में दूसरा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने नुक्ता एक जगह से हटा कर दूसरी जगह रख दिया है ।

श्री क० ना० तिवारी : इस स्टेटमैंट में यह दिया गया है कि इन कामों पर कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया लगायेगी और कुछ पंजाब गवर्नमेंट लगायेगी तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट इस पर कितना खर्चा बर्दाश्त करेगी और केन्द्रीय सरकार कितना बर्दाश्त करेगी ?

Dr. K. L. Rao: The works are executed by the different agencies but the total cost will be borne by the Delhi Administration.

Shri Heda: May I know whether the hon. Minister is in a position to give an assurance to this House and the people of Delhi that at least this year we will get water which is not polluted and that also in adequate quantities?

Dr. Sushila Nayar: So far as the Health Ministry is concerned, we can give this assurance that we shall treat the water very well, as we did last year, so that the people do not suffer. So far as flood control is concerned, it is the responsibility of my colleague. He is doing everything possible in that direction.

श्री रामेश्वरानन्द : यमुना के पानी को शुद्ध करने की अपेक्षा क्या दिल्ली में कोई ऐसा स्थान नहीं मिल सकता है जहां कि ट्यूबवेल लगा कर शुद्ध पानी जनता के पीने के लिए निकाला जा सके । ताकि

स्वास्थ्य पर उस का कोई हानिप्रद असर न पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के इस सुझाव पर भी गौर कर लिया जायेगा।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की ओर से मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कहा कि यमुना का पानी खराब होता जाता है और उसे शुद्ध करने की बनिस्बत दिल्ली में उपयुक्त स्थान पर ट्यूबवैल लगाये जायें ताकि उनसे पीने के वास्ते शुद्ध जल निकाला जा सके, उस पर मैं ने मिनिस्टर सहाब से कहा कि वे इस पर विचार कर लें अब और इस से ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : कोई एसी योजना है उन के पास ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं मंत्री जी को कह रहा हूं कि कोई एसी योजना बे ताकि स्वामी जी को तसल्ली हो ।

Unemployment during Fourth Plan

+

*384. **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri Yashpal Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Hem Barua:
Shri Mohan Swarup:
Shri Indrajit Gupta:
Shri P C. Borooah:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 503 on the 1st October, 1964 and state:

(a) whether all those development schemes and the guiding principles which would be ultimately responsible for removing unemployment during the Fourth Plan period have been finalised; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Work on development programmes under the Fourth Plan is still in progress.

(b) Does not arise.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether the Commission has decided how much will be invested in each of the sectors—cottage industries, heavy industries and small-scale industries—in order to provide employment?

Shri B. R. Bhagat: Yes, Sir. The preliminary memorandum contains all the information.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether all the schemes, such as manpower utilisation scheme and others, which are aimed at solving unemployment, are going to be repeated in the Fourth Plan?

Shri B. R. Bhagat: They will not only be repeated but revised and expanded in the Fourth Plan.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के पास इस तरह का कोई हिसाब है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तो उस वक्त कितने बेरोजगार हिन्दुस्तान में रह जायेंगे ? कितने देहातों में होंगे और कितने शहरों में होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : हां, मौटे तौर से मैं कह सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक 13 मिलियन आदमियों को काम मिलेगा और जो बेकार आदमी रह जायेंगे उन की संख्या 23 मिलियन होगी ।

Shri Ranga: How many in towns and how many in villages?

Mr. Speaker: He says he has not got the figures for the villages.

Shri S. M. Banerjee: As the unemployment figures will increase after the Third Plan is over, apart

from giving some general assurances to the people, has the Government in mind some schemes like unemployment insurance for those who are registered as unemployed for inclusion in the Fourth Plan?

Shri B. R. Bhagat: We are opposed to unemployment doles. So far as the question of providing unemployment insurance is concerned, it is being examined.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम इस बात के साक्षी हैं कि सरकार ने जितने व्यक्तियों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, उतने व्यक्तियों को वह रोजगार नहीं दे सकी । माननीय मंत्री ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुछ अनुमानित आंकड़े दिये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा कि सरकार जितने लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दे, उतने व्यक्तियों को काम में खपा सके ।?

श्री ब० रा० भगत : तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 140 लाख यानी 14 मिलियन आदमियों को काम देने का टारगेट बनाया गया था । उस के बजाये 130 लाख यानी 13 मिलियन आदमियों को काम मिला । यह बात सही कि जितने आदमियों को काम देने का टारगेट बनाया गया था, उन से कम आदमियों को काम मिला । ऐसा योजना के पूरी तरह से कार्यान्वित न होने के कारण हुआ या इस कारण हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय टारगेट--फिनांश्ल टारगेट--तो पूरे हो गए, लेकिन दाम बढ़ने के कारण फिजिकल टारगेट में कुछ कमी रही । पिछले अनुभव के आधार पर हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनी आपेरेशनल एफिशेंसी को बढ़ा सकें, फेज्ड प्रोग्राम बना कर फिजिकल प्रोग्राम को पूरा कर सकें और उस के आधार पर टारगेट पूरा किया जा सके ।

Shri P. R. Chakraverti: Keeping in view that there will be more than 30 million unemployed at the end of this Plan, may I know whether Government propose to introduce some measure for giving them relief in the form of security measures?

Shri B. R. Bhagat: Apart from trying to absorb all the new entrants during the Fourth Plan, we are working out some scheme of unemployment insurance. We are examining it. We have to work out the financial and other aspects of it first.

श्री विभूति मिश्र : हमारें मंत्री जो बड़े न्यायी आदमी है और वह लोंगो को रोजी-रोटी देने के सम्बन्ध में योजना बना रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि देश के हर इलाके के लोगों के साथ समान रुप से न्याय हो और उन सब को ठीक तरह काम मिलें ।

श्री ब० रा० भगत : इस पर पूरी तरह से विचार किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : इस पर ठीक विचार नहीं किया जाता है ।

श्री क० ना० तिवारी: जिस तरह थर्ड फ़ाइव-यीयर प्लान में शार्टफ़ाल हुआ है, उसी तरह सम्भव है कि फोर्थ-फाइव यीअर प्लान में भी शार्टफ़ाल हो उस हालत में मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या इस बात का तख़मीना लगाया गया है कि कितने लोग बेरोजगार रह जायेंगे और उन को रोजगार देने की क्या व्यवस्था की गई है ।

श्री ब० रा० भगत : अध्यक्ष महोदय, पिछले जवाब में जो अशुद्धि रह गई थी, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं मैं ने चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू में बैकलाग 23 मिलियन बताया था 23 मिलियन तो नये लोग होंगे, जो कि काम खोजने आयेंगे । अनएम्पालायमेंट का बेकलाग 12 मिलियन होगा । चौथी पंच-वर्षीय योजना में प्रोग्राम पूरा हो,

इस के लिए हम इंटेंसिव लेबर स्कीम्ज ग्रौर रूरल वर्क्स की योजनायें बना रहे हैं ग्रौर हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम के फ़िज़िकल टारगेट्स पूरे करें ।

Shri P. C. Borooah: May I know whether it is a fact that in the formulation of the Fourth Plan the planners have in mind that it should be a production-oriented and not employment-oriented plan and, if so, what action is proposed to be taken to see that more employment opportunities are provided to the unemployed and under-employed?

Shri B. R. Bhagat: It will be both production-oriented as well as employment-oriented.

Shri S. N. Chaturvedi: May I know why Government is working at cross purposes by launching schemes like pre-fabricated houses which create or cause a lot of unemployment in the building trade?

Shri B. R. Bhagat: I do not know if pre-fabricated houses cause a lot of unemployment. If it is so, we have to find out other means of giving them employment.

Mr. Speaker: Probably he means they are not labour-intensive.

Shri Narendra Singh Mahida: Will the Minister give the figures of educated unemployed persons during the Plan period?

Shri B. R. Bhagat: I want notice for that.

श्री ग्रोंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बताई है क्या उस में खेतिहर मजदूर भी शामिल है हैं ग्रगर नहीं, तो सरकार उन के लिए क्या कर रही है ।

श्री ब० रा० भगत : वे भी शामिल हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार के ध्यान में यह बात ग्राई है कि कई कारखानों में मजदूरों क छंटन कर द गई हैं, जिससे बहुत से मजदूर बेकार हो गये हैं? क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाने का विचार कर रही है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में यह कार्यवाही न की जाये ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर लेबर मिनिष्ट्री समय समय पर ध्यान देती है ।

श्री शिव नारायण : सरकार ने कहा है कि वह १३ मिलियन लोगो को रोजी नहीं दे पाई है । मैं यह जनना चाहता हूं कि जिन को रोजी नहीं दी गई है, क्या उनको सबसिडी के तौर पर कुछ पैसा दिया जायेगा, ताकि वे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चला सकें ग्रौर क्या सरकार उनको पैन्शन देगी, जो कि फ़ारेन कंट्रीज में दी जाती है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस का जवाब दे दिया है ।

श्री शिव नारायण : पैन्शन के बारे में जवाब नहीं दिया है ।

Shri P. Venkatasubbaiah: In the Memorandum of the Fourth Plan, it has been stated that by the end of the Third Plan 3.5 million people will be employed in the agricultural sector so far as the increased agricultural production is concerned. If that is so, may I know whether that target will be reached and, if not, what would be the back-log for the Fourth Plan?

Shri B. R. Bhagat: So far as the agricultural sector is concerned, the actual achievement in agriculture during the Third Plan will be 3.5 million.

श्री बलजीत सिंह : मैं यह जनना चाहता हूं कि जो डेम्ज ग्रौर दूसरे प्राजेक्ट्स कम्पलीट हो चूंके हैं, वहां ग्रनएम्लायमेंट ज्यादा बढ़ गया है, क्या उस के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : यह तो अलग अलग स्कीमों का सवाल है । उन पर जरूर विचार कया जायेगा ।

श्री दलजीत सिंह : जो डैम और प्राजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं, जैसे भाकड़ा डैम, वहां लोग बेकार हो गए हैं । क्या उस बेकारी को दूर करने के लिए कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : जो दूसरे प्राजेक्ट्स बनते हैं, उन में उन लोगों को लगाने की कोशिश की जाती है या दूसरा काम देने की कोशिश की जाती है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : तब तक वे बेचारे क्या करेंगे ?

Shri Ranga: Is it not a fact that Government have not inaugurated or instituted any special schemes to provide employment to agricultural labour as such and that the under-employment from which they have been suffering has yet to be tackled?

Shri B. R. Bhagat: All these are very big problems and the hon. Member will realise that they cannot be tackled during the course of one Plan period. It has to be a programme over a period. We have been trying to tackle the problem in the Third Plan and in the Fourth Plan we are undertaking various schemes so as to provide more employment in areas where the incidence of unemployment is more due to concentration of population. We are also developing rural works and other schemes so as to provide more employment in the rural areas.

श्री भागवत झा आज़ाद : तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यह स्पष्ट हो गया है कि हर योजना में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है । क्या चौथी पंच-वर्षीय योजना में बाजार में आने वाले 230 लाख आदमियों का इन्तजाम होगा या 130 लाख लोगों का जो बेकलाग हैं, उस का भी इन्तजाम होगा होगा तो विकास योजनाओं और मार्गदर्शी सिद्धान्तों की किन बातों पर विचार किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : कोशिश यह की जा रही है कि चौथी योजना जो नई लेबर फोर्स है यानी 230 लाख जो अभी माननीय सदस्य ने बताई है, उनको पूरा का पूरा काम मिल जाए कम से कम इतना हो जाए । उसके बाद और पीछे जो लोग बचे हैं उनको भी जहां तक सम्भव हो काम मिल जाए ।

Foreign Capital

\+

*385. Shri D. C. Sharma:
Shri P. C. Borooah:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri D. B. Raju:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri M. N. Swamy:
Shri Harish Chandra Mathu
Shrimati Renuka Ray:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Daji:
Dr. Ranen Sen:
Shri Dinen Bhattacharyya:
Shri Bishwanath Roy:
Shri Brajeshwar Prasad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shrimati Ramdulari Sinha:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the question of giving incentives to bring about increased equity participation by foreign capital has been considered; and

(b) if so, the outcome thtreof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). Some incentives were being given all these years to capital investment which applied to

indigenous as well as to foreign capital and these together with certain additional incentives proposed in the Finance Bill, 1965 are listed in the statement placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3966|65].

Shri D. C. Sharma: May I know why it is that in spite of the incentives which our Government have been giving, the capital market, as described in financial papers or other Dailies and Weeklies, continues to be capital-shy?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The reasons for this are rather very deep. There has undoubtedly been a shift in the aount that people have for investment. It is also true that the classes which have been accustomed to invest in small measure probably do not have the money for purposes of investment. Also, the classes which have more money are not investing because they are not being approached. It is very difficult to pinpoint any particular factor as being something which contributes to the fact that flotations are not subscribed for freely.

There is another factor also, namely that people are not prepared to wait for a long time for a return on their investment.

Taking all these things into consideration, certain incentives have been provided by Government. One has to wait and see what will happen. But basically, my view is—and it is a purely personal view—that an approach to areas where there is capital for investment is not being made, and people who want capital or the brokers who raise capital stick to major cities and do not go out to the rural areas.

Shri Ranga: Where is the money in the rural areas?

Shri D. C. Sharma: To have foreign capital in a country is playing with fire, as has been the experience of the African, Latin American and other countries of the world. And those countries are trying to get rid of the foreign capital by measures of expropriation and other things. May I know what guarantee Government are going to have that the foreign capital does not have any political repercussions on our democratic structure in this country?

Shri T. T. Krishnamachari: The same conditions that we have in regard to curbing political influence of indigenous capital.

Shri P. C. Borooah: May I know whether some special concessions which are not given to Indian entrepreneurs are proposed to be given to the foreign investors, and if so, what those concessions are, and to which investments these concessions will be extended?

Shri T. T. Krishnamachari: The concessions generally are common excepting for the fact that we allow foreign capital to be repatriated, and also the dividends. Another set of concessions which are being given in collaboration with the countries from which capital is imported is that the Governments of those conntries—two of them particularly, the United States Government and the Government of West Germany—have insured those companies which bring capital into India, against possible loss.

Shri P. C. Borooah: Will there be a tax holiday?

Shri T. T. Krishnamachari: The tax holiday is common to everybody.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि जिन क्षेत्र से पूंजी प्राप्त हो सकती है उन क्षेत्रों से पूंजी इसलिए प्राप्त नहीं हो सकी है उन से उचित सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका है । मैं जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों से पूंजी प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री भविष्य में किस तरह सम्पर्क स्थापित करने की सोच रहे हैं, कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

Shri T. T. Krishnamachari: A Minister of the Government of India is not an agent of any particular group of people who want to raise capital. Private capital has got to be secured by private people and they have got to canvass for it; it is not

possible to expect a Minister or anybody else here to go and do the canvassing for them.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ग्राश्वाशन दिला सकती है कि ग्रधिकतम शेयर भारतीय होंगे ।

श्री ब० रा० भगत : ग्रभी तक तो यह है कि जिन में बाहर से हम शेयर लेते हैं उन में ज्यादातर भारत.य ही होते हैं

Shri P. R. Chakraverti: Has Government examined the basic question whether increasing equity participation of foreign capital is desirable or loan from foreign countries is preferable to the former in the interest of the country?

Shri T. T. Krishnamachari: The difference between loan and capital is this. Loan is something which has to be returned fairly early and the people who put the money in it are not really interested in anything else. Capital is a thing which generally stays, and even though we allow terms for repatriation, it is very rarely that capital is repatriated, and they plough in their profits oftentimes, as companies have done in India. From a long-term point of view, as between loan and capital, capital is preferable; but it is a matter of individual judgment.

Shri Harish Chandra Mathur: What is the hon. Finance Minister's vision of the capital he wants to invite? What will satisfy him in the present state of our economy, and what, he thinks, is not likely to distort the state of affairs here?

Shri T. T. Krishnamachari: This raises a very big question. According to our Fourth Plan projections of estimates, we need a little more of foreign assistance not only for the purpose of establishing new industries but also for the purpose of paying back the monies due. The question is whether this should be available in the form in which it has been coming, whether something should not be added to it by way of foreign private capital investment. But then the hon. Member should also be aware that we are not the only country wanting foreign private capital. There are very many other countries, Canada, Australia, Brazil, not to speak of some of the European Common Market countries and the countries in Africa. These are there. So it is very difficult to say how much of it will be coming.

The real point about it is this. If capital comes on our terms—and those terms are very clear—it is welcome; if capital will only come on their terms, I am afraid we will say we do not want it. I will make it very categorical that while India needs foreign assistance and foreign capital, she is not prepared to take it on other people's terms.

Shri Ranga: Let us not try to be brave!

Shri T. T. Krishnamachari: May be. I am sorry. We are both of the same age; but we have been born differently. My hon. friend does not want to be brave. I do want to be brave because I think all my friends here are brave.

Shri Ranga: You are very brave indeed!

Shri T. T. Krishnamachari: Therefore, while we give every possible concession to foreign capital consistent with our self-respect, we are not taking it on terms not acceptable to us.

The hon. Member might ask: 'what is your estimate?' I cannot say. We are having it in a trickle. Another factor we have to take into account is that not only are we suffering from difficulties in foreign exchange; many countries are suffering from difficulties in balance of payments.

The United Kingdom, for instance, even the United States. They are putting restrictions on foreign lending and foreign investment. The climate at the moment may not be very good

but things do change. Therefore, we take a long-range view of things and make our preparations subject to our principles and our self-respect.

Shri Ranga: The Finance Ministers also must change.

Shrimati Renuka Ray: Is the Government aware that some of these concessions which are meant to encourage foreign investment in the equity capital of Indian companies had led to some mal practices by which the high-ups in some of these companies seem to have swelled their bank accounts abroad and, if so, is Government taking any steps about plugging these loopholes by which unaccounted money in foreign exchange is being acquired.

Shri T. T. Krishnamachari: The concessions have not given rise to any abuses.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether the foreign investors find it rather difficult to make investments because the scope of the existing exemption is limited only to priority industries?

Shri T. T. Krishnamachari: That is so, Generally priority industries which we want to establish are industries which we try to encourage, and if foreign capital is needed for that purpose, foreign capital is encouraged to come in.

Shri H. N. Mukerjee: From the point of view of the independence of our economy and at a time when foreign capital is being shoed out in most underdeveloped countries which have got a policy of some kind of socialism.

Shri Ranga: Question.

Shri H. N. Mukerjee: . . . the policy of this country had been to prefer foreign loans as a lesser evil to foreign private capital. Do I take it that the Finance Minister in his individual judgment, to which he referred several times in his reply, has given a new shift to Government policy? Or, is it that the Government has made up its mind about giving a welcome to foreign private capital which, experience shows, is very dangerous to us?

Shri Ranga: Question.

Shri T. T. Krishnamachari: The hon. Member is trying to put words in my mouth. At any rate, merely because of the fact of being old, I am not quite so easily caught. The position is really this. We have been asking for foreign loans. We feel that the quantum of foreign loans may not be adequate; maybe the conditions of these loans are particularly acceptable to us, partly because of the terms, party because of the repayment conditions. So, we would like a sort of top dressing of foreign capital if it comes because it has certain advantages, a sort of a linking of a particular foreign capitalist with an institution here, and make him develop the institution. There are various other factors also such as the question of postponement in regard to repatriation. But one factor which I would like the hon. Members to understand is this whatever foreign capital comes, it is not coming in as a flood, it is coming in only as top dressing; it is never likely to come in as a flood. Therefore, all this bogey of foreign capital coming here and the Government yielding to the persistent demands of foreign capitalists, I am afraid, is somewhat outside the mark.

Shri Indrajit Gupta: The hon. Minister has just said that foreign private capital participation in equity capital will be acceptable only on our terms and conditions and not on terms dictated by anyone else. May I know from him how this very welcome assurance will operate in the case of West German private capital participation which, as we can see from examples of the other countries, certainly dictates its own terms in respect of the relations of the receiving countries with the other German Government, of East Germany, and any assistance that may be coming from there?

Shri T. T. Krishnamachari: My hon. friend is trying to mix up the two issues. One is coming in of capital from West Germany. The other thing is mixing up of their own particular proclivities in regard to the relationship with their neighbour country, which was part of their own territory. I am afraid these are completely distinct issues. If West German capital comes in here, it comes, as I said, on terms acceptable to us, but if the condition is going to be something else, those conditions have to be determined by other circumstances, not by the question of capital coming in.

Shri Bishwanath Roy: In view of the industrial policy of the Government, may I know whether, as a result of the incentives proposed or given to the foreign capital, the Indian economy would be affected adversely in course of time?

Shri T. T. Krishnamachari: I would like to assure the hon. Members that nothing will be done, whether by means of allowing foreign capital to come in or by encouraging Indian capital to invest, which will ultimately affect either the economy of this country or the balance of political power that exists in the country.

Shri R. S. Pandey: Is it not true that many foreign investors are willing to come on the condition of equity participation, but that at the same time they have complaints against delay and lack of favourable conditions in this country? May I know where the Government stands?

Shri T. T. Krishnamachari: That people complain of delay is a thing which is known, it is a thing which I am cognizant of. We are trying to remedy the position. But the question of favourable conditions is something which I am not able to understand, because things change from concern to concern. All that we can do is this, we can hold the carrot, but I have no influence to make the donkey take it.

Shri D. C. Sharma: I do not know if foreign countries would like it.

Fourth Plan

+

*386. Shri P. C. Borooah:
Shri Yashpal Singh:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri S. C. Samanta:
Shri R. S. Tiwary:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri J. B. S. Bist:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Harish Chandra Mathur:
Shri Sivamurthi Swamy:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hem Raj:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Man Sinh P. Patel:
Shrimati Renuka Ray:
Shri R. S. Pandey:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri K. C. Pant:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri P. K. Deo:
Shri Kapur Singh:
Shri Narasimha Reddy:
Shri R. Barua:
Shri L. N. Bhanja Deo:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have re-examined the Fourth Five Year Plan allocations in the light of the recent discussions of the National Development Council on the Plan proposals; and

(b) if so, decisions taken in this regard?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). The National Development Council having generally endorsed the proposals of the Planning Commission regarding the size and objectives of the Fourth Plan, constituted five committees to advise on policy issues concerning the

formulation of sectoral programmes and resources for the Fourth Plan. The Committees have not yet completed their work.

Shri P. C. Borooah: Since the Planning Commission have decided to adhere to their original proposal of making the Plan outlay Rs. 22,500 crores, may I know what steps are being taken to remove the misgivings from the mind of the public including the Congress President, Shri Kamaraj, that the Plan has got inflationary potential?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): These matters are now being examined, and I hope to be able sometime, probably when I reply to the Budget discussions in this hon. House, to make the position clear.

Shri P. C. Borooah: May I know whether the Planning Commission consider that there should be some little bit of additional taxation to curb inflationary pressures, and if so, what is the Government's idea about the additional taxation required to curb this inflation?

Shri B. R. Bhagat: The Committee on Resources which is going into this matter, which met once and which is going to have more meetings, will consider all this.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि यह जो निर्णय लिये गये हैं उनको कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा जिससे कि सदस्य लोग उन पर गौर कर सकें ।

श्री ब० रा० भगत : मेमोरन्डम तो रख दिया गया है, और इसके बाद जो निर्णय होगा या ड्राफ्ट प्लेन आयेगी वह भी सभा की मेज पर रक्खी जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : जो स्मृति पत्र दिया गया है उसमें जितनी धन राशि का अनुमान दिया गया है योजना में लगाने के लिये उसके सम्बन्ध में क्या देश में विभिन्न तब्कों के द्वारा जोर दिया जा रहा है कि वह बहुत अधिक है और उसे कम कर दिया जाये । क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और यह बात अन्तिम समझी जाय कि उस धन राशि में तब्दीली नहीं होगी, या सरकार दबाव में आकर उस पर पुर्नविचार करना चाहती है ।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, वह राशि मान ली गई है । मेमोरेन्डम में जो राशि बतलाई गई है उसे नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल, प्लनिंग कमिशन और गवर्नमेंट ने भी मान लिया है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : इस योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई है । उस में राष्ट्रीय रक्षा, खाद्य समस्या या उद्योग धन्धे, किस को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री ब० रा० भगत : सब कुछ स्मृति पत्र में लिखा हुआ है ।

Shri S. C. Samanta: May I know which organisations or agencies have been represented in the five committees that have been formed?

Shri B. R. Bhagat: They are the committees in which the States are represented and the Planning Commission.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether the attention of the Minister has been drawn to a statement made by the Minister of Agriculture that there will be a separate plan for agriculture, and if so, whether that plan is incorporated into this? What are the salient features of the Agriculture Plan that is being contemplated by the Ministry of Agriculture?

Shri B. R. Bhagat: I do not know if the Minister of Agriculture made such a statement, but the other day I answered a question in this House that there is no question of a separate plan, but a self-contained plan for agriculture, providing for all the inputs so as to achieve the targets, is being attempted within the Fourth Plan.

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि चौथी पंच वर्षीय योजना में जो राशि रखी गयी है उसमें मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी जाएगी ?

श्री ब० रा० भगत : मध्य प्रदेश का प्लान जब तय होगा उसमें वह निर्धारित की जाएगी।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Central Cadre of Nursing

*387. **Shri Hari Vishnu Kamath:** **Shri Himatsingka:** **Shri Rameshwar Tantia:**

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether any progress in the formulation and implementation of the proposal for constituting the Central Cadre of Nursing Services has been made; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). A decision regarding constitution of the proposed Central Nursing Service is yet to be taken.

Report of Indian Team Re: Irrigation in U.A.R. and Jordan

*388. **Mharajkumar Vijaya Ananda:** **Shri Mohan Swarup:** **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri D. J. Naik:** **Shri R. S. Pandey:** **Shri P. G. Sen:** **Shri Ram Sewak:**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the five-man team of senior Indian Irrigation, Agricultural and Planning Officials which visited U.A.R. and Jordan have submitted a report of the findings of irrigation development and agricultural extension activities in both the countries;

(b) if so, the main observations made by them; and

(c) the extent to which their observations are practicable for implementation suiting to Indian conditions?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Tax Evasion

*389. **Shri A. N. Vidyalankar:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Onkar Lal Berwa:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there exists any system of blacklisting the persistent tax evaders and to publish their lists from time to time for the benefit of the public or for the Income-tax Department;

(b) whether it is a fact that certain experts on tax collection administration had suggested such measures; and

(c) if so, whether Government have considered the desirability of giving wider publicity to the names of such offenders against the law?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) Though there is no system as such of blacklisting tax-evaders, Government have been publishing in the official Gazette the names of persons on whom a penalty of Rs. 5,000 or more had been imposed for concealment of income for tax purposes and of those who had been convicted as a result of prosecution proceedings under the Income-tax Act.

(b) This measure was suggested by the Direct Taxes Administration Enquiry Committee.

(c) The existing arrangement is considered adequate.

चीन में बनी वस्तुओं का भारत में चोरी-छिपे लाया जाना

*390. श्री मधु लिमये :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वासप्पा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० बरुआ :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के रास्ते चीन में बने सामान के भारत में चोरी-छिपे लाये जाने के समाचारों की ओर गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न वस्तुएं जिनके मूल्य 75 रुपये से अधिक नहीं हो बिना शुल्क दिये ही भारत में लाई जा सकती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेपाल के पास भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली मुद्रा चलन में है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) सरकार को ऐसी रिपोर्टों का पता है ।

(ख) नेपाल से आने वाले लोगों को सामान लाने के लिये वैसी ही रियायतें दी जाती हैं जैसी कि दूसरे देशों से आने वाले व्यक्तियों को दी जाती हैं । नेपाल में उनके ठहरने की अवधि पर निर्भर रहते हुए, इनमें 500 रुपये से 1000 रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निःशुल्क आयात भी शामिल है ; लेकिन शर्त यह है कि किसी भी वस्तु का मूल्य 75 रुपये से अधिक न हो और सीमा शुल्क अफसर इस बात से संतुष्ट हो कि कोई विशेष यात्री बार-बार तो भारत नहीं आ रहा है और भारत में बिक्री के लिये विदेशी वस्तुओं को तो नहीं ला रहा है ।

(ग) जहां तक सरकार को पता है नेपाल के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों में नेपाली मुद्रा का परिचलन नहीं है ।

(घ) इस समय चीनी सामान बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे भारत में नहीं आ रहा है । फिर भी, मामले पर कड़ी निगरानी है और जब भी आवश्यक होगा, समुचित कार्यवाई की जायेगी ।

Search of a Businessman's House in Calcutta

*391. Shri Mohammad Elias:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 446 on the 10th December, 1964 regarding searches in certain premises in Harrington and Canning Streets, Calcutta and state:

(a) whether investigation by the Customs and Income-tax authorities has since been completed; and

(b) if not, how long it will take to complete the investigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) and (b). Investigation in certain aspects of the matter has been completed by the Customs and

some show-cause notices issued. Further investigations by the Customs and Income-tax authorities are still in progress and will be completed as soon as possible.

Mr. Chester Bowles' Scheme for Rural Development

*392. { **Shri Hem Raj:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena: }

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 554 on the 17th December, 1964 and state:

(a) the progress made in the finalisation of the scheme sponsored by Mr. Chester Bowles for rural development in India; and

(b) when the scheme will be finalised?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b) The details of a scheme for evolving in one district in each State a proto-type of integrated and comprehensive development which is one Plan ahead, have been carefully considered in the light of the comments of the State Chief Ministers. It has been decided that as an integral part of the formulation of States' Fourth Five Year Plans, preparation of district development plans should be undertaken urgently in such sectors as Agriculture, Co-operatives, Village & Small Industries, Elementary & Social Education, Rural Water-supply and Sanitation, etc.

India's Foreign Liabilities

*393. { **Shri Indrajit Gupta:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia: }

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether India's foreign liabilities have gone up by Rs. 1,736 crores between 1955 and 1961;

(b) the manner in which it is proposed to service such a huge and growing national debt on foreign account; and

(c) the amounts owed to the U.S.A., U.K. and U.S.S.R.?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir. This represents the increase in the gross liabilities of the official and non-official sectors together.

(b) The external debt has been incurred for the development of the economy and the resources for servicing the debt would have to be found from increasing production and exports. Government are also endeavouring to improve the terms on which assistance is obtained.

(c) As on December 31, 1961 the gross liabilities of India's official and non-official sectors together amounted to Rs. 916·9 crores to the U.S.A., Rs. 664.7 crores to the U.K. and Rs. 68·5 crores to the U.S.S.R.

Planning Commission

*394. { **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Mohan Swarup: }

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 103 on the 10th September, 1964 and state:

(a) whether the proposal to prune and streamline the staff in the Planning Commission has since been considered by the Planning Commission; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). The proposal is still under consideration in the Planning Commission.

School Health Programme

*395. **Shrimati Renuka Barkataki:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to launch a comprehensive School Health Programme in the country; and

(b) if so, the main features of the programme?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). A scheme for School Health Programme is proposed to be included in the Fourth Five Year Plan. The main features of the Scheme are:

(1) Proper sanitation and safe water supply for the schools.

(2) Mid-day-meals.

(3) (i) Medical inspections, (ii) Detection of physical defects (iii) Treatment and correction of these defects as far as possible (iv) Preventive Care including immunisation (v) Health Education. The first two are the responsibility of the Education Ministry and the last one of the Health Ministry.

Bird & Company

*396. **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh:
Shri Indrajit Singh:
Shri D. C. Sharma:
Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether adjudication proceedings against M/s Bird & Co. have been finalised;

(b) the reason for the delay in a final verdict on the matter; and

(c) whether any injunctions were issued on the adjudication and when they were vacated by the court or withdrawn by the parties?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) The Customs adjudication proceedings are in progress.

(b) Having regard to the number of transactions, the period covered by them and the complexities of the cases, the lengthy explanations given by the party in reply to the show cause memos issued to them, the adjudication proceedings require time for completion. There has been no avoidable delay.

(c) Injunctions were issued by the High Court of Calcutta. They were not vacated. However, M/s Bird & Co. and other concerned parties withdrew their petitions with the permission of the High Court of Calcutta.

पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी समस्यायें

*397. **श्री बालकृष्ण सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा किया था, और वहां के लोगों ने उन्हें सिंचाई, विद्युत तथा बाढ़ सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया; और '

(ख) यदि हां, तो उनके सामने क्या बड़ी कठिनाइयां रखी गईं और क्या सरकार उन्हें दूर करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस क्षेत्र के लोगों ने केन्द्रीय मंत्री के ध्यान में निम्नलिखित समस्यायें लाईं :—

(1) सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता,

(2) गंगा के साथ साथ उपजाऊ भूमि पर खडडे न बनें, इसके लिये प्रतिकारक उपायों को अपनाने की आवश्यकता,

(3) मिर्जापुर व विन्ध्याचल घाटों पर कटाव, और

(4) ग्रामीण क्षेत्रों तथा वाराणसी नगर में बिजली की कमी ।

उपर्युक्त कठिनाइयों के सम्बन्ध में सोचे गये निम्नलिखित उपा ों की केन्द्रीय मंत्री ने जांच की :

(1) इलाहाबाद, जौनपुर और वाराणसी जिलों के कुछ भागों में इस समय सिंचाई नहीं हो रही है । इन भागों की सिंचाई के लिये इलाहाबाद से 20 मील प्रतिसत्रोत श्रिगमेरपुरघाट पर गंगा से लिफ्ट केनाल में पंपों द्वारा पानी डालने के लिये उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों ने प्राथमिक प्रस्ताव तैयार किये थे । इस स्कीम की जांच की गई और राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि वे 2,00,000 एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई के लिये लगभग 1000 क्यूजक पानी को पम्प करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों को अन्तिम रूप दें । इस स्कीम पर लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्चा होगा ।

मंत्री ने उस क्षेत्र में नलकूपों का निरीक्षण भी किया तथा उनके चालन की जांच की ।

(2) गंगा के साथ साथ खडडे न बनें इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में किये जा रहे उत्तलन कार्य (Terracing Work) का निरीक्षण किया गया और राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई कि वे गंगा में मिलने वाले नालों पर रोक बान्धों जैसे अनुपूरक कार्यों को शीघ्र ही हाथ में लें ।

(3) मिर्जापुर और विध्याचल के कुछ घाट कई जगहों पर गंगा से प्रभावित होकर टूट गए हैं । वे सब बुरी अवस्था में हैं । बाकी घाटों का भी निरीक्षण किया गया । कटाव रोध कार्यों का कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकार पहले से ही इस समस्या की जांच कर रही है ;

(4) यह सूचना दी गई थी कि वाराणसी शहर में बिजली की कमी मुख्यत: गैर सरकारी लाईसेन्सदार की वितरण प्रणाली में त्रुटियों के कारण है । राज्य बिजली बोर्ड से प्रार्थना की गई थी कि वे लाइसेन्सदार के ठेके की अवधि का ध्यान रखते हुए स्थिति में सुधार लाने के उपायों की जांच करें ।

राज्य बिजली बोर्ड से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह उन जिलों के ग्रामीण इलाकों में बिजली की आम कमी को, जहां तक हो सके, पूरा करने के लिये उपायों की जांच करें ।

Raids on Firms in Bombay and Kerala

*398. **Shri Surendra Pal Singh:**
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 458 on the 10th December, 1964 regarding violations of Foreign Exchange Act by certain Bombay and Kerala firms and state:

(a) whether the detailed examination of the seized documents has since

been completed; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) and (b). The seized documents are still under detailed examination in the Enforcement Directorate.

Ayurvedic Colleges

*399. Shri D. C. Sharma:
Shri Subodh Hansda:
Shri Daljit Singh:
Shri Yashpal Singh:
Shri Sezhiyan:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Mohan Swarup:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Kapur Singh:
Shri P. K. Deo:
Shri Narasimha Reddy:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether a proposal to upgrade a number of Ayurvedic Colleges in the country to the level of Post-graduate and Research Institutions is under consideration; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The Government of India have under their consideration proposals to upgrade Trivandrum Ayurvedic Centre into a Post-Graduate Training-*cum*-Research institute. A similar institute is also likely to be set up at Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi. The details are being worked out.

The Government have also given a grant of Rs. 1,30,000 for a post-graduate centre at the Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, Poona, for a similar purpose.

Legislation of Abortion

*400. Shri Hem Raj:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the progress made by the Committee set up to study the legalisation of abortion in the country; and

(b) whether the Committee will also study the public opinion in the country and, if so, the method adopted to do so?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The Committee has examined the provisions relating to abortion in the Indian Penal Code and in abortion laws in some foreign countries and considers that the problem is complex involving medical, social and moral issues requiring consultation on wide scale.

The Committee has prepared a Questionnaire to study the opinion of medical, social, legal, religious organisations, State Governments, M.Ps. and the Press.

Interest on G.P.F. Accumulations

*401. Shri D. C. Sharma:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the desirability of increasing the rate of interest on General Provident Fund accumulations of Central Government employees in view of the recent increase in the Bank rate; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). The rate of interest on the balances in the General Provident Fund and other similar funds is determined every year on the basis of the average redemption yield, during the five immediately preceding years, on the Central Government's rupee loans with an outstanding maturity of more than five years. As the increase in the bank rate is not relevant in this context except in so far as redemption yields may be affected hereafter, the question of increasing the rate on provident fund balances, as determined already, does not arise.

Selective Credit Controls

969. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the advantage of selective credit controls of farm commodities;

(b) the manner in which such a control is exercised;

(c) whether the operation of such control is causing some hardship; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken to mitigate such hardship?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) The control of advances against the security of food-grains or other agricultural commodities is necessary, in order to prevent hoarding and profiteering, and to ensure the expeditious and orderly distribution or marketing of such commodities.

(b) Banks are required to retain minimum margins in respect of such advances, and to restrict the level of the advances within certain ceilings, which are prescribed from time to time, with reference to the level of the advances during corresponding periods in some previous years. The margin and ceiling requirements are determined separately, if necessary, in respect of advances made to parties holding stocks for or on behalf of State Governments, or to exporters, or against warehouse receipts, or in respect of advances made in the surplus States or areas. Advances granted against documentary bills drawn in connection with the movement of the commodities and advances to co-operative processing and marketing societies are generally exempted.

(c) No.

(d) Does not arise.

International Commission on Irrigation and Drainage

970. { Shri Murli Manohar: Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the International Commission on Irrigation and Drainage has accepted the invitation of the Government of India to hold its sixth plenary session in India in 1966;

(b) if so, details of the conference; and

(c) the number of foreign delegates expected to attend the conference?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The invitation to hold its Sixth Plenary Session in India was extended to the International Commission on Irrigation and Drainage by the Central Board of Irrigation and Power, which acts as its Indian National Committee. The invitation has been accepted by the Commission.

(b) The Session will be held at New Delhi from the 4th to 15th January, 1966. The Central Board of Irrigation and Power, is making necessary arrangements.

The following are among the main subjects to be discussed at the Session:—

(i) Reclamation of saline lands under irrigation;

(ii) Sediment in irrigation and drainage channels;

(iii) Development of deltic areas;

(iv) Integrated operation of reservoirs for irrigation, flood control and other purposes.

In addition, there will be special lectures and discussions on the latest developments in the field of irrigation, drainage and flood control and display of charts, models and maps, to be followed by study tours by the delegates, to acquaint them with the progress made in India in these sectors.

(c) About 400.

Electricity Rates in Malabar

971. **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Kerala Electricity Board decided to enhance the rates of electric power in the Malabar region of Kerala;

(b) if so, to what extent and for what purpose; and

(c) the reasons for not enforcing this increase in the Travancore Cochin area?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) There is no proposal to enhance rates in Malabar area alone. The Kerala State Electricity Board have, however, a proposal under their consideration to levy a summer surcharge of 30 per cent on all industries in the State irrespective of the fact whether they are located in the Malabar area or in the Travancore-Cochin area.

(b) Kerala State Electricity Board is getting about 25 MW of power from the Madras grid to avoid power cut during the summer. The Madras State Electricity Board has demanded 9:5 paise per unit for this supply. The surcharge is proposed to be levied by the Kerala State Electricity Board to meet the higher cost of power being obtained from Madras during summer.

(c) Does not arise.

Bharat Sevak Samaj

972. **Shri Rama Chandra Mallick:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether any grant was sanctioned by Government to the Bharat Sevak Samaj during 1964-65;

(b) if so, the total amount given so far during the aforesaid period; and

(c) the total amount sanctioned to the Bharat Sevak Samaj, Orissa Branch during the same period?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes Sir.

(b) The Planning Commission have sanctioned a total amount of Rs. 11,29,844 to Central Bharat Sevak Samaj during 1964-65, so far.

(c) The grants-in-aid are sanctioned to the Central Office of the Bharat Sevak Samaj. An amount of Rs. 18,000 has been remitted to the Orissa Branch by the Central Bharat Sevak Samaj.

Flood Protection

973. **Shri Ram Harkh Yadav:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Hamburg University in Germany has made a special offer to India to place at her disposal its knowledge and experience in flood protection in India; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) The matter is under examination.

All India Institute of Medical Sciences

974. Shrimati Akkamma Devi: Will the Minister of **Health** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1830 on the 24th December, 1964 and state the further progress made in the completion of the departmental proceedings against the delinquent officials concerned on the administrative side of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): The progress made in respect of departmental proceedings against the delinquent officials on the administrative side of the All India Institute of Medical Sciences is as follows:

Sl. No.	Name and designation of the officer	Progress made
1.	Shri K.C. Dhingra, Ex-Administrative Officer.	The departmental proceedings against Shri K.C. Dhingra have since been finalised and the penalty of 'Censure' has been imposed on him by the President, All India Institute of Medical Sciences.
2.	Shri T.S. Sodhi, Superintendent.	The departmental enquiry against Shri Sodhi has since been completed and the report of the Inquiry Officer is under consideration. A decision will be taken shortly.
3.	Shri G.L. Chopra, L.D.C.	The Special Police Establishment has taken up the investigation into the case. Results of the same are awaited.

N.D.C.'s Committee Meeting

975. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Maheswar Naik:
Shri Vishwanath Pandey:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether a meeting of the National Development Council Committee on 'Industry, Power and Transport' was held in New Delhi recently;

(b) if so, the matters discussed thereat; and

(c) the nature of the decisions arrived at?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The Committee of the National Development Council on Industry, Power and Transport has met thrice. The first meeting, which was preliminary was held on January 2, 1965; the second was held on February 12 & 13, 1965 to discuss Industry and Transport; and the third was held on February 23, 1965 to discuss Power. The next meeting of the Committee has been scheduled for 15th & 16th March, 1965.

(b) The following important issues were considered:

(i) *Industry*

1. Policy regarding location and dispersal of industries including development of backward regions;
2. State participation in private sector projects;
3. Association of State Governments with central public sector projects;
4. Provision for industries in State Plans in the Fourth Five Year Plan;
5. Development of co-operative industrial ventures; and
6. Provision of institutional finance to State and private sector projects.

(ii) *Power*

1. Utilization of the latest developments in technology.
2. Taking over of big power projects by the Centre from the States for construction, operation and maintenance.
3. Consideration of the recommendations of the Committee on the Working of the State Electricity Boards (Venkataraman Committee Report).
4. Quantum of power generating capacity to be set up in the Fourth Plan.
5. Rural electrifications in relation to potentialities of industrial and agricultural growth in the areas.
6. Extraction of coal from the captive mines by Electricity Boards.

(iii) *Transport*

1. Preparation of a long-term plan for an integrated transport network (1966-76).
2. Scope of State transport plans, including requirements of border areas.
3. Integrated view of the entire road network in the country.
4. Linking up of the programme for rural roads with agricultural production and marketing programmes and allied fields.
5. Scope of public sector programmes in relation to road transport.
6. Institutional and other financing arrangements for private transport industry; role of Cooperative transport.
7. Coordination of plans of development for major and minor ports within each region.

(c) The Committee has not yet concluded its deliberations. The suggestions and recommendations of this Committee will alongwith the suggestions and recommendations of the other N.D.C. Committees be considered at a special meeting of the National Development Council.

Post Graduate Medical Studies

976. **Shri Surendra Pal Singh:**
Shri R. G. Dubey:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry is considering a proposal for the introduction of an all India examination for Post Graduate Medical Studies; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) The matter is still under consideration.

Aid Sought by U.P. Government

977. Shri Surendra Pal Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Government of U.P. have sought the help of the Centre in securing financial assistance from the International Development Association, an affiliate of the World Bank for constructing 1000 tube-wells in the State;

(b) if so, whether the Centre has used its good offices in securing the required help for U.P.; and

(c) the results thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir; however some information about the U.P. Government's plans for the second stage of their tube-well construction programme was given to a World Bank team which visited the State recently. The Bank's reactions are awaited before further action is taken.

(b) and (c). Do not arise.

Training in Execution of Local Schemes

978. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 509 on the 1st October, 1964 and state:

(a) whether Government have finalised the scheme to train the educationists and teachers in planning and execution of local schemes; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The scheme is still under consideration.

(b) Does not arise.

Gold Smuggling at Palam, New Delhi

979. **Shri D. C. Sharma:**
Shri P. G. Sen:
Shri Ram Sewak:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Customs Authorities made a gold haul worth Rs. 4 lakhs at Palam, New Delhi, on the 20th December, 1964; and

(b) if so, the result of the investigations made in this regard?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) On 20th December, 1964, Customs Officers at Palam airport seized some metallic substance suspected to contain gold and weighing 47.675 Kilogrammes, gold bullion weighing 19 grammes and platinum wire weighing 3 grammes from a person who had arrived from abroad. The value would depend on the actual gold content, but roughly, it is estimated at Rs. 1.6 lakhs.

(b) The case is still under investigation.

Arrest of Smugglers

980. **Shri Yashpal Singh:**
Dr. P. Srinivasan:
Shri Paramasivan:
Shri Dighe:
Shri Chandak:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of smugglers arrested in India by the Customs Authorities from 1st January, 1964 to 31st January, 1965;

(b) the number out of them convicted;

(c) the value of goods recovered from their possession; and

(d) the details thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (d). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Price of Electricity

981. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether in his address to the Federation of Electricity Undertakings of India on the 26th December, 1964, he advised the electricity undertakings to keep down the price of electricity by imparting greater operational efficiency and reducing wastage in transmission of power through greater technical skill;

(b) if so, how much price could be reduced; and

(c) the reaction of the federation?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Federation of Electricity Undertakings of India was advised by me on the occasion of their twentieth annual general meeting on 26-12-1964 in Bombay that it was necessary to modern-

ise the private sector undertakings for achieving optimum efficiency by harnessing modern technical developments for getting better results. I had also suggested that the Federation might appoint a Committee to go into the question.

(b) Does not arise.

(c) The reaction of the Federation was generally favourable.

Indo-Pakistan Flood Control Scheme

982. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards the proposal made by the President of Pakistan for a joint Indo-Pakistani Scheme to control floods in East Pakistan and Eastern India;

(b) if so, whether any attempt has been made to find out its details; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) and (c). In pursuance of an agreement reached in August, 1956 between the Governments of India and Pakistan, we are already giving to East Pakistan during the monsoon (i) flood warnings from stations in Bihar, Assam and Tripura, (ii) heavy rainfall data from Shillong to Assam, and (iii) any other information asked for relating to the Brahmaputra Valley or other assistance, as considered necessary, for formulating flood schemes in East Pakistan.

Grand Hotel, Simla

983. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Bhagwat Jha Azad:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the working of the Grand Hotel, Simla, is being organised;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the main features of the reorganisation?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) To provide better lodging and boarding facilities to its clientele and to place it on a better financial footing.

(c) The hotel will be divided into two portions, one of which, to be known as 'Holiday Home', will be reserved for Government servants visiting Simla. The suites in this portion will be provided with geysers and kitchenettes. The other portion will be given on lease to a private hotelier who will run it as a hotel.

Private Trade in Gold

984. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Chuni Lal:
Shri Heda:
Shri M. Rampure:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh demanded a ban on private trade in gold and the recognition of goldsmithy as a cottage industry; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) The Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh have demanded that Government should import and distribute gold to artisans and the public through Government agencies, recognise goldsmithy as a cottage industry and shoulder all responsibility for its development etc.

(b) It is not possible to agree to these demands because they presuppose the import of gold which the country cannot afford.

Rural Electrification

985. **Shri P. C. Borooah:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Yashpal Singh:
Shri Mohammad Elias:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a scheme for the rapid expansion of rural electrification is to be included for implementation under the Fourth Five Year Plan;

(b) the precise details of the scheme and its cost;

(c) whether the State Governments have submitted their proposals in this respect; and

(d) if so, the details of the proposal received from the Assam Government?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) The precise details are being worked out. However, it will be the policy of the Government of India to give priority to schemes for energising pumps for lift irrigation in order to increase agricultural production.

(c) Scheme Reports from six States including Assam have been received.

(d) The Assam State Electricity Board has submitted a scheme for electrification of 260 villages at an estimated cost of Rs. 96 lakhs during the year 1965-66. Scheme reports for the subsequent years are expected to be received in due course.

Old Government Quarters in New Delhi

986. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether a high level Government decision was taken some time ago to replace all the old Government quarters and bungalows which have already completed their normal life in the D.I.Z. area in New Delhi with new buildings and avoid wasteful expenditure in repairing and renovating the old buildings;

(b) if so, the up-to-date progress made in that direction in pursuance of the decision;

(c) whether it is a fact that despite this policy decision a number of old buildings have been and are being repaired and renovated; and

(d) if so, the total expenditure so far incurred on such renovations and how much of further repairs stand approved?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). Before any proposal for redevelopment of the DIZ area was thought of, Government had approved heavy repairs to, and renovation of, old houses in the area. Such work was being carried out as and when the houses could be vacated for the purpose. However, about the end of 1962, the first phase of redevelopment of the area was sanctioned. 611 quarters on Punchkuin Road were demolished and the construction of 720 type I quarters on the site taken up. Most of these quarters have been completed and allotted. Plans for the next phase of redevelopment are under preparation.

In the context of the programme of redevelopment, heavy repairs and renovation have been stopped. Ordinarily no more houses in the D.I.Z. area are being renovated now.

श्री बी० के० दत्त का इलाज

987. { **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि महान् शहीद सरदार भगत सिंह के साथी श्री बी० के० दत्त आजकल आल इयन्डया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली में इलाज करा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस्टीट्यूट के अधिकारियों को हिदायतें भेजी हैं कि वे उन की उचित देखभाल करें ; और

(ग) यदि नहीं तो इस के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सुनार

988. { **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर के लागू होने के पश्चात् लगभग 63,000 स्वर्णकार बेकार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार उन्हें अन्य रोजगार देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) अब तक कितने स्वर्णकारों को रोजगार दिलाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप लगभग 2,70,000 स्वर्णकार प्रभावित हुए थे ।

(ख) और (ग). भारत रक्षा (नौवां संशोधन) नियमावली 1963 के कारण 2,28 000 व्यक्तियों ने प्रमाणित स्वर्णकारों के रूप में फिर से अपने व्यवसाय को अपना लिया है । 46,000 सुनारों को वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिये ऋण स्वीकृत किये गये हैं । 11,000 को नियोजन केन्द्रों के मार्फत रोजगार दिया गया है और 8,000 को अन्य रोजगार सम्बन्धी सहायता दी गई है । इस प्रकार दूसरे व्यवसायों में बसे हुए सुनारों की संख्या में वे सुनार शामिल हैं जिन्होंने प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था ।

अमरोहा में फिल्म निर्देशक के मकान की तलाशी

989. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों ने अमरोहा में बम्बई के फिल्म निर्देशक श्री कमाल अमरोही के घर की तलाशी ली ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) कुछ कागज पकड़े गये थे और उन की जांच की जा रही है ।

Consumer Goods

990. Shri Harish Chandra Mathur: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the increase expected in the supply of consumer goods for retail trade during 1965 over that of the last year; and

(b) the break-up of the consumer items and the increase?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). A statement showing the estimated in-

creases in 1965 in the supply of certain consumer goods for which data are available is attached. These estimates are tentative and based on present indications. The supply position of foodgrains is expected to improve materially but estimates of the total output during the 1964-65 season will be available only after some time.

Statement

	Unit	1964 (estimates)	1965 (expectations)	Approximate percentage increase in 1965 over 1964
Sugar	Million tonnes	2·3	2·7	+16
Cotton cloth	Million metres	7132	7500	+5
Vanaspati	Thousand tonnes .	360	400	+11
Bicycles	Thousand Nos.	1384	1600	+15
Electric fans	Thousand Nos.	1112	1300	+17
Radio receivers	Thousand Nos.	466	550	+18
Electric lamps	Million Nos.	70	74	+6
Paper and paper boards	Thousand tonnes .	490	525	+7

Rats and Mice in Delhi

991. **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the wide-spread prevalence of rats, mice and similar species in Delhi; and

(b) if so, the steps being taken to curb this menace and the assistance being offered to the citizens to combat this menace effectively?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) Measures against domestic rats are being taken by the various local bodies and against field rats by the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage under the Ministry of Food and Agriculture. The measures taken by the various authorities are as stated below:—

(i) *Delhi Municipal Corporation*:

The staff engaged for control of rat nuisance is working in gangs. Each gang consists of 1 Rat Gang Jamadar and 3 Rat Gang Coolies. 23 such Rat Gangs are operating at present in the Corporation areas. The rats are caught by trapping. The staff also uses cyano gas and poisonous baits to kill the rats. In 1964, 4,81,656 rats were trapped.

(ii) *New Delhi Municipal Committee*:

Rat traps and rat poison baits are issued to the residents of the New Delhi Municipal Committee area, free of cost, through 21 rat catchers appointed for the purpose.

(iii) *Delhi Cantonment Board*:

Steps taken are Trapping and baiting inside building and Cyanogassing of rat burrows outside buildings.

(iv) *Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage*:

Anti-rat campaigns are organised in the cultivated fields by the Agriculture Department of the Delhi Administration. The Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage has been assisting the Delhi Administration by supplying rat poison and equipment. The Directorate also conducts rat control work in kitchen gardens.

कोटा में आय-कर कार्यालय

992. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोटा में एक आयकर कार्यालय काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो 1960 से 1964 तक वसूल किये गये कर के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह कार्यालय किराये की इमारत में चल रहा है और यह जगह पर्याप्त नहीं है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय की इमारत के लिये भूमि खरीदी हुई है ; और

(ङ) यदि हां तो इसके निर्माण में देर होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) कर निर्धारण-वर्ष	कर (आंकड़े हजार रुपयों में)
1960—61	2,026
1961—62	2,028
1962—63	1,967
1963—64	3,840

(ग) जी हां । लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मितव्ययिता स्तरों के अनुसार किराये पर ली गयी इमारत में जगह पर्याप्त है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वर्तमान संकटकालीन स्थिति और असैनिक व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए अभी कोटा में आयकर कार्यालय की इमारत के निर्माण को स्थगित कर दिया गया है ।

दिल्ली में धोबियों के लिये आवास

993. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में धोबियों की आवास की समस्या सुलझाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) संभावना है कि समिति दो तीन महीने के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

Delhi Slum Clearance Scheme

994. **Shri Heda:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the salient features of the Matia Mahal Slum Clearance Scheme, near Jama Masjid, Delhi;

(b) the amount involved;

(c) any target fixed for rehabilitating slum dwellers; and

(d) the progress made so far?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). There is no specific Slum Clearance Scheme for the Matia Mahal area. However, there is a programme for the re-development of the following two properties abutting on the Matia Mahal Road:

(1) Dujana House; and

(2) Haveli Sadar-e-Sadoor.

The project at (1) above involves the construction of 116 small two-roomed tenements, 12 large double roomed houses, 24 shops, 6 stalls and 18 offices, at an estimated cost of Rs. 12·45 lakhs, 40 small two-roomed tenements have been completed and 40 families of the area rehabilitated in those tenements. Construction work on the remaining part of the project has not yet commenced.

The project at (2) above involves the construction of 72 tenements and a fire station, at an estimated cost of Rs. 8.48 lakhs. Construction work on this project has not yet commenced.

Clearance of Drilling Equipment at Delhi

995. **Shri Daljit Singh:**
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Daji:
Shri Warior:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1488 on the 17th December, 1964 and state:

(a) the progress so far made to provide amenities like water and electricity in quarters constructed for Government employees in the Ramakrishnapuram Colony, New Delhi; and

(b) the number of quarters and shops which are under construction at present?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) 4,836 houses have been completed in Ramakrishnapuram and provided amenities like water, electricity etc.

(b) On the 1st March, 1965, 4,129 quarters and 74 shops were under construction.

Housing Programme in Madhya Pradesh

996. **Shri R. S. Pandey:**
Shri Uikey:
Shri Radhelal Vyas:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh is the most backward State in regard to its housing programmes; and

(b) if so, the steps Central Government are taking to give it special assistance to span the gap in housing programmes?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). Amongst the States, Madhya Pradesh stands eighth both in the provision of funds for housing schemes as well as their utilisation. The State has made a provision of Rs. 500 lakhs in its Third Plan, out of which Rs. 191.83 lakhs have been utilised during the first three years.

Clearance of Drilling Equipment at Calcutta Port

997. **Shri A. N. Vidyalankar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it was brought to his notice that large quantities of valuable

equipment, spare parts and other material urgently needed for oil drilling and exploration at Port Canning and Rudrasagar (Assam) had been held up at the Calcutta Port because of delay on the part of the Customs authorities in giving clearance in early January, 1965;

(b) whether he enquired into the causes and the responsibility fixed; and

(c) the steps proposed to be taken to avoid similar delays in future?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). Yes, Sir. Enquiries revealed that the Calcutta Customs authorities were not responsible for the delay in clearance of the consignments in question. The responsibility is that of the agencies entrusted with the job of clearance by the Oil & Natural Gas Commission who are reviewing their arrangements in this regard.

Land for Philosophical Hall in Delhi

998. Shri Sivamurthi Swamy: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether any representations have been received by his Ministry for the allotment of a plot of land for constructing a philosophical hall at Delhi; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). A request has been received from the Shivanubhava Samithi at New Delhi for allotment of land for construction of a Shivanubhava Mantap, a library and a guest house. Detailed particulars of the proposal in the prescribed proforma were called for from the Samithi on the 30th January 1965. These are still awaited.

Gole Market Area, New Delhi

999. { **Shri Daji:**
{ **Shrimati Vimla Devi:**

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ground rent is charged by the Land and Development Officer for staging Ramlila within the residential plots of different squares in the Gole Market area, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that no ground rent was charged by the C.P.W.D. in previous years for staging Ramlila on the eve of Dussehra festival;

(c) if so, whether Government have changed their policy during the last two or three years; and

(d) if not, why ground rent is not being charged by the Land Development Office from the Government servants for using their plots for religious purpose?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) According to the general policy, rent|damages are realised for use of Government lands. This case is also hit by that policy. In such cases, however, generally nominal charges are levied.

Sub-Standard Thermometers

1000. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken to check the sale of sub-standard clinical thermometers in the country; and

(b) if so, the nature thereof and the result achieved?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The I.S.I. are

currently engaged in drawing up the standards for clinical thermometers. When such standards are available, it will be possible to exercise quality control over such thermometers.

Visit by World Bank Officials

1001. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank Officials visited India during January 1965 for first-hand study of the problems of the Indian economy; and

(b) if so, the outcome of the discussions held by them?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) (a) The Hon'ble Member obviously refers to the visits of Mr. Geoffrey Wilson Vice-President of the World Bank and Dr. Alderwereld, a Senior Official of the Bank. Their visits were not for any specific study of the problems of the Indian economy but were undertaken in the normal course of the operations of the World Bank in its capacity as a significant lender to India.

(b) Does not arise.

Family Planning in Rajasthan

1002. Shri Karni Singhji: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government have received any scheme on family planning from the Rajasthan Government; and

(b) if so, whether any decision has been reached on the same and the nature thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes. The Government of Rajasthan in November, 1964, submitted the following scheme for re-organising the Family Planning Programme at an estimated expenditure of Rs. 1.09 crores:

1. Setting up of 45 Urban Family Planning Centres.
2. Setting up of 175 Rural Family Planning Organisations.
3. Establishment of 23 District Family Planning Bureaus.

(b) The scheme was accepted in principle by the Government of India and the Government of Rajasthan were informed in January, 1965, that they should go ahead with the scheme and that additional Central Assistance would be made available for the purpose.

Water Supply to Delhi from Punjab

1003. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the negotiations regarding the water supply to Delhi from Punjab have failed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government are considering to settle this dispute?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Aid from Russia for Fourth Plan

1004. **Shri P. C. Borooah:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. Barua:
Maharajkumar Vijaya Ananda:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Government of India have apprised the U.S.S.R. Government about India's needs for Soviet aid for the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the Soviet Government's reaction thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). There have been general discussions with the Soviet authorities for assistance for the Fourth Five Year Plan and this matter is still in a preliminary stage.

कर-अपवंचक

1005. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के आय-कर आन्दोलन (ड्राइव) से पचास से साठ हजार कर बचाने वालों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां तो उन में से कितने व्यक्तियों को आय-विवरण देने के नोटिस दिये गये थे ; और

(ग) उन से कितनी आय होने की संभावना है ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) 6,11,794 new assessees have been discovered during the period from 1st January, 1964 to 31st December, 1964.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) This information cannot be known till all the assessments are completed.

Public Sector Undertakings

1006. **Shri Indrajit Gupta:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there has been any noticeable improvement in the profits of the public sector companies during 1963-64; and

(b) the extent to which these compare with the average profitability of private sector companies?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) The comparison of the nature suggested is not feasible.

Problem of Small Towns

1007. **Shri Hem Raj:**
Shri K. C. Pant:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether the Committee set up by Government to study the problems of small towns in the hilly and border areas has since completed its report; and

(b) if so, the main recommendations/suggestions made therein and action taken thereon by Government?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes. Copies of the Report are being placed in Parliament Library.

(b) The recommendations made by the Committee are given in the statement, laid on the Table of the House. [*Placed in Library, see* No. LT-3967/65].

The report has been forwarded to all the State Governments/Union Territories and the concerned Ministries of the Central Government for taking action on the recommendations with which they are concerned.

Opium Smuggling

1008. **Shri U. M. Trivedi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang of smugglers belonging to Ujjain, who smuggled opium from a village near Neemuch in Mandsaur District, was recently arrested near Jabalpur; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) A gang of three smugglers believed to be from Ujjain was arrested at Jabalpur on the 30th December, 1964, but the place from which the opium was smuggled has not been established.

(b) All the accused persons and the goods seized in this case have been handed over to the Police and the matter is under investigation.

Fourth Plan

1009. Shri Indrajit Gupta:
Shri Daji:
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to dovetail the Fourth Five Year Plan with the developmental plans of certain Western and Eastern countries;

(b) if so, the object of the proposal and its main features; and

(c) whether any country has suggested, at either Government or private level, such dovetailing to solve its own problems?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). At the Sixteenth meeting of the Central Advisory Council of Industries held in New Delhi on January 28, 1965, Deputy Chairman of the Planning Commission had observed that planning authorities from Western as well as Eastern countries were suggesting that there should be greater consultation between them and the Planning Commission regarding future development programmes so that some kind of dovetailing can take place to mutual advantage. This would enable us to know, in advance, what foreign countries were intending to do and foreign countries, in turn, would know what our plans were. He visualized that developments on these lines, may take place, in the next year or so, with four or five countries in order to gain experience.

Rural Industrial Projects in Orissa

1010. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Rama Chandra Mallick:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the number of rural industrial projects functioning at present in Orissa; and

(b) the amount given by the Centre to the State for the purpose during 1964-65?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Two Rural Industries Projects, viz., Barpali and Jajpur are functioning at present in Orissa State.

(b) Rs. 10 lakhs have been allocated during 1964-65 by the Centre to Orissa State for the two Rural Industries Projects.

Payment of Royalty to Foreign Concerns

1011. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Rama Chandra Mallick

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of royalty paid to foreign concerns both by the Public and private sectors during 1964-65 (so far)?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The figures of remittances on account of royalty payments to foreign concerns are not separately available but they are merged with the figures of payments for the use of trade marks, copyrights, rentals payable for machinery etc. During the period April-September, 1964 for which information is available about Rs. 1.8 crores were remitted to foreign concerns on account of these payments including royalties.

Primary Health Centres

1012. { **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Health** be pleased to state the number of Primary Health Centres in the country which have remained without doctors for more than three months during 1964-65?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): The information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library, see* No. LT-3968/65].

Managing Agencies

1013. { **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of cases where permission was granted and the number where the permission was refused for extending managing agencies under the Companies Act during 1964-65?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): During the period of 1st April, 1964 to 28th February, 1965, approval was granted to the extension of the tenure of the existing managing agents in thirty-three cases and refused in forty cases.

Foreign Exchange to Students

1014. { **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Rama Chandra Mallick

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of students who were given foreign exchange to study abroad during 1964-65;

(b) the amount of foreign exchange given to them during the same period; and

(c) whether any students were refused foreign exchange during the same period?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) During 1964, foreign exchange was released in favour of 6628 students. This is inclusive of repeat permits in favour of 3338 students who had gone abroad earlier.

(b) The amount of foreign exchange released came to Rs. 452 lakhs.

(c) Yes, Sir.

समवायों में कदाचार

1015. { **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ कम्पनियों में उद्योगपतियों के स्कूलों और कालिजों से निकले हुए अनुभवहीन पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों को बहुत बड़े बड़े वेतन देकर नियुक्त किया जाता है और ये वेतन काफी अनुभवी और पुराने संचालकों के वेतनों से भी अधिक होते हैं ; और

(ख) यदि हां तो कम्पनी कानून विभाग द्वारा कम्पनियों में उद्योगपतियों के रिश्तेदारों की नियुक्तियों को रोकने और विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). कुछ एक प्रकार के मामलों में जैसे कि प्रबन्ध अधिकर्ताओं के सहयोगियों या प्रबन्ध निदेशकों या पूर्णकालिक निदेशकों की प्रारम्भिक नियुक्तियां करने के लिए समवाय अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना आव-

श्यक है । ऐसे मामलों में सरकार यह देखती है कि निर्दिष्ट प्रकार की नियुक्तियों की स्वीकृति न दी जाए । समवाय अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी है कि निदेशक के हिस्सेदार या रिश्तेदार को कोई लाभप्रद पद दिए जाने से पहले कम्पनी के अंशधारियों द्वारा विशेष संकल्प के रूप में इस दिशा में पूर्व-सहमति प्राप्त कर ली जाए । ऐसे मामलों में संभवतः अंशधारी अपेक्षित रोक लगाने के अधिकार का प्रयोग करते हैं । अन्य मामलों में जहां न तो सरकार की और न अंशधारियों की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक हो वहां इस प्रकार के अवांछनीय आचरण की संभावना अवश्य हो सकती है । सरकार को इस प्रकार के अवांछनीय आचरण के प्रचलन की कोई सामान्य सूचना नहीं मिली किन्तु जब सरकार की जानकारी में इस प्रकार का विशिष्ट दृष्टांत होता है तो सरकार इस की अवश्य ही जांच पड़ताल करती है ।

औद्योगिक उत्पादों की बिक्री पर कमीशन

1016. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादों/कृषि उत्पादों की बिक्री से दलालों उप-दलालों या बिक्री-एजेंसियों जैसे बिचौलियों को मिलने वाले कमीशनों या अंशों का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस अध्ययन से पता चला है कि बिक्री एजेंटों को मिलने वाले भारी अंश के कारण इन वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या मूल्यों में हुई वर्तमान वृद्धि के प्रसंग में सरकार का विचार ऐसा अध्ययन कराने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

तुलनात्मक उत्पादन लागत का अध्ययन

1017. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी भारतीय इकाइयों के उत्पादनों की लागतों और मूल्यों और उसी प्रकार की जापान, इटली, पश्चिमी जर्मनी और अन्य विकसित देशों की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादनों की लागत और मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार हमारे देश की अधिक लागत—अधिक मूल्य वाली अर्थ-व्यवस्था और कम लागत वाली विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था के अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जिस तरह के अध्ययन का संकेत किया गया है उस तरह का कोई एक अध्ययन नहीं किया गया । टैरिफ आयोग, समय-समय पर, उन उद्योगों के प्रतिनिधि एककों (यूनिट) द्वारा बनायी गयी चीजों की लागत की जांच करता है जिन्होंने टैरिफ सम्बन्धी सुरक्षा के लिए आवेदन-पत्र दे दिया हो या जिन्हें टैरिफ सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गयी हो या जिनके द्वारा बनायी गयी चीजों की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जानी हो । इस सम्बन्ध में यह आयोग, आवश्यकता पड़ने पर, भारत में बनी वस्तुओं की लागत और कीमतों की तुलन अन्य देशों से आयात की गई वस्तुओं के जहाज-उतरते-मूल्यों (लैंडेड कास्ट) से करता है ।

(ख) लागत कम करने के लिए अब तक जो उपाय किये गये हैं उनमें पुराने स्थापित उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना नये उद्योगों को अनुकूलतम (आप्टिमम) स्तर तक उत्पादन करने में सहायता देना और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की मार्फत अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने की भावना उत्पन्न करना भी शामिल है। सरकार कुछ निर्मित वस्तुओं की कीमतों का विनिमयन भी कर रही है। ये प्रयत्न जारी रहेंगे।

Live Worms in Ostermilk

1018. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newspaper report that live worms have been found in Glaxo's Ostermilk in Bombay;

(b) if so, whether any enquiry has been made in this matter; and

(c) the action taken by Government?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) and (c). The Government of Maharashtra called for a report from the Bombay Municipal Corporation in the matter. The information received from the Corporation revealed that no information or any complaint about the presence of live worms in Ostermilk was received by them prior to the enquiry by the State Government on 1st December, 1964. The Food Inspector of the Bombay Municipal Corporation visited the market on the 2nd December, 1964, but he could not find any stock of the batch (No. 731) complained of or of any other batch either in the shop of vendor from where the tin of Ostermilk was alleged to have been purchased, or in any other shop. He could not also get any stock of that batch in the Glaxo laboratories. On equiry, the Food Inspector learnt that on account of great demand for baby food and the short supply made by the manufacturer, the supply received had been exhausted. It was not, therefore possible to test a sample of Ostermilk belonging to batch No. 731. He, however, could get a sample of bach No. 805 from the Glaxo laboratories which on analysis was found to be fit for human consumption.

The Glaxo Laboratories had also reported that no such complaint was received by them from any other purchaser out of several purchasers to whom hundreds of tins of batch No. 731 were sold in the market.

Boards for Screening Films for Export

1019. Shri R. Barua:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to constitute Boards for the screening of films for export purposes; and

(b) if so, the number of Boards so far constituted for the purpose?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) One each at Bombay, Calcutta, Madras and Delhi.

Land Reforms

1020. Shri Vidya Charan Shukla: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have finalised consideration of the Report of the US Study Team on Land System in India; and

(b) if so, the details of the recommendations accepted by Government?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). Copies of Mr. Ladejinsky's Report have been forwarded to the State Governments.

The suggestions made therein are receiving their consideration with due regard to local conditions and needs.

International Monetary Fund

1021. Shrimati Sharda Mukerjee
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any indication of an increased loan from the International Monetary Fund has been received by Government; and

(b) whether any concessions are expected from the International Monetary Fund regarding the servicing of the loans in view of the shortage of our foreign currency and gold reserves?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). In my statement on foreign exchange situation made in this House on the 17th of last month, I informed the House that I had authorised our Executive Director on the Board of the International Monetary Fund to request that institution for a stand-by credit to the maximum extent possible. Consequent upon this request negotiations are now in progress with the Fund. Until they are completed it is not possible to say what the outcome will be.

Power Rates for Industries

1022. Shri Rameshwar Tantia:
Shri Himatsingka:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to have uniform rates of power for industries throughout India; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No.

(b) Does not arise.

New Capital Project of Madhya Pradesh

1023. **Shri Vidya Charan Shukla:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the request of the Madhya Pradesh Government for additional grant for the new Capital project; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No specific request for additional grant for the new capital project of Madhya Pradesh has been received by the Government of India.

(b) Does not arise.

I.T. Prosecutions in Madras

1024. Shri Daji:
Shri Warior:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Economic Offences Division has launched prosecutions against eight textile millowners in Madras State; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Opium Factory, Ghazipur

1026. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to shift the opium factory of Ghazipur (U.P.) to some other State; and

(b) if so, when and the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Irrigation Projects

1027. Shri Maheswar Naik: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a study of five irrigation projects by the Planning Commission's Water Utilization Panel of the Committee on Plan Projects has revealed that there is not only an 'inadequate utilization of water available', but also a lag in the agricultural production effort;

(b) whether the same is also applicable to other projects; and

(c) the measures being contemplated to remedy matters?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Panel has not yet finalised its reports on the five projects.

(b) and (c). Do not arise.

Aid from Yugoslavia

1028. **Shri Koya:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri P. L. Barupal:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Y. D. Singh:
Shri P. H. Bheel:
Shri M. Rampure:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Managing Director of the Yogoslav Bank of Foreign trade has offered credit for the Fourth Plan which is more than that given for the Third Plan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rural Water Supply in Assam

1029. Shrimati Renuka Barkataki: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the total number of rural water supply projects in Assam for which the Union Government have extended assistance during the Third Five Year Plan period (so far); and

(b) the amount of money that has been given as assistance?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) 10 Schemes.

(b) According to the existing procedure allotment of funds is not made scheme-wise but the grant-in-aid is sanctioned at the end of each year for broad groups or categories of schemes. Three-fourths of the total Central assistance allocated for a financial year is, however, released to each State on monthly basis in nine equal monthly instalments as lumpsum ways and means advances during the course of the year.

The Central assistance given to the Government of Assam during the first three years of the III Five Year Plan for all *Centrally aided 'Health' Schemes* including 'Rural Water Supply Schemes' in the State is as under:

	Grants sanctioned (Rs. in lakhs)
1961-62	66·74
1962-63	64·76
1963-64	64·43
1964-65	69·16 (As allocated including assistance in kind).
1965-66	Allocation of Central assistance is yet to be finalised.

Final payment sanctions for 1964-65 indicating the adjustment of ways and means advances will be issued after obtaining full figures of expenditure from the State Governments.

Symposium Organised by National Buildings Organisation

1030. **Shrimati Maimoona Sultan:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether a symposium was recently organised by the National Buildings Organisation;

(b) if so, the main observations made therein; and

(c) the decisions Government have taken in the light of the same?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes. A symposium on 'Housing Finance' was held on the 1st, 2nd and 3rd February, 1965.

(b) and (c). The recommendations made by the Symposium were received in this Ministry on the 4th March, 1965. These are under examination.

Science Fees

1031. Shri Jedhe: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to include the 'Science Fee' in 'Tuition Fee' for the purposes of re-imbursement of education allowance to Central Government employees;

(b) if so, the date from which this decision is being implemented;

(c) whether it is also a fact that the 'Science Fee' for Girl students includes (i) Domestic Science fee and (ii) Physiology and Hygiene fee for re-imbursement purposes; and

(d) other fees|funds which have been included in the category of 'Science fee' for re-imbursement purposes?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (d). Yes, Sir; for purposes of re-imbursement, Tuition fees include fees charged for Science as well as for any other subjects taught as subjects in the regular school curriculum. This decision is applicable from the 1st May, 1964, when the scheme of re-imbursement came into force.

Sugar Production

1032. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the *Economics Times* of the 23rd February, 1965, captioned "Tax Disparities Affect Sugar Production Trend", explaining how tax disparities in respect of three main users of sugarcane, namely sugar, gur and khandsari industry, has gone to affect sugar production in the country; and

(b) if so, the steps envisaged to remove such tax disparities?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) The remedial measures are taken whenever considered necessary. To enable the sugar factories, *inter alia* to purchase cane in competition, excess production incentive in the shape of rebate of Excise duty is given wherever called for.

There is no real comparison between the economy of a manufacturer of sugar in a modern factory and of a khandsari and "gur" maker. It is the policy of the Government to protect, if necessary, even by fiscal measures, the weaker sections of industries whose products are taxed.

गाजीपुर अफीम कारखाने के कर्मचारी

1033. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजीपुर अफीम के कारखाने में जो लेबोरेटरी अटेंडेन्ट्स हैं वे तीसरी श्रेणी के कर्मचारी माने गये हैं परन्तु उनका वेतन क्रम उस हिसाब से नहीं मिलता है जिस हिसाब से केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को सुलभ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं, सामान्यत: नहीं । गाजीपुर अफीम के कारखाने में लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट्स के पदों का वेतन-क्रम रु० 80–1–85–2–95–दक्षतारोध–3–110 है । इस वेतन-क्रम के अनुसार इन पदाधिकारियों को सामान्यत: चतुर्थ श्रेणी में रखा जाना चाहिए । । लेकिन यह देखते हुए कि इनमें से कुछ पदों पर मैट्रिक पास व्यक्ति लगे हुए हैं और उनको कैमिस्टों के निर्देशन में तकनीकी किस्म के काम करने पड़ते हैं, जैसे नेमी कार्यों में केमिस्टों की सहायता करना, यह निर्णय किया गया है कि मैट्रिक पास लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट्स तीसरी श्रेणी में और बिना मैट्रिक पासों को चतुर्थ श्रेणी में माना जाये ।

(ग) और (घ) हां, मामला विचाराधीन है ।

Sharing of West Flowing Rivers

1034. **Shri Ravindra Varma:**
Shrimati Renuka Barkataki:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Madras have sought Central assistance for schemes for sharing the water of the West flowing rivers in the State; and

(b) if so, Government's reaction to the schemes?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) Government are trying to bring about a settlement amongst the States concerned regarding the sharing of the waters of the West flowing rivers.

Irrigation in Kerala

1035. **Shri A. K. Gopalan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Government of Kerala have asked for one crore of rupees from the Central Government for the purpose of Irrigation Schemes;

(b) if so, the details of those schemes; and

(c) the amount allotted for the irrigation purpose for the period 1965-66 and the proportion of loan and grant in the said amount?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). The Government of Kerala have sought additional assistance amounting to Rs. 181 lakhs during the year 1965-66 for the following irrigation projects in the State:

1. Neyyar-I and II stages.
2. Pothundy.
3. Chitturpuzha.
4. Periyar Valley.
5. Gayatri.
6. Kallada.
7. Pamba.
8. Kuttiady.

(c) The proposal is under consideration. No grants are given for major and medium irrigation schemes

Irrigation Potential in Rajasthan

1036. **Shri Tan Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the extent of irrigation potential in Rajasthan which is yet to be exploited;

(b) whether ground water surveys have been conducted; and

(c) the steps proposed to be taken by the Central Government to ensure the fullest possible development and utilisation of irrigation potential?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) About 3 million acres.

(b) Yes; for deep tube wells.

(c) Adequate provision is being made in the State Plan for execution of major and medium irrigation projects within the available financial resources.

The minor irrigation programme is being accelerated as much as possible, consistent with techno-economic feasibility and the available organisational and material resources.

As regards utilisation of irrigation potential, the State Government are paying special attention for the construction of field channels wherever necessary. They have also been requested to promote and develop area programmes for speedy utilisation of irrigation potential. In the case of Chambal area, the State Government of Rajasthan and Madhya Pradesh have set up a Joint Study Team for preparation of an intensive agricultural development programme.

Lease of Building Plots

1037. **Shri Hem Raj:**
Shri P. L. Barupal:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of commercial residential and press plots leased out or sold each year from 1949 to 1963 in Sunder Nagar, Golf Link, Jor Bagh Nursery, Diplomatic Enclave and Mathura Road, New Delhi;

(b) the number of plots in each category, locality-wise, where building work had not been undertaken till the 31st March, 1963 in default of the two years' time limit clause of the lease agreement;

(c) the number of plots, category-wise, in each of the above year group, where the Chief Commissioner, Delhi had exercised his right of re-entry but the matter was compromised after imposing penalty against the defaulters, along with the total amount of penalty realised;

(d) the number of un-built plots, out of the above, in each locality and each year's group where the right of re-entry had been exercised along with the forfeiture of the premium money and the ground rent paid as well as the total amount so forfeited and the compromise refused; and

(e) the number of plots out of the above, if any, still unbuilt?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Utilisation of Water Resources

1038. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the suggestions made about the utilisation of water resources in the country at the 37th Annual Meeting of the Central Board of Irrigation and Power held recently in New Delhi; and

(b) the action being taken in persuance thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library.*

See No. LT-3969/65).

Pay Commission in Kerala

1039. { **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken by the Government of Kerala to appoint a Pay Commission for Government employees; and

(b) if so, the composition and the terms of reference of the Commission?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes.

(b) The Commission consists of:

(i) Shri K. M. Unnithan (Chairman).

(ii) Shri P. S. Nataraja Pillai, M.P. (Member).

(iii) Dr. E. K. Madhavan (Member) and

(iv) Shri C. Thomas, Finance Secretary, Kerala Government (Member).

The terms of reference of the Commission are:

(i) to examine and recommend changes in pay structure of Government employees;

(ii) to review present rates of dearness allowance and suggest changes.

The Commission may also make other recommendations for promoting efficiency of services and economy in administration.

Dearness Allowance to Employees of Local Bodies in Kerala

1040. **Shri Pottekkatt:**
Shri A. V. Raghavan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal with the Government of Kerala to provide interim relief in Dearness Allowance to the Employees of Local Bodies;

(b) the amount of assistance proposed to be sanctioned by the Government of Kerala to the Local Bodies; and

(c) when the same will be implemented?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). The Kerala Government have permitted the Panchayats, Municipal Corporations, Municipal Councils and Guruvayoor Township in the State to grant an increase in the dearness allowance by way of interim relief to full time, including contingent, emplovees from 1st October, 1964. The expenditure in this regard is to be met by the Local Bodies themselves. The State Government intend giving some assistance to those Local Bodies which are unable to meet the expenditure from thier own funds. The Kerala Government have not so far sanctioned any specific assistance to any of the Local Bodies for this purpose.

सामान्य बीमा के लिये आचरण संहिता

1041. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या वित्त मंत्री 25 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम को, जिसे सामान्य बीमा कारोबार करने के लिए भी हाल में प्राधिकार दे दिया गया है, सामान्य बीमा परिषद् की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा स्वेच्छा से निर्मित आचरण संहिता का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार, सामान्य बीमा कम्पनियों के कार्य के बारे म जांच करने के लिये खोले गये विभाग को, बन्द करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम एक सांविधिक निकाय है जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किया गया है । निगम का हिसाब-किताब और रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जाती हैं और इसलिए निगम अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है । बीमा अधिनियम, 1938 का भाग II-क, जिसका सम्बन्ध भारतीय बीमा संस्था, संस्था के परिषदों और उनकी समितियों से है, जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होता । साथ ही निगम को सामान्य बीमा परिषद् की कार्यकारी समिति के नियंत्र में रखने से कोई लाभ नहीं होगा, जिसमें मुख्यतः सामान्य बीमा उद्योग के ही प्रतिनिधि होते हैं ।

(ग) सरकार ने ऐसा कोई विभाग नहीं खोला है । इसलिए उसे बन्द करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DECLARATION OF EMERGENCY IN A MANIPUR SUB-DIVISION AND NECESSITY FOR CALLING OF TROOPS

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

"मणिपुर के उच्चायुक्त द्वारा वहां के एक सबडिविजन में की गयी आपात की घोषणा और सेना के बुलाए जाने की आवश्यकता ।"

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): Sir, on receipt of reliable information that groups of Nagas were returning with arms and ammunition from Pakistan and were likely to pass through the territory of Manipur on their way to Nagaland, the Chief Commissioner declared the sub-divisions of Churachandpur and Tengnoupal as disturbed areas under section 3 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act, 1958, for a period of one month with effect from March 1, 1965. The Governor of Assam and the Chief Commissioner of Manipur have been exercising their powers under the Act mentioned above from time to time, whenever, in their opinion, circumstances made such a step necessary. I might add here that in addition to the two sub-divisions mentioned above, the Jiribam sub-division has been under a similar declaration for the same reasons for some time past.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल यह है कि जो मणिपुर का पूर्वी सीमा का विभाग है वह तो पाकिस्तान के नजदीक है लेकिन सटा हुआ नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी इलाका है वह बर्मा से सटा हुआ है । क्या सरकार के पास इस बात की कोई शिकायत है कि जो हथियारी नागा पाकिस्तान से नागालैंड की ओर बढ़ रहे हैं वे बर्मा होते हुए उखरूल, टंगनोपाल आदि जो इलाके हैं उन में से हो कर गुजर रहे हैं और उनको रोकना सम्भव नहीं हो रहा है क्योंकि इस इलाके में शस्त्र सन्धि की स्थिति कायम की गयी है । एक ओर पूरब की तरफ पाकिस्तान है लेकिन वह दूर है, बीच में कछार आदि का इलाका है, वहां (पूर्वी क्षत्र में) आपात की घोषणा की जाती है, लेकिन जो बर्मा से सटा हुआ इलाका है उस में शस्त्र सन्धि है । बर्मा हमारा मित्र राष्ट्र है । इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस शस्त्र सन्धि की स्थिति को समाप्त करेगी और बर्मा सरकार से विनती करेगी कि ये जो हथियारी नागा वापस लौ

रहे हैं उनको रोकने के काम में वह हमारी सेना की सहायता करे ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह जो सूचना अपने दी है कि नागा लौट रहे हैं वह सही है, लेकिन उनका खास रास्ता क्या है यह कहना कठिन है, लेकिन जो सबडिवीजन हमारे राज्य में पड़ते हैं उनकी ओर से आने की भी संभावना रही है, इसलिए हमने घोषणा की है। जहां तक बर्मा की ओर से आने का सवाल है इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

श्री मधु लिमये : उखरूल और टंगनोपाल तो हमारे मणिपुर के इलाके में पड़ते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि जो आपका बर्मा के बारे में सवाल था, उसके बारे में उनको सूचना नहीं है ।

क्योंकि यह आपका सजेशन है, इस पर ध्यान रखा जायेगा ।

श्री ज० भ० कृपालानी (अमरोहा) : हम पूछ सकते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है ।

12·05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT, DEFENCE SERVICES, 1965

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): Sir, on behalf of Shri T. T Krishnamachari I beg to lay on the Table a copy of the following papers:—

(i) Audit Report, Defence Services, 1965, under article 151(1) of the Constitution. [*Placed in Library, see* No. LT-3961/65].

(ii) Appropriation Accounts of the Defence Services for the year 1963-64 and Commercial Appendix thereto. [*Placed in Library, see* No. LT-3962/65].

REPORT OF STUDY TEAM ON IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL ORGANISATION

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of Report (Part I) of the Study Team on the Import and Export Trade Control Organisation. [*Placed in Library, see* No. LT-3963/65].

NOTIFICATION *re* GOLD BONDS AND KERALA GENERAL SALES TAX ACT

Shri B. R. Bhagat: On behalf of Shri Rameshwar Sahu, I beg to lay on the Table—

(1) a copy of Notification No. F. 4(2)—W&M/65, dated the 27th February, 1965, regarding issue of 7 per cent Gold Bonds, 1980. [*Placed in Library, see* No. LT-3964/65].

(2) a copy each of the following Notifications making certain further amendments to the Kerala General Sales Tax Rules, 1963, under sub-section (3) of section 57 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 10th September, 1964, issued by the President in relation to the State of Kerala:—

(i) S.R.O. 205/64 dated the 7th July, 1964.

(ii) S.R.O. 242/64 dated the 13th August, 1964.

[*Placed in Library, see* No. LT-3965/65].

12·06 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"(1) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and

[Secretary]

Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Income-tax (Amendment) Bill, 1965, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd March, 1965, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.

(2) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 1965, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th March, 1965, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recomendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.07 hrs.

RE. POINT OF PROPRIETY

Shri Daji (Indore): Sir, before you take up the next item of business, I want to make a request. The matter came up before the House the year before last. At that time, after a short discussion, it was decided that we would not press the matter, but that the Minister of Parliamentary Affairs would keep it in mind. Today, we learn that the budget discussion has already begun in the Rajya Sabha first. After all, it is ridiculous that the House which votes the grant does not discuss the general budget first, but that it is first discussed in the other House. It is first discussed by the House which cannot vote the grants! The matter was raised the year before last, not as a point of privilege but as a point of propriety. The Minister of Parliamentary Affairs gave us an assurance that this will not be prepared in future. There are so many reports about Corporations and undertakings which can be discussed there now, so that the budget discussion can be had here first. When the budget discussion starts here on the 19th, actually it becomes stale especially when it is discussed in the other House first. It is not as a matter of right, but as a matter of propriety, it must be discussed first in this House.

Mr. Speaker: Though I entirely agree with him on this matter, so far as this question is concerned, he ought not to have raised it in this manner. (*Interruption*).

Shri Daji: It is a very serious matter that we are raising.

Mr. Speaker: We can take it up tomorrow.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I think you said you agree. Am I right?

Mr. Speaker: Yes; I agree.

Shri Hari Vishnu Kamath: I welcome it, Sir. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. We cannot take it up at this moment.

12.10 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1965-66—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1965-66. Out of 9 hours, 5 hours 10 minutes have been taken and 3 hours and 50 minutes remain. Dr. M. S. Aney may continue his speech.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): When will the hon. Minister reply, Sir?

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil): The Minister of State would be replying. That would be the final reply.

Mr. Speaker: We have to end this discussion at 4 O'clock: Therefore, I will call him at 3.15.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Speaker, Sir, before I proceed to make my points, I would like to make, with your permission, a correction to the statement which I made yesterday by mistake. I mentioned that the Darwha-Pusad line was dismantled during the first World War. That is not correct, it was dismantled in the Second World War. That is the correction which I want to make in the statement which I made yesterday.

Having said that, I will proceed to one other point of local importance. There is a station called Majri which is a junction on the line between Wardha and Balharshah. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. There are talks on every side that I cannot follow the proceedings.

Dr. M. S. Aney: From the Majri junction, a branch line goes to the Rajur collieries. On that line, there is an important town called Wani. My point is that from Majri to Rajur, there are only three trains which are mixed trains. The trains that go on that route have no upper class compartments. Only third class bogies are attached to those trains. Besides, the trains which go on the Majri route do not have corresponding trains for the passengers to go either to the North or to the South. They have to wait for some hours every time. So, I want the hon. Railway Minister to look into the time-table and see that at least one train for going and one for coming which would correspond to the train which goes on this section may be given. The through-trains do not stop there. Only the Janata Express stops at that station. That is one suggestion that I have to make as regards the time-table.

Then I come to some points which are of some general importance, in my opinion, about the administration of the Railways itself. I was glad to find in the report that there is some improvement in the punctuality of trains. This year the percentage of punctuality has improved compared to last year. In my opinion, punctuality is the essential quality of railway trains. People talk about other amenities, this, that and the other. If the trains run punctually I am prepared to condone the lack of many other amenities, because if the trains do not run punctually the passengers have to undergo greater difficulties than due to the lack of other amenities that they want to be given to them.

Secondly, in my opinion, if the railways have done any service to the country it is this, that for the first time the people of India have learnt that big things can be done in a regular way. The sense of punctuality can probably be introduced among the masses and the general public more by the running of railway trains in time than by anything else. We have learnt many things from the British. We have taken many things from them. But we have not taken the virtue of punctuality. This big organisation running over the whole country taking thousands of passengers with thousands of trains running in time is a phenomenon which has no doubt impressed to a great extent about the utility of punctuality. Gradually, it ought to be encouraged more and more. Therefore, I insist that more attention should be paid to this question of punctuality.

But one thing I want to say. Though I agree with the general conclusion mentioned here, my own personal experience is somewhat different. Whenever I travel by the G.T. Express,—in the course of the year I have to travel more than five or six times—at least on the day I travel, I find that, unfortunately, for some

[Dr. M. S. Aney]

reason or the other, the train is generally not running to time and it is late by half-an-hour, one hour and even four hours. This is my personal experience. Therefore, I want to say, along with the general improvement in the punctuality of trains particular attention should be paid to the G.T. Express also because bulk of the traffic from Madras to Delhi is carried by this train.

Then, I want to draw the attention of the House to another good thing which the Railways have done. I am glad that the railway staff, apart from their ordinary duty, at the time when there was the Chinese aggression, have done some good work to help and save the country. Special mention must be made of the work done by the armed battalions added to the special force or the emergency force in November 1962, in guarding important areas and installations of the railways, protecting trains on the North-East Frontier Railway against attack by the Naga hostiles, maintaining order at the eastern border stations at the time of the large ingress of the refugees and during the student disturbances in West Bengal, Bihar and Orissa. I believe, this is a service which the Railways have done and which you have to recognise. I think, the same spirit will actuate people in the other services of the country. Then, I believe, we need not be afraid of any disturbance inside the country or any difficulty in meeting our enemies if they dare to make an attempt to invade the country and enter inside the territories of India. I want this spirit for the defence of India to be a characteristic for the other services of the Government of India.

Then, I turn to the question of pulling of alarm chains. It is a matter of pity that in India the passengers blame the railway servants for not doing their duty properly; but generally I find that there is a tendency among the passengers also not to look to the convenience of their co-passengers and needlessly pull the alarm chains. This is one of the reasons which adds to the unpunctuality of the railway services. I am told, alarm chains were pulled on about 72,567 occasions in 1962-63 and on 84,333 occasions in 1963-64: that means, with the growing expansion and our progress, this tendency of abusing the use of the alarm chain is also increasing. Something ought to be done in that line. I believe, the Railway Board will find out some way of checking this tendency and punishing those persons for abusing the alarm chains seriously so that this tendency may not grow and is checked.

The total number of losses and irregulrities is given in the Annexure to the Audit Report of the Railways at page 39 which is 1,04,219 and the total amount of the loss is valued at Rs. 1,58,65,319. I have read those reports as carefully as I could and I find that in most of those cases the negligence of the Railway officers is to a great extent responsible for it. There are so many cases that I cannot read them out just now. This kind of loss which the Railways have to incur more or less on account of the negligence of their own servants ought to be taken care of. If you take into account the petty losses here and there and total them together, I am sure, the need for improving or adding to railway fares etc. Which the hon. Minister was compelled to dc will probably be obviated. I am sure, as they care to get more revenue, they should also try to save as much as possible and regain every farthing due to them from the people in the proper way. In that way there is a possibility of this thing being less cumbersome to the people.

It is often mentioned here that among our Ministers there is no co-operation. It is a house divided between itself. This is the point that, I

find, is being made by some persons outside. How far this is true, I cannot say; but the speech of the Railway Minister as well as the Report of the Railways, which are placed before us, show that the Finance Department, the Department of Commerce and Industry and the Department of Railways have to a great extent gone hand in hand with each other and decisions were taken by them after due consultation. I think, this spirit of co-operation and co-ordination which is shown in the working of the Railway Department will be a characteristic of the working of all the other departments and we shall have no ground even to hear the whispering reports that there is no co-operation among the ministers and the things of Government are going on better.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यबाद देती हूं कि आप ने मुझे समय दिया। परसों मंत्री महोदय की स्पीच सुनने के बाद हम को उम्मीद हुई कि आईन्दा रेलवे विभाग अच्छा काम करने की कोशिश करेगा।

पिछले दिनों में बहुत से आनरेबल मेम्बर्ज ने सिकन्दराबाद में साउथ सैंट्रल जोन खोलने के बारे में विचार प्रकट किये और कहा कि इन दिनों में इस के लिए दो करोड़ रुपये ख़र्च करना वाजिबी नहीं है।

12.22 hrs.

[SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

जो मेम्बरान दो करोड़ रुपये के बारे में बोले हैं, मैं उन को कहना चाहती हूं कि पहले हैदराबाद हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी स्टेट थी और उस का रेलवे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा और शानदार था। आज हैदराबाद की हालत यह है कि यद्यपि वह हिन्दुस्तान के बीच में स्थित है, लेकिन वहां से दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कहीं भी डायरेक्ट जाने की सहूलियत नहीं है। मैं आप को बताना चाहती हूं कि अस्सी साल पहले से हैदराबाद स्टेट में 1400 मील रेलवे लाइन थी। वहां पर गाड़ियां बहुत शानदार थीं, रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस बहुत अच्छी थी, वहां के मुलाज़िम बहुत अच्छे और ट्रेनिंग-प्राप्त थे और उनको सैलेरीज़ भी अच्छी दी जाती थीं। बदकिस्मती से पालिटिक्स के कारण हैदराबाद स्टेट में पुलिस एक्शन हुआ। उस से बुराई तो निकल गई, लेकिन अच्छी बात को भी धक्का लग गया।

हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के सब रिसोर्सिज़, जिन की मिल्कियत 200 करोड़ रुपये थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। पच्चीस तीस साल पहले स्टेट रेलवे के डेवेलपमेंट और एक्सटेंशन का नक्शा बनाया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी इतनी मिल्कियत, इतने रिसोर्सिज़ और ताकत ले ली गई, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे बोर्ड या रेलवे मिनिस्टर ने कभी इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया कि हमारी जरूरत क्या है और हम क्या चाहते हैं। हमारे यहां रेलवे के अतिरिक्त और कोई सहूलियत नहीं थी। लेकिन उस को भी ले लिया गया और हमारी जरूरतों की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम लोग अठारह साल से ख़ामोश बैठे रहे और हम ने कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं किया। कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक कोई सत्याग्रह आदि नहीं किया जाता, है, तब तक सरकार काम नहीं करती है। यह बात सुन कर मुझे बहुत बुरा लगा।

हैदराबाद स्टेट में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना कई मकान दफ्तरों की इमारतें हैं जो कि पंद्रह सत्रह सालों से बेकार पड़े हुए हैं। किसी दूसरी जगह जोन खोलने से इमारतों आदि पर बहुत ख़र्च करना पड़ता जब कि यहां ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। मंत्री महोदय ने किसी के दबाव या इनफ्लुएंस की वजह से यहां जोन नहीं

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]
खोला है, बल्कि इन सब सहूलियतों के कारण ऐसा किया है।

आन्ध्र प्रदेश से लगभग सात आठ लाख टन धान दूसरी स्टेट्स को हर साल जाता है। वहां की पापुलेशन साढ़े तीन करोड़ है और लोगों को कई जगह आने जाने की जरूरत पड़ती है सिकन्दराबाद पुराने जमाने का स्टेशन है और वहां पर बहुत कन्जेस्सन है। हैदराबाद भी छोटा सा स्टेशन है। इन हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर ज़ोन बनाने से लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। इस में पालिटिक्स का कोई प्रश्न नहीं है। यह मिनिस्टर बहुत सोचने वाले और काम करने वाले। इसलिए उन्होंने वहां पर जोन खोलने का एलान किया है। हम आशा करते हैं कि वह वहां पर रेलवे के डेवेलपमेंट के लिए पूरी कोशिश करेंगे और वहां पर जोन कायम रहेगा।

अगर हैदराबाद से कलकत्ता जाना हो तो हैदराबाद से गाड़ी पुरी एक्सप्रेस के नाम से निकलती है काज़ीपेट में जी० टी० गाड़ी को लगा देते हैं विजयवाड़ा में उस को कलकत्ता मेल का नाम दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि हैदराबाद से कलकत्ता जाने के लिए चार गाड़ियां चार नामों से लगाना कौन सी अच्छी बात है। इस लिए हैदराबाद से कलकत्ता डायरेक्ट गाड़ी होनी चाहिए। इसी तरह हैदराबाद से दिल्ली और बम्बई आदि भी डायरेक्ट गाड़ी होनी चाहिए। हिन्दुस्तान में हमारी पापुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे करोड़ों रुपये के रेलवे के रिसोर्सिज केन्द्रीय सरकार ने ले लिये हैं। इस लिए रेलवे मंत्री को हमारी ज़रूरतों और समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक वैलफ़ेयर फंड का सवाल है वह बीस करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुझे इस बात की खुशी है लेकिन अच्छे मिनिस्टर्ज़ और अच्छे आफ़िसर्ज़ होते हुए भी इस फंड का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं होता है। जिस को जरूरत होती है, उसको कोई मदद नहीं दी जाती है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे मुलाजिमों को बीवी-बच्चे बहुत मुश्किल में होते हैं। जिस स्टशन पर पद्रह बीस मुलाजिम हैं वहां पर इंडस्ट्री खोलनी चाहिए प्राडक्शन सैंटर खोलना चाहिए। ऐसे स्टेशनों पर औरतों के लिए कोई धन्धा नहीं होता। इस लिए वे स्टेशन के आस-पास कोयला चुनती रहती हैं। उनकी अविवाहित जवान लड़कियां कोई धन्धा न होने के कारण पटरियों पर कोयला चुनती रहती हैं। अधिकतर रुपया बड़ी बड़ी इमारतों और दवाखाने आदि पर खर्च कर दिया जाता है। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं इस लिए उन को अच्छी स्कीम बना कर ग़रीब मुलाज़िमों को सहूलियत पहुंचानी चाहिए। और वेलफ़ेयर फंड के रुपये का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि वह महिलाओं को और अधिक सुविधायें देने के पक्ष में हैं और उनको सुविधायें दी जाएगी। उन के लिए गाड़ियों में और अधिक डिब्बे सुरक्षित रखे जायेंगे। लेकिन आजकल जो होता है वह मैं आपको बतलाना चाहती हूं। महिलाओं के साथ उन के भाई भी सफर करते हैं। भाई लोग जो होते हैं वे जितना भी सामान उनके पास होता है सारे का सारा महिलाओं के डिब्बों में रखवा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि महिलाओं का डिब्बा सामान से ही भर जाता है और उन के बैठने तक की जगह नहीं रहती है। इस तरह से आप चाहे और अधिक डिब्बे महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दें कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं। वहत तगड़े मिनिस्टर हैं। उनको देखना चाहिये कि महिलाओं का डिब्बा सामान से ही न भर जाए। जितना सामान एक यात्री ले जा सकता

बीस किलो या तीस किलो उस से अधिक सामान किसी महिला के पास उस के डिब्बे में नहीं होना चाहिये। जो फालतू सामान है उसको भाई रखे या वह लगेज में जाय लेकिन महिलाओं के डिब्बे में इस तरह से सामान नहीं भर दिया जाना चाहिये। पूरा का पूरा डिब्बा सामान से ही भर जाता है।

आंध्र प्रदेश में जहां तक मेरी कंस्टिट्युएंसी का सम्बन्ध है वहां कोई रेल नहीं हैं। वहां के लोग बहुत गरीब हैं। हमारे आंध्र प्रदेश का भी आपको खयाल करना चाहिये। मैं एक दो लाइनों के बारे में कहना चाहती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं कि इस पर सहानुभूति से विचार किया जाए। एक सैक्शन तो हमें लिगमपेली से संगा रेड्डी, जोगीपेट, नारायणखेट होते हुए एनांदेड़ तक मिलना चाहिये और दूसरा हैदराबाद से इब्राहिम पटन, नालागुंडा, नागार्जुन सागर और माचलरा तक मिलना चाहिये। नागार्जुन सागर बन रहा है। यह बहुत बड़ी योजना है। इस क्षेत्र के लिए एक रेल योजना तो होनी चाहिये। इस तरफ रेलवे लाइन आपको देने के बारे में विचार करना चाहिये यह जो दो सैक्शन मैं ने बताये हैं, इन पर आप गम्भीरता से विचार करें, यह मेरा आप से निवेदन है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : हम महिलायें इस सदन में दो परसेंट भी नहीं हैं। दो परसेंट में से भी एक परसेंट को भी बोलने का समय नहीं मिलता है। जब कोई बोलती है तो आप दो दो मिनट के बाद घंटी बजाते रहते हैं। यह उचित नहीं है।

एक और बात जो मैं कहना चाहती हूं ....

एक माननीय सदस्य : आखिरी बात है न ?

श्रीमती लक्ष्मीबाई : जब हम बोलती हैं तो बीच बीच में टोका जाता है और उस में हमारा काफी टाइम चला जाता है। इससे घबराहट भी होती है और हम बोल नहीं सकतीं हैं। चार दिन तक कोशिश करने के बाद आज समय बोलने के लिए मिला है लेकिन फिर भी हमें बोलने ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है।

मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जल्दी लैटर्ज का जबाब दिया जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो दो और तीन तीन महीने पहले खत लिखे जाते हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता है। यह मैं अपनी बात बता रही हूं। पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होना चाहिये। मिनिस्टर लोग आजादी के बाद अपने आ गये हैं, उनको तो अच्छा काम करना चाहिये।

जहां तक कैटरिंग का सम्बन्ध है, इसको अच्छी लाइंज पर चलाया जा रहा है, जो पद्धति है वह अच्छी है। लेकिन जब कोई एम० पी० वगैरह जाता है, वह सफर करता है तब तो खाना अच्छा दे दिया जाता है लेकिन जब कोई एम० पीज सफर नहीं करता है तो खराब खाना दिया जाता है है। वे लोग टिकट वालों से पूछते रहते हैं कि कोई एम० पी० तो नहीं आ रहा है और अगर नहीं आ रहा होता है तो खराब खाना दे देते हैं। लोग हम से कहते हैं कि आप टूर करते रहें ताकि उनको खाना तो अच्छा मिलता रहे। मैं चाहती हूं कि बिना बताये हुए मंत्री महोदय या रेलवे बोर्ड के मैम्बर जा कर इस चीज को देख लिया करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोगों को खाना अच्छा मिलता रह सकता है। पटना से मैं आ रही थी। उस डिब्बे में न लाइट थी और न पंखा। गाड़ियों में देखने वाला कोई नहीं होता है।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

एक एटेंडेंट होता है जो अपने आप को लार्ड समझता है । वह एक डिब्बे में दरवाजा बन्द कर के सो जाता है । यह जो चीज है इसको भी आपको देखना चाहिये । वह ड्यूटी पर रहे इसका आपको ध्यान रखना चाहिये ।

आपने इस डिपार्टमेंट में लाखों लोगों की फौज भरती कर रखी है । एक व्यापारी होता है वह अगर सौ रुपया इनवैस्ट करता है तो उसको पांच रुपया मुनाफा होता है, अगर हजार करता है तो उसको पचास रुपया होता है और लाख करता है तो और भी ज्यादा होता है । रेलवे में हमने करोड़ों और अरबों रुपया लगा रखा है लेकिन बचा कर ये हमें कुछ भी नहीं देती हैं । जो कमाती हैं वह खा जाती हैं । यह बात ठीक नहीं है । रेलों को पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए नहीं किया है कि ये जो कमायें खा जायें । हमें उन से आशा थी कि ये कमा कर हमें देंगी । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है काफी रुपया कमा कर रेलों को हमें देना चाहिये । इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Even in this highly critical House with persons like Shri Kamath....

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): My hon. friend is also a good critic.

Shri Harish Chandra Mathur: It could safely be stated that the railways have by and large done very well. Their performance has been satisfactory to an extent, and there have been no shortages of wagons anywhere. But this should not throw us into a sense of complacenaj; these shortages that we have not felt have been absent not because we have overstepped our production on the railway side but because our iron-ore and coal development and industrial growth had not been to the extent that they were expected to be. That has given a set back to the railways in their revenues also. This has constantly to be borne in mind.

The hon. Minister made a strong point by saying that our railways were very credit-worthy. There is no doubt about it that when they want some foreign loan, there is no difficulty in getting it. The railways are credit-worthy. They are financially sound and they are on a stable basis. But I think that I can go a step further than the hon. Minister and say that even if we do not increase these fares and freights, the railways would certainly have remained credit-worthy, and my hon. friend the Railway Minister is only making a virtue out of a vice by advancing this argument that in order to keep the railways credit-worthy, he is raising further revenues.

The hon. Minister had also advanced the argument about the increase in the customs duties and said that this 10 per cent additional levy would cost the railways additional expenditure. May I know whether the hon. Minister is in a position to give us an assurance that with a decrease in the customs duties he will effect a reduction in the fares and freights because, as I learn from the hon. Minister of Finance, this increase is only an emergency measure of a temporary nature to get over a particular difficulty regarding foreign exchange?

I think the hon. Minister has unfortunately overstressed the commercial aspect of the railways. The railways are certainly one of our most important commercial undertakings. But they lack of the commercial attitudes and salesmanship which are the most important qualities of a commercial concern. Profitability is also important. When we talk about a commercial enterprise or commercial undertaking, we know that it should be profitable, but then we want that the other commercial attitudes also should

be there. For instance, take the question of clientele-satisfaction. That aspect of the railways also should not be ignored in the case of the railways. I wish that the hon. Minister also does not forget that the railways are also a public utility concern.

During all these days we have been talking in this House about the co-ordination between all modes of transport, such as the railways roads and waterways but we seem to have completely forgotten it now. I do not know what has happened. The railways as a big brother have not been very fair to road transport. That has been the complaint of road transport all the time. The co-ordination committee was appointed only with a view to sort out all the difficulties and to see that road transport got its due share. There are certain inhibitory factors operating against road transport at present and if the report of the co-ordination committee which has gone into it is put in cold storage, it is not to the disadvantage of the railways; it is only to the disadvantage of road transport. This has got to be borne in mind.

Then I wish a little more attention is necessary regarding the railways' distribution of zones and divisions. Since 1951-62 upto 1963-64, the tonnage lifted has increased by 96 per cent and the ton kilometres by 132 per cent. We must take note of this increase in load in various sections. I definitely am prepared to say that our zones shoud not be carved on any other considerations except the economic ones on which railway working is based. As we have, say, in the irrigation department, the grid system or zone system, on similar lines the railways should also have certain norms on which their zones should be based. They should be based on scientific criteria; at present, they are a little lopsided.

I would not say that we want a zone for Rajasthan, but I do not want to say that there is urgent need for a metre gauge zone to be carved out separately. Metre gauge has been very much neglected all these years.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung—Now there is quorum.

Shri Harish Chandra Mathur: Why do I say this?

As a matter of fact, if you refer to the Kunzru Committee report if you refer to previous reports and if you refer even to the record which was made out at the very initial stage when zones were carved out, this zone was there. Somehow it does not suit the convenence of certain people. I think this is a matter on which the hon. Minister should throw some light. A metre gauge zone will give better attention to the metre gauge area and there would also be standardisation. Otherwise, we are faced with this type of difficulty.

While on this subject, I would say that you should also look at your divisions. Some of them are very lopsided. Take the Delhi Division. It has a staff of about 30,000 people. Do you think a Division with 30,000 staff would be properly managed? Do you think any personal contact could be kept? I think I need not go further into it, but Divisions have also to be looked into.

Coming to the question of the improvements we expect on our railways, let us not confine our vision only to our own house. Let us see how the entire world is advancing. What has happened elsewhere? The Japanese National Railway has acquired a prestige in the entire world. Their speed is about 200 kilometres an hour. It is on a particular section; I do not say it is the general rule. On the other hand, where are we? During all these 10, 12 years we have made no progress whatsoever in this front. The speed is 50 kilometres an hour on one of our best sections, 55.0 kilometres and 60

[Shri Harish Chandra Mathur]

kilometres. Now, we cannot live in a compartment like that. Therfore, there is urgent need for us to look into this matter.

While on speed, I would also like to refer to punctuality. I am told punctuality has improved. But that is not the personal experience of Members. While from the records we find that puctuality has improved, Dr. Aney told us that every train he travelled in was running late. I will not say that the trains by which I have travelled all were running late. But I have shrewd suspicion that the Jodhpur-Jaipur train was always running late. I warned the raiway administration a year earlier. I asked them to mend matters. There was a meeting of Divisional Superintendents. They changed timings. They provided cushion. Yet, what is the state of affairs? This is from information supplied by the railways themselves. During the month of October, the train was on right time only on 12 days; for 13 days it was late by 15 minutes, on 6 days late by more than 15 minutes. Again in November the train could run on right time only 14 times; 9 times it was late by 15 minutes, on 7 days for more than 15 minutes.

13.46 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I therefore think that a better analysis and better attention has got to be made if we are to be sure, if we are to carry conviction with the people that punctuality has improved and speed has improved.

Then I wish to draw the pointed attention of the hon. Minister to another matter. I had been in correspondence with him for some time on this. I took the opportunity of going and also meeting the Minister and discussing this matter with him. This was regarding the inflated rates they charge on certain sections. There are four sections—-Kotkal section, Khandwa-Hingoli section, Fathepur-Churu and Ranivara-Bhildi—where the freights and fares are more than the ordinary ones they are charging. Here they are $1\frac{1}{2}$ times, 2 times and 90 per cent more. I see absolutely no justification for it. They say that their returns are not good. But may I ask whther they charge lesser fares on those routes where the retunrs are better? Have they fixed a maximum and a minimum. Or is it one pool system for the entire country? Do they consider that the backward sections deserve a little more sympathy or do they want to burden them all the more? Are we following different policies in different modes of transport? As everybody knows, the Caravelle service between Delhi and Madras is running at a very heavy loss. On that account, is the fare from Delhi to Madras different from that from Delhi to Calcutta or Delhi to Bombay? No.

Let us understand and adhere to some principle. As a matter of fact, if the principles enunciated on the floor of the House bear any meaning, it is that the backward areas have got to be given a better lift. I do hope the hon. Minister will give particular attention to this matter.

I have never during the 12 years I have been a Member of Parliament asked for a particular line connection in this area or that area. You can go through the records of all my speeches. But I do wish to say this. Let them not ignore these areas and only attend to those where there is a vociferous demand. We are not hear only to ask about these things. But the fact remains that the Sirohi and Jalore districts have been completely neglected. There has been a consistent and persistent demand. I have been receiving letters all the time. It is no use saying that if all such demands are added up, it would need a thousand crores and so nothing can be done. But I ask that at least this should be taken note of. They should go into the matter and find out.

Another point. You must take much better care of your personnel planning. The railways have always been proud about their personnel. Even Shri T. T. Krishnamachari told me the other day that they have for other public undertakings to depend on recruitment from the railways. That is a great compliment to the railways. I know they have got extremely fine officers, and I do wish to pay a compliment for rebuilding the bridge in the South which was blown away by heavy storm, within two or three months. One of the General Managers,--I have never had the good fortune of meeting him--Shri Ganguli, did an exceedingly fine job of it. Though the target was three months, he built the whole thing in two months time with the utmost economy. But I wish to point out that there is a flight of officers from the railway administration on the one hand, because there are so many projects which are taking them away, and on the other hand, you are now not attracting the best officers. Previously, anyone who passed engineering, would straightaway adopt for the railways, but now they do not do so. Only last evening a young man came to me--he has got an offer from UPSC,--asking my advice whether to go to the railways or elsewhere. I do hope that this thing will be particularly taken note of. Your officers do not get even after having put in 20 years of extremely satisfactory service, promotion even as a junior administrative officer. This is a matter which definitely has got to be looked into.

I also wish in the end that they would select at least 25 railway stations and make them models. Please take those railway stations which are very much visited by foreign tourists. At present, all the platforms are strewn with goods of all kinds, and are dirty, and unfortunately there is the beggar menace. These beggars are known. There are five or six houses attached at all the stations. It is not they are not known. You have got rules and regulations, but they are not implemented. I wish you select 25 or 30 stations and make a good start.

श्री म० प्र० शर्मा (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं दोबारा रेलवे डिमांड्स पर नहीं बोलना चाहता था लेकिन दो कारणों से मुझे बोलना पड़ रहा है।

सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डिमांड नम्बर २ में जो आरा से ससाराम लाइन का सर्वे करने की बात कही गई है मेरा विश्वास है कि सर्वे के बाद उस काम को मंत्री महोदय जल्दी पूरा कराएंगे। इस बारे में मैं विशेष रूप से इसलिये कहना चाहता हूं कि ऐसा देखा गया है कि बहुत से कामों के बारे में ऐसा होता है कि अगर उस इलाके के मंत्री होते हैं तो उन कामों को शुरू तो करा दिया जाता है लेकिन बाद में रेलवे मंत्रालय उन कामों को बन्द करवा देता है। मैं इस बारे में कोई खास उदाहरण नहीं देना चाहता।

कुछ जरूरी बात रेलवे मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मुझे आशा थी कि रेलवे के जनरल बजट की बहस से बाद पाटिल साहब कुछ इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि रेलवे की जो प्रगति हो रही है उसके पीछे जो काम करने वाले हैं उन के लिये उनकी क्या योजना है। रेलवे की यहां बड़ी तारीफें हो रही हैं कि रेलवे बहुत सुचारु रूप से चलने वाली संस्था बन गई है देश की बड़ी सेवा कर रही है और इसमें बहुत सी प्रगति की बात की जा रही हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही जा रही है, रेलवे के डीजलाइजेशन की बात कही जा रही है, रेलों की स्पीड बढ़ाने की बात कही जा रही है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि यह सारी जो रेलवे की प्रगति हो रही है उस के पीछे जिन तमाम चीजों की आवश्यकता है उनमें सबसे बड़ी चीज रेलवे में काम करने

[श्री अ० प्र० शर्मा]

वाले जो १२ लाख लोग हैं उनके कोआपरेशन की आवश्यकता है । रेलवे मंत्री की सराहना बहुत की गई कहा गया कि उनकी डाइनेमिक पर्सनलटी है । बहुत उदार दिल के हैं लेकिन बहस का जो जवाब पाटिल साहब ने दिया उसमें यह नहीं बताया कि क्या रेलवे कर्मचारियों की उन्नति के लिए निकट भविष्य में कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे प्रोत्साहित हो कर व ज्यादा अच्छे ढंग से काम करें । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूं ।

वेजबोर्ड के सम्बन्ध में उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हम अपने कर्मचारियों को इतना सतुष्ट और सुखी रख रहे हैं कि वेज बोर्ड का सील अपने काम पर लगवा देने पर उनको इससे अधिक संतोष नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि उन्होंने पुराने ढंग से सवाल का जवाब दिया है । रेलवे मंत्रालय इस बात का दावा करता है कि रेलवे में काम करने वाले सभी लोग सतुष्ट हैं । लेकिन अगर पता लगाया जाए तो मालूम होगा । जैसा कि मैं ने बहस के दौरान कहा भी था कि अफसरों से लेकर नीचे दरजे के सभी कर्मचारी लोग आज असंतुष्ट हैं । इसका कारण यह है कि वे देखते हैं कि अन्य उद्योगों में लोग उनसे ज्यादा प्रगति कर रहे हैं । वेज बोर्ड देने के मानी वेज बोर्ड के सील लगवाने की बात नहीं है । यह यूनीवरसल डिमांड है और मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इस बारे में प्रकाश डालेंगे । आज देश में एक ऐसी हवा बह रही है कि अगर किसी मांग के पीछे आन्दोलन होता है तो सरकार उस पर विचार करती है । मैं चाहता हूं कि इसका सरकार मौका न आने दे । यह सभी मजदूर संगठनों की मांग है । इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में चार लाख लोगों का शोषण हो रहा है जिनको कैजुअल लेबर कहा जाता है इन को आज भी एक रुपया चार आना एक रुपया आठ आना और एक रुपया १२ आना रोज पर रखा जाता है । जितना कांस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें अधिकतर ये लोग ही काम करते हैं । मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री इन की तरफ भी ध्यान देंगे और इनके वेतन में वृद्धि करेंगे ।

आखिर में मैं रेलवे श्रम सम्बन्धी मैशिनरी के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । इसके न होने से लोगों में बड़ा असंतोष बढ़ रहा है और अगर यह नहीं किया जायेगा तो यह असंतोष और बढ़ेगा और उससे किसी को फायदा नहीं होगा । इस बारे में जिस ढंग से रेलवे आज जवाब दे रही है वह संतोषजनक नहीं है । मजदूर मांग कर रहे हैं कि जो भी झगड़ा हो उसको आपस में पंचायत से तै किया जाये । इसका जवाब दिया जाता है कि जो भी आज मैशिनरी है वह लोगों की शिकायतों को दूर करने में सफल है और अच्छा काम कर रही है और इसलिये इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में सारे मजदूर संगठनों की एक राय है चाहे वे किसी दल से सम्बन्ध रखते हों कि आज जो परमानेंट नैगोशिएटिंग मैशिनरी रेलवे में है वह बेकार है और उस से मजदूरों को कोई फायदा नहीं हो सकता । मजदूरों को उस समय तक फायदा नहीं हो सकता जब तक कि रेलवे बोर्ड के स्तर पर आरबिट्रेशन का प्रावीजन नहीं होता । मैं २५ साल से मजदूरों में काम कर रहा हूं । मैं जो यह बात कह रहा हूं वह इसलिये कह रहा हूं कि इसके बिना लोगों में बड़ा असंतोष बढ़ रहा है । मैं आशा करता हूं कि अपने जवाब में राजस्व मंत्री मैंने

दो तीन बातें आपके सामने रखी हैं उनका उत्तर देंगे।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक रेलवे पबलिक सरविस कमीशन की स्थापना होनी चाहिये और इसमें रीजनल लेंग्वेज या हिन्दी के माध्यम से क्लास ३ कर्मचारियों की भरती के समय परिक्षा होनी चाहिये इसके सम्बन्ध में कंसलटेटिव कमेटी में श्री पाटिल ने आश्वासन दिया था कि रीजन के आधार पर नहीं बल्कि औचित्य के आधार पर इसकी आवश्यकता है और इसी आधार पर इसकी स्थापना की जायेगी। मेरा सुझाव है कि जहां चार पब्लिक सरविस कमीशन वहां पांच किये जाएं और बिहार में किसी एरिया में इस न सरविस कमीशन क हैडक्वार्टर रखा जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मेंने राजस्थान के बारे में कुछ बातें परसों कही थीं लेकिन लेबर के मामले में मुझे कुछ और कहना है।

मेरा निवेदन है कि जो कैजुअल लेबर है इसके लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाए कि दो साल बाद, एक साल बाद या 6 महीने बाद उसको परमानेंट कर दिया जाएगा क्योंकि अभी उसके लिये कोई ऐसा समय मुकरर नहीं है कि उसको कब परमानेंट किया जायेगा। परमानेंट न होने से उनको अस्पताल की कोई सुविधा नहीं मिलती। यदि कोई उनको दवा दे भी देता है तो अच्छी दवा उनको नहीं दी जाती अच्छी दवायें उनको बाजार से लानी पड़ती हैं। मेंने पिछले महीने कोटा में अस्पताल का रजिस्टर देखा तो पता चला कि अस्पताल द्वारा बाजार से जो अच्छी दवायें खरीदी गयी हैं वे बड़े बड़े आदमियों के लिये ही खरीदी गयी हैं, छोटी लेबर का नाम तो उस रजिस्टर में नहीं था।

12.06 hrs;.

सारी अच्छी अच्छी दवायें बड़े बड़े आदमियों को मिल जाती हैं जबकि छोटे छोटे कर्मचारियों से कहा जाता है कि वे अपने लिये दवाइयां बाजार से खरीद कर लायें। अब जो सवा या डेढ़ रुपया रोज उसे मिलता है उसमें वह अपना पेट पाले कि दवाई लाये? इसमें आज वह अपना पेट तक नहीं पाल पा रहा है। अब उस बेचारे लेबरर को या क्लर्क को 110 रुपया महीना मिलता है। इस 110 रुपये का आप उसका और उस के परिवार के खाने, पीने और कपड़े आदि आवश्यकताओं का बजट बना दें और देखें कि वह आखिर इस 110 रुपये में किस तरीके से अपनी गुजर बसर करे? आज 110 रुपये में उसकी गुजर होती नहीं है तब 45 रुपये और 60 रुपये में किस तरीके से गुजर करे? जरूरत आज इस बात की है कि कैजुअल लेबर को फिक्स अप कर दिया जाय, उनको बारहमासी कर दिया जाए और रैगुलर हो जाने से उनको यह विश्वास हो जायेगा कि वह एक अवधि के बाद सर्विस में परमानेंट हो जायेंगे। उनके लिये कोई टाइम फिक्स कर दिया जाये कि कब उनको परमानेंट कर दिया जायेगा :

रेलवेज में करीब 44 हजार कमर्शल कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उन बेचारों को कोई भी सहूलियत रेलवे द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। रेलवेज ने उनको टैम्पोरेरी समझ रक्खा है। न उनके लिये ग्रेड का सवाल है न कोई वर्दी का सवाल है और उनको एक बिलकुल अछूत के मुआफिक बना कर रख छोड़ा है। चोरी आर० पी० एफ० वालें करें और पैसा कमर्शियल क्लर्क की तनख्वाह से काटा जाय, मालगुदाम का खलासी किसी पेटी आदि के ताले को खोल दे, गड़बड़ कर दे तो उसका पैसा कमर्शियल क्लर्क से काटा जाय। अगर कोई मालगाड़ी खराब होने के कारण रुक जाय तो डैमरेज कमर्शियल क्लर्क से लिया जाय, बारिश में सामान भीग जाय तो उसका पैसा कमर्शियल क्लर्क से काट लिया जाय। जब चाहे नीचे दाब लिया, कमर्शियल क्लर्क एक दुधारू गाय के समान है कि जब

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

चाहे दह कर दूध बाढ़ लिया । आखिर यह कैसा कर्मशियल क्लर्क है जो कि रेलवेज़ को इतनी आमदनी कर के देता है लेकिन फिर भी रेलवेज की उस पर कृपादृष्टि नहीं होती है । इसलिये मेरा मंत्री जी निवेदन है कि इन कर्मशियल क्लर्कस की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय और उन्हें जरूरी सहूलियतें ग्रेड आदि की प्रदान की जायें ।

एक मेरा निवेदन यह है कि कोटा जंक्शन स्टेशन पर एक भी थाना नहीं है । 20,000 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं । अभी पिछले साल दिसम्बर के महीने के अन्दर एक सरदार हैड क्लर्क की जवान एम० ए० पास लड़की को दिन के अन्दर क्वाटर के अन्दर कत्ल करके डाल दिया गया । एक भी थाना नहीं है न ही सिपाही हैं । केवल 4 सिपाही लेकर एक क्वाटर में खोस रक्खे हैं । उन चार सिपाहियों के हाथ में छोटे छोटे डंडे दे रक्खे हैं । अब आप ही बतलाइये यह बेचारे 4 सिपाही 20,000 कर्मचारियों को क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ? इसलिये वहां पर पुलिस की समुचित व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है ।

90 डाउन देहरादून की गाड़ी के अन्दर काफ़ी रश होता है क्योंकि सारी सवारियां जयपुर जाने वाली होती हैं । उस में केवल दो ही थर्ड क्लास के डिब्बे होते हैं जो कि बिल्कुल नाकाफी होते हैं और सारे मुसाफिर उस में बैठ नहीं पाते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि नागदा से मथुरा तक एक रेल गाड़ी चलाई जाय या मथुरा से नागदा तक चलाई जाय लेकिन यह गाड़ी चलाई जानी बहुत ज़रूरी है । जयपुर 11 बजे यह गाड़ी जाकर उतार देती है उस में जयपुर से सवाई माधोपुर तक जाने के लिये कोई स्लीपर कोच का डिब्बा नहीं है ।

कोटा स्टेशन पर जो ओवरब्रिज उस में एक पार्टीशन जाली लगा दिया जाय जैसा कि विजयवाड़ा वगैरह में लगा हुआ है ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सके । इस ओवरब्रिज में पार्टीशन बनाने के लिए मैं ने कई दफा कहा है कि उसमें चार फुट का जाली का पार्टीशन खड़ा कर दें जैसा कि कई स्टेशनों पर है तो उन की शिकायत रफा हो सकती है क्योंकि उस में 12 15 गांव के आदमी निकलते हैं। मुसाफिर भी इधर से उधर आते जाते हैं, गाड़ी का टाइम कारखाने का टाइम मिल जाता है, और इस के न होने से काफी अव्यवस्था फैल जाती है । इसलिए अगर यह जाली के पार्टीशन की व्यवस्था कर के अलग हो जाय तो उत्तम रहेगा । कोटा में रेलवे कर्मचारियों को राशन मिलने की कोई भी सुविधा नहीं है । 9 मील जाना पड़ता है । इसलिये कालोनी में ही व्यवस्था की जाय ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । लोको वर्कशाप के अन्दर जो कैंटीन वगैरह हैं उन में शैडयूल्ड कास्टस वालों की सुविधा का कोई ख्याल नहीं किया जाता है । जब से श्री जगजीवन राम रेलवेज से गये हैं तब से इस ओर ध्यान नहीं रहा है । कैंटीन आदि की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और कैंटीन आदि के बारे में किसी भी शैडयूल्ड कास्ट वाले की कोई भी शिकायत सुना नहीं जाती है । वहां कैंटीन में हम देखते हैं कि हरिजन कर्मचारियों के लिए अलग तश्तरियां पटक रखी हैं। मंत्री महोदय इसे स्वयं जा कर चैक कर सकते हैं । ट्रालियों के अन्दर यही हाल है। उन को नहीं चलाने देते और कैंटीन के अन्दर यही हालत है । मैं नहीं समझता कि इस के रहते हरिजनों के साथ कैसे इंसाफ हो सकेगा ? इसलिये मेरा आग्रह है कि आज हरिजनों, शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के साथ जो वहां पर छुतछात बर्ती जा रही है वह दूर की जाय ।

आज कितने ही हरिजन कर्मचारी रेलवेज के नहर के किनारे झोंपड़े डाल कर पड़े

हुए हैं । उन को एक भी क्वार्टर नहीं दिया गया है । क्या वे रेलवज़ के कर्मचारी नहीं हैं जो कि उन को क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है ? मेरा निवेदन है कि उन को क्वार्टर मंत्रालय को देना चाहिए । अगर उन को रखना है तो मंत्रालय उन्हें क्वार्टर दे वरना उन को छुट्टी दे देनी चाहिए ।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर 20,000 रेलवेज़ के कर्मचारी हैं । उन के लड़कों के लिए एक एक कोठरी दे रक्खी है पढ़ने के लिए । 110 लड़के पढ़ाने के लिए एक मास्टर और एक क्वार्टर देना बिल्कुल नाकाफी है क्योंकि एक क्वार्टर में तो 110 भेड़ बकरी भी नहीं ठीक से बांधी जा सकती हैं । कहने का मतलब यह है कि इस तरह से उन 110 बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह से पढ़ने के लिए भरा जाता है । वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए 1250 हैं जबकि मास्टर कुल दस ही हैं और उन को पढ़ने के वास्ते कमरे केवल चार ही हैं । अब एसी हालत में वह किस तरह से उस जगह पढ़ सकते हैं ? जरूरत इस बात की है कि अगर वहां दस हजार क्वार्टर आप बनायें तो एक बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना आवश्यक है लेकिन वह स्कूल नहीं बनाया गया ।

अब मैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार का मामला बतला दूं कि वहां पर किस किस तरीके से गड़बड़ घुटाला होता है ? भ्रष्टाचार मिटाने के ऊपर हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर रेलवे के अन्दर से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाय तो सोने की पटरी बन सकती है लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त होने की जगह और बढ़ता ही जा रहा है । इस का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 200 केस इस साल में कांग्रेस के नेताओं, उच्च अधिकारियों तथा साधारण कांग्रेसी सदस्यों के प्राप्त हुए हैं । यह शिकायत भी मिली है कि सरकारी अधिकारी अपने फ्री पास अपने मित्रों को तथा कुछ दूर के रिश्तेदारों को देते हैं । सब से खतरनाक बात कांग्रेस के नेताओं के बारे में यह बतलाई जाती है कि उन में से अधिकांश के पास रेलव पास नहीं होता, दूसरों को व दिये रहते हैं और इस बारे में जब उन की चैकिंग होती है तो वे टी० टी० को सर्विस छुड़ा देने की धमकी देते हैं । यह एम० पीज०, एम० एल० एज०, कांग्रेस के बड़े नेता यह रेलव के फ्री पास अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि दूसरों को इनका इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं । उन लोगों को फ्री पास न जाने कहां कहां चलता रहता है । अब जब यह हालत हो और इस तरह का भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाय तो देश से भ्रष्टाचार दूर करने की बात केवल एक मजाक ही बन कर रह जाती है ।

उत्तरी जोन के अन्दर जनवरी के महीने में 40 केस बगैर पास के सामने आये हैं जिनमें कि लाखों रुपये का घुटाला हुआ है । फ्री पास का अगर इस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों तथा कांग्रेस के नेताओं द्वारा दुरुपयोग किया जाता रहा तो यह भ्रष्टाचार रेलवेज से और देश से कैसे दूर हो सकेगा !

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । यह जो स्लीपर कोच का डिब्बा है उस डिब्बे के अन्दर जो कंडक्टर रहता है वह बेचारा लैट्रीन के पास बैठता है । कंडक्टर के पास अपने बैठने के लिए कोई सीट ही नहीं है । वह दूसरों को सीट देता है लेकिन स्वयं के लिए कोई सीट नहीं है । अब इस तरह से बगैर सीट के रात भर जागता हुआ चले यह कहां तक उचित होगा ? इसलिए उसे सीट देने की व्यवस्था की जाय ।

कोटा जंकशन स्टेशन पर कोटे की कमी है । हमारे यहां के लिए फ्रंटियर मेल में कोई कोटा ही नहीं है । जहां सवाई माधोपुर और मथुरा में चार, चार दे रखे हैं, वह

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

कोटा में कोटे की कमी है । उसके लिए कोई कोटा नहीं है । वहां से फर्स्ट क्लास का डिब्बा लगता है । उसमें भरत राम और चरत राम के कहने पर ऐयर कंडीशंड डिब्बा लगाया गया जिस पर कि लाखों रुपये का नुक्सान हो रहा है लेकिन फिर भी वह मंगलवार और शनिवार को चल रहा है । उस से फर्स्ट क्लास में चार सीटें रह जाती हैं । जहां 12 सीटें थी वहां अब केवल 4 ही रह जाती हैं इसलिए उस ऐयर कंडीशंड बोगी को बन्द किया जाय और उसकी जगह थर्ड क्लास का डिब्बा लगा दिया जाय ।

एक अन्य बात मैं यह कहूंगा कि कोटा से चलते हुए बीना आने वाली गाड़ी में सिर्फ चार डिब्बे लगते हैं । यह इतने कम हैं कि यात्री बाहर लटकते हुए जाते हैं इसलिए डिब्बों की तादाद और बढ़ायी जानी चाहिए । इतना बड़ा रन है और शाम को जब वह गाड़ी आकर पहुंचती है तो वहां यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ रहती है कि वह इन चार डिब्बों में समा ही नहीं पाते हैं इसलिये एक, दो डिब्बे इसमें और जोड़े जाने चाहियें ताकि ग्रामवासी सहूलियत के साथ उनमें सफर कर सकें । इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि कोटा से 50 मील के फासले पर एक बारा स्टेशन पड़ता है । बारा से किशनगंज 10 मील है और शाहाबाद उससे थोड़ा 20—25 मील पड़ता है इसलिए बारा से किशनगंज-शाहाबाद तक यह गाड़ी बढ़ा देने में डकैतों पर जो लाखों रुपया साल का खर्च होता है, वह बच जायगा । रेल निकाल देने से वहां काफ़ी चहल पहल हो सकती है । वहां पर लोहे की खदानें भी काफ़ी हैं जिनका कि रेल चला कर पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है । रेल की सीटी और गाड़ी के पहियों की आवाज से चोर डाकू भाग खड़े होंगे जिस तरह से कि मेरी आवाज सुनकर कांग्रेसी सदस्य भागते हैं । अब मैं अपनी आवाज के लिए कर क्या सकता हूं ? सरकार डाकुओं की समस्या का सामना करने में जो लाखों रुपया खर्च करती है वह इस रेल लाइन से निकाल देने से बच जायेगा । इस इलाक़े में रेल की लाइनें बिछाई जायें ।

फलोदी से 9 मील के फासले पर मलादिन में 200 नमक के कुंवें हैं । अगर यह सात, आठ मील का टुकड़ा बना दिया जाय और रेल से इसे सम्बद्ध कर दिया जाय तो काफ़ी मात्रा में नमक वहां से मिल सकता है । यह टुकड़ा बन जाय तो बहुत इनकम हो सकती है । उससे आगे चलकर रामदेवरा स्टेशन है । वहां पर हर साल हजारों रुपया टैम्पोरेरी शैड बनाने में लगता है । त्रिपाल डाल दिया जाता है, उतार लिया जाता है और इस तरह उतारने और लगाने में वह त्रिपाल नष्ट भी हो जाते हैं । जहां से आपको लाखों रुपये की आमदनी होती है वहां पर मंत्रालय को एक शैड बनाने में क्या आपत्ति है ! चार चार ट्रेनें वहां पर जाती हैं, ट्रौली वहां पर जाती जरूर है इसलिए अगर वहां पर कुंआ खुदवाया जाय तो उचित होगा क्योंकि वैसे ही वह रेगिस्तानी इलाक़ा है । मुझे आशा है कि मैंने यह जो चन्द एक सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं उन पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और उन्हें अमल में लाने का प्रयास करेंगे ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Deputy Speaker, there is a proverb in the English language that those people who knew only England did not know anythig about England. Now, when I think of the Indian railways I am reminded of that proverb. The people who know the Indian railways only do not see them in their proper perspective and are unable to realise the magnitude of this undertaking, the immensity of its work and the mammoth organisational work that is being done in connection with them. I feel that every one has a grouse against the railways and perhaps I have more grouses than anybody else, but it should be said with an eye on truthfulness that the railways are a model national undertaking and that our other public

undertakings should take a lesson from the railways.

It has been said that the Railway Board is a steelframe of the railways. I think that is so. But I feel that it is a steel-frame which has been oiled well, which has been lubricated well and which has been functioning quite efficiently. Can you have or think of any organisation of this size which is a brain-trust of this small size? I think I should be failing in my duty if I do not say that on the whole the Railway Board has given a good account of itself and the railways have been showing an upward tendency in revenue, in efficiency and in the nature of amenities to the passengers and other things. I congratulate all the workers of the railways, from the railway porters—these are the people with whom I deal more often than with anybody else—to the Railway Minister who is one of the most regal of commoners. I feel that each one of them, whether they belong to the loco class or the commercial class or any other class, deserves our congratulations for the good work that they are doing. I hope that they will continue to do good work.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय हाउस में को˜म नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung. Now, there is quorum. The hon. Member may continue.

Shri D. C. Sharma: I value the railways for one reason more than anything else, and it is this: that they are perhaps the only integrating force in this country What has happened to our languages? What has happened to our administrative services? We wanted to have the administrative services as the cementing bonds between one State and another—the judges and other services. But I find at the railways are at present the one organisation in this country which brings about intergration between Gurdaspur and Trivandrum, between Calcutta and Gurdaspur, between one part of the country and another part of the country. I wish that this thing should persist, should continue, and the railways should do this function of national integration much more efficiently than they have been doing before.

When I go to Trivandrum, I travel with my South Indian friends and I do not find any difference between them and myself so far as our outlook is concerned; we take the same food and we talk the same language and the same thing happens to citizens all over India, and I believe that the railways have played their role in cementing the national bonds of this country much more effectively than any other agency, be it the administrative services, the high court judges, the educational system or anything else. But unfortunately whenever there is trouble in this country, the railways suffer more than anything else. The people burn the railway stations; they set fire to the railway carriages. They do all kinds of things. The railways, I think, have to pay the price for being the source of national solidarity in this country.

But I want to put one question to the Railway Minister who is unfortunately not here, but his robust Minister of State is here and his lean Deputy Minister is also here. I feel that both of them taken together may come up to him though nobody singly can come up to him. I want to ask one question: why can't you have some trains which can be show-pieces all over the world. The Olympic Games were held in Japan recently; they put a new railway track; they designed new trains; they made new compartments. They had new kinds of locomotives and they accelerated the speed of the trains to an abnormal extent. I ask this question as to why this kind of thing is not done in this country. Why can't we compare ourselves with some other country, say, Japan, so far as some of these show-pieces in the matter of railway transport are concerned? Of course, on the whole, we compare very favourably with them, but we should produce a locomotive which runs very fast and which can make me say when I go

[Shri D. C. Sharma]

to France or Japan or any part of the world: "We have also a train which travels at the rate of 200 km. per hour" and so on. That is what I wanted to say, and I hope the Railway Minister will do something in this regard.

I do not look upon the Railway Minister only as an employing agency. I want the Railway Ministry to be an ideal employing agency. Of course, I would like to have a wage board for every type of worker. I would like to have a wage board for teachers also. But if a wage board is not possible, I would say that the different categories of railway employees should have the pay-structure rationalised in terms of the locality where they serve, in terms of the danger which their job involves and in terms of difficulties of the profession which they profess. Unfortunately, it is not done.

Take, for example, the ticket collectors. They have a very difficult job to do. I do not know what the railways are doing about it. Take the case of those persons who are working in NEFA, in the Northeast Frontier Railway. What are you doing for them? Have you given them anything by way of compensation, because they are living in a very dangerous place and they are manning the railways at a place where there is perpetual unending and unceasing crisis? You do not do anything of that kind. You want to have only one yard-stock by which you will measure everybody. I think this policy of uniformity should be reconsidered.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): They are given extra.

Shri D. C. Sharma: I would like that you give them more, because, my hon. friend Dr. Ram Subhag Singh, whose good health I envy and who is sitting here will realise that they work in a place where there is always the fear of death every moment. I think you must pay them sufficient compensation for the hazards of their professions which are involved in the exigencies of the situation.

I have read Dr. Beecham's Report about English Railways. He has done away with all the uneconomic lines there. That is how they are making the finances of the Railways sound. But we are not doing that here. That is a good thing.

I want to ask the Railway Ministry one thing. We want to construct a railway line from Pathankot to Kathua, from Kathua to Jammu, and from Jammu to Riyasi. But, why are they taking such unconscionably long time in constructing that? It is a strategic line. It is a line which is fraught with military advantages. It is a line which would be our life line in times of emergency. It is a line which would be needed at any moment and yet they are so slow about it. I want a categorical answer to my question, why so much time is being taken. I would be told that there are so many rivers. How can we produce a land where there will be no rivers? I would be told that there are so many mountains. I cannot produce a land where there will be no mountains. It is the work of the engineers to overcome the disabilities created by rivers and by mountains and if they are not able to do so, they are not worth the salt. Therefore I think this strategic necessity of our country will be realised and this railway line constructed quickly—from Pathankot to Kautha, from Kautha to Jammu, from Jammu to Riyasi and, Sir, if you don't mind my saying this, from Riyasi to Rajouri, which happens to be the birth-place of my mother and I would like that place to be connected by railway line.

Then, I would like to say something on another thing. I want the Railway Ministry to be also the Ministry of Education. It should teach people

cleanliness. It should teach people how to use and protect the national property. It should teach people how to be tolerant towards others—tolerance which is the supreme virtue of democracy. I think the Railway authorities have got to do this important work.

Now, we have the announcers in the stations. These announcers talk in English, which, I think, somebody in Iceland can only understand. Some of them talk also in Hindi, which somebody living in the other world only can understand. They should not only announce the arrival and departure of trains and the amount of time by which the trains are going to be late, but they should also inculcate in the minds of people as to what they should do so far as clearliness is concerned, so far as the carrying of luggage is concerned and so far as tolerance towards others is concerned and such other things.

One word more and I will finish. I visited some time back the Railway workshop in Jamalpur. Whenever I write to the Railway Ministry about anybody, their first reaction is a negative reaction; they never accept the proposition in the first instance. I found in the Jamalpur Workshop some of our best technicians working—young men, middle-aged men and persons who were going to be retired very soon. I saw what wonderful work they were doing in the technical development of the Railways. I also saw they were not doing only routine work, but they were doing inventive work also. One of them has invented a crane. I think one Mr. Suri had also done something very good.

Shri Bade (Khargone): But the Government has not adopted it.

Shri D. C. Sharma: But the Railway Ministry is absolutely impervious to their potenialities, technically and otherwise. I wrote to the Railway Minister sometime back, but I have not received any reply so far. But I know what their answer would be—the matter has been examined and nothing can be done. As everyone knows, we are in need of so much of technical know-how that we must do something to these technical people working there. They should be given proper lift; they should be given proper allowance. I think they belong to Class III service. They deserve a much better status and much better service scale than they have now.

The Railways have a surplus budget now. When you have a surplus budget, why don't you dole out money to every class of workers who are associated with you? Why don't you give money to the Officers who are in the scale of 600—1,200? What wrong they have done, what harm they have done and what displeasure they have incurred—I do not know. While I am on this, I want that subsidised grain-shops should be there at every railway station where there are 20 or more persons employed. The Railways are like the universe. They have the highest and the lowest; they have tall trees and small trees. They have technicians and engineers and they have all types of workers. I want that the Railways should be in a position to say that are doing their very best and that they are giving the right kind of deal from the railway porter to the member of the Railway Board and that nobody in between the two is left out, so far as upgrading of salary and allowances is concerned.

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैंने देखा है कि जिन को दस दस बार बोलने का मौका मिल चुका है उनको फिर मिल जाता है और जो बेचारे कभी नहीं बोलते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है। उनको भी मौका मिलना चाहिये। उनको अवसर न देना उनके साथ अन्याय करना है। महिलाओं का खास आपको ध्यान रखना चाहिये।

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

में रेल मंत्रीजी से प्राथना करती हूं कि मध्य प्रदेश की ओर भी वह देखें। उसकी जरूरतों को भी देखें। वैसे तो रक्षा के लिए जहां रेलों की जरूरत है उसको प्राथमिकता देनी होगी लेकिन उसके बाद पिछड़े हुए इलाकों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। में मानती हूं कि काश्मीर में तथा दूसरी जो इस तरह की जगहें हैं उनमें रेलों की उन्नति होनी चाहिये। लेकिन उसके बाद जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। हमारे मध्य प्रदेश में जैसे सागर है, दमोह है, जबलपुर या मध्यभारत का इलाका है इनमें रेलों की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। वहां भी इसमें सुधार होना चाहिये।

तीसरी क्लास के जो डिब्बे हैं उनमें हिन्दुस्तान की आम जनता सफर करती है। उन डिब्बों में न तो पानी का इंतजाम होता है और न ही रोशनी का अच्छा प्रबन्ध होता है। कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। सब चीजें टूटी फूटी पड़ी रहती हैं कोई पूछता ही नहीं है। उसका सुधार होना चाहिये।

मध्य प्रदेश में लकड़ी, कोयला, भूसा आदि का अधिक व्यापार होता है। वक्त पर इस माल का लोडिंग हो सके इसके लिए यह जरूरी है कि उनको रेल के डिब्बे, वैगेंज समय पर मिलते रहें। लाखों रुपये का माल पड़ा रहता है लेकिन वैगंज ही नहीं मिलते हैं। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है और उनके लिये समय पर वैगंज का प्रबन्ध करना जरूरी है ताकि ये जो चीजें हैं कोयला, लकड़ी, भूसा आदि है इनको भेजा जा सके।

मैंने कई बार सुझाव दिया है कि सागर, दमोह आदि में न तो कोई ब्रिज बना है, न कोई अच्छा रेलवे स्टेशन बना है और न ही फाठक बने हैं। फाठकों के अभाव में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार मैंने रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचा है लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। शायद इसलिये वे हमारी बात नहीं सुनते हैं कि में हिन्दी में बोलती हूं और मेरी बात का कोई वज़न नहीं है। अंग्रेज़ी में मैं बोलती तो शायद ध्यान दिया जाता। सब के साथ आपको एक सा व्यवहार करना चाहिये। जिस जिले में कुछ नहीं हुआ है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिये। आप तो बड़े बड़े शहरों को ही बनाये जा रहे हैं, उनकी तरफ ही ध्यान देते जा रहे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में ही अच्छी अच्छी रेलवे लाइनों की व्यवस्था करते हैं। जो बैकवर्ड एरियाज़ होती हैं उन में कुछ नहीं किया गया। कई दफे वहां के मेम्बर यहां पर इन बातों को यहां कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि सागर में मकरोनिया पर रेल का फाटक बनाना चाहिए। वहां पर यूनिवर्सिटी है और काफी लोग आते जाते हैं जिससे रोज ऐक्सिडेंट्स होते हैं। इसी तरह से दमोह में पथरिया फाटक बनना चाहिये। यहां पर ब्रिज बनाये जायें। रात दिन यहां की जनसंख्या बढ़ती जाती है इसलिये बिना ब्रिज बनाये हुये उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। स्टेशनों पर यात्रियों के लिये शेड बनाये जाने चाहियें, वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। उजाले का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। स्टेशनों पर बाग बगीचे लगाये जाने चाहियें। इसके लिये बार बार कहा जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जो रेलें चलती हैं वे समय पर नहीं चलती हैं। दो, दो चार, चार घंटे लेट पहुंचती हैं जिससे लोगों को वहां बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ता है। फिर रेलें सिगनल के पास आ कर खड़ी करदी जाती हैं। जैसे ही स्टेशन का सिगनल पास आता है लोग चेन खींच लेते हैं और घंटों वहां रेलें खड़ी रहती हैं। वहां पर जितने यात्री बिना टिकट होते हैं वे उतर जाते हैं। इसमें न कुछ पुलिस कर सकती है और न टिकट कलेक्टर कर सकता है। यह हालत कटनी में भी है, बीना में भी है, सागर में भी है और दमोह में भी है। लोग चेन खींच

कर उतर जाते हैं लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। वह लोग न जाने कितने यात्रियों के बैग ले कर भाग जाते हैं, कितनों का दूसरा सामान ले कर भाग जाते हैं। कितनी ही जगहों पर जेबें कट जाती हैं। वहां पर न पुलिस होती है न कोई ग्रौर। इसके लिये रेलवे की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। इस तरह से काम करने वाले रेलवे वालों से मिले रहते हैं इस लिये किसी बात का ठीक पता नहीं लग पाता। इसलिये रेलवे मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि उनको इसके लिये कड़े कदम उठाने चाहियें। जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहां पर उनको नई रेलवे लाइनें बनानी चाहियें ग्रौर सड़कों का निर्माण भी करना चाहिये। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का एरिया बहुत बैकवर्ड माना जाता है। इसलिये उनको सागर से हीरापुर तक ग्रौर सागर से छतरपुर, बरमान ग्रौर नरसिंहपुर तक नई रेलवे लाइनें निकालनी चाहियें जिसमें कि वहां पर डकैती ग्रादि बन्द हो जायें। चूंकि वहां पर कोई ग्रच्छा प्रबन्ध नहीं है किसी बात का इसलिये वहां पर डकैती ग्रादि बहुत करते हैं। वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिये वहां पर रेलवे लाइन निकालने की बहुत जरूरत है। वहां पर ग्राज काफी भुखमरी है। रेलवे लाइन निकालने से वहां के लोगों को खाने के लिये भी मिलेगा ग्रौर रेलवे का काम भी ग्रच्छा चलेगा।

कहीं कहीं पर स्टेशनों पर दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं कितने मरीज मर जाते हैं। इसके लिये भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। खाना भी ग्रच्छा नहीं मिलता है। ग्रगर कोई खाना चाहता है तो उसको बासी ग्रौर सड़ा हुग्रा खाना मिलता है। ग्रगर उनसे कहा जाये तो कानून बघारते हैं ग्रौर किसी की कुछ सुनते नहीं हैं। वहां पर मदरासी लोगों के ग्रलावा कोई होता भी नहीं है। वहां पर हिन्दुस्तानी ग्रादमी भी होना चाहिए। क्योंकि ग्रगर मदरासियों से कोई बात की जाये तो वह समझते नहीं हैं ग्रौर यही कारण है कि ग्रच्छा खाना नहीं मिलता।

जहां तक रेलवे में नौकरियों का सवाल है, वहां पर ग्राज भी नौकरशाही चल रही है। जब तक वहां पर ग्रधिकारियों को 100 या 200 रु० न दिये जायें किसी को नौकरी में भरती नहीं किया जाता। वह कहते हैं कि तुम हिन्दी वाले हो, धोती कुर्ता वाले हो। तुम सूट-बूट पहनने वाले नहीं हो। इस तरह की बातें कह कर उनको नौकरियां नहीं दी जाती। इसलिये रेलवे मंत्रालय को यह देखना जरूरी है कि किसी को नौकरी पाने के लिये 100 या 200 रु० न देने पड़ें। हमारे मंत्री लोग बड़े चतुर हैं। वे इसके लिये कड़े कदम उठायें जिससे कि हमारी रेलवे व्यवस्था ग्रच्छी हो।

इसके बाद मैं यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि कलकत्ते से दिल्ली तक रेलवे लाइन बिल्कुल जमीन के ग्रन्दर ग्राये। ग्रौर यहां से काश्मीर तक भी एक रेल ग्रन्डरग्राउन्ड चले जिसमें किसी को मालूम न पड़े कि कौन कहां ग्राता जाता है। ग्रापकी काफी ग्रामदनी है, ग्राप के फालतू पैसा पड़ा हुग्रा है। उससे ग्राप ऐसी लाइन निकालिये जिसमें कि जमीन के ग्रन्दर रेल चल सके।

मेरी ग्राप से यह भी प्रार्थना है कि महिलाग्रों के लिये एक ग्रलग गाड़ी मद्रास से दिल्ली तक के लिये चलाई जाये।

एक माननीय सदस्य: क्या उस पर काम करने वाली भी सब महिलायें होंगी।

श्रीमती सहोदराबाई राय: क्या हुग्रा। महिलायें बड़े बड़े काम कर सकती हैं। वे ग्राजकल बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, हवाई जहाज चलाती हैं। उनको बराबर का हक है। इसलिये वह यह काम भी कर सकती हैं।

इसके ग्रलावा हर ट्रेन में महिलाग्रों के लिये बड़ी कम जगह होती है। हर एक रेल के ग्रन्दर महिलाग्रों के लिये थर्ड क्लास के दो डिब्बे ग्रौर ज्यादा जोड़ने चाहियें।

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

रेलवे में जो मवेशी आदि चलते हैं उनके लिये भी खाने पीने की, पानी आदि की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये । उन में बेचारे मवेशी प्यासे मर जाते हैं ।

बड़े बड़े जंक्शनों पर रेलवे कर्मचारियों के अन्दर शराबखोरी और जुआ बहुत चलता है । इसके लिये आप को कड़े कदम उठाने चाहियें । रेलवे डिपार्टमेंट में जुआ और शराबखोरी से जनता को बड़ी परेशानी होती है । कर्मचारियों के घर वाले भी रोते हैं कि कर्मचारी को जो 100 रु० मिलते हैं वह उसको जुआ और शराब में उड़ा देता है तो घर का काम कैसे चले । साथ ही एक कर्मचारी को एक जगह पर पांच पांच, छः छः साल नहीं रहने देना चाहिये क्योंकि वह लोग वहां के लोगों से घुल मिल जाते हैं और फिर उनको कोई डर नहीं रहता है कि वह पकड़ लिये जायेंगे । मेरा सुझाव है कि एक कर्मचारी को जगह पर तीन साल से अधिक नहीं रहने देना चाहिये । उन का उसके बाद किसी दूसरी जगह को ट्रांस्फर कर देना चाहिये । अधिक समय एक जगह पर रहने से वे स्थानीय आदमी से बन जाते हैं और काम ठीक से नहीं करते, उल्टे छोटे कर्मचारियों को डांटते हैं । इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि हरिजन और आदिवासी लोग रेलवे में ज्यादा भरती होने चाहियें । वे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि उनको नौकरी पाने के लिये 100 या 200 रु० अधिकारियों को न देने पड़ें ।

मैं ब्रिज बनाने के बारे में पहले भी कह चुकी हूं । सागर दमोह की तरफ आप देखें तो वहां किसी तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है । न ब्रिज हैं, न शेड हैं और न कोई दूसरा प्रबन्ध है । इसलिये सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर आदि स्थानों पर ब्रिज बनना चाहिये, उन लाइनों पर स्टेशन बनाये जायें । हर पांच पांच मील पर एक स्टेशन होना चाहिये । हर एक जगह पर दवादारू की व्यवस्था हो । साथ ही मध्य प्रदेश में सागर से छतरपुर, हीरापुर के लिये लाइन निकालना बहुत जरूरी है । वह हीरा की खान की जगह है । अगर आप वहां लाइन निकालेंगे तो लाखों रुपयों का हीरा वहां से निकल सकता है । साथ ही रेलवे व्यवस्था अच्छी होगी, कोयले की प्राप्ति होगी, व्यापार ज्यादा अच्छा चलेगा । अन्न जो वहां पर इतना अच्छा होता है, गेहूं आदि, वह हर एक राज्य में जा सकता है । वहां के लोगों को पलटनों में भरती किया जा सकता है । इससे जो बैकवर्ड एरिया है उसकी भी उन्नति होगी ।

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir I appreciated very much the compliments paid by the Railway Minister to the Railway Board and the Railway Administration. I shall only remind him of the assurances given by the Ministers themselves which still remain to be respected by the Administration. I have referred to them a number of times in this House. But they bear a reference once again.

I represent an area which plays a leading role in the political life, in the cultural life and the history of the province of Bengal. Unfortunately, this area was a victim of partition and all the means of communication that the area had were lost to Pakistan. The journey from there to Calcutta is, I should say, a beastly journey and inhuman journey, a journey which should not be forced on people. When the people found themselves in this distressing condition they appealed to the Government repeatedly. As a result of their repeated appeals Railway Minister after Railway Minister visited that area. Shri Lal Bahadur Shastri, who is now the Prime Minister, visited that area as Railway Minister and assured the

people that the district will be connected to the main railway line. This was said at Balurghat, headquarters of the district. Shri Jagjivan Ram, when he was the Railway Minister, went there, met the people at Balurghat which is the headquarters of the district and assured them that a railway connection would be given to them.

Shri D. C. Sharma: Whoever has gone there has been asked to go.

Shri C. K. Bhattacharyya: One has been raised to the Prime Ministership. Mr. Sharma is so forgetful because of his age.

So, the people are appealing to Government to come to their rescue. In fact, I say, for me, to come to Delhi from Calcutta is much easier than to go to my constituency from Calcutta. It takes 24 hours to come to Delhi and it takes 26 to 28 hours to go to Balurghat or Raiganj from Calcutta. It is not that the Railway Minister or the Railway Administration does not know about that. But, after repeated appeals made by the people and demands made in this House by my humble self that there was a proposal that a broadgauge line would be planned from Khejuriaghat going upto Siliguri. When that line was planned, the people expected that their distress would now be removed.

Here, in this House while introducing the Railway budget the then Railway Minister, Shri Jagjivan Ram also made a statement in his budget speech that the line was being constructed to open up the District of West Dinajpur. It was unusual for the Railway Minister to specifically mention the name of particular district. But, Shri Jagjivan Ram did mention that when the line was to be constructed it would open up the district of West Dinajpur. What happened afterwards? The assurance made to the ears was belied to the heart. Though the line was constructed strangely enough it by-passed the district of West Dinajpur. I pay my compliments to the Railway Board that they have been successful in violating the statement made in this House by the Railway Minister in his budget speech. The line was constructed but it by-passed the district. The distress of the people remained and still remains today. They are appealing to the Government of West Bengal; they are also appealing to the Railway Administration and here in this House I have repeated their appeal many a time.

This District has two main centres—one is known as 'Balurghat' the present headquarters and the other is known as 'Raiganj' which is prospective headquarters of the district. The district was partitioned and as a result lakhs and lakhs of refugees came over here from the other side of the district and settled there. It lost all its communications. The problem has two aspects. That for the town of Balurghat is that it has to be connected by a new line to the broadgauge line that has been constructed from Khejuriaghat to Siliguri, the problem is for the town of Raiganj is that it has to be connected to the same broadgauge line by converting the metregauge line that runs from Barsoi to Radhikapur through Raiganj—a distance of 33 miles into broadgauge.

For the construction of a line from Balurghat to the broad-gauge line, surveys were made. It was not like other North East Frontier Railway lines to the Railway Minister referred when he said that these lines were not a paying proposition. Through repeated surveys it was proved that this line at least would be paying. They had that assurance. I would request the hon. Minister for Railways to go through the files and to probe into this matter. Let him find out as to what the problems of the people are and how the distress of the people can be removed. Though this line would be paying, it was not opened. The distance involved would be 60 miles. It could have been taken up. I have been repeatedly urging this from 1957. This could have been taken up in three

[Shri C. K. Bhattacharyya]

stages or even in six stages and in that way it could have been done by now and thereby the sufferings of the people could have been removed. But it was not.

At last, the Railway Board replied to me that though I have been repeatedly appealing to them but the Government of West Bengal had not include that in their Third Five Year Plan. I approached the Government of West Bengal. They reported to the Railway Board stating that they had included it in the Second Five Year Plan. I do not know how the Railway Board by-passed this. I also do not know what the reaction would be now after they have got a reply from West Bengal Government.

Dr. M. S. Aney: May I ask one question? After that proposal was by-passed, Shri Jagjivan Ram continued in that ministry.

An hon. Member: It was completed long years after.

Mr. Deputy-Speaker: Anyway, the hon. Minister will reply.

Shri C. K. Bhattacharyya: Anyway, although the Minister had given that assurance to the people there and made a statement in this House thereafter giving his assurance in his budget speech, how is it that that has not been put into action?

An hon. Member: Because the Ministers are not stable.

Shri C. K. Bhattacharyya: At least the Railway Administration is stable. Of course Ministers have been changing but the Railway Administration has not changed lock stock and barrel.

So, Sir, that was not done. Now what is the position regarding Raiganj? I was urging that the small metre-gauge line be converted into a broad-gauge line so that it might be connected with the broad-gauge line.

Here again the assurance given by the Minister has been frustrated by the Railway Administration, when the broad-gauge line was opened at Khejuriaghat I was there. The present Chairman, Railway Board (Shri B. C. Baijal) (he was then the General Manager) was there and Shri B. C. Ganguly, who as General Manager of the Southern Railway has earned so much reputation by quick reconstruction of the Pamban Bridge was there then as Chief Engineer Shri Jagjivan Ram in the presence of them all said that this small line would have to be converted into a broad-gauge line.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri C. K. Bhattacharyya: That assurance given by the Minister openly to the people in the presence of the Railway dignitaries remains unfullfilled even now.

When I tell the Railway Board that this should be done, they say that Raiganj has got a metre-gauge line. The Railway Administration forgets that this line is connected with Calcutta and for quick and direct transit to Calcutta Raiganj needs to be connected to the broad-gauge line. I have tried to impress upon the Railway Board that the interest of the district lies in its having a direct connection with Calcutta through broad-gauge line and not with Patna or Lucknow through the metre gauge line. This Khejuriaghat line was constructed in a way that it runs over the metre-gauge line completely duplicating the railway-line in one area which is already connected by a metre-gauge line. There over the metre-gauge line this broad-gauge line goes.

Both the people there get metre-gauge line and the broad-gauge line while people in the other areas are deprived of railways and are suffering. Nobody comes to their rescue.

When this broad-gauge line was proposed it was declared to be for opening the West Dinajpur District. Now it is of advantage to all parts of North Bengal, Cooch-Behar, Jalpaiguri, Darjeeling and even the farthest areas of Assam but not for the District for which it was mentioned. All the other people will take advantage of it while it was being denied to other people.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Abdul Ghani Goni.

Shri Abdul Ghani Goni (Jammu and Kashmir): I thank you for having given me this opportunity to speak. I fully agree with what Shri D. C. Sharma said just now. We have got a stable Minister in the Railway Ministry, Dr. Ram Subhag Singh. But, I find that Kashmir is not in the Railway Map of India. I am somewhat shocked to see that. This demand has been made repeatedly for the last fifteen years by the Members from Kashmir. It has been repeated this time also.

I thank them all for supporting the demand for the extension of the railway line to Jammu and Kashmir also. Formerly, we had in fact a railway line up to Jammu from Sialkot. Unfortunately, that line was discontinued. Then there was another route very close to Srinagar from Rawalpindi. That was also discontinued. Now there is only one link which connects Kashmir with the rest of the country through Pathankot. That road from Pathankot to Jammu is always subject to disturbance from the Pakistan side. Daily we hear about incidents of violation of the cease-fire line by Pakistan because they are out to disturb our lifeline.

My demand for the extension of the railway line to Jammu and Kashmir is not merely for our comfort. I am demanding it on three grounds. The first ground, of course, is defence. Jammu and Kashmir is a strategic State. We have got Pakistan on one side and China on the other and our troops have to defend that part of the country from our two enemies. I am very sorry to say that not only the Railway Ministry but even the Central Government as a whole were not very clear about their policy towards Kashmir. They moved very slowly. Two years back I asked a question about the railway connection at least up to Jammu and I was told at that time that the railway line from Pathankot to Jammu will be completed by April 1964. We were very happy to hear that reply. Now it is nearing April 1965 and our demand is yet to be fulfilled. So, I would request Dr. Ram Subhag Singh, not because he is the Minister of State for Railways but because he always takes personal interest in Kashmir, to pay a visit to Kashmir and inspect the railway line which is under construction from Pathankot to Katua. Though the construction has been going on for the last four years and though we see labourers working there every day, only four or five *nullas* and one river have been bridged. The progress of the work is very slow and I feel there is something wrong somewhere. I would request the hon. Minister to make an announcement whether he is prepared to extend the line up to Kashmir or not, from the point of view of defence.

Then I want this railway line for another reason. As Shri D. C. Sharma was saying, the railways play an important role in national integration. When I find that Jammu and Kashmir is not in the railway map of India, I feel isolated. The building of the line up to Kashmir is one of the ways of giving practical shape to the integration of Kashmir, economically and otherwise, with the rest of India.

Thirdly, the absence of the railway line to Kashmir deprives Kashmir of many economic benefits and puts it to much hardship. As I said in the very beginning, it is not only for our comforts that I am asking for this railway line. We have got rich deposits of coal and other minerals which remain

[Shri Abdul Ghani Goni]

unutilized for want of transport facilities. Then we have got large quantities of timber which we are supplying to the railways themselves as sleepers. If there is a railway line, they will be able to get their sleepers at a cheaper price. Then, if there is a line up to at least Riasi from Jammu it will cover the coal-bearing areas and coal can be had at an economic price, instead of bringing it from far-off Bengal, Bihar coalfields. According to reports, we have got fine quality coal for a 65 mile belt and it can be exploited. Now, mainly due to transport difficulties, we are not able to exploit it, because its transport by road will be costly and uneconomic.

Then, the biggest trade of Kashmir is tourism and it is affected adversely because of the absence of a railway line. Though tourists are attracted to Kashmir, for most of the time there is road blockade, or other modes of transport like cars and buses are not available. If there is a railway line, the tourist industry in Kashmir will flourish. It was doing very well before 1947, under the regime of the Maharaja. It can be developed even now by having that rail link. When tourists come from abroad, they naturally want to visit Kashmir. But when they find that it is not connected by rail they drop it out of their programme.

I understand the Railway Ministry have conducted a survey for a railway line from Pathankot to Udhampur from the point of view of defence. The immediate programme is to have a line from Pathankot to Katua, where there is a small station. I would request that the Katua station should be treated as an important terminal station and at least the three important trains, namely, the Kashmir Mail, the Srinagar Express and the Sealdah Express should start from Katua instead of from Pathankot. Also, at Katua arrangements should be made for the tourist traffic like good hotels and restaurants. In that case, Kashmir will get a little benefit out of the tourist traffic. Though we are now thinking of having it only up to Katua a distance of 18 or 20 miles, finally it has to connect Riasi for coal and Udhampur for defence purposes.

Then I would suggest a ring railway in Srinagar from Anantnag to Uri. Though there was a proposal for it in the beginning, we did not hear much about it later. So, I would request the Ministry to look into the question of having a ring railway in Srinagar so that it will be beneficial, economically and in other respect, to the people who are residing in the valley and to those people who visit the valley.

With these words, I support the Demands for Grants. I thank you for giving me this opportunity to take part in this debate.

Shri Basumatari (Goalpara): Day before yesterday when I was listening to the eloquent speech of hon. Minister of Railways, I felt it was giving us encouragement and impetus. Just now when I heard hon. Member telling the House of his frustration, I also felt frustrated. If an hon. Member like him, who comes from a powerful State feels so much frustrated, you can imagine how much a person like me, who comes from poor and backward State like Assam, will feel frustrated. After 1947 Assam also suffered in the same way, as Bengal has suffered. There is only one railway line with Pakistan on one side and Bhutan on the other through a corridor of 40 miles. We all know how difficult and troublesome it was during the emergency to evacuate people from Assam because there is only one unstable railway line. By unstable I mean that the railway line from Jalpaiguri in Bengal has to pass through areas which are not safe. At the same time, the railway line has to cross many big and powerful rivers, not the kind of rivers which we see in other States.

14 hrs.

Of course, after the emergency the track has been strengthened by extending the bridges over the rivers. That is a very good sign and I am glad about it. Also, I am very much grateful that they have sanctioned a broad-gauge line from New Jalpaiguri to Jogighopa. That has been done only due to the emergency. The people of this area become very much frustrated with the thought that it is for the benefit of the people from the other parts of the country. So, my hon. friends from Assam vehemently and strongly suggested that this broad-gauge railway line should be extended up to Gauhati from Bongaigaon. This suggestion should be attended to; at the same time, we expect that this should be included in the Fourth Plan.

When we see so much enthusiasm on the part of the Central Government about Assam, we feel very glad, but since the days of emergency are passing away many leaders are asking why Assam should get priority and why Assam should get so much facilities because Assam has got only one crore of population. Of course, in a democratic country, population is a great factor to be counted, but Assam's case must be taken as a national cause. Why do I say that the problem of Assam should be taken as a national cause? It is because it has already shown to the country a glaring instance at the time of the Chinese attack. The problem of Assam should not be taken as a State problem, but it should be taken as a national problem.

When we talk about the lines, this and that, we think on the basis of States. If you think about a strategic State like Assam on the basis of States, I do not know how you can protect India. We are just like Kashmir. Just now hon. friend from Kashmir said how Kashmir is in difficulty and is surrounded on all sides by foreign countries. So is the case of Assam. I want to say that Kashmir and Assam are in the same position. Therefore this problem of Assam should be taken very, very seriously as a national cause.

Sir, you know the history of the track from Jalpaiguri to Assam. It was not for public utilisation; it was for the tea gardens only which were owned by the British. It was not at all developed. Even if you compare it with other States in matter of standards you will find it quite below the standard in all respects. If you go to the station, you will find that compared to other stations it is very dilapidated. All the chairs in the waiting rooms are broken and the walls are full of dust and dirt. Hon. Minister, Dr. Ram Subhag Singh, knows about Assam very well that a sizable population of Bihar goes to Assam every year and stay there for six months. So, I have been requesting him to have a special train for Assam to carry the mazdoors from Bihar. All the works there are done by the mazdoors from Bihar and they go in lakhs from Bihar to Assam in the month of October and come back only in March and April. Therefore, I have been requesting hon. Railway Minister that there must be some special trains for the mazdoors. In view of the large number of mazdoors our people, that is, the people of Assam, cannot avail of the trains.

If you go through the time table, you will find the amazing thing that almost all the trains run at night and that cannot be availed of by the people of Assam. Therefore, naturally only people from outside can avail of it. We do not mind that; but there should be some facility for the people of the State also.

Another most important thing is employment. The employment problem is a very grave problem. It is because of this that the language question is there. The language question is so acute only because of employment. Employment is an economic question. If you compare the employment given by the Railway Department not only to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but other communities also

[Shri Basumatari]

from Assam you will find that Assam has got very meagre opportunities. You will be surprised to know that not a single officer from Assam has up till now been appointed by the Railway Ministry.

The hon. Railway Minister paid compliments and said that our railway officers are very efficient. I have no dispute about that; but just now Shri Bhattacharyya pointed out that promises after promises made by Ministers are not implemented. I do not know in what way the Minister can then pay a compliment to them. This is the largest public sector undertaking and it should set an example in all respects, in efficiency of administration and everything, to other public sector undertakings. If you compare the corruption in other departments with corruption in Railways, you do not see any less corruption in the Railways. I have cited examples of that so many times at the time of discussion of the Railway Budget and Railway Demands. How can you pay a compliment then?

My hon. friend from Assam cited an example that the trains in Assam move at the speed of 20 miles an hour. He was calculating the speed of only one line; but there is one line from Rangiya to Tezpur where the train goes only at the speed of 12 miles an hour. The distance from Rangiya to Tezpur is only 90 miles and it takes 12 hours to reach there. The trains move so slowly as if they were bullock carts. Therefore their speed should also be increased.

Another point that I want to make is about the appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if I do not mention that, I shall be failing in my duty. I hope, nobody will mind my citing the instance of the days when Shri Jagjivan Ram was the Railway Minister. In those days there had been plenty of employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now, the day before yesterday hon. Railway Minister pointed out that he will look into this question very sympathetically. But then he was also referring to the statement made by Shri Jaipal Singh. That was wrong and I said so. Shri Jaipal Singh did not say that there should not be any reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of appointment. What he said was that there should not be any reservation for promotion which was challenged by the High Courts and the Supreme Court. He was referring to that only. I say this after seeing the proceedings. He did not say that there should not be any reservation for the appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I request the hon. Minister, specially the Minister of State, Dr. Ram Subhag Singh, who is very sincere and who wants to do what he says, to see to it. I hope, he will do it. The other day he said to me, "You need not speak here; you write to me or tell me and I will do everything for Assam". I hope, he will repeat the promise in the House which he has given to me when I talked to him privately.

श्री बलजीत सिंह (उना) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय ने बजट में जो स्कीमें दी हैं और मंत्री महोदय ने जो एशोरेंसिज दी हैं, उनके लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हूं ।

रेलवेज का विस्तार बहुत बड़ा है, । कई बातें एसी हैं, जिन का जिक्र बजट या मिनिस्टर महोदय की स्पीच में नहीं किया गया है । राज्य सरकारों की तरफ से दो तीन लाख रुपये लगा कर बस स्टेंड बनाए जाते हैं । चूंकि रेलवे अधिकारी और राज्य सरकारें एक दूसरे को कन्टैक्ट नहीं करती हैं, इसलिए वे बस स्टेंड स्टेशनों से बहुत दूर दूर बन जाते हैं, जिस के कारण रेल और बस का आपस में ताल मेल नहीं रहता है । इसका नतीजा यह होता है कि मुसाफिरों को तकलीफ होती

है । इसके अलावा जो ब्रांच लाइनें हैं, उनको भी नुक्सान उठाना पड़ता है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । पंजाब में होशियारपुर में एक बस स्टैंड बना हुआ है । वह स्टेशन से बहुत दूर है । जो लोग रेल में आ कर चढ़ते हैं उन्होंने कई बार मांग की है कि एक स्पेशल बोगी होशियारपुर से दिल्ली के लिए लगा दी जाए लेकिन इसके जवाब में कहा जाता है कि पैसैंजर्ज इतने नहीं जाते हैं कि स्पेशल बोगी लगाई जाए और फ़िगर्ज़ निकाल कर दिखा दिये जाते हैं । बस स्टैंड वहां से कोई मील के फ़ासले पर है । इसका नतीजा यह होता है कि मुसाफिर लोग जालंधर तक बस में सफर करते हैं और जालंधर आकर दिल्ली की गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं । अगर वहां से बोगी लगा दी जाए तो ऐसा होगा कि लोग उस में सफर करके सीधे दिल्ली आ सकेंगे ।

इस साल के रेल बजट में आपने किरायों में वृद्धि की है । इससे ब्रांच लाइनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा । वहां पर बसों से रेल का मुकाबला है । बसों से लोग ज्यादा सफर करना शुरू कर देंगे । इसके साथ साथ जो सुविधायें ब्रांच लाइनों पर आपको पैसैंजर्ज को देनी हैं वे आप नहीं दे पायेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि फिगर्ज लाओ कि कितने लोग सफर करते हैं, सफर करने वालों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है । मुसाफिरों को अगर बस में जाने से फायदा होगा तो वे उसमें चले जायेंगे और आपको घाटा होगा । मैं इस लिए आप से विनय करूंगा कि अव्वल तो जो बढ़ोत्तरी किरायों में आपने की है वह आप न करें । और अगर करनी है तो कम से कम एक सौ किलोमीटर को आप छोड़ दें, सौ किलोमीटर तक कोई बढ़ोत्तरी न करें । अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो ब्रांच लाइनें हैं वे नुकसान से बच जाएंगी, वर्ना वे सफर करेंगी ।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि जब रेलवे बजट बनाया जाता है तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनका कोई खयाल नहीं रखा जाता है । मिसाल के तौर पर मैं पंजाब का जिक्र करता हूं । रेलवेरिपोर्ट 63—64 में यह बताया गया है कि पिछले साल में आपने पैसैंजर एमेनेटीज के लिए कितना खर्च किया है । आपने कहा है :

> "An amount of Rs. 61.64 lakhs was spent during the year 1963-64 on the provision of goods shed facilities like improvements of the circulating area and approach roads, extension of goods platforms and sheds, construction of waiting rooms for customers, provision of drinking water near the goods sheds, etc."

इस में आपने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा एमेनेटीज़ दी जा रही हैं । लेकिन मैं विनय करता हूं कि पंजाब में जो पिछड़े हुए इलाके हैं, अम्बाला से कालका तक और रोपड़ से नंगल तक की बात मैं कहता हूं वहां कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं । जालंधर से होशियारपुर और मुकेरियां साइड में और जोगेन्द्रनगर से पठानकोट तक कोई सुविधा नहीं दी गई हैं । उन लाइनों पर न तो शैड प्रोवाइड किये गये हैं, न ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज दी गई हैं और न ही कोई और सुविधायें दी गई हैं । अगर पिछड़े हुए इलाकों को डिवेलेप करना है, मुल्क के दूसरे इलाकों के बराबर उनको मिलाना है तो यह लाजिमी है कि आप सुविधायें देते समय इन पिछड़े हुए इलाकों का ज्यादा ध्यान रखें ।

आपने अपनी स्पीच में कहा है कि कई नई लाइनें बनेंगी, कई जगहों पर सर्वे का काम हो रहा है । लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक पिछड़े हुए इलाकों का सम्बन्ध है कोई सर्वे वहां नहीं कराया जा रहा है । और न ह कोई नई लाइनों की व्यवस्था

[श्री दलजीत सिंह]

रखी जा रही है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पिछली बार यहां इस सदन में एक रेजोल्यूशन आया था और सरकार ने हमें विश्वास दिलाया था कि आप पिछड़े हुए इलाकों की भलाई के लिए, उनका डेवेलेपमेंट करने के लिए सभी प्रकार की सुविधायें देने पर विचार करेंगे । नई लाइनें बनाने की बात भी इस बजट में कही गई है । मैं मंत्रालय से कहूंगा कि कम से कम इस का चौथा हिस्सा पिछड़े हुए इलाकों में नई लाईनों की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाए ताकि वे इलाके भी आगे आ सकें । और दूसरे इलाकों के मुकाबले में तरक्की कर सकें ।

मैं ने कहा है कि एक रेलवे लाइन बनी हुई है रोपड़ से नंगल तक और उधर मुकेरियां से तेलवाड़ा तक बन रही है । मैं विनय करता हूं कि अगर इस लाइन को मिला दिया जाए तो एक तो सरकार को यह सुविधा होगी कि बड़ी बड़ी मशीनरी इत्यादि आसानी से लाई लेजाई जा सकेगी और दूसरे डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से भी इसका होना बहुत जरूरी है । हमें एक सीधी लाइन दिल्ली से पठानकोट तक मिल जाएगी वाया नंगल, पोंग डैम की तरफ से होते हुए और इस से पिछड़े इलाके डिवेलप करेंगे और डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से भी यह फायदेमंद रहेगी ।

मैं ने पिछली बार मंत्रालय से कहा था कि जहां डैम खत्म हो जाए, डैम्ज पर सरकारी काम खत्म हो जाए जैसे भाखड़ा डैम है या नंगल डैम है, वहां पर अगर रेलवे वर्कशाप खोल दी जाए तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की लेबर आप को आसानी से मिल सकती है, ज्यादा मिकदार में और अच्छी लेबर मिल सकती है और जो चीज उस वर्कशाप में बनने वाली होती है, उन को बनाने में आसानी हो सकती है । यह चीजें बहुत सस्ती साबित हो सकती हैं । चौथे प्लान में इस का भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

जहां तक पैसेंजर एमेनेटीज का सम्बन्ध है मैं पहले भी विनय कर चुका हूं और अब फिर करता हूं कि ब्रांच लाइनों पर जो सुविधायें पैसेंजर्ज को मिलनी चाहियें नहीं मिलती हैं । दिल्ली से कालका मेल के साथ डिब्बे नंगल के लिये लगते हैं वह केवल दो लगते हैं । उन में इतनी भीड़ होती है कि लोग खड़े हो कर सफर करते हैं । अम्बाला जा कर जब उन को सर्दियों में गाड़ी तबदील करनी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल होती है । मैं ने मंत्रालय से कई बार विनय की है कि यहां से अगर एक सीधी गाड़ी नंगल के लिए चला दी जाए तो लोगों को बहुत सहूलियत हो सकती है, उन को रात में सुविधा हो सकती है । नंगल एक अहम डैम है । वह तमाम हिमाचल प्रदेश को मिलाता है । सौ मील तक इर्द गिर्द के लोग वहां आ कर गाड़ी पकड़ते हैं । अगर उन को सुविधा दी जाए, एक सीधी गाड़ी चला दी जाए तो पिछड़े हुए इलाकों के जितने लोग सफर करते हैं, उन को लाभ पहुंच सकता है ।

फर्स्ट और सैकिंड क्लास के डिब्बों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में नंगल डैम और भाखड़ा डैम, यह डैम बहुत बड़े टूरिस्ट सैंटर हैं । और इन को देखने के लिए वी० आई० पीज० बहुत अधिक तादाद में जाते हैं । लेकिन गाड़ी में जो इन क्लासिस के डिब्बे लगाये जाते हैं वे बिलकुल रद्दी होते हैं । उन के बारे में कोई नहीं देखता है कि किस तरह से ये डिब्बे लग जाते हैं । दिल्ली स्टेशन पर जो कंडेम्ड डिब्बे होते हैं वे लगा दिये जाते हैं । उन में न पानी की सुविधा होती है और न ही कोई दूसरा अच्छा प्रबन्ध होता है । इस तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए । वी० आई० पी० तक यह कहते हैं कि ये रद्दी डिब्बे किस तरह से लग जाते हैं ।

अब मैं रोपड़ नंगल की लाइन के बारे में विनय करता हूं। बारह चौदह साल पहले पंजाब सरकार और रेल विभाग के बीच एक मुआहिदा हुआ था जिस के बारे में कई बार दरख्वास्त की गई है कि उस को खत्म कर दिया जाए। इस मुआहिदे का क्या नतीजा हो रहा है इस को आप देखें। इस की वजह से रोपड़ से नंगल डैम तक न तो पैसेंजर एमेनेटीज प्रोवाइड होती है, न एम्प्लायीज को कोई सुविधा होती है और न उन के लिये क्वार्टर बनाये जाते हैं। जब भाखड़ा डैम बन रहा था उस वक्त यह मुआहिदा हुआ था। उस में यह था कि हाफ एंड हाफ खर्चा दोनों करेंगे अब भाखड़ा डैम भी तैयार हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट कुछ खर्च करना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में रेल वालों को तो कम से कम इस पर गौर करना चाहिये और इस लाइन को टेक ओवर कर लेना चाहिये।

रेल मंत्रालय कहता था कि यह लाइन नुकसान में है। लेकिन वह नुकसान में नहीं रह गई है। मैं ने कुछ एवरेज निकाले हैं और उन के अनुसार आप को दस लाख रुपये की आमदनी केवल नंगल डैम से होती है। ऐसी सूरत में पैसेंजर एमेनेटीज प्रोवाइड न की जायें, एम्प्लाईज को सहूलियतें न दी जायें तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय पंजाब के नुमाइंदों को बुला कर और उन से बात कर के इस को टेक ओवर कर ले ताकि जो सुविधायें आप अपने एम्प्लाईज को दे सकते हैं दें। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने कई बार मांग की है कि चंडीगढ़ पंजाब में एक बहुत अहम मुकाम है। इस लिये इसे जगाधरी और लुधियाना से मिला दिया जाये। लेकिन आज तक इस पर विचार नहीं किया गया। खास तौर पर चंडीगढ़ स्टेशन जो है वह बहुत छोटा सा स्टेशन है। वहां पर पार्सल यूनिवर्सिटी पेपर्स जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों वे भीग जाते हैं और जितना दूसरा सामान होता है वह भी खराब हो जाता है। इसलिये मैं विनय रूंगा कि एक तो इस तरफ ध्यान दिया जाये, दूसरे जो पैसेंजर अमेनेटीज दी जा सकती हैं वे दे दी जायें।

Shrimati Savitri Nigam (Banda): Sir, I stand here to support the railway grant wholeheartedly. I am grateful that at this fag end I have been given an opportunity to express my views on this problem of how to extend the facilities of railway to the entire country as well as various other problems concerning this Ministry. I know I come from a backward area. I am also neglected like my area. I do not mind saying so. For the last several days, many members have made very, very useful suggestions and have raised many vital problems. There is no doubt that the Railway Minister who is a man with great imagination, initiative and experience has dealt with those problems and suggestions in a very successful and effective manner. So, I do not want to repeat many of them.

Luckily our Railway Minister has got a good team of Deputy and State Ministers as well as very good top officials who have got a great insight into the problems and that has created a new hope in our hearts. I can say that that is why we have been rather encouraged to give some more suggestions.

Railway is a big commercial as well as social welfare organisation. It is not only a mere service, but also a social welfare organisation. The progress of the country depends on the proper functioning of this organisation—social economic and other types of progress. I would also emphasize that the success of the railways not only depends on these few top officials but also on the lakhs and lakhs of small and big workers and employees who are working for it. I would suggest that the hon. Railway Minister and his team should find out some incentive to be provided to all those workers so that they may be encouraged to do good work. Human nature being what it is, there are different types of people. Some are not so efficient; some are

[Shrimati Savitri Nigam]

lazy and do not want to put in hard work. Even in the laziest person, if he is given some incentive, a new initiative is created, because even the laziest person would like to improve himself or herself, if he or she is given an opportunity to work and a new atmosphere is created and new incentives are given. I would, therefore, suggest that efficiency and good work must be recognised. Some competitions should be held and prizes given not only to high officials, but different sections and various categories of employees in the various departments working in the railways.

There has been no competition among the catering departments. The result is that even good workers in the catering department are not getting any encouragement with the result that our catering department is a losing concern. I would not go into the merits or the various complaints against the catering department. Being a housewife I know that our people are very fussy about food. They do not go into the calorific or nutritional value of food, but they go into the taste of food. So, there are bound to be complaints. But cooked food is such a thing that even a person dealing in 100 per cent pure and good food can very easily get from 100 to 200 per cent profit. In spite of that, our catering department is a losing concern. I would suggest that more and more women should be associated at every level, especially in the advisory capacity and if possible in the supervisory capacity. I think it is beyond the capacity of men to do much here in the catering department.

Dr. M. S. Aney: I agree with you wholeheartedly.

Shrimati Savitri Nigam: Food can be very well managed by women—much better than men.

Now I will come to another suggestion. For the sake of getting something from the Railway Ministry, for this purpose everybody has become backward, because most of the members have said that their areas are backward. It has put me in a fix. The country is one. We should have some integrated approach. There is no doubt that some of the areas have been very much backward. We should not have any narrow approach. It will neither help the country, nor the railways. I very much appreciate that our needs are innumerable whereas our resources are very limited. What I would suggest is this: We should decide upon some priorities. Some indicators should be fixed by the railway department itself and according to those indicators, whichever area comes first in backwardness should be given top priority. Unless it is done we would not know which area is really backward and if some member is vocal he would exercise too much influence on the Railway Ministry whereas the really backward area will remain backward and the forward area will get more and more facilities.

Regarding this, I would like to say another thing. There is an efficiency department in the railways. It is doing wonderful work. Why not the efficiency department make an exhaustive survey to find out which are the most backward areas and which need more facilities. On then we would be able to develop the entire country, not a particular area because it is very well known that the strength of the chain lies in its weakest link.

Now I would like to say a few words about Bundelkhand which is my area—not because it my area....

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): After all this?

Shrimati Savitri Nigam: I am sure the hon. member will have some patience. I am not going to ask for any new thing. I am saying that this area has been neglected. The condition of this area is very pathetic because of two reasons. First of all, I should say that during the freedom movement in 1857, a majority of the people who

were executed or who were given life imprisonment came from this area. That is why the Britishers wanted to keep this area backward. There was no facility not only with regard to railway line, but even with regard to schools. You will be surprised to know that for an area of 1,500 sq. miles there is only one college and that was opened this year. In 1929 this area was given a railway line. The materials were brought to the site. But somebody wrote a letter to a Member of the House of Commons. Immediately everything was withdrawn. After spending lakhs of rupees, everything was withdrawn. Since that time that area has never been given a railway line. All those who worked for the nation have been given some facility, recognition or help by the Congress Government, but this unfortunate area which has done so much for the freedom of the country has not been given even a single railway line. I would appeal to Dr. Ram Subhag Singh who is a man of the masses and who is a Congress leader also, and also the Deputy Railway Minister Shri Sham Nath who is also a Congress leader, that they should find ways and means at least to restore that railway line to this area which is a political sufferer, which had already been there.

I shall now come to certain other points which are equally important and which need to be given thought and priority. The policy regarding the allotment of wagons needs a thorough overhaul. I would like to say that there are several categories in the matter of allotment of wagons, A, B and C categories. Food transportation on behalf of the Central Government is given 'A' priority. But from where do they bring the food? From the States. You will be surprised to know that at the State level they are given only 'B' priority. The result is that while the 'A' category wagons are waiting on the spot, the 'B' category wagons do not get a chance, and both become idle. That is why you find that on the one hand people are craving and dying to get proper allotment of wagons, on the other hand there is a lot of idle capacity of wagons lying unutilised. I hope this position will be rectified.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shrimati Savitri Nigam: Sir, I know you are very generous and I hope you will not mind giving me two minutes.

So much has been said about overcrowding and suggestions have been made that more janata expresses should be started. It is a good suggestion, and I hope that all those suggestions will be considered. But I wish to make an entirely new and different suggestion in this matter. Half the overcrowding can be controlled if certain new methods are adopted by the Railway Ministry and the railway officers to bring about some improvement in the habit of people travelling with heavy luggage, if some arrangement could be made by the railway authorities to put such luggage in different compartments or make such arrangement by which the luggage is booked and sent by a compartment other than the compartment where the people sit, the overcrowding could be reduced to a very great extent.

I would also like to suggest that new methods should be adopted to protect the Railway property. All the old methods have not proved successful, and lakhs and lakhs of rupees worth of property of the Railways are either stolen away or they deteriorate. New techniques should be adopted in this respect, and there should be new stores. And the disposal of the waste property should be made very prompt and quick.

Sir, I thank you for giving me the time.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बैकवर्ड एरियाज की और बैक बेंचेज की बारी मालूम होती है ।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मैं भी ऐसे एरिया से सम्बन्ध रखती हूं जहां सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है, न रेलवे लाइन है, न सड़कें हैं और न और कुछ है। वहां जा कर तो ऐसा मालूम होता है कि वहां पर कोई सरकार ही नहीं है। वह एरिया है गोंडा और बलरामपुर का।

मैं मंत्री जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि इस खतो-किताबत के बाद कुछ किया गया। लखनऊ से पास होते हुए भी रास्ता इतना लम्बा हो जाता था कि उसमें बहुत समय लगता था क्योंकि कई गाड़ियां बदलनी पड़ती थीं। तो बहुत प्रार्थना करने पर मंत्री जी ने लखनऊ से बलरामपुर तक एक सीधी गाड़ी चलायी ताकि गाड़ी बदलनी न पड़े। जब यह गाड़ी चलने वाली थी, तो विरोधी पार्टी ने, जो कि हर बात की बहुत खबर रखती है कि क्या होने वाला है, यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम ने यह काम करवाया है। उस [illegible] पार्टी ने एक पोस्टर बंटवाया कि उनके अनथक परिश्रम करके यह गाड़ी चलवायी है। खैर तो वह गाड़ी चली और जब गाड़ी चली तो कांग्रेस वाले कहने लगे कि हमने चलवायी है और दूसरी पार्टी के लोग कहने लगे कि हमने चलवायी है। लेकिन कुछ समय बाद उस गाड़ी की यह हरकत शुरू हुई कि चाहे जब रुकने लगी और चाहे जब चलने लगी और इस कारण घंटों लेट होने लगी, चार-चार पांच-पांच घंटे लेट होने लगी। इस पर जनता को बड़ा [illegible] आया तो कांग्रेस वाले कहने लगे कि जनसंघ ने यह गाड़ी चलवाई और जनसंघ वाले यह कहने लगे कि कांग्रेस ने चलवाई।

मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देती हूं कि हमारे कहने पर उन्होंने उस गाड़ी को जरा तेज करवाया है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उसको और तेज करवाने की कोशिश की जाये।

मुझे यह भी कहना है कि इस गाड़ी में जो फर्स्ट क्लास के कम्पार्टमेंट हैं वे भी बड़े रद्दी हैं। मालूम होता है कि जो सब जगह से खराब हो जाते हैं वे वहां लगा दिये जाते हैं। उनमें अगर पानी का टैप खोला जाता है तो पानी के बनिस्पत कोयला ज्यादा निकलता है, न उनमें बिजली है, न खिड़की दरवाजे ठीक से खुलते और बन्द होते हैं। वे अपनी मरजी से खुलते और बन्द होते हैं मुसाफिर की मरजी से नहीं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस तरफ तवज्जह दी जाए।

वैसे तो फर्स्ट क्लास के कम्पार्टमेंट हर इलाके के कुछ ऐसे बने हैं कि उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जो वाश बेसिन हैं उनके ऊपर स्टैंड इस तरह लगे हैं कि उनके बीच में सिर डाल कर हाथ मुंह धोना बहुत कठिन होता है। मैंने यह भी देखा कि कई जगह उनको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया गया है। पता नहीं, जनता ने यह काम किया है या रेलवे ने अपनी गलती महसूस करके उनको दूसरी जगह लगाया है।

इसी सिलसिले में मुझे यह भी याद आता है कि तीसरे दरजे में जो सोने के लिए एक के ऊपर एक तीन-तीन बर्थ बनायी गई हैं वे ऐसी हैं कि जो आदमी सब से ऊपर की बर्थ पर सोता है उसको उतरना मुश्किल होता है, उसको कुली ही उतारता है क्योंकि वह बैठ नहीं सकता और उसके लिए यह समस्या होती है कि पहले सिर को नीचे करे या पैरों को। इसलिये उसको लेटे लेटे हुए को कुली उतारता है।

इसी तरह की कुछ बात मैंने फर्स्ट क्लास में देखीं। उनमें ऊपर की बर्थ अगर खुला हो और अगर नीचे ऊंचे कद का आदमी बैठा हो तो उसको बहुत दिक्कत होती है। वह सीधा नहीं बैठ सकता। एक बार मैंने देखा कि एक सरदार जी नीचे की सीट पर लेटे हुए थे। वे किसी को बैठने नहीं देते थे। जब ऊपर की बर्थ पर सोने वाला उठ गया और वह बर्थ ऊंची की गई तो वे उठ कर बैठे। मैंने पूछा कि क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पर मैं इसलिये लेटा था कि जब तक ऊपर की बर्थ खुली रहती है तब तक मैं बैठ नहीं सकता। उनकी गरदन ऊपर की बर्थ तक आती थी। जब फर्स्ट क्लास के लोगों को इतनी तकलीफ होती है तो तीसरे दरजे के लोगों को तीन बर्थ होने की वजह से कितनी दिक्कत होगी इसका अच्छी तरह अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इसका इन्तिजाम करें। उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन इस फैसिलिटी के बिना तो लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो गोंडा जिले का बलरामपुर का एरिया है वह नेपाल के बारडर से बहुत मिलता जुलता है। हमारे यहां का आखिरी स्टेशन जो जरवा शहर का है वहां लाखों रुपये का पत्थर रेलवे और दूसरे लोग तुड़वाते हैं। लेकिन उस पत्थर को लाने के लिए वैगन्स की बड़ी बदइन्तिजामी है। वहां हजारों मजदूर काम करते हैं। उनके खाने का कोई बन्दोबस्त नहीं है, रहने का कोई बन्दोबस्त नहीं है और जो पत्थर वे तोड़ते हैं उसको लाने का कोई ठीक इन्तिजाम नहीं है। उस तरफ वैगन्स देने का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके अलावा उसी एरिया में जो बारडर का एरिया है, गोंडा जिले में, कई साल पहले रेलवे ने एक सरवे करवाया था सादुल्ला नगर और अतरौला के बीच में। उस सरवे को हुए दस पन्द्रह साल हो गये। वहां से सीधी लाइन जरवा तक आने वाली थी और इस तरह बारडर तक जा सकती थी। लेकिन लाइन नहीं बनी। सरवे होने से लोगों को उम्मीद हो जाती है। मालूम होता है कि कुछ सरवे तो रेलवे सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए ही करवा देती है। मैं चाहती हूं कि उस तरफ ध्यान दिया जाए और कुछ न हो तो कम से कम कुछ आदमियों को उस तरफ भेजा जाए ताकि लोगों को उम्मीद हो कि लाइन बनेगी। इस तरह उम्मीद करते करते काम हो भी जाया करता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो सरवे किया गया था उस पर अमल किया जाए और यह लाइन डाली जाए।

मुझे एक और ताज्जुब होता है कि जो ट्रेन एग्जामिनर रात को ड्यूटी देते हैं उनको एलाउंस नहीं दिया जाता। यह एलाउंस असिसटेंट स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर को दिया जाता है और लोगों को दिया जाता है जो रात में काम करते हैं। लेकिन न मालूम क्यों ट्रेन एग्जामिनर्स को नहीं दिया जाता। जितनी गाड़ियां स्टेशन मास्टर देखता है उतनी ही ट्रेन एग्जामिनर देखता है। जितनी गाड़ियां असिसटेंट स्टेशन मास्टर देखता है उतनी ही ट्रेन एग्जामिनर को देखनी पड़ती हैं। पर उन को उस कैटेगरी में नहीं डाला गया है। कुछ रेलवे जोनों में यह नाइट अलाउंस ट्रेन एग्जामिनर्स को मिलता था। इस के बारे में लखनऊ के ट्रेन एग्जामिनर्स ने पत्र लिखा कि जब उन जोंस के लोगों को यह नाइट अलाउंस मिलता है तो हमें वह क्यों नहीं दिया जाता है। अब इसका परिणाम उलटा हुआ। बजाय इसके कि उन्हें भी यह नाइट अलाउंस दिया जाता जिन लोगों को अभी तक वह भत्ता मिलता था उनका भत्ता काटे जाने की नौबत पैदा

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हो गई है। मेरी समझ में ट्रेन एग्जामिनर्स की नाइट अलाउंस की प्रार्थना को रेलवे मंत्रालय को स्वीकार कर लेना चाहिये। अब अगर रात को काम करने से स्टेशन मास्टर की सेहत खराब होती है तो ट्रेन ऐग्जामिनर्स की सेहत रात को काम करने से अच्छी तो हो नहीं सकती है उसकी भी सेहत ख़राब ही होगी।

एक बात और परेशानी की है और वह रेलों में कैटरिंग की व्यवस्था का सवाल है। हमारा ऐसा अनुभव है कि पहले जब हम लोग रेलों में सफर किया करते थे तो आसानी से और समय पर अच्छा खाना व चाय वगैरह हम लोगों को मिल जाया करती थी। आज से दस, पन्द्रह साल पहले का हमारा यह अनुभव है कि हमें वक्त पर मांगने पर खाना व चाय अच्छी मिल जाया करती थी लेकिन अब वह बात हमें दिखाई नहीं देती है। अब अगर हम लंच मांगते हैं तो कह दिया जाता है कि लंच नहीं मिल सकता है उस का समय निकल गया है, चाय मांगो तो उस के लिए भी कह दिया जाता है कि चाय का टाइम निकल गया है। अगर स्टेशन पर किसी तरह वेटर न आये उस से कंटैक्ट न कर सकें तो फिर आप कितना ही चाय या खाना मांगते रहें कोई सुनवाई नहीं करता है और न खाना आपको मिलता है और न ही चाय। इस के कारण अक्सर हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न तो उतर कर दौड़ कर डाइनिंग कार तक पहुंच सकते हैं और न ही आर्डर दे सकते हैं। कई दफ़े तो दिन भर बगैर कुछ चाय या खाना मिले ही निकल जाता है अगर वेटर साहब ने मेहरबानी नहीं की आर्डर लेने के लिए। लखनऊ से दिल्ली को दो तरफ से वाया मुरादाबाद और वाया कानपुर दो गाड़ियां चलती हैं। जो गाड़ी लखनऊ से कानपुर हो कर दिल्ली जाती है तो उसमें तो सुबह कहीं चाय तक भी नहीं मिल पाती है। अगर उनसे कहो कि दूसरी ट्रेन पर तो चाय वगैरह मिल जाती है तो जवाब यह मिलता है कि चूंकि उसमें प्राइवेट ठेकेदार का इंतजाम है इसलिये मिल जाती है यहां चूंकि रेलवे डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग है इसलिए नहीं मिल पाती है। रेलवे की विभागीय कैटरिंग की यह व्यवस्था बहुत ही अफ़सोसनाक है। रात भर का सफर किये हुए यात्रियों को बगैर चाय के स्टेशन पर आ कर उतरना पड़ता है। दिल्ली तक उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिये मेरी प्राथना है कि मंत्रालय इधर ध्यान दे और चाय वगैरह यात्रियों को देने के वास्ते मुनासिब इंतज़ाम किया जाये।

गाज़ियाबाद स्टेशन पर ट्रेन एक मिनट के लिए रुकती है। चाय आदि के लिए जब स्टेशन मास्टर से कहते हैं और गार्ड से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करें अगर वह चाय आदि नहीं लाया है? चूंकि गाड़ी बहुत कम समय के लिए वहां पर ठहती है इसलिये अक्सर बाक़ी चेंज भी यात्रियों को बैरा लोग नहीं देते हैं। अब या तो वास्तव में उन के पास पैसे वापिस करने का समय नहीं होता है या वापिस करने की इच्छा नहीं होती है और बेचारे यात्रियों को बाक़ी चेंज से भी हाथ धोना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों की तरफ़ तवज्जह दें। जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें रेल की सुविधा का विस्तार करें। वे खुद वहां तशरीफ़ ले जायं और देखें कि वहां की क्या हालत है?

श्री बाकलीवाल (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए में आप का बड़ा आभारी हूं। अभी

थोड़ी देर पहले शर्मा जी ने कुछ रेलवेज एम्प्लायीज़ और लेबर के सम्बन्ध में कहा था जिससे कि मेरा बोझा कुछ हलका हो गया है लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

भिलाई में हमारा मार्शलिंग यार्ड है। एक कौलोनी बनी हुई है। कुछ मकान भी बन गये हैं। पहले कहा गया था कि 3,000 मकान वहां के रहने वालों के लिए बनेंगे लेकिन बने केवल 1,500 क्वार्टर हैं। केवल 30 परसेंट रेलवे कर्मचारी उन क्वाटरों में रहने लगे हैं। सब कमचारियों को अभी क्वार्टर नहीं मिले हैं। 10,000 से ऊपर आबादी वहां हो चुकी है।

एक प्राइमरी स्कूल वहां खुला हुआ अवश्य है हालांकि वह भी बड़ी मुश्किल से खुला। बीच में रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि एजूकेशन तो स्टेट सब्जेक्ट है और इसे स्टेट वाले करेंगे, हम रेलवे वाले इसे क्यों करें। बहरहाल जब बहुत उसके लिए कहा गया तो जा कर यह प्राइमरी स्कूल वहां पर उन्होंने खोला है। प्राइमरी स्कूल में पांच क्लास हैं, पांच से भी ज्यादा क्लास हो गये हैं लेकिन टीचर्स दो ही हैं। मैं यह इसलिये मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहता हूं कि कभी-कभी एफिशिएंसी जिस डिपार्टमेंट में हो उस में भी कैसी-कैसी बातें हो जाती हैं? रेलवे विभाग द्वारा खोले गये इस प्राइमरी स्कूल के दो साल हो गये लेकिन रजिस्टर या स्टेशनरी उनको नहीं मिली थी और नतीजा यह होता है कि टीचर्स बेचारों को अपने पास से लेकर लिखना पड़ता था। अब तो मुझे मालूम हुआ है कि रजिस्टर और स्टेशनरी आदि मिल रही है। वहां पर मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गया है। प्राइमरी स्कूल में दो ही टीचर्स हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। टीचरों की तादाद बढ़ाई जाय। अभी जो एक प्राइमरी स्कूल चलता है वह बहुत कम पड़ता है और वहां और प्राइमरी स्कूल खोला जाये। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राजहरा में भी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है।

रेलवे के कर्मचारियों को आज के महंगाई के युग में तनख्वाह नाकाफ़ी साबित होती है और जब वे तनख्वाह में इज़ाफ़ा की मांग करते हैं तो वह हक बजानिब है अगर तनख्वाह उनको कम भी मिले तो भी वे संतोष कर सकते हैं लेकिन उनको रहने की अच्छी जगह मिले, सफ़ाई हो, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा सुलभ हो और उनके और उनके परिवार वालों के इलाज के लिए अस्पताल आदि की व्यवस्था समुचित रूप से हो। रेलवेज में मार्शलिंग यार्ड खुल गया, अस्पताल खुल गया, घर बन गये लेकिन सिनैटरी कंडीशंस ठीक नहीं रक्खी गयी है। जितने स्कूल खुलने चाहिएं उतने नहीं खुल पाये हैं। वहां अस्पताल तो है मगर एक लेडी डाक्टर नहीं है। राजहरा में तो डाक्टर भी नहीं है। राजहरा और दुर्ग में सिनैटरी कंडीशन ठीक नहीं है और ड्रैनेज की व्यवस्था नहीं है। राजहरा स्टेशन के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिसको कि लोगों ने एनक्राच कर रक्खा है। उसमें उन्होंने मकान बना लिये हैं, मकान बना लिये इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने मकान बना कर उन्हें किराये पर दे रक्खा है। रेलवे डिपार्टमेंट उन्हें ख़ाली नहीं करा पा रहा है।

कैजुएल लेबर की बात श्री ए० पी० शर्मा ने कह दी है। उन की तीन श्रेणी हैं सी० पी० सी०, और मिनिमम वैजेज वाले व ओपेन लैंड की अलग अलग कैटेगैरीज हैं। कैजुअल लेबरर्स की अलग-अलग रेट हैं। सी० पी० सी० के लिए 75 जमा 28 डी० ए० है। 1 रुपया 75 पैसे

[श्री काकलीवाल]

मिनिमम वैजेज के लिए है ग्रौर 1 रुपये 52 पैसे ग्रोपैन लैंड के लिए है । मैं नहीं समझता कि एक ही काम करने वालों को यह कम मजदूरी क्यों मिलती है ? यह काम करने वाले ग्राखिर खाते तो एक सा ही हैं ग्रौर काम भी उतना ही करते हैं तो फिर इनमें मजदूरी के बारे में क्यों फर्क किया जाता है ? इन सब श्रेणियों की मजदूरी को बराबर कर दिया जाये । ग्रगर यह कर दिया जाये तो यह सब झगड़ा मिट सकता है ।

मैं चाहता हूं कि दुर्ग भिलाई, भाटापारा ग्रौर ग्रनूपपुर में रेस्ट गिवर्स ग्रौर लीव रिजर्व की संख्या बढ़ायी जाये । वहां पर कर्मचारियों को पिछले चार साल से रेस्ट एंड लीव नहीं मिल पायी है इसलिए लीव रिजर्व की संख्या बढ़ायी जाये । एक तो ग्रोवरटाइम उनसे कराने के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ता है ग्रौर दूसरे एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ता है ।

एक दूसरा ग्रसन्तोष रेल कर्मचारियों में इस स्टौ गैप प्रमोशन या ग्राफिशिएटिंग चार्ज को लेकर फैल रहा है । होता यह है कि ग्रगर किसी से उसका ग्रफसर खुश हो गया तो भले ही वह जूनियर क्यों न हो उसको ग्राफिशिएटिंग चांस प्रमोशन का दे दिया जाता है ग्रौर फिर बाद में जब प्रमोशन देने की बात ग्राती है तो उस ग्राफिशिएटिंग चार्ज वाले को सीनियर करार देकर उसे प्रमोट कर दिया जाता है । नतीजा इसका यह होता है कि बहुत से लोग जो कि सिन्यारिटी की बेसिस पर प्रमोट होने चाहिएं वे प्रमोट नहीं हो पाते हैं । इसलिये मेरा इस बारे में सुझाव यह है कि ग्राप इस प्रमोशन के काम को रैगुलराइज करें ताकि मुलाजिमों के मन में ऐसा भाव पैदा न हो कि उनके साथ कोई बेइंसाफ़ी की गई है या ग्रमुक के साथ बजा तौर पर पक्षपात किया गया है ।

मार्शलिंग यार्ड के पास चरौदा नाम का स्टेशन बनाया है । भिलाई कारखाने की वजह से यह सब चीजें बनी हैं । ग्रास-पास में भिलाई के लोग काफ़ी रहते हैं ग्रौर वहां से उन्हें ग्रभी ग्राने जाने की कोई सुविधा नहीं है । उस स्टेशन पर गाड़ी खड़ नहीं होती है । वह स्टेशन नहीं है । मैं चाहता हूं कि वहां पर एक शैड बना कर तुरन्त स्टेशन चालू कर दिया जाय ग्रौर गाड़ी वहां खड़ी हो ताकि ग्रासपास के लोगों को जिन्हें कि ग्रपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जाना पड़ता है उन्हें सुविधा हो जाये । ऐसा होने से वहां के लोगों को भिलाई ग्रौर दुर्ग में काम करने वालों को इधर से उधर ग्राने जाने में बड़ी सुभीता हो जायेगी ।

दुर्ग स्टेशन बहुत इम्पार्टेंट स्टेशन है ग्रौर वह डेवेलप हो रहा है । लेकिन जब भिलाई का कारखाना बना है तो भिलाईनगर भी उसका ही भाग है । इस लिए मंत्री महोदय उसकी तरफ़ भी ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है । हाउस में कोरम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है—ग्रब कोरम हो गया है । माननीय सदस्य ग्रपना भाषण जारी रखें ।

श्री काकलीवाल : मैं ग्रपने क्षेत्र की भी बात कहना चाहता हूं । हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया धान में सरप्लस है । वह हिन्दुस्तान की बहुत सी जगहों को धान सप्लाई करता है । लेकिन ग्राज वहां जो रेलवे का डेवेलपमेंट हुग्रा है,

वह सिर्फ़ धान या अन्य अन्न में सरप्लस होने की वजह से नहीं, बल्कि उस के लिए धन्यवाद है हमारी प्राकृतिक सम्पत्ति को। अगर हमारे यहां भिलाई का कारखाना न खुलता, तो सम्भवतः हमारे यहां भिलाई से दल्ली-रजहरा और भिलाई से नंदनी की दो नई लाइनें न होतीं। मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वहां भी कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाये, तो आज जो किसानों को रेल-हैड न होने के कारण भाव कम मिलता है, वह स्थिति न हो और उन को पूरे दाम मिलें और वहां के लोगों को लाभ हो।

दुर्ग से जबलपुर लाइन का बहुत दिनों से सरवे हो चुका है। वह लाइन चालू करनी चाहिये। अगर रायपुर-धमतरी-राजीम लाइन को, जो कि छोटी लाइन है, बड़ा कर दिया जाये, तो ज्यादा सुविधा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

Shri D. J. Naik (Panchmahals): I thank you for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants relating to the railways. Perhaps, I am the last speaker. . . .

Shri C. K. Bhattacharyya: But not the least.

Shri D. J. Naik: The railway Administration is the biggest administratartion in the public sector. It has two aspects; one is the commercial aspect and the other is the service aspect. So far as the commercial aspect is conerned, I think the performance is satisfactory and efficient. So far as the service aspect is concerned, there are several shortcomings and deficiencies. Still the nation can be proud of this public sector undertaking. It is a progressive public sector undertaking.

I am glad that during the year 1965-66, on the Western Railway, the preliminary-*cum*-final location survey for doubling the line from Godhra to Baroda is being undertaken and similarly the preliminary engineering-cum traffic survey from Ahmedabad to Gandhinagar, the new capital of Gujarat is also being undertaken. I am very happy that these two surveys have been included in the programme for 1965-66. For that, I congratulate Shri S. K. Patil and Dr. Ram Subhag Singh, the two capable Ministers in the Railway Ministry, who are also dynamic. I hope that the service deficiencies and shortcomings will be mitigated very much.

Shri C. K. Bhattacharyya: Congratulate them in anticipation.

Shri D. J. Naik: Yes.

I have some suggestions also to offer. There are several scheduled areas in this country which are very much undeveloped. I might mention Bastar in Madhya Pradesh which is a wholly undeveloped area. A railway line must be there from Raipur to Jagdalpur if we want to develop that area and if we want to do some service to the Scheduled Tribes people. Similarly, the Nimar area of Madhya Pradesh also requires development. Both these areas are full of minerals and full of forest produce. From Indore to Dohad also a railway line must be laid. Some years back, a preliminary survey was made but nothing has been done up till now. These two areas require development and for that purpose railway line is necessary, both from the point of view of the development of the area as also of the people living therein.

The Ankleshwar oil-field is a very rich oil-field. There is one Dahej port on the Bay of Cambay. That port is being developed now. I would suggest that that port should be linked with Baroda by a broad gauge line. Baroda is fast developing industrially,

[Shri D. J. Naik]

and, therefore, this line should be laid, and a preliminary survey should be undertaken for this purpose and this should be done in the Fourth Plan.

I would like to mention some other complaints also. The Scheduled Tribes labourers are being cheated by the contractors. They are taken up to Kotah from my area and they are cheated by the contractors. So, I would suggest that some method should be devised by the Railway Administration so that the contractors would not take advantage of the illiteracy and ignorance of the Scheduled Tribes. I suggest that co-operative societies should be sponsored by the Railway Administration with the co-operation of non-official agencies, and that is the only way to safeguard the interests of the ignorant and illiterate Scheduled Tribes people.

On the Western Railway, there are two trains from Delhi to Bombay, the Janata Express and the Dehra Dun Express. Both these trains are overcrowded; they are overcrowded to such an extent that the people have sometimes to travel on the roofs. I would suggest that one more train should be run either from Ratlam to Ahmedabad or from Bhopal to Ahmedabad. There is one passenger train from Bhopal to Ahmedabad, but that runs very slowly, at hardly a speed of 15 k.m. an hour. So I would suggest that an express train should be run between Bhopal and Ahmedabad, so that the two State capitals or the two important cities in the two States could be linked by a fast means of communication. That would remove the congestion on the Dehra Dun Express as well as the Janata Express. I would request that my suggestion may be looked into.

So far as fuel consumption is concerned, I find that the expenditure is going up. I have looked into the explanation given in the Demands for Grants booklet in regard to fuel consumption. I would suggest that this matter may be looked into, because to my mind the explantion given is not satisfactory. I would request the Railway Ministry to look into this matter and see that the expenditure on fuel consumption is brought down.

Similarly, the expenditure on compensation for lost or damaged goods is also increasing. There is pilferage in the yard, and there is pilferage at other places also. This should be looked into, and some method should be devised so that the incidence of pilferage could be minimised, and the compensation for damaged or lost goods could be lessened.

Then, I would mention one point relating to my constituency. I would like to point out that there is a platform shed constructed at the Dohad station which is so small and which is, in fact, a mockery of a shed. My hon. friend Dr. Ram Subhag Singh has seen that station. The Railway Minister Shri S. K. Patil also knows about that area. I would suggest that a larger platform shed may be constructed at that place. It is only 50 feet in length and about the same size in breadth. It should be extended.

In regard to the deluxe train, while the Down train coming to Delhi stops at Godhra, the up train does not stop there. I would suggest that that deluxe should stop at Godhra because it is the headquarters of the district and is a growing and developing town. I hope the Minister will look into these two suggestions.

15 hrs.

Another suggestion is about catering. I understand railway catering is far better than private catering. Even then, there is difference in catering in a deluxe train and that in the janata, the former of a higher type and the latter of inferior standard. Catering should be uniform and equal everywhere irrespective of the class travelled by passengers. Sometimes I tra-

vel by third class; if I give an order, it is not immediately attended to; it takes some time. When I travel by firs class, I find that the order is immediately attended to. That difference should not remain between first class and third class passengers. Catering should be uniform and similar in standard in all the trains, in all clases. Otherwise, our talk of a just social order and a socialistic society will remain mere words, not implemented in action.

श्री वीरप्पा (बीदर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से आता हूं । मेरा जिला मैसूर स्टेट का आखिरी जिला है । उस आखिरी जिले का मैं रहने वाला हूं । उस क्षेत्र की रेलवे के बारे में जो एक कमी है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं । वह कमी यह है कि सिकन्दराबाद से परली जाने वाली जो गाड़ी है वह बहुत ही धीमी चलती है । मैंने गुजशता साल इसका जिक्र किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि उसकी स्पीड में कोई अन्तर नहीं आया है । आप उन्हीं को भोजन दिया करते हैं जिनके पेट पहले से भरे होते हैं लेकिन जो भूखे होते हैं उनको आप भी भोजन देना नहीं चाहते हैं । जो लोग पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, वे जो कहते है उसकी कोई कीमत नहीं होती है । ऐसा नहीं होना चाहिये । आप को पिछड़े हुए इलाकों की तरफ भी ध्यान देन चाहिये, वहां जो कमियां है, उनको भी दूर करना चाहिये । मेरे एरिया में जो रेल हैं उसमें न पानी की व्यवस्था है न लाइट की व्यवस्था है और न ही उस गाड़ी की रफ्तार तेज है । उस रेल रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवस्थान परली बैजनाथ है । वहां पर बहुत अधिक संख्या में यात्री जाते हैं और वहां यात्रा करते हैं । वहां बहुत दिक्कत पैदा होती है । यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये ।

एक और कमी की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । विकाराबाद से उदगीर तक कोई दवाखाने की व्यवस्था नहीं है । चाहता हूं कि बीच में बीदर में एक दवाखाने की आप व्यवस्था कर दें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहीराबाद से शोलापुर तक जहां तक हो सके एक नई लाइन होनी चाहिये । बाबू जगजीवन राम जी जब रेल मंत्री थे उस वक्त वह मैसूर जब पधारे थे तो पब्लिक की ओर से एक डैपुटेशन उन से जा कर मिला था और मैंने उन से कहा था कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा भी ख्याल किया जाए, हमारा कोई ख्याल नहीं करता है तो उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था । लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । गुजशता साल भी मैंने यहां पर यह चीज आपके सामने रखी थी । लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जहीराबाद से शोलापुर 190 मील है । यह लाइन वाया हुमनाबाद से जाए । बीच में बहुत सी मंडियां हैं, बिजिनेस खूब होता है, इस वास्ते इस लाइन पर नुक्सान होने की कोई आशंका नहीं है, फायदा ही आपको होने वाला है ।

सिकन्दराबाद से बंगलोर तक के लिये एक बड़ी लाइन के बारे में भी मैंने कहा था लेकिन अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि आप इसके हर एक पहलू पर ध्यान दें । आपके समय के जो कारनामे हैं वे बहुत सुन्दर हैं, यशस्वी हैं । लेकिन आप हमारे जो बैक्वर्ड एरियाज हैं, उनको भी देखें । जहां तक हो सके आप दक्षिण रेलवे के ऊपर ध्यान दें । वहां पर रेल के डिब्बे जला कर एक धोखा किया गया है । मैं चाहता हूं कि जहां पर जलाये गये हैं उन के कोटे में से और जितने जलाये गये हैं, उतने उनके कोटे में से काट करके रेलों की भरपाई की जाए । यह जो मद्रास राज्य में हुआ है । डिब्बों को नुक्सान पहुंचाया गया है, बिला वजह पहुंचाया गया है, इसके बारे में रेल मंत्रालय को विचार करना चाहिये कि क्या यह उचित नहीं होगा कि उनके कोटे में से इतने डिब्बे

[श्री बौरूपा]

काट दिये जायें और इस तरह से भरपाई की जाए ।

15.07 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

अन्त में हरिजनों और गिरिजनों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । इनको रेलों में अधिक सहूलियतें दी जानी चाहियें । जिस तरह से परीक्षाओं में आप हरिजनों और दूसरों को कंसेशन देते हैं, उसी तरह से नौकरियों में उनका कोटा न रहते हुए भी आप उनको सहूलियत दें, यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

Mr. Chairman: Shrimati Lakshmikanthamma. I will allow six or seven minutes as I wish to call the hon. Minister of State at 3.15.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): Madam, thank you very much for the opportunity given to me. First of all, let me express my sadness at the way in which the language riots have resulted in damage to public property, including railway property. I feel in democracy there are other methods peaceful methods, in which one can express one's dissatisfaction at the way things are going on. I feel, Sir........

Mr. Chairman: At least the hon. Member should address me as 'Madam'.

Shrimati Lakshmikanthamma: Madam, when Shrimati Vijayalakshmi Pandit was presiding over the UN General Assembly, she said that the word 'Chairman' could be used for a woman even if she was presiding.

Mr. Chairman: That is my ruling too. But in your case I was thinking that you might address me as 'Madam'.

Shrimati Lakshmikanthamma: Madam, I congratulate the Ministry and the staff and workers on the speedy completion of the Pamban bridge. It was really a pleasant surprise that within the quickest time this bridge was completed. We never expected this would be done in such a short time and traffic resumed.

As regards the new railway zone with Secunderabad as headquarters, opinion has been expressed that Guntakal and Waltair should also be included in it. By the time the Nagarjunasagar project wil be completed, lakhs and lakhs of acres will come under production. Meanwhile, a survey should be made for a line to connect Hyderabad *via* Nagarjunasagar and Ongole. This is very urgent from the point of view of transport of foodgrains to other parts of the country.

A survey is being undertaken for the Bhadrachalam Road-Dantewara railway line. The other day I visited Kothagudam and Dantewara. Last time I had asked the Deputy Minister and he said that that bridge would go through. Bhadrachalam as you know is a very important pilgrim centre, next only to Tirupati and Srisailam. When I went there the survey was going on, and people told me that the bridge would be constructed not at Bhadrachalam proper, but 20 miles away. I would like to impress on the Minister that it is very important to connect this pilgrim centre. It will also get very good revenue for the railways while helping the pilgrims and passengers who visit these places. He should ask his engineers to explore the possibility of connecting Bhadrachalam proper through this line Kothagudam to Dantewara.

15.11 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

As has been mentioned here by Members from Andhra Pradesh as well as others, the people of Andhra Pradesh are very much agitated over the rail-cum-road bridge over the Godavari at Rajamundry. I am very

thankful that the Railway Ministry has been very considerate in this matter. Since the Railway Minister is an important member of the Cabinet, he should help us in this matter. This is almost assuming the importance of the language problem in Madras, and this sort of feeling should not be allowed to grow. They have every reason to get agitated over this. While the construction of the rail bridge will cost Rs. 4 crores, this will cost only another Rs. 2·5 crores. So, they should take up this rail-cum-road bridge when the railway bridge is constructed.

A demand has already been voiced about a through train to Hyderabad. Some time back I made a request that the G. T. Express should stop at Khammam, my constituency, which is the district headquarters as well as an important business centre. When two years back I wrote on this matter to the Ministry I was surprised to get a reply saying that this train could not be stopped at Khammam, as it was only 60 miles from Bezwada. They told me where I should get down, which train I should catch to reach Khammam, as if I do not know myself. I never wanted this information. I wanted that because of the importance of Khammam as district headquarters and a business centre the G.T. Express should stop there.

The trains come there at all sorts of odd hours, and they stop for only one or two minutes. I have had bitter experience of this. When I wanted to get into the train, the doors were locked in First Class, they would never open, and there was no time to get into the third class. By the time you go from the first class to the third class, the train would have already moved. Once it so happened that the train went away without my being able to get into it. We should also alert the conductors in the first class compartments and see that they get up at every station and help in opening the doors.

Regarding railway catering, I only want to say one word. The bearers have to pay Re. 1 or something like that extra for their food. I think it is not an easy job even for us, in spite of our free ticket, to move about. How difficult it must be to travel by train to and fro! When they have to travel for so many hours, we should at least give them this facility of free food.

As for facilities for women, most of the lady Members have mentioned about it. Sometimes upper berths are given for pregnant women. How do we expect pregnant women to get up? It may be dangerous to their very lives. So, I think this upper berth system in ladies compartments should be dispensed with, though I do not say there may not be some energetic women.

It is my experience that most of the first class waiting rooms in my constituency are unclean and dirty. Whenever I bring it to the notice of the authorities, they spray DDT, but afterwards it continues in the same old state. It is hell. You would rather stand outside in chillness and suffer than bear these bugs and mosquitoes. So, there should be regular spraying and cleaning of these waiting rooms.

In my place, all trains come in the middle of the night at 1 O'clock or 3 O'Clock. The licensed collies take your things to be put in the train, but when the train comes, he is sleeping. You have to go and wake him. You do not know where he is sleeping. By the time you find him the train goes away. So, there should be a shift system for these licencesed coolies.

The public should give all co-operation to the railways in the speedy running of the trains. I know that in Guntur and other places people get into the train, pull the chain and ask others to come in. In this connection, there is a joke. It is not so much a joke, it must have really happened. It seems that some people saw an old woman walking by the side of the railway track and

[Shrimati Lakshmikanthamma]

asked her to get into the train, but she replied that she had some urgent work and had to go very soon, so she would not get into the train. So, the trains are running at that speed.

In conclusion, I have one or two small requests to make. I want halting stations at Pattabhipuram in Guntur District and Mangalagiri Road, and the railway bridge at Guntur to be extended to Arundalpet side, so that passengers getting down may go either side as is done at Vijayawada.

Dr. Ram Subhag Singh: I was listening very carefully . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि दो मंत्री पहले ही अंग्रेजी में बोल चुके हैं। अगर डा० राम सुभग सिंह हिन्दी में बोलें तो ज्यादा अच्छा है। उनकी मातृभाषा भी हिन्दी है।

डा० राम सुभग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यान से अभी अन्तिम वक्ता महोदया का भाषण सुन रहा था। उन को जो दुःख हुआ रेल की यात्रा में उसके कारण मुझे बड़ा दुःख हुआ। अब से हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको कोई खास कठिनाई न हो।

यह बड़े सन्तोष की बात है कि इस सदन के कतिपय सदस्यों ने, करीब एक दर्जन सदस्यों ने रेलवे के इस रोल का बड़ा ऐप्रिसिएशन किया कि इसके कारण देश में एकता की भावना बढ़ती है और दूर दूर के प्रदेशों में पूर्व से लेकर पश्चिमी तट तक और लद्दाख से लेकर धनुषकोटि तक के लोगों में, एकता की भावना जगी है, और इस बात का सबूत यह भी है कि पम्बन पुल के बनने पर लोगों में हर्ष की ज्योति जगी है। इन प्रशंसात्मक बातों से हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिला, और हम जरूर यह प्रयत्न करेंगे कि यह कार्य हमारा और भी आगे बढ़े।

आज यदि आप रेल के नक्शे को भारत के मानचित्र के सन्दर्भ में देखें तो पायेंगे कि जहां जहां रेल गई हैं वहां वहां कोई न कोई तरक्की का कार्य हुआ है। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल करीब 12 लाख वर्ग मील से ज्यादा है और इस में दो पोने दो लाख वर्ग मील पहाड़ और जंगल हैं जो प्रधानतया उत्तर हिमालय में, राजस्थान में और पश्चिमी किनारे पर पड़ते हैं। यह इलाके ऐसे हैं जिनका बड़ा सामरिक महत्व भी है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने, और विभिन्न दलों के सदस्यों ने, इस बात पर बल दिया है कि रेल का विस्तार होना चाहिए और यह विस्तार होना चाहिए औद्योगिक दृष्टि से, कृषि की तरक्की की दृष्टि से, वन सम्पदा के इस्तेमाल की दृष्टि से, खनिज पदार्थों के इस्तेमाल की दृष्टि और सामरिक महत्व को देखते हुए भी। तो सारा खाका ऐसा होना चाहिए जिससे भारत के कोने कोने के लोगों में एकता की भावना और बढ़े और इस दृष्टि से जब हम रेल के कार्यों को देखते हैं तो स्वभावतः उससे जरूरत से ज्यादा संतोष होता है। आप चले जाइए नियर फ्रांटियर डिवीजन से द्वारका और माधोपुर तक और कन्याकुमारी तक—वहां रेल नहीं हैं लेकिन टिन्नेवेली में है—या धनुषकोटि चले जाइए—वहां जो दुर्घटना हुई उसका हमको बहुत दुःख है—आप देखेंगे कि लोगों को रेल से प्रेम है और वह समझते हैं कि इसके चलते उनका विश्वास कायम रहेगा। वैसे आवागमन के और भी साधन हैं, जैसे हम हैलीकाप्टर से जाकर कहीं भी उतर सकते हैं। जैसे कि संसद में सारे भारत का विश्वास है कि इसके चलते देश की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता पर कभी आंच न आयेगी उसी तरह से लोगों में विश्वास है कि रेल के चलते उनमें आत्मबल रहेगा। रेल के चलते लोगों में यह विश्वास रहता है कि मुम बन

के वक्त हमारे पास कहीं से भी सहायता आ सकती है। जिन दिनों चीन का आक्रमण हुआ उन दिनों मैं तंजोर में था। वहां के लोगों में जो भावना थी उस समय नेफा और लद्दाख के लोगों को मदद करने की वह देखने योग्य थी। रेल एक ऐसी कड़ी है जो देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस का व्यापक रूप से विस्तार हो।

अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक हजार किलोमीटर कैरिड फारवर्ड लाइन्स बनीं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की थीं और इसके बारे में.....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : क्या बम्बई मंगलोर लाइन भी बनाएंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : लिमये साहब को यह समझना चाहिये कि जब वह बोले तो हम चुप रहे थे, अब उनको चुप रहना चाहिये।

2600 किलोमीटर लाइन की बात थी। अभी तीन चार महिला सदस्याओं ने भाषण दिए। उनमें श्रीमती सहोदरा बाई थीं जिन्होंने गोआ में काफी शानदार काम किया था, श्रीमती सुभद्रा जोशी थीं, श्रीमती सावित्री निगम थी और श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा थी। इन चारों का अपना निराला स्थान है। इन सभी ने अपने इलाकों के बारे में चर्चा की और उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि उनके इलाके पिछड़े हैं। पिछड़े तो मैं मानता नहीं क्योंकि ये चारों बहुत आगे हैं लेकिन इनके इलाकों की जरूरतों की देखभाल जरूरी है।

कल श्री राम सहाय पांडेय ने बताया कि योजना में चालीस पचास करोड़ रुपया नई लाइनों के लिए और उन्होंने बस्तर और रायपुर में लाइनें बनाने की बात कही। कई और सदस्यों ने मध्य प्रदेश में ज्यादा लाइनें बनाने की बात कही। गुजरात में हुबली कारबार में लाइन की बात कही गयी। श्री टेकू साहब ने हासपेट और बलारी के बारे में कहा और श्री बसुमतारी जी ने आसाम के बारे में कहा। आसम के सम्बन्ध में माननीय रेलवे मंत्री ने बताया कि क्या योजना है और वहां क्या करने के हमारे अरमान हैं।

15.28 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

जो हमारी योजना बनेगी उसमें यह देखना होगा कि हमारे देश के कौन से अविकसित इलाके हैं, कौन इलाके सामरिक महत्व के हैं। श्री अब्दुल गनी गोनी ने काश्मीर के बारे में कहा। कठुआ लाइन तो अगले अक्तूबर में ही खुल जाएगी और वहां से रियासी के लिए भी लाइन के बारे में सोचा जा रहा है। वहां जाने को दो रास्ते हैं यह सोचा जा रहा है कि किस तरफ से यह लाइन जाए। जम्मू काश्मीर हमारे निगाह में है और उसको हम अपनी निगाह से ओझल नहीं होने देंगे। उन्होंने श्रीनगर की भी चर्चा की। हम मानते हैं कि उसका भारत की स्वतंत्रता के लिए जरूरत से ज्यादा महत्व है। श्री बसुमतारी जी ने, श्री पी० सी० बरुआ ने, श्री हजारिका ने, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अगरतला आदि के बारे में चर्चा की है। इन सब बातों को देखना पड़ेगा। जिस समय सदन के सामने योजना का प्रारूप आवेगा उसे देखना होगा कि योजना में किस का समावेश किया जाना चाहिए। इस संसद को अधिकार होगा कि उस पर तमाम दृष्टियों से विचार करे और योजना में हम जो रकम रखना चाहते हैं उसके बारे में फैसला करने का अधिकार संसद को है और संसद यह तय करेगी कि उस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जाए।

लाइट रेलवे के नेशनलाइजेशन के बारे में भी कहा गया। अणे साहब ने कुछ डिसमेंटल्ड रेलवेज के बारे में कहा। ये लाइनें नागपुर

[डा० राम सुभग सिंह]

के आसपास की हैं । उन पर विचार किया जाएगा । उन्होंने कहा कि जब देश को जरूरत थी उस वक्त उन लाइनों को उखाड़ा गया, अब उनको लगाना चाहिये । उनकी बात सही है । उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और दृष्टि से ओझल नहीं किया जाएगा । जो बातें उन्होंने बतायीं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जगदलपुर के इलाके के बारे में और दूसरे इलाकों के बारे में कहा । उनकी बातों पर विचार किया जाएगा और जो कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा सकता है किया जाएगा ।

सबसे बड़ी बात स्टाफ के कोआपरेशन की हमारे कई साथियों ने उठायी । श्री ए० पी० शर्मा, श्री प्रिय गुप्त, बरुआ, जी श्री डी० सी० शर्मा आदि ने इस बात को हमारे सामने विशेष रूप से रखा । इसमें सन्देह नहीं कि जो हमारे साथी रेलवे में काम करते हैं उनका काम बड़ी सतर्कता का है । अगर किसी और काम में कोई कर्मचारी कुछ कम सतर्कता भी करे तो सारा काम खराब नहीं हो जाएगा लेकिन अगर रेलवे का ड्राइवर चाहे कोई दूसरा कर्मचारी थोड़ी भी शिथिलता दिखलावे तो काम में बड़ी क्षति हो सकती है । इस दृष्टि से मैं इस काम को बहुत महत्व का मानता हूं और ऐसा करने की कोशिश की जाएगी कि इस विभाग में काम करने वाले साथी संतुष्ट रहें । उन्होंने समय समय पर देश हित के कार्यों में शानदार सहयोग दिया है और जब जब मौका आया है उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर देश का साथ दिया है ।

जब चाइनीज आक्रमण हुआ उस वक्त रेलवेज ने उस इलाके में जो पार्ट अदा किया वह अत्यन्त शोभनीय है । ऐसी स्थिति में यह देखना ही होगा कि जो उनकी आवश्यक जरूरतें हैं सहानुभूति-पूर्वक उनकी पूर्ति करने का यत्न किया जाये ।

केजुअल लेबरर्ज के बारे में भी कहा गया है । हमने नार्दर्न रेलवे और पड़ौस की तीन चार रेलों से खबर मंगाई हैं कि उनकी मजदूरी क्या है । उनसे मालूम होता है कि करीब दो रुपये से ज्यादा दिये जाते हैं । लेकिन इस हाउस में इस विषय में जो दो बातें कही गई हैं मैं उनको पूरी तरह नहीं मानता हूं । मिनिमम वजिज एक्ट एक पुराना एक्ट है । हर एक स्टेट में---और केवल स्टेट ही नहीं अलग अलग जिलों या सब-डिविजन्ज भी---उनकी मजदूरी की दरें अलग अलग हैं । जो भी हो हमारी यह मंशा कभी भी नहीं होगी कि जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं ---और वह भी कैजुअल---हम उनको किसी भी तरह ऐसी स्थिति में डालें जिन में उनको नहीं डालना चाहिए । इस दृष्टि से हर साल उनकी वज पर रिव्यू कराने की कोशिश की जायेगी । हम मिनिमम वजिज एक्ट के बारे में भी लेबर मंत्रालय से बात करेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है ।

जहां तक स्टाफ की को-आपरेशन का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि जो दोनों बड़ी बड़ी फेडेरेशन्ज हैं उनसे हमको पूरा सहयोग मिलता रहा है । जब वे रेलवेज को सबसे बड़ी नैशनल अंडर-टेकिंग की दृष्टि से देखते हैं---जैसा कि माननीय सदस्य श्री डी० सी० शर्मा ने उसको माडल अंडरटेकिंग बताया है--- और उनके सदस्यों और रेलवेज के उन कर्मचारियों के द्वारा जो काम हो रहा है जो कि किसी भी फेडरेशन के सदस्य नहीं है तो यह असम्भव है कि हम ऐसी कोई

कार्यवाही करें जिस से वे समझें कि उनके जायज हक पर कुठाराघात किया गया है।

श्री माथुर ने कहा कि फतेहपुर, चुरू खांडवा, हिंगोली रानीवाड़ा और भिल्दी आदि जगहों पर इन्फूलेटिड रेट लिया जाता जाता है। हम उस की देख-रेख करेंगे कि कैसे वहां दुरुस्ती लाई जाये। उन्होंने यह भी कहा कि जोन साइंटिफिक स्टडी के आधार पर बनाए जायें। यह कोशिश बराबर रही और आगे भी रहेगी कि बगैर साइंटिफिक स्टडी के कोई जोन न बनें। उन्होंने खासकर मीटरगेज जोन की बात कही। उस साइंटिफिक स्टडी का जो भी परिणाम होगा वह भविष्य में सामने आयेगा।

माननीय सदस्य श्री खाडिलकर ने पूना-मिरज लाइन और सतारा के बारे में जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्य श्री महीड़ा ने कहा कि यद्यपि राजकोट टाउन पर स्टेशन नहीं है लेकिन उस नाम की टिकटें अभी भी चलती हैं। हम उस अड़चन को दूर कर देंगे।

श्री जाधव ने मनमाद में पानी की शार्टेज का जिक्र किया। उस को दूर किया जायेगा।

श्री राधेलाल व्यास ने मध्य प्रदेश और इन्दौर वगैरह की दिक्कतों का हवाला दिया। हम उन दिक्कतों को भी दूर करेंगे।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन पर जो इलाहाबाद-भटनी रेलवे लाइन पर है आज तक गाड़ी खड़ी नहीं होती है।

डा० राम सुभग सिंह: श्री सरजू पाण्डेय मुझ से बात कर लें क्योंकि उन्होंने डिस्कशन के वक्त यह बताने का कष्ट गवारा नहीं किया।

श्री हेडा ने रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन की तथा-कथित अनियमितताओं की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया हालांकि उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया। मैं उनसे बात कर लूंगा। अगर वह कोई उदाहरण देंगे तो उसकी पूरी जांच करा ली जायगी। श्री त्रिवेदी ने भी ऐसी अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। हम उन्हें भी देखेंगे।

यहां पर डिब्रुगढ़ की भी चर्चा की गई, गोहाटी से लमडिंग तक डाइनिंग कार देने के लिए कहा गया और वहां की ट्रनों की स्पीड बढ़ाने की मांग की गई। यह जरूरी है कि वहां स्पीड बढ़े क्योंकि एक से अधिक माननीय सदस्यों ने उस इलाके की ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के बारे में कहा है खासकर लमडिंग-बदरपुर लाइन पर।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़): सब गाड़ियों की स्पीड बढ़ानी चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह: माननीय सदस्य को हरियाना एक्सप्रेस काफी स्पीड वाली गाड़ी दी गई है।

श्री प्रिय गुप्त ने धनुष्कोटि के बारे में जुडिशल एन्क्वायरी की बात कही। श्री राजाराम ने भी यह कहा उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है उसको यहां और राज्य सभा में भी बता दिया गया। उससे ज्यादा कुछ कहने की हम आवश्यकता नहीं समझते।

जहां तक दार्जलिंग सेक्शन और अन्य इलाकों में विन्टर एलाउंस देने की बात है कायदे से जो कार्यवाही हो सकेगी, वह की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): रेलवे पोर्टर्ज।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य ने रेलवे पोर्टर्ज के बारे में कहा था। उसके बारे में कई एक विचार धारायें यहां पर बताई गईं। उन सबको देख कर और एक सामंजस्य निकाल कर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ज्योतिषी ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा और साथ ही रेलवे मंत्रालय में शिकायत मंडल की स्थापना की ओर ध्यान आकृष्ट किया। शिकायत मंडल और जगहों में बना था। यहां भी थोड़ी कोशिश हुई थी। लेकिन शिकायत की गुंजायश कम से कम हो, इस मंत्रालय का यह जरूर प्रयास होगा ।

श्री भंजदेव ने कहा कि स्टैटिस्टिकल पेपर्ज कम दिये जाते हैं। स्थिति यह है कि 200 अंग्रेजी की और 160 हिन्दी की प्रतियां रखी गई थीं। अगले साल हम उनको और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रंगा ने कूप्पम सबवे के बारे में बताया। वहां की लोकल पंचायत की सुविधा के अनुसार जो कुछ वहां कायदे से सम्भव होगा, वह किया जायेगा।

श्री मानसिंह पटेल ने मीटरगेज पर डीलक्स ट्रेन देने के लिए कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए फारैन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है और चूंकि फारैन एक्सचेंज की सुविधा नहीं है, इस लिए उसमें इस वक्त कठिनाई है। जब इस विषय में सुविधा होगी, उस वक्त इस बात पर विचार किया जा सकेगा।

श्री माते ने, जो अपने भाषा में बोले और जो इस समय यहां नहीं हैं, कहा कि कुछ आश्वासन दिये गए थे। इस समय मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि क्या क्या आश्वासन दिये गए थे। पिछले कागजों को देखा जायेगा और उन्होंने जो दिल से सुझाव दिये हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए वहां के लोगों की जरूरत का खयाल रखा जायेगा ।

श्रीमती कमला चौधरी ने गाजियाबाद और मेरठ आदि स्टेशनों के बारे में कहा और श्रीमती सुभद्रा जोशी ने भी कहा कि वहां पर चाय की दिक्कत है। उन्होंने अठारह साल पहले का अनुभव बताया। पता नहीं अठारह साल पहले चाय की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी या नहीं। लेकिन इस बारे में सुधार की कोशिश की जायेगी ।

सुरेन्द्रपाल सिंह ने गांवों के लोगों को नौकरियां देने की बात बताई है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं जब किसी महिला का नाम आप लेते हैं, तो श्रीमती कहते हैं लेकिन जब किसी पुरुष सदस्य का नाम लेते हैं तो श्रीमान या श्री इत्यादि नहीं कहते हैं।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह पक्षपात है।

डा० राम सुभग सिंह : इसको मैं सुधार लूंगा अब से।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने गांवों के लोगों को नौकरियां देने के बारे में कहा है। हमारे माननीय सदस्य श्री बसुमतारी ने कहा है कि नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर कोई भी उनके इलाके के आदमी नहीं हैं खास करके शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के। उन्होंने इनका खास तौर पर जिक्र किया है। यह बात उनकी बिल्कुल निराधार है। वहां पर दो अफसर ग्रेड के हैं। एन० ई० एफ० रेलवे में। जितनी ज्यादा गुंजाइश होगी, इनकी तादाद हम बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया है कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे इनके

अधिकारों में कोई कमी आए या इनको यह अनुभव हो कि इनके रास्ते में कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं ।

प्रोमोशन और रिक्रूटमेंट की बात भी की गई है। सारी बहालियां क्लास तीन की जो हैं वे रेलवे सर्विस कमीशन से होती है। जो कायदे से बहालियां होती हैं और जो कोटा है जितना भी अलग, और जिसके बारे में सहानुभूति दिखलाने की बात कही गई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन को मंत्रालय की नीति क्या है यह बात बतला दी गई है। उन सारी चीजों को देख कर ही बहालियां होती हैं। जहां तक क्लास दो या क्लास एक का सम्बन्ध है, उसमें भी सहानुभूति का अभाव नहीं रहेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको क्या आप लोग मानते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं आ रहा हूं उस बात पर भी ।

Shri Sonavane (Pandharpur): Sir, about Scheduled Castes and Scheduled Tribes, no mention has been made of Class II and Class I posts; all reference is only to Class III and Class IV posts.

डा० राम सुभग सिंह : आपकी बात ठीक है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम) : मेरे मित्र सहानुभूति की बात कह रहे थे । मैं इसको नहीं समझता हूं । सहाभुति क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : जयपाल सिंह जी ने बताया है कि गलत नीति अपनाई गई थी । इन्होंने जो भी कहा था रिक्रूटमेंट के बारे में कहा था और यह कहा था कि उस में कोटा वगैरह रहना चाहिये । प्रोमोशन में यह चीज नहीं रहनी चाहिये । इनके खयालात को हम जानते हैं । लेकिन जो नीति निर्धारित की गई थी और जो रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन को बता दी गई थी और जो कुछ हिदायतें थीं वे शायद माननीय जयपाल सिंह जी को अच्छी नहीं लगीं । उस नीति में इधर कोई तबदीली नहीं हुई है और वही नीति चल रही है । इसी लिए मैंने कहा कि जो नीति बतलाई गई है उसी पर चला जा रहा है । उसके चलते मैंने सहानुभूति की बात कही है ।

हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने कहा कि गांवों के लोगों को नौकरी नहीं मिलती । मैं मानता हूं कि इसमें शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोग भी हैं । वे भी हैं जो त्यक्त हैं । हमारी निगाह शहरों से गांवों की ओर अब जायेगी और गांवों की ओर ही नहीं झोंपड़ियों की ओर भी जाएगी और झोंपड़ी विहीनों की ओर भी जाएगी । उनको अब तक समान अधिकारों से वंचित किया गया है, सहानुभूति काट दी है । उनका भी हक इस राष्ट्र पर है । उनको भी एक सम्मानित नागरिक का हक प्राप्त है । यही हक उनको प्रदान किये जाने चाहियें . . .

श्री जयपाल सिंह : मुझे क्षमा करें, मैं कुछ पूछना चाहता हूं । मैं हिन्दी अच्छी नहीं जानता हूं (इंटरप्शंज) अगर आप कहें तो मैं बंगला भी बोल सकता हूं । मैं दूसरी जगह नौकरी कर रहा था अभी इसीलिए मैं हाजिर नहीं था । यह कहा गया है कि जो हक मिला वह वही था जो पहले से आ रहा है और अभी भी वही चला आ रहा है । मैंने अपने भाषण में यही कहा था कि पहले जो मन्त्री थे, भूतपूर्व जो मंत्री थे उन्होंने जो कुछ किया उसके जरिये से रेलवे प्रशासन में एक बहुत गलती हो गई, एक भूल हो गई . . .

Sir, if you do not understand I may say it in English. What I sad was that one of his predecessors. . . . .

डा० राम सुभग सिंह : मैं समझ गया हूं ।

Mr. Speaker: He is finding me blank.

Shri Jaipal Singh: What I said was....

Shri Kapur Singh (Ludhiana): His Hindi is charming. Let him continue.

श्री जयपाल सिंह : मैं हिन्दी भक्त नहीं हूं । ग्राप हिन्दुस्तान को बरबाद कर रहे हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : उससे ग्रौर बहस पैदा होगा । ग्राप ग्रपना सवाल करें ।

श्री जयपाल सिंह: जिस भाषा में चाहते हैं मैं बोल देता हूं । ग्रगर मातृ भाषा में बोलूं तो हमारे दोस्त ग्रड़ोस पड़ोस के...

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप सवाल करें ।

श्री जयपाल सिंह : ग्रपने भाषण में रेल मन्त्री, भूतपूर्व रेल मन्त्री जो थे उन्होंने सवाल उठाया था कि सारे जितने हरिजन हैं चाहे वे लायक हों या नालायक हों, ऐसे ही ऊपर ऊपर चढ़ जायें, नौजवान जो हैं ग्रभी वे । यह जो बकवास...

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप यह डैमंस्ट्रेट कर रहे हैं ?

श्री जयपाल सिंह : यह जो भाषण है, इसके बारे में मैं कह रहा हूं । ग्राप जो मुझे परामर्श देंगे मैं वही करूंगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप सवाल करें ।

श्री जयपाल सिंह : जो भूतपूर्व मन्त्री थे उन्होंने यही कहा कि जितने भी हरिजन हैं—ग्रादिवासियों का नाम ही नहीं है —वे ग्रादिवासी नहीं थे, हरिजन थे...

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप नया भाषण दे रहे हैं ? सवाल तो एक दो मिनट में हो जाना चाहिये । ग्रापने सात ग्राठ मिनट ले लिये ।

श्री जयपाल सिंह: मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो सूचना दी है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को वह यह थी कि जो भी हरिजन हैं, चाहे लायक हों या नालायक हों, वे ऐसे ही ऊपर चढ़ जायें, क्या यह सही है ग्रौर यह सवाल ग्रभी तक है या नहीं है ?

Shri Sonavane: Sir, May I seek one clarification Shri Jaipal Singh said only about Scheduled Castes. There are Scheduled Tribes also.

डा० राम सुभग सिंह : खत्म कैसे हो जाएगा ?

यहां यात्रियों की सुविधा के बारे में भी माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है । ग्राडिट रिपोर्ट की ग्रोर इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान ग्राकर्षित किया गया है । पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर भी ध्यान ग्राकर्षित किया गया है । यह कहा गया कि तीन करोड़ रुपये निर्धारित रहते हैं ग्रौर उसका पूरा इस्तेमाल इधर दो तीन पिछले सालों में नहीं हुग्रा है । इस बारे में ग्रभी मैंने मन्त्री महोदय से परामर्श किया है ग्रौर इन्होंने इस बात को मान लिया है कि तीन करोड़ के बजाय चार करोड़ यात्री सुविधाग्रों पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाए । चार करोड़ हमारे पास होगा ग्रौर इसमें से एक भी पैसा बचने न पाये, ऐसी हमारी कोशिश होगी । सारी छोटी ग्रौर बड़ी लाइनें जो हैं इन सब में इसको खर्च किया जाएगा । जहां तक यात्रियों की सुविधा का सवाल है, उनको ग्राराम पहुंचाने का सवाल है तीसरे दर्जे के लोगों की सुविधाग्रों पर विशेष ध्यान रहेगा ।

हमारे शिव नारायण जी ने सिलीगुड़ी लाइन के बारे में कहा है । उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । उसमें कार्य हो रहा है, उसके सुधार के बारे में कार्य हो रहा है ।

हमारे शर्मा जी ने लाइट रेलवे के बारे में कहा है । उन्होंने कहा है कि सर्वे होता है लेकिन बनता नहीं । पता नहीं उनको कहां का ग्रनुभव है ? किस गलत ग्रनुभव के ग्राधार

पर उन्होंने कहा कि सर्वे करा लिया और बना नहीं ? यहां यह नहीं होने को है कि जो कहा जाये वह पूरा न हो। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, ठीक है, क्योंकि भारत में हम लोग चाहेंगे कि यह प्रणाली बने कि जो कुछ हम कहें वह जरूर पूरा हो।

कुछ अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी उन्होंने चर्चा की और रीजनल लैंग्वेज की भी मैं मानता हूं कि अंग्रेजी एक बड़ी विकसित भाषा है। इस की जरूरत है, और जरूरत के अनुसार वह रहेगी, लेकिन यदि सरकार को असली सेवा करनी है तो हमें रीजनल भाषा की ओर मुड़ना पड़ेगा और आम लोगों का, चाहे वह लद्दाख का आदमी हो, चाहे रामेश्वरम् का हो चाहे द्वारका का हो, नेफा नागालैण्ड का आम कार्यकर्त्ता हो, उसके हित का ध्यान हमें रखना होगा और इस दृष्टि से ही यह मन्त्रालय अपने कार्य को बढ़ाने का यत्न करेगा।

श्री बैरवा ने चोरियों की चर्चा की। जहां तक उनके कोटा में स्कूल और पुलिस स्टेशन की बात है, जो दिक्कत है उसको हम दर्याफ्त करेंगे। जहां तक पुलिस स्टेशन का ताल्लुक है, वह कहते हैं कि वहां पर 20, 22 हजार कर्मचारी हैं और चोरियां होती रहती हैं, या दिन दहाड़े महिलाओं का कत्ल होता है, जिसका उन्होंने वर्णन किया, तो यह एक आवश्यक चीज है। आर० पी० एफ० की भी चर्चा की गई। जो दोष हैं उनको मैं पहले ही मानता हूं, लेकिन जो सेवायें इस फोर्स ने की हैं, खास कर इस की स्पेशल इमर्जेन्सी फोर्स ने चाइनीज आक्रमण के जमाने में जो सेवायें की हैं, जिनके सहारे के बिना यह असम्भव होता कि परकंग से लेहे तक सवा तीन किलो-मीटर लम्बी लाइन नई बनाई जा सकती। जिस वक्त सब के मनोबल टूट गये थे, उसको जिन्दा रक्खा, इस क्षेत्र में या और क्षेत्र में, तो उसकी बुराइयों को और जो अच्छे कार्य हैं उनको देख कर, अच्छे कार्यों के दबाव में त्रुटियों को देखने का हम यत्न करें।

श्री भट्टाचार्य ने वेस्ट दीनाजपुर के बारे में बतलाया। वह उनका जिला छूटा जरूर है। उन्होंने फाइलों वगैरह का जिक्र किया। तो फाइलों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं।

श्री दलजीत सिंह ने बस स्टैण्ड की कठि-नाई बतलाई कि होशियारपुर से बहुत दूर है। बैकवर्ड एरियाज की ओर करीब करीब सभी लोगों ने ध्यान दिलाया। श्री नायक ने भी बतलाया दोहद वगैरह की बातें। खास तौर से बस्तर के बारे में श्री वीरप्पा जी ने भी बत-लाया। प्रोफेसर रंगा ने कल कहा था कि जो चर्चा पिछले वर्ष हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई उसे संसद् को बतलाना चाहिये। जो भी सुझाव दिये गये उन सबके जवाब एक पुस्तिका के रूप में तैयार करके लाइब्रेरी में रख दिये गये थे, और इस साल भी हम करेंगे जितने भी सुझाव इस साल दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ दतस्तों ने यह तकलीफ प्रकट की कि यहां पर केवल नकारात्मक उत्तर दिये जाते हैं। रेलवे मन्त्रालय इस में भी समयानुसार तबदीली करेगा। जिस की जितनी जरूरत है, खास कर जनता की जरूरत जिस जगह पर जितनी है उसके अनुसार काम होगा। अगर कालेज और स्कूल बनेंगे रेलवे लाइनों पर, या छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलेंगी और लाखों की आबादी बढ़ेगी तो जरूर सब की सुविधा को देखते हुए जितनी जरूरत होगी हम रेलों को बढ़ायेंगे। जो भी सुझाव आये हैं उनकी बदौलत हमें पूरी जानकारी हुई कि देश का मूड कैसा है। केवल यह संसद् ही एक ऐसा स्थान है जिसमें हर इलाके के लोग अपने अपने इलाके के नेता हैं। इसलिये वे जो भी बातें कहेंगे हम उन की कद्र करेंगे और जो भी गुंजाइश होगी राशियों के अन्तर्गत और उनकी जितनी जरूरत होगी दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का यत्न करेंगे।

अभी यहां ट्रेनों की गति की बातें हुई और नई ट्रेनों के बारे में भी। तो जितने रैक्स

वगैरह उपलब्ध होंगे उन के अनुसार उन को बढ़ाने की बातें होंगी ।

बहुत से सदस्यों ने टाइम टेबल की चर्चा की । टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिसके लिये यहां पर विस्तृत जवाब देना सम्भव नहीं है । वे सारी बातें अलग से देखी जायेंगी ।

अभी बतलाया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में । उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर है, जिस तरह से बतलाया गया । लेकिन अभी सन् 1950 में कांस्टिट्यूशन लागू हुआ है और रेलवे मन्त्रालय के कई मन्त्रियों ने पहले सोच समझ कर कुछ निश्चय लिया । वह निश्चय है । और अभी माननीय सदन में जो भावनायें प्रकट की गई हैं उनके बारे में या और लोगों के बारे में, वे सुझाव भी सामने हैं । उन सारी बातों को देखते हुए जो मुनासिब बात होगी जरूर की जायेगी ।

मैं पुनः सारे सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने एक विश्वास की भावना और एक वातावरण यहां पैदा किया जिससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिला ।

Shri A. P. Sharma: May I ask for clarification?

Mr. Speaker: No Sir. There are so many Members and I cannot give opportunity to all.

Shri A. P. Sharma: The hon. Minister has stated....

Mr Speaker: Even before I have allowed him, he has begun to speak. How can he do that Shri R. S. Pandey.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : चौथी पंचवर्षीय योजना में से रेल के विस्तार के लिये अनुमानित राशि से 182 करोड़ रुपये काट दिये गये और केवल 40 करोड़ रुपया स्वीकार किया गया । इस अनुदान से चौथी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में जो विस्तार हम रेलवे का करना चाहते थे वह अब नहीं कर सकेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय ने क्या किया ।

श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) : अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ और उसके सम्बन्ध में यहां पर कुछ सदस्यों ने जो विचार प्रकट किया, उसको देखते हुए इस फैसले के ऊपर पुनः विचार होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : पुनः नहीं कहा ।

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या मैं यह समझ सकता हूं जो नीति इसके पूर्व अपनाई गई थी उसमें परिवर्तन करने का इरादा सरकार का है ।

Shri N. R. Laskar (Karimganj): The hon. Minister has not referred to any thing about introduction of a Janta Express in N. F. Railway

अध्यक्ष महोदय : जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में वह रक्खेंगे उसे आप पढ़ लें ।

Shri Narendra Singh Mahida: Regarding the East African ex-railway employees I want to know whether they will be re-employed here or not.

अध्यक्ष महोदय : जो जवाब में नहीं कहा गया उसके बारे में यहां क्या कहा जा सकता है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : संविधान के अनुसार 18 प्रतिशत रिजर्वेशन है सीटों में । मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा जब तक आप फर्स्ट क्लास, सेकेण्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में रिजर्वेशन को पूरा कर लेंगे ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद से हृयनी लाइन पर गोविन्दपुर का स्टेशन जो पांच साल से बन्द पड़ा हुआ है वहां पर गाड़ी क्यों नहीं खड़ी होती ।

अध्यक्ष महोदय : गाड़ी न खड़ी होने का क्लैरीफिकेशन क्या दिया जा सकता है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : पाटिल साहब ने परसों कहा कि हमें 500 कीलो मीटर नई लाईन बनाना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अजमेर की लाइन का भी इसमें ख्याल किया जायेगा ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि जांच कराई गई है और नार्दर्न रेलवे में कैजुअल लेबरर्स को 2 रु० से कम कहीं नहीं दिया जा रहा है । तो क्या यह मान लिया जाये कि कैजुअल लेबरर्स को 2 रु० से कम नहीं दिया जायेगा ।

Shri Priya Gupta (Katihar): May I ask one question?

Mr. Speaker: Has he spoken during the debate?

Shri Priya Gupta: That criterion never arose when you gave Members permission to ask question. In fact, I spoke in the debate.

टाइडल वेव से रामेश्वरम सेतु बह गया । आपने तय कर लिया है कि इसमें जुडिशल एन्क्वायरी नहीं होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप खुद इस की समीक्षा और परीक्षा कर चुके हैं कि रेलवे की तरफ से रेलवे के मजदूरों ने नोटिस दिया था कि उस वक्त उस तरफ गाड़ी जाना खतरनाक है । आपने इस बात को एग्जामिन किया है या नहीं ।

16 hrs.

डा० राम सुभग सिंह : अभी शर्मा जी ने कैजुअल लेबर के बारे में कहा । मैंने कहा था कि नारदर्न रेलवे से और तीन रेलवेज से पूछा गया था । उन्होंने बताया कि दो रुपया से कम नहीं है । जैसा मैंने पहले कहा था, वेजेज़ ऐक्ट को देख कर और दूसरी जगहों पर जो स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करके जो उनके हित में होगा किया जाएगा ।

जहां तक गोविन्द पुर स्टेशन की बात है, इसका मुझे पता नहीं है, पता लगाया जा सकता है ।

इसी तरह अफ्रीकन लेबर के बारे में महीदा जी ने कहा । जो भारतीय वहां से लौट कर आए हैं उनकी सब बातों का पता लगाने के बाद कुछ बताया जा सकेगा ।

धनुष, कोटि के बारे में प्रिय गुप्ता जी ने कहा । वहां अफसर जांच करने गए थे और मन्त्री महोदय भी गए थे । उन्होंने जांच कर ली है । जुडीशियल एनक्वायरी से कोई फायदा नहीं होगा । जो वहां मौसम की रिपोर्टें ब्राडकास्ट की जाती हैं उनमें टाइडल वेव का कहीं जिक्र नहीं था और वैसी कोई बात नहीं थी ।

बेरवा जी ने जो बात कही उसके बारे में हमने कोई वायदा नहीं किया था । हाउस में जो बातें होती हैं वे लिखी जाती हैं । अभी जो फैसला है वह यह है कि 6 बरस पहले के लोगों को रीन्सटेट किया जाएगा ।

श्री आर० एस० पांडे ने योजना के बारे में सवाल किया, उसके बारे में मन्त्री महोदय बतलाएंगे ।

Mr. Speaker: May I put al lthe cut motions to the vote of the House together?

Some hon. Members: Yes, Sir.

All the cut motions were put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order

[Mr. Speaker]

paper be granterd to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of Demands Nos. 1 to 11, 11A 12 to 16 and 18.'"

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants (Railways) which were adopted by Lok Sabha are reproduced below.—Ed.*)

DEMAND NO. 1—RAILWAY BOARD

"That a sum not exceeding Rs. 1,18,64,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Railway Board.".

DEMAND NO. 2—MISCELLANEOUS EXPENDITURE

"That a sum not exceeding Rs. 3,63,63,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Miscellaneous Expenditure.".

DEMAND NO. 3—PAYMENTS TO WORKED LINES AND OTHERS

"That a sum not exceeding Rs. 34,13,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Payment to Worked Lines and Others.".

DEMAND NO. 4—WORKING EXPENSES—ADMINISTRATION

"That a sum not exceeding Rs. 52,68,93,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966, in respect of Working Expenses—Administration.".

DEMAND NO. 5—WORKING EXPENSES—REPAIRS AND MAINTENANCE

"That a sum not exceeding Rs. 167,73,90,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Repairs and Maintenance.".

DEMAND NO. 6—WORKING EXPENSES—OPERATING STAFF

"That a sum not exceeding Rs. 1,06,78,34,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Operating Staff.".

DEMAND NO. 7—WORKING EXPENSES—OPERATION (FUEL)

"That a sum not exceeding Rs. 107,76,66,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Operation (Fuel).".

DEMAND NO. 8—WORKING EXPENSES—OPERATION OTHER THAN STAFF AND FUEL

"That a sum not exceeding Rs. 32,00,17,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Operation Other than Staff and Fuel."

DEMAND NO. 9—WORKING EXPENSES—MISCELLANEOUS EXPENSES

"That a sum not exceeding Rs. 29,97,17,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Miscellaneous Expenses.".

DEMAND No. 10—WORKING EXPENSES—LABOUR WELFARE

"That a sum not exceeding Rs, 20,17,16,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Labour Welfare.".

DEMAND No. 11—WORKING EXPENSES—APPROPRIATION TO DEPRECIATION RESERVE FUND

"That a sum not exceeding Rs, 85,00,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Appropriation to Depreciation Reserve Fund.".

DEMAND No. 11-A—WORKING EXPENSES—APPROPRIATION TO PENSION FUND

"That a sum not exceeding Rs. 12,10,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Working Expenses—Appropriation to Pension Fund.".

DEMAND No. 12—PAYMENTS TO GENERAL REVENUES

"That a sum not exceeding Rs. 115,90,17,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Payments to General Revenues.".

DEMAND No. 13—OPEN LINE WORKS (REVENUE)

"That a sum not exceeding Rs. 11,00,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966, in respect of Open Line Works (Revenue)."

DEMAND No. 14—CONSTRUCTION OF NEW LINES

"That a sum not exceeding Rs. 65,82,32,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Construction of New Lines.".

DEMAND No. 15—OPEN LINE WORKS—CAPITAL, DEPRECIATION RESERVE FUND AND DEVELOPMENT FUND

"That a sum not exceeding Rs. 519,01,64,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Open Line Works—Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund.".

DEMAND No. 16—PENSIONARY CHARGES—PENSION FUND

"That a sum not exceeding Rs. 3,12,40,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966 in respect of Pensionary Charges—Pension Fund.".

DEMAND No. 18—APPROPRIATION TO DEVELOPMENT FUND

"That a sum not exceeding Rs. 29,23,67,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st of March, 1966, in respect of Appropriation to Development Fund."

16.03 hrs.

MOTION *RE*: HOME MINISTER'S STATEMENT ON ANTI-NATIONAL ACTIVITIES OF PRO-PEKING COMMUNISTS

Mr. Speaker: Now the House will take up the discussion on the Motion of Shri P. K. Deo.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I want to rise on a point of order. I have gone through the Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. But before I do it I would invite your kind attention to page 19 of the statement of our Home Minister under the heading "The parallel party centre and its activities". He has mentioned there......

Mr. Speaker: He has written to me that he is raising it under Direction 115.

Shri S. M. Banerjee: I am coming to that. He has mentioned there:

> "The new party centre which operated from New Delhi under A. K. Gopalan's personal direction became the clearing house for the exchange......"

Mr. Speaker: I must point out to him that he cannot raise it in this manner. If he wanted to point out any discrepancy or inaccuracy in the statement of the Minister....

Shri S. M. Banerjee: I am coming to that.

Mr. Speaker: First I have come to that; therefore, he should listen to me.

Shri S. M. Banerjee: I have already mention it.

Mr. Speaker: He would not listen to me! He has written to me that he wants to raise a point of order under Direction 115(1) and (2). Is that all that he has written to me or is there anything else also?

Shri S. M. Banerjee: This is all. In support of that I will quote......

Mr. Speaker: No. He ought to have written to me what inaccuracy is there, what is the statement that has been made and what is the correct thing.

Shri S. M. Banerjee: Kindly bear with me; otherwise, how do you know......

Mr. Speaker: No, This is the Direction.

Shri S. M. Banerjee: Do you consider that there are no inaccuracies in the statement? You allow me....

Mr. Speaker: Shri Banerjee is a seasoned parliamentarian. He is pointing out to me Direction 115. He should kindly read it.

Shri S. M. Banerjee: I am reading it.

Mr. Speaker: It reads:—

> "A member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister or any other member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and......".

Shri S. M. Banerjee: Exactly.

Mr. Speaker: But he has not pointed that out to me.

Shri S. M. Banerjee: I have not; but I want to raise only that point.

Mr. Speaker: I have not got the particulars. Let him write to me first and then I can allow him.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियम बता दूं ?

Mr. Speaker: Order, order. One hon. Member is already speaking and Shri Madhu Limaye gets up.

श्री मधु लिमये : आपने कहा था बुलाया इसलिए मैंने कहा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बुलाया था ?

श्री मधु लिमये : मैंने समझा कि खत्म हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने कैसे समझ लिया ।

I am just making it very clear that Shri Banerjee has not written to me the particulars of that inaccuracy.

Shri S. M. Banerjee: I am submitting to you why I have not done that.

Mr. Speaker: I cannot hear the "why" at this moment. I cannot allow it at moment Shri Banerjee might raise it at some other time after he has given me the particulars of the inaccuracy.

Shri S. M. Banerjee: I did not give the particulars. I am only raising that on a point of order because of one thing in this......

Mr. Speaker: I cannot allow it. I cannot be taken by surprise.

Shri S. M. Banerjee: There is no question of taking you by surprise. I am not taking you by surprise.

Mr. Speaker: I do not know what he is going to raise. I cannot do that. I am telling him again and again. I cannot do it.

Shri S. M. Banerjee: Kindly hear me.

Mr. Speaker: No. He will kindly resume his seat

Shri S. M. Banerjee: It has been mentioned in the document and we should be given an opportunity.

Mr. Speaker: I have told him thrice to sit down and he will not sit down.

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे कोई इत्तला नहीं दी : व्यवस्था का प्रश्न किस बात पर है ?

श्री मधु लिमये : आपने कहा कि इस प्रस्ताव पर बहस होगी । उसी के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के मुताबिक है ?

श्री मधु लिमये : नियम 186 तथा 337 ।

मैं विशेषकर आप का ध्यान नियम 186 की दूसरी धारा की ओर खींचना चाहूंगा जहां कहा गया है :

"उस में प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे, "

इसी प्रकार नियम 337 में लिखा है :

"यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वा वाक्यांश या पद हैं जो प्रतर्कात्मक, असंसदीय, व्यांगात्मक, असंगत, आडम्बरपूर्न या अन्यथा अनुसूचित हों, तो वह , स्वविवेक से, ऐसी सूचना में, परिचालित किए जाने से पूर्व संशोधन कर सकेगा ।"

अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि मेरा भी नाम इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है और मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । शायद आप का ध्यान इस बात की ओर न गया हो इसलिए दिला देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान चला गया है । उस के बारे में कोई बहस करने की जरूरत नहीं । आप का नाम भी इस में है और फिर भी आप यह सवाल उठा रहे हैं । आप अपनी बात कहिए ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो प्रस्ताव दिया था, हो सकता है कि मैं ने बाद में दिया इसलिए जो पहले आया उसको पहले लिया गया है, मुझे याद है कि उसमें मैं ने लिखा था कि :

"कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी और उस पर गृह मंत्री का बयान" लेकिन जिस शक्ल में यह प्रस्ताव हमारे सामने आया

[श्री मधु लिमये]

है उसमें 'कुछ अभियोग लगाए गए हैं। एक अभियोग है :

पीकिंग समर्थक साम्यवादी :

दूसरा अभियोग है :

राष्ट्र विरोधी कारवाइयां ।

तीसरा आरोप है तोड़फोड़ का और चौथा आरोप है हिंसात्मक कार्यवाही की तैयारी । अब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव में यह संशोधन किया जाय और इस रूप में उस को रखा जाय कि कम्युनिस्ट नजरबन्दों की गिरफ्तारी और गृह-मंत्री का उसके ऊपर बयान जोकि 18 फरवरी 1965 को सभा की टेबुल पर रक्खा गया था क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मत है । हो सकता है कि कुछ लोग उस से सहमत हों और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग उस से सहमत न हों इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव में वह न आये ....

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । मैंने माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया । जब श्री पी० के० देव स्टेटमैंट कर रहे थे कि उस पर बहस हो तो उन के जो शब्द हैं वे मंत्री जी के जो उनकी हैडिंग और टाइटल हैं स्टेटमैंट की उसी को वह कोट कर रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज या कोई आरोप नहीं लगाया था ।

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय वह..........

अध्यक्ष महोदय : बस और नहीं ।

श्री मधु लिमये : उसमें कोटेशन मार्क नहीं था

अध्यक्ष महोदय : अब इस तरह से बहस नहीं चला सकते । आपने जो कुछ कहना था कह दिया है बाकी फैसला मुझे देना है । अब आप क्यों बारबार खड़े होते हैं ।

श्री मधु लिमये : एक ही बात याद रक्खी जाय कि उस में कोटेशन मार्क नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट ग्रोफ आर्डर नहीं है । उस स्टेटमैंट की जो हैडिंग में दिया हुआ है वह ही यहां पर उन्होंने दिया है ।

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Mr. Speaker, Sir, I beg to move....

श्री मधु लिमये : मैं ने कहा तो है कि उसमें कोटेशन मार्क नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय : जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं आप हमें इस तरह से डांट करके रोक देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से बारबार मना करने पर भी बहस चलाये ही जा रहे हैं और मदाखलत कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं कोई बेकार में तो मदाखलत कर नहीं रहा हूं । मेरा तो केवल यह निवेदन है कि उस पर उद्धरण चिन्ह लगाया जाय कोटेशन मार्क लगाया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : कोटेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है । मेरा ख़याल है अब आप मुझे कार्यवाही शुरू करने देंगे और मदाख़लत नहीं करेंगे ।

मैं समझता हूं कि श्री पी०के० देव के लिए पन्द्रह मिनट का समय काफी होगा । दो घंटे का समय है और इसमें दस, बारह आदमियों को बुलना है ।

Shri P. K. Deo: Half an hour. It is an important debate. We may extend the time, if necessary.

अध्यक्ष महोदय : सब को तो मैं तब भी वक्त नहीं दे सकूंगा अगर बहुत से लोग बोलना चाहेंगे । मेरा खयाल है कि आप पन्द्रह मिनट में खत्म करने की कोशिश करें बाकी लोग दस, दस मिनट लें ले तो ठीक होगा ।

Shri P. K. Deo: It is an important debate.

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बात है श्र. प० के० देव बीस मिनट ले लें ।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): I also request that some more time be given.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है वे बीस मिनट ले लें ।

Shri P. K. Deo: Sir, I beg to move:

> "That this House takes note of the statement of the Minister of Home Affairs on the anti-national activities of pro-Peking Communists and their preparations for subversion and violence, laid on the Table of the House on the 18th February, 1965."

In this country's history we come across individuals like Jaychandra, Mir Kasim and Mirjafar, who have not only betrayed the cause of the country by their treachey and treason but have brought foreign enemy to this mother land and have changed the course of history.

Shri Abdul Ghani Goni (Jammu and Kashmir): He has made a wrong statement. It was only Mirjafar and not Mir. Kasim. (*Interruption*).

Mr. Speaker: If there is a mistake, that might be corrected.

Shri P. K. Deo: If there is any error, that might be corrected.

Mr. Speaker: It is a *bona fide* error He has mentioned that name wrongly.

Shri P. K. Deo: We expected a fully documented White Paper and we expected that this paper will throw some light as to from where large amounts of funds are coming for the pro-Peking Communists. We thought that this document will throw some light regarding the Bank of China affair and the circumstances under which the Indonesian Consulate had to be closed. It has not thrown any light on these things. But at the same time I take the opportunity to congratulate the hon. Home Minister for his bold statement in this grey paper which has completely exposed the sinister design of those misguided men who did not mind to barter away this country's independence, security and honour to the enemy for their personal and party interest.

Since last six years, we have been pressing constantly from these benches that the Government should ban this party with extra-territorial loyalty who always look to Russia and China for their inspiration and finance. But all these words have fallen on deaf ears. Even though the Government realised it, they could not act because of influence and pull of the crypto-communist and fellow travellers inside the ruling party.

On the 12th September, 1959, when the discussion on the first White Paper on Chinese aggression took place in this House, which I had the privilege to initiate, I gave a note of caution to the Government to look at the coming events with eyes wide open. The words of Mr. Dange still ring in my ears when he said:

> "Communist Party firmly believes that there will be no invasion from China over this country. I guarantee that there will be no invasion as far as China is concerned. I cannot talk of others."

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): There is no invasion; it is only aggression.

Shri P. K. Deo: The time has unfolded: Who is right? Even though some of the leaders of the Communist Party may swear by the Amritsar Congress declaration which envisaged a peaceful parliamentary transition to socialism, important leaders like Ranadive, Muzzaffar Ahmed, Harekrishna Koner, Pramod Das Gupta and others came in their true colour in criticising the so-called peaceful evolution stand as nonsense and advocated the path to be followed, set out, by the Chinese in the Peking Review No. 17 of 24th June, 1958:

> "Through revolution in one form or another, the working class must smash the bourgeois state apparatus and replace the bourgeois dictatorship by proletariat dictatorship."

In the critque of the gatha, Mr. Marx writes in 1857:

> "Between capitalism and communist society lies the period of the revolutionary transformation of one to the other. This corresponds to the period of political transition when the State can be nothing but revolutionary dictatorship of the proletariat."

Lenin in his "State and Revolution" states:

> "Dictatorship of the proletariat is the rule unrestricted by law and based on force of the proletarian over the bourgeois."

Sir, these writings from Marx or Lenin......

Shri Daji (Indore): This is called the devil quoting the scriptures. (*Interruption*).

Shri Kapur Singh (Ludhiana): He has called the Member who is speaking as a devil. I do not think it is parliamentary.

Mr. Speaker: For the last few days I have really been very much distressed to see how things have been proceeding. If noise takes the place of argument, then that will be the end of democracy. The House itself should be mindful of its reputation. So far we have created an impression that there is some parliamentary democracy which is prevailing in India.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): नन्दा साहब ने उस को खत्म कर दिया ।

Mr. Speaker: I would request the hon. Members to listen with patience however unpalatable the arguments might be. Arguments should be countered with arguments and not with other demonstrations.

Shri Daji: In regard to the observation which has been made......

Mr. Speaker: He will kindly sit down. Now he will hear........

Shri Daji: I want your guidance.

Mr. Speaker: Order, order.

Shri P. K. Deo: I want to point out communist is like *The Bible* to a that the writing of these men to a Christian. The communists follow but one principle and that is the principle of opportunism, and opportunism has but one principle that it follows no principle Only expediency has determined their course of action and nothing else and by this method Mr. Churchill had said 'Never so few people ruled so many'. In September, 1959, they championed the Chinese cause and described the MacMahon line as a fraud and accused India of aggression.

Shri Kapur Singh: Shame!

Shri P. K. Deo: We also saw that if there was a conflict between national interest and party interest, Mr. Ranadive had advised that they should not take an unprincipled stand saying "that they should not defend the country against Chinese aggression and give up internationalism'. Internationalism seems to be their creed. It does not confine itself to national boundaries or look after national interests.

When there was Chinese aggression and forceful occupation of 12,000

square miles of our territory, and when there was the cold-blooded massacre of our policemen in the Hot Springs in 1959, the *New Age* monthly tried to justify those actions by quoting the Chinese Prime Minister's letter. We persistently demanded at that time from this side that the Communist Party should be banned

Shri Jaipal Singh (Ranchi-West): Why?

Shri P. K. Deo: They fooled the Government, one section supporting the Government and the other section opposing the Government. Government are in the habit of not realising the realities. They saw the situation through the wrong end of the telescope. That was so because inside the Cabinet, the dice were loaded in favour of the communists because of the presence of fellow-travellers in the Cabinet, because at that time the Defence Minister was toasting *'Hindi Cheeni Bhai-Bhai'* with his Chinese counterpart.

Now, the cat has come out of the bag, and already when the communists were knocking at our door, India's sensitive and palpable border was exposed to communist infiltration and subversion. To exploit the economic distress and ignorance of the hill people in that area, our friends were active giving a rosy picture of China, as if the world did not know that there was large-scale famine and slavery of the worst type parpetuated there. And this whispering campaign and subversive propaganda was going on in full swing in Darjeeling and the Kumaon Hills which are the main recruiting centres of the country. All the official organs of the Communist Party have been supporting this move. Mr. Mao's picture, the picture of one whose hand has been tainted with Indian blood was conspicuously displayed at the communist party conferences at Bagdogra, Guntur, Bombay city, and Berhampore. Even in the Punjab where this picture was not displayed our friend Surjit says that even though the picture was not displayed the picture had been engraved in their hearts.

Shri M. R. Masani (Rajkot): Shame!

Shri P. K. Deo: Their anti-national character is evident from this that their activities had culminated in the rejoicing and the thundering cheers at the West Bengal Conference when Shri Basavapunnaiah announced that China had exploded a nuclear bomb. In 1948, at the call of Mr. Stalin that there should be communist uprising in Asia, our friends started the uprising here and the Telengana movement gathered momentum. I do not want to repeat the grim trail of death and destruction left by the communists in the years 1948-51 in Telengana which they wanted to convert as the Yenan Province in China to be a springboard to overthrow the Government of India by violent revolution. The cult of acid bulb and guerilla struggle advocated by Mr. Mao was fully employed. But the Telengana revolution misfired due to the firm dealing by Sardar Vallabhbhai Patel. They want to repeat the same thing now. There has been a striking similarity in their *modus operandi* at this moment. That is because the external security of the country is being threatened by the presence of a ruthlesss and a heavily armed neighbour like China at the northern border, who will provide a hinterland and a powerful base for their logistic and ultimate success, if they want to overthrow the Government by revolution.

Inside the country, there have been rising prices, food shortage, corruption and sheltering of corrupt men by Government, and lastly, the presence of a powerful communist lobby inside the Congress, which is ideally suited for the launching of this violent struggle. There has been infiltration inside the Government. In this regard, I would like to point out that the various policies of Government, for which I hold the Government responsible, have led to this situation. This would not have happened if they had listen-

[Shri P. K. Deo]

ed to wise counsel, if they had banned the Government at the right time....

Mr. Speaker: Banned the Government?

Shri P. K. Deo: I am sorry—banned the Communist Party. They should have banned the Communist Party at the right time. Instead, they allowed them to function as a party. They allowed them to contest the election in Kerala. It is a wonder how they allowed a party which does not believe in democracy to function in this way. Their definition of democracy is a one-party government. When the Communist party, somehow or other steps into power, they never quit it in favour of any other party. This is their conception of democracy and this is their state of affairs. But that party has been allowed to function in this country, and now we are to face the music!

Lastly, by the detention of the communists on the eve of the Kerala elections a halo of martyrdom was provided to them. Otherwise, they would never have been returned as the single largest party in those elections.

An hon. Member: How does he know?

Shri P. K. Deo: This is due to the folly of Government. We do not want that anybody should be detained under the Defence of India Rules or that emergency powers should be used for the detention of any individual. Whether he is Sheikh Abdullah or he is my friend, Shri Gopalan, he should be properly tried in a court of law. If the hand of law is not long enough to deal with these people properly, amend the law. We are prepared to support it. Even in the case of the DMK, we went to the extend of amending the Constitution to regulate their activities. To bring to book these communists, if any amendment of the law is required, the Government should come out with concrete proposals and they will get our full support.

A word regarding the Rightist communists. As a result of the world communist ideological conflict, there have been two groups, and there have been two groups in all the satellite states.

Shri Daji: In all parties (*Interruptions*).

Shri P. K. Deo: I am sure if China and Russia join hands tomorrow, these two parties will immediately form into one party. There is no doubt about it (*Interruption*). There is no patriotic urge. It is only a reflection of some difference of opinion between Russia and China. Their support to the Government in this struggle against China is only strategic, to camouflage their real intentions. This reminds me of the Siamese twins; if one is beaten, the other at once cries. Similarly, it is very difficult to distinguish between these two, the invisible and imaginary line between these two. It is like the difference between "investigation" and "inquiry".

I warn Government to be more careful regarding the crypto-communists inside the ruling party. They have infiltrated into the Congress.

Shri Daji: Who?

Shri P. K. Deo: In my own State, I know so many communists have joined Congress ranks and are in the payroll of the Kalinga empire of Biju and Biren Mitra. If you want, I can name them....

Mr. Speaker: Order, order.

Shri P. K. Deo: The sapling of democracy has yet to take firm roots in our country. We cannot afford the luxury of allowing the saboteurs of democracy to function in this way.

Shrimati Renu Chakravartty: May I say that when this particular allegation has been made about Communists in Orissa being in the pay of

Shri Biju Patnaik he should produce some proof? We must know it. He has no right to say it. He should substantiate these things.

Mr. Speaker: Motion moved:

"That this House takes note of the statement of the Minister of Home Affairs on the anti-national activities of pro-Peking communists and their preparations for subversion and violence, laid on the Table of the House on the 18th February, 1965."

I had asked the Mover to take 15 minutes, and he has taken quite 15. Other Members should be equally careful. Shri Mukerjee.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On the adjournment motion on the language issue we sat till 7.15. Let us now sit longer.

Shri S. M. Banerjee: We will sit till 7 o'clock if you allow us.

Shri Jaipal Singh *rose*—

Mr. Speaker: I have called Shri Mukerjee.

Shri Jaipal Singh: I am rising on a point of order, if you do not mind.

Mr. Speaker: What is the rule under which he is raising it?

Shri Jaipal Singh: I am sorry I have not got the Rules book here. You must give me some indulgence.

Shrimati Renu Chakravartty has raised a point of order which is eternal in parliamentary practice, that is to say, no one can be criticised who is not here unless there is evidence. I am not a Communist, I will never be a Communist, despite the charm that Shrimati Renu Chakravartty and Shri Mukerjee may have, but the point is that certain things have been cited by the Maharaja of Kalahandi. Unless the people are there to defend themselves, or the Treasury Benches defend them,—they might, they have been doing that all along—we must have evidence. An hon. Member of Parliament has no business to mention in this House anything unless we have evidence.

Mr. Speaker: I am not going into that evidence. He only said that some Communists were in the pay roll. He has not named those Communists, and I have not allowed. Such a statement can be made.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta-Central): In his delightful innocence of political thought and of history, Shri Deo has given us a delectable mishmash of ignorance and malice, and I congratulate Shri Nanda for having at least converted one super-enthusiast advocate for the cause which he has propounded before us.

An hon. Member: Not one, many.

Shri H. N. Mukerjee: I have very little time. I am afraid I shall ignore much of what he has said, particularly regarding some of our people being saboteurs of democracy and that sort of thing. I will treat that kind of accusation with the contempt which it deserves.

The Home Minister has placed before us not a White Paper, but a dark and dismal document which seeks to justify the indefensible detention without trial of nearly a thousand Left Communists on grounds that, as he has propounded them, do not stand a moment's scrutiny. In the process, the Home Minister has dealt a blow to the parliamentary ideas that we have inherited, to which I shall refer in the beginning.

Parliamentary life involves the principle, as Sir Erskine May has pointed out, that service in Parliament is paramount to all other claims. But nearly all Members of a recognised group in this House, including Shri A. K. Gopalan, whose seat is here unoccupied by him, are prevented from performing their service to this House indefinitely and

[Shri H. N. Mukerjee]

by virtue of executive action, executive action stealthily decided upon even before the last session of Parliament was over, and this has distorted the picture of this House as portrayed by your recognition of different political trends in the country. Our friend Shri A. K. Gopalan is being dubbed as a pro-Peking Communist and as an anti-national individual, virtually a traitor to India, and he cannot even come here to face his accusers.

I want to know what is happening in this country. Is there a war being fought on our soil? Is Shri Nanda running a revolution which requires a certain amount of authoritarian decision? No. Shri Nanda and his friends are too busy looking after— I borrow Shri Deo's expression—the Siamese twins of Orissa's politics and other proteges of that unspeakable sort. They are too busy using the Defence of India orders putting in prison our people—the Secretary of my State Committee in Orissa, for example, and so many PSP workers at the time of the agitation in Orissa.

He is too busy doing that sort of thing. And lately he has taken recourse to political vendetta which has landed him into producing this wonderful document. This document makes it clear that the notion of the overriding menace from left communists is a hoax, a hoax intended to camouflage the anti-democratic aims, a political ritual designed especially to alarm the Kerala electorate to vote for the Congress, a plan that has boomeranged on the ruling party. Obviously the people of Kerala did not believe what the Government wanted them to believe about the left communists. Shri Nanda said at a press conference that he was giving the people of Kerala a chance to reject them and the people of Kerala gave him a fitting reply by sending these communists as a single majority group. Mr. Nanda is trying to take recourse to some manipulation of figures regarding the percentage of the vote. I have seen a statement by Mr. E. M. S. Namboodiripad contesting the claim of Mr. Nanda regarding the percentage of votes cast in favour of the Congress or of left communists. Very amazing. It is a futile controversy. In the Lok Sabha the Congress has a massive majority on the basis of a minority vote. Why this double standard talk is being indulged in, I do not understand.

But, Sir, to come back to fundamentals. Detention without trial, as even my ingenous friend Mr. Deo was constrained to point out, violates every decent democratic instinct. In the *Liversidge* case during the Second World War, the British Judge said how even in the clash of arms the laws of England are not silent. The Government knows that there is the Supreme Court judgment hanging like the sword of Damocles over its head, the judgment which said that in passing the Defence of India Act, Parliament has disregarded the constitutional provisions of articles 14 and 22, that when the Presidential Order under article 359 ceases to be operative, as it must, sometime or the other, the infringement of citizenship rights caused thereby can be challenged in courts of law, that after the Emergency is lifted the executive would remain liable for wrongful detention. We know that the Government had made an effort to amend the Constitution and to avoid the effects of this judgment but that effort has misfired so far. What other mischievous moves are in contemplation, I do not know.

And meanwhile, in the name of emergency which has become in the minds of the people little more than a fake, in the name of emergency which helps to prop up the structure

of an administration which has proved itself inefficient and corrupt and a moral blight on this country, political repression is being practised by the Government in power. In particular, it has happened in Kerala, where the name of the Congress is mud and people have returned the left communists as the largest single party. Therefore, they are entitled in all propriety to be called to form the State Ministry. I have got a copy of a telegram from Mr. Namboodiripad. He says that he has sent a telegram to the Prime Minister and the President asking for facilities so that the members elected and the members of the State Committee of his party are released and they could hold consultations just as the syndicate in Congress and so many other people hold consultations in regard to their parliamentary programme. But of course nothing is being done about it.

Sir, in this country we see most wonderful things. I am very sorry to say this, but I have to say it because it is my country. Indian nationals spying for Pakistan are caught napping in the very act and are prosecuted in court. It is a good thing they are prosecuted in court. But in the case of these people, not one single case of prosecution is there. What I see is this. Political personalities, whether it is Chakravarti Rajagopalachari or Jaiprakash Narayan or lesser people who sometimes lurk in this august House also, have been openly suggesting the giving over of Indian territories to Pakistan. or trickling down to rebel claims to Nagaland, and nothing is done in regard to that. But as far as the left Communists are concerned, not a single step is taken except that of putting them in jail and having no kind of trial about it.

If over the India-China issue anyone violates the country's interests, hold him up by all means, but do not just call left Communists pro-Peking, give them a bad name and hang them. One of their leaders, Shri Jyoti Basu, has said that his party says nothing more in relation to the Colombo proposals—I have got his statement here—than what has been said by Congress M.Ps.,—among them my hon. friend Shri Khadilkar over there—and the statements which have been made by the Prime Minister himself in regard to the settlement of the India-China issue. This is what has happened.

Shri Nanda's perfervid eloquence before a very safe microphone in All India Radio did not prevent even the *Hindustan Times* of the 6th January speaking of—I am quoting—"...the startling degree of disbelief in the case he has put forward". It further states that "the Government seem to have acted primarily to divert attention from the worsening food and price situation and secondly to evade the imminent Congress debacle in the elections in Kerala." Since then the debacle has taken place and the Government continues in its course of self-righteous arrogance. I am reminded of what Dean Swift once said: "I never wonder to see men wicked: I often wonder not to see them ashamed." Perhaps the Government tries to wear today the mask of pride but its true name is fear.

Is there any proof in this document of imminent danger on account of left Communists to peace and tranquillity or to the security of our country? There is none. If Government has other material, they should not be kept up its sleeves but it should utilise them for prosecutions if they dare to launch them before courts of law. Till such material is brought out and examined, this document is no more than a scrap of paper, except for those who have got to say 'yes' to Shri Nanda and also to some who are blinded by the anti-Communist prejudice. This document will convince nobody who has got a head over his shoulder.

We have our differences, very serious and basic differences, with left Communists who have broken away from the party and formed their sepa-

[Shri H. N. Mukerjee]

rate organisation, but with all our strength, we condemn this flagrant misuse of power against them; we condemn this attack on a political group merely because of its ideological predilections. Those of its leaders who have not been arrested, like Shri Namboodiripad or Shri Jyoti Basu, have challenged the Government to prove one act—one overt or covert act—over the India-China issue. It is not for us to answer the allegations which Government have put in so vaguely. These two gentlemen, Shri Namboodiripad and Shri Basu, have sought to do it to the extent possible.

For instance, Shri Nanda has mentioned the visit to Himachal Pradesh by four Bengal Communists. One of them did not go. They had gone to a celebration, to the Ghadar party, in Jullundur at Bhagat Singh's birthplace. One of them had not gone to Himachal Pradesh. The other three went to Himachal Pradesh, because many people—the Home Minister also—want sometimes to see a very beautiul place. Shri Ramamurthi, a Member of the upper House, went to Himachal Pradesh and it is mentioned here as if he was conspiring with people near the border. Is it open to Shri Nanda to appear to claim that Members of Parliament even, let alone other citizens of this country, cannot go to those places merely because they are very near the frontier and if only they go there, they are going to be hauled up on this kind of suspicion which is not only misdirected, but utterly frivolous and absolutely ridiculous? This is the sort of thing which he is doing.

Shri Jyoti Basu has said repeatedly that there are allegations of propaganda in Darjeeling and other districts of West Bengal and that these allegations are completely false and he has challenged this Government to produce some proof.

Shri Nanda has referred to a meeting, a demonstration, in Trivandrum where most objectionable slogans were supposed to have been shouted, and Shri Namboodiripad has given a statement to the press that if these slogans were shouted, it is a most terrible thing and he does not surely approve of them, but he knows that these slogans were not shouted because, if they were in a town like Trivandrum, the matter could easily be brought to court.

Then again, Sir, Shri Nanda talks about monies coming from certain quarters, especially from China, to the Left Communists, which has throughout put this party of Pro-Peking Communists in large funds through various clandestine channels. I have been shouting myself hoarse in this House trying to find out who exactly is getting money through the Bank of China. I heard my friend, Shri Dwivedy, referring to certain people, mentioning their names and telling the Government that these were the people who were getting money from the Bank of China. They never said a word about it. On the other hand, I find, in the West Bengal Legislative Council, a member of Shri Tridib Kumar Chaudhuri's party, not a member of our party, placed on the Table of the West Bengal Legislative Council, a whole statement which he had collected, which he certified, which he vouched for, mentioning the names of Congress supporters who had got overdrafts from the Bank of China—like Surajmal Nagarmal, Gian and Sons, Krishna Lal Birani and Co., Rajkumar, Proprietor of Khemchand Rajkumar, Mahanti Corporation, Ray and Sons who are Andamans timber contractors for the Government of India and some other people including a member of the Rajya Sabha who has been welcomed with open arms by the Congress Party and taken in as a member of the Congress Parliamentary Party in the Rajya Sabha. So this matter could be pursued. I want to find out for myself as well as for other people in my party what is the truth of the matter. Shri Jyoti Basu himself has said: "I deny this allega-

tion regarding monies from the Bank of China and challenge the Home Minister to prove his contention." If it is proved, naturally we have to accept it as a fact. But the position at present is that no proof is forthcoming and this kind of allegation is thrown in the air, this kind of kite-flying goes on, so that mud can be thrown at certain people, so that this party may be maligned in the very cheap and malicious manner in which the Swatantra Party tries to indulge in that kind of activity.

In this document of Shri Nanda there is no proof of Left Communists endangering India's internal and external security except very vague allegations regarding what they may be contemplating or what they might be doing. Shri Jyoti Basu has said that if they have planned or are planning an internal revolt to synchronise with a fresh Chinese attack, let them be tried. He has said openly in public "let them be shot, whoever is trying to do that kind of thing in this country, whoever is trying to synchronise trouble in this country with an attack from the side of China". He has said that they should be tried straightaway and shot. If you can do it, certainly it would be an act necessary in the interests of the country. But before you have got the proofs, before Government has got the guts to place some evidence before the country, before Government can at least make one test case in order to show its *bona fides*, this kind of accusation is political chicanery of a sort which I hate to characterise.

Shri Nanda speaks of reliable information which has come to him in the last two months. If they are reliable, test it in a court of law at least in a few cases. If Government cannot do it, let them not smear so many people with slander and stow them away in jail without trial. I know some people like my friends of the Swatantra Party are very happy. They want to go further and ban the Communist Party, to smash the Communist movement; exploiting the opportunity now that the party has split. They are welcome to their hopes.

For over a hundred years this spectre of Communism has haunted some people. But Communism advances in step with history, and whatever the obstacles today, in this country or elsewhere, as sure as the sun will rise tomorrow, a socialist society will be achieved everywhere, including in my country. Meanwhile, the Government do not seem to know that the right of every Indian to his fundamental liberties is wrapped up in the very constitutional bundle and if in fear of Communism that bundle is thrown out protection for the liberties of our citizen will be cast aside. Let Shri Deo have his moments of elation over Government's action against Communists. But let him remember that when the bell of repression tolls, it also tolls for thee of the Swatantra party!

Mr. Speaker: He should conclude now.

Shri H. N. Mukerjee: I am concluding.

Shri Nanda says that he had to make a "very disagreeable decision." Since the document offers no tangible justification, it is a sickening document which makes a mockery of all talk of political democracy. On the flimsiest of evidence Government hauls up a whole section of the Indian Left on the plea that they are anti-national These are antics of the Government which does not quite know what it is doing unless, of course, astrologers and soothsayers have taken over the reins. For Heaven's sake, I ask the Government, behave with decency and understanding; release the detenus; let the Left Communists be free to form a government in Kerala, if they can, and let some fresh air come and clean up the stink that from Orissa to Kerala pervades our politics today.

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Mr. Speaker, Sir, the document placed on the Table of the House by the Home Minister makes a really revealing study. Professor Hiren Mukerjee was pleased to ask if there is a war going on. He should know that there is really a war going on between India and China. Although it is not being fought at present, the war is very much present, and the people who are put behind the bars by Government, and rightly so, are the agents of China and they are the proved agents of China. We do not need any further proof than are given in the document by the Government.

Really one wonders at the forbearance and tolerance shown by this Government towards these modern traitors and Quizzlings and it is actually late in the day to put them in the jails. One really wonders why they were released earlier. After the Chinese invasion they were arrested and kept in jail for some time. In fact, they should have been kept in detention until the Chinese aggression was removed from our borders, from our motherland. Unfortunately, the democratic instincts in our leaders, particularly in our Home Minister, are too strong. We do not relish the idea of keepink anybody behind the bars. Probably because of this, the Home Minister released these traitors and Quizzlings and put them again to action. But they could not be left out for long. They began to indulge in their nefarious activities and even when such activities came to the notice of Government, they still hesitated in putting them behind the bars by taking action against them.

Really, the late arrest of these Communists gave them some advantage in Kerala, to which Shri P. K. Deo has already referred. I am sure the Government will not be taken in by all these protestations that are being made here by the Right Communists. I need not describe the Right Communists or what they are. They have been amply described by their Left comrades how they are and what they are. I can quote from a document that the Left Communists have circulated in Kerala, and this is what they consider Professor Hiren Mukerjee and his party to be:

> "The people of Kerala are not deceived by these renegade Communists who have provided cover for the large-scale attack by the Indian troops against Chinese troops."

So, according to the Left Communists those people are the renegades. We need not go into the details of what they are.

I must congratulate the Government on the very swift and very secret sweep they made on these traitors in our country. It speaks very well of the organisation of the Home Ministry and its grasp over the affairs of the country. I would warn the Government that they should not consider these wolves to be democrats when they talk of elections and forming a Government in Kerala or when they talk of democracy. The document placed on the Table of the House by the Home Minister gives only a small part of the evidence that is in the possession of the Government. It is said so by the preface of the Home Minister. Even then, it is such damaging revelation that we can ask the Government to set up a special tribunal by a special Act of Parliament and try these people as the Nazi war criminals were tried after the Second World War. They could be tried by a special Act and a special tribunal. We do not fight shy of trying these people. I am quite sure that all these allegations against the traitors can be easily proved.

I need not quote a good deal of it, but I will quote a few instances which are given in this document and where their faith in violence is amply prov-

ed. The document referring to that on page 29 says:—

"With reference to the Indian situation, it added:

'Democracy in our country is recently introduced and deep roots have not yet been struck by it. The working class and other mass organizations have not been united and powerfully built; the Communist Party in itself is very weak; most the parties either of the Left or the Right category in the country are rabidly anti-communist . . . The bureaucracy and the armed forces are strictly kept in isolation from any impact of political and social activities. To be more plain, it is sought to be maintained more as a mercenary type as in the former British days. In the face of all this reality, to talk of the peaceful path in our country more or less as a fact of reality as an inevitable path, is nothing but self-deception and deception of others'.".

Another elaboration of this attitude is given on page 34 of this document. At a press interview given by Mr. Basavapunnaiah in Calcutta on November 8, when he was questioned by pressmen, he said about the equivocal nature of the resolution which they passed at their Calcutta conference that they were not in a position to come out openly with their stand on the border dispute because of the Defence of India Rules. So, they always keep the people and the Government in the dark and try to mislead them. Still, whatever they said in public has put them in very unfavourable light and has proved their unfaithfulness to the country.

The mouthpiece of the Tamilnad Communist Party, which is known as *Sengodi*, says in an editorial:—

"Our slogan is the lesson taught by Lenin that there is no revolutionary party, if there is no revolutionary idea."

They say—

"Our aim is to follow the path shown by Castro of Cuba".

They want to initiate in this country the same kind of bloody revolution as was initiated by Castro.

The demand for the release of the elected detenus in Kerala is very funny in my opinion. This is particularly so with reference to what Shri Namboodiripad said which is very revealing and which will just show what are their designs in Kerala and in the country in general. Here is what Shri E. M. S. Namboodiripad said:—

"The Left communists when once in power want to utilise their being in power as a springboard for promoting conflicts between the Centre and the State Government and accentuate 'class struggle on a Government to Government plane'.".

This is from the article that was published in *Desabhimani*, Left CPI daily, on August 27, 1964. Here he is also angry at the limitations placed on the powers of the State in the present Constitution.

This clearly shows what their designs are in Kerala and it rightly gives us the basis to reject their demand to allow them to go and form the government in Kerala.

17 hrs.

Sir, Prof. Hiren Mukerjee talks of morals. It is hardly left to Communists to talk of morals. I will give a few instances of what these comrades have done in Kerala, as to how they have amassed wealth and made purchases. I do not know where from they get the money. But they have done so. I will challenge anybody

[Shri Vidya Charan Shukla]

from Kerala to disprove these allegations that I am making. Mr. Gopalan, a Member of this House, has purchased a cardamom estate in Kerala recently . . . (*Interruption*). He has purchased a costly cardamom estate and his wife has recently acquired a big cinema house in Allepey district.

Shrimati Renu Chakravartty: Since they are not here, these things should not be allowed. If it is a legitimate acquisition, there is no point . . . (*Interruption*).

Shri Indrajit Gupta (Calcutta-South West): Are we allowed to say what Mr. Shukla has done?

Shri Vidya Charan Shukla: Yes. I throw a challenge . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. Members should first take care to see that the facts are correct. (*Interruption*) It is always left to the good sense of the Members. They must be sure of the facts that they want to state on the floor of the House. This freedom of speech is there. But that privilege should not be misused at any moment. One must first make enquiries about it. I do not say that the reference is irrelevant in that context. Probably, he wants to prove that they have been getting money from some other sources.

An hon. Member: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Order, order. But when we are accusing someone, a Member of the House, or the Members of his family who are not here, certainly we ought to take the greatest care that might be possible so that there is not any mistake.

Shri H. N. Mukerjee: Would it not be necessary from the point of view of the regulation of the proceedings of this House, when this kind of a statement is made, that the source, the basis on which statement is made, is also indicated and, if necessary, the papers concerned might be placed on the Table of the House?

Mr. Speaker: If someone writes to me that this was incorrect, certainly I will find out from the Member from where he got it and the House has the authority to take action against the Member if any wrong statement is made. That is the usual practice. At this time, I cannot stop him. The other day also in my ruling I said that the House in England has taken action, very strong and very severe action, if an irresponsible or incorrect statement has been made.

Shri Vidya Charan Shukla: I am making the statement with full sense of responsibility. I want to repeat the allegations again and I challenge the Members of the Communist Party to disprove what I say. If they disprove this, I am prepared to apologise and I am prepared to undergo whatever punishment you want to give me. I am absolutely sure of the facts.

Mr. Speaker: His 10 minutes are over.

Shri Mohammad Elias (Howrah): You go to Kerala and make the statement where Mrs. Gopalan defeated the Congress Member by 17,000 votes.

Shri S. M. Banerjee: They have sacrificed much more. You are talking nonsense. Something is being said against a lady. That is their characteristic. We should also be allowed to say such things.

Shri Vidya Charan Shukla: Mrs. Gopalan is a politician. She is not a housewife. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order.

Shri S. M. Banerjee: You release Mr. Gopalan and he will reply to your charges.

Shri Vidya Charan Shukla: These members of the Communist Party

amassed wealth from sources which are undisclosed to us and the assets have been acquired under very suspicious circumstances.

Shri S. M. Banerjee: What about your father? There were charges against him.

Shri Vidya Charan Shukla: They were cleared in a court of law and the Blitz which had made these charges had apologised.

Shri H. N. Mukerjee: He talks nonsense, absolute nonsense, rabid nonsense...... (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: Once you encourage this sort of a thing, everything is going to be. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: If one Member is speaking, others have to listen.

Shri Mohammad Elias: He must not speak nonsense at the back of the Member of this House who is not here.

Shri S. M. Banerjee: It is the moral degradation of the Congress if I use this expression.

Shri H. N. Mukerjee: On this occasion you will see the provocation which was there. We have all known Shri A. K. Gopalan here and he has a reputation in Kerala; I was there only ten days ago. I know the kind of reputation which some Congress leaders have in Madhya Pradesh. It is a rabid thing, it is a rabid lie to say that moneys are being acquired by men like Shri A. K. Gopalan in this way, and then to get away with it only because Shri A. K. Gopalan is not here to contest it; how can I contest it? How can I tell him that it is false? How can a Member of the Communist Party, who is not Shri Gopalan himself, tell the House that this accusation is a damn lie?

Shri Vidya Charan Shukla: He can say this later on.

Mr. Speaker: That would mean in another manner that no allegations can be made against all those Communists who are not here as to how they acquired money and from which sources . . .

Shri H. N. Mukerjee: He has mentioned Shri A. K. Gopalan and his wife. I am not saying anything . . .

Mr. Speaker: What can I do? That is under discussion? How can I bar it? But I shall ask the hon. Member to take greater care.

Shri Muhammad Elias: He has no right to talk about morals. It is all immoral. In spite of the CBI report and the report in Punjab, my hon. friend is still talking about morals.

Shri Vidya Charan Shukla: I want to take very strong objection to what Shri S. M. Banerjee said. Those charges were cleared in a court of law, and the people who made the allegations had apologised . . .

Shri S. M. Banerjee: The people have said that. I have not said that.

Shri Vidya Charan Shukla: I am very sorry, therefore, that my hon. friend Shri S. M. Banerjee should have chosen to repeat that kind of thing on the floor of the House. Shri S. M. Banerjee is only revealing himself. I need not say anything further about it.

Shri S. M. Banerjee: My hon. friend is revealing.

Shri Vidya Charan Shukla: The Left Communist Party members have revealed themselves in many ways as for instance on the issue of Kashmir. When China and India were together they were always saying that Kashmir was an integral part of India and there should be no plebiscite. As soon as Pakistan began to flirt with China, they changed their view; they took a somersault and they had begun to say that the integration of Kashmir with India was not final and that a plebis-

[Shri Vidya Charan Shukla]

cite should be held. My hon. friend Shri H. N. Mukerjee was alleging that some Congress leaders had accounts in the Bank of China. May I ask him to deny whether the following members whom I am going to name had accounts in the Bank of China or not? The names of those persons are: Sarvashri Niranjan Sen Gupta (CPI Left), Promode Das Gupta (CPI Left), Muzaffar Ahmed (CPI Left), S. A. Dange (CPI Right), Jolly Mohan Kaul (CPI Right), Naren Sen (CPI Left), and Mohammed Ismail (CPI Centrist). All their accounts were bad and overdrawn also.

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): All wrong.

Shri Vidya Charan Shukla: I allege this. If my hon. friend has got the guts and has got the facts, he can prove this to be wrong, and if it is proved to be wrong I am prepared for any punishment which the Speaker may decide.

All the leading members of the Communist Party have been maintaining accounts in the Bank of China and they have been lavishly given overdrafts from that bank, and I am sure Government will make inquiries and find out the position.

Shri Surendranath Dwivedy: Government have already made inquiries.

Shri Vidya Charan Shukla: May I again reiterate my demand that a special Act of Parliament should be passed to set up a tribunal to try these traitors?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मेरी सब से बड़ी शिकायत यह है कि स्वतंत्रता के बाद पिछले 17 वर्षों में इस ने कुछ इस प्रकार के निर्णय जिनका कि प्रभाव देशव्यापी या विश्वव्यापी पड़ता हो, जब भी लिये हैं वह हमेशा आधे मन से लिये हैं । उस का दुष्परिणाम यह होता है कि उस में देश को भी फंसना पड़ता है और सरकार को भी फंसना पड़ता है । यह समस्या जो इस समय उपस्थित हुई यह भी लगभग उसी प्रकार की है । एक ओर सरकार कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है दूसरी ओर सरकार शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को खुली छूट भी देती है । एक ओर सरकार नागालैंड को भारतवर्ष का उसी प्रकार एक भाग मानती है जैसे कि अन्य प्रदेश हैं दूसरी ओर यही सरकार है जिस ने पादरी स्टाक को खुली छूट भी दे रक्खी है । एक ओर यही सरकार गोवा को भारतवर्ष में मिलाने के पश्चात उसको भारत का एक अभिन्न अंग बनाना चाहती है लेकिन फिर उसे आधे मन से गोवा को अभी तक न जाने क्यों महाराष्ट्र से अलग किये हुए है । भाषा समस्या के सम्बन्ध में भी सरकार की दुर्बल नीति का यह दुष्परिणाम है कि एक ओर वह संविधान की प्रतिज्ञा का पालन भी करना चाहती है और दूसरी ओर श्री कामराज और उन के साथियों को प्रसन्न भी रखना चाहती है और इस तरह भाषा समस्या को उलझाये भी रखना चाहती है । आधे मन से जब जब सरकार ने निर्णय लिये हैं उस का दुष्परिणाम इस देश को देर तक भोगना पड़ा है । यह ही स्थिति आज साम्यवादियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी है । साम्यवादियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक की बुद्धिमत्ता थी कि वामपंथी साम्यवादियों की गिरफ्तारी के नाम पर आप ने 600 से ऊपर साम्यवादियों को तो गिरफ्तार किया लेकिन जो उनकी बागडोर संभालने वाले हैं, श्री नम्बूदरीपाद और श्री ज्योति बसु, उन को जेल से बाहर रक्खा ? आधे मन से लिये गये निर्णय का आपका क्या प्रमाण है ? दूसरा ओर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को जब पता है कि यह इस प्रकार की अराष्ट्रीय कार्यवाही

कर रहे हैं जिस से देश की सुरक्षा किसी भी समय संकट में पड़ सकती है तो क्यों नहीं यह सरकार साहस के साथ इस प्रकार का निर्णय लेती कि भारतवर्ष में साम्यवादी पार्टी पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ? जब जब यह सरकार आधे मन से काम करती है, उस का दुष्परिणाम देश को--और इस सरकार दोनों को---भुगतना पड़ता है चुनावों से पहले इस प्रकार के आधे मन से लिए हुए निर्णय के जो परिणाम स्वाभाविक थे, केरल के चुनाव-परिणामों से वे स्पष्ट हो गए ।

मैं साम्यवादी दल के बहुत लम्बे चौड़े इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को कुछ पुरानी याद जरूर दिलाना चाहता हूं । 1939 में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया, तो साम्यवादी पार्टी हिन्दुस्तान की वह पार्टी थी, जिस ने यह कहा कि क्या एक एक आदमी को जेल भेजने से गांधी देश को स्वतन्त्र करा सकता है । लेकिन गांधीजी उस समय देश में एक वातावरण का निर्माण कर रहे थे । 1942 में जब उन्होंने देश में वातावरण का निर्माण कर के "डू और डाई" का नारा लगाया, उस समय यही पार्टी थी, जिस ने उस का भी विरोध किया और कहा कि जब गांधी ने देश को तैयार ही किया तो फिर उसने सारी जनता को एक साथ क्रान्ति की भट्टी में क्यों झोंक दिया ।

गांधी जी को छोड़िये, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे क्रान्तिकारी व्यक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने क्विजलिंग और कौमी गद्दार तक कहा । पर यह क्यों ? जिस समय द्वितीय महायुद्ध हो रहा था, तब नेताजी के आन्दोलन से या आजाद हिन्द फौज के आन्दोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चोट लगती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चोट लगने का मतलब यह था कि चर्चिल को चोट लगती थी और चर्चिल को चोट लगने का मतलब था कि स्टालिन को चोट लगती थी, क्योंकि वे दोनों मिल कर हिटलर के खिलाफ़ लड़ रहे थे । कम्युनिस्ट पार्टी का पिछला इतिहास इस प्रकार गद्दारी का रहा है ।

क्या हम नहीं जानते कि देश-विभाजन के समय किस प्रकार आधे कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग की पीठ थपथपाते थे और उस को देश विभाजन के लिए प्रेरित करते थे? क्या हम नहीं जानते कि काश्मीर के प्रश्न पर यही साम्यवादी दल कुछ समय पहले तक यह कहता था कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस के सम्बन्ध में जनमत संग्रह जैसी कोई मांग नहीं हो सकती, लेकिन श्री नम्बूदरीपाद ने मई में त्रिवेंद्रम में और प्रमोद दास गुप्ता ने 25 जून को मुजफ्फरपुर में जो प्रैस वक्तव्य दिये उनमें यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि जबसे चीन और पाकिस्तान की समझौता हुआ है कम्यूनिस्ट पार्टी का भी मस्तिष्क बदल गया है वक्तव्य देने के ढंग बदल गए हैं ? सरकार ने कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर तेनाली अधिवेशन के बाद विशेष रूप से ध्यान देना आरम्भ किया जहां माओ-त्से-तुंग और चाऊ-एन-लाई के चित्र लगा कर उन की पूजा की गई जो हिन्दुस्तान के सैनिकों के हत्यारे हैं जिन के हाथ उन के खून से रंगे हुए हैं ।

जिस दिन श्री नन्दा ने यह श्वेत-पत्र इस सदन में उपस्थित किया था मैं ने उसी समय भी पूछा था कि उन के पास कौन सा इस प्रकार का पैमाना है जिस से वह वामपन्थी और दक्षिण-पन्थी कम्युनिस्टों को पृथक पृथक करते हैं ? जब कम्युनिस्ट पार्टी का इस प्रकार का इतिहास ही है कि जिस तरह आज उन्होंने दक्षिण-पन्थी और वामपन्थी ये दो अलग अलग चोले पहन लिए हैं उसी तरह वे पहले भी समय के आधार पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते रहे हैं । आज प्रो-पीकिंग और प्रो-मास्को पृथक-पृथक दिखाई देते हैं लेकिन ख्रुश्चेव के हटने के बाद अगर कल प्रो-पीकिंग और

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

प्रो-मास्को दोनों गुट एक हो जाते हैं मास्को तथा पीकिंग की दोस्ती हो जाती है तो श्री नन्दा के पास कौन सी शक्ति है कि वह वामपन्थी और दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टो को अलग अलग बना कर रखेंगे ?

क्या श्री नन्दा यह नहीं जानते कि जब 1933–34 में पापुलर फ्रन्ट का आन्दोलन चला था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग ऐसा था जो उस में सम्मिलित होने के लिए कहता था और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो अलग रहने की बात कहता था ? क्या उन को यह बात पता नहीं है कि जब फ्रांस में लियों ब्लम की गवर्नमेंट बनी थी जो कि सोशलिस्ट । तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक विंग ने उस की गवर्नमेंट में सम्मिलित होना स्वीकार किया और दूसरा विंग उस से बाहर रहा ? क्या श्री नन्दा को यह पता नहीं है कि देश विभाजन के समय इसी कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग मुस्लिम लीग के साथ था और दूसरा उस से अलग मंचा बना कर काम करता था ?

मैं श्री नन्दा से यह भी पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में जिस समय भीषण नरसंहार —कत्ले-आम—चल रहा था तो क्या श्री राजेश्वरराव, जो आज अपने आप को दक्षिण-पन्थी कम्युनिस्ट कहते हैं उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जेनेरल सैक्रेटरी नहीं थे । आज जिस तेलंगाना का उदाहरण दे कर वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी यह कहती है कि हम तेलंगाना के इतिहास को दोहराना चाहते हैं क्या यह वही राजेश्वरराव नहीं थे जिन्होंने तेलंगाना के उस सारे कांड को करवाया था ?

Shrimati Renu Chakravartty: Mr. Shastri was a supporter of Godse.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केरल में जो अभी चुनाव हुआ है उस के परिणामों से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए । जिस प्रकार वामपन्थी कम्युनिस्टों को दक्षिण पन्थी कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया है, जिस प्रकार यह मिली हुई कुश्ती केरल में हुई है कम से कम अब सरकार को उस से सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए इस उदाहरण से शिक्षा ले कर काम करना चाहिए ।

अगर मेरी किसी बात में असत्यांश है तो मैं चाहूंगा कि दक्षिण-पन्थी साम्यवादी लोग आज इस बात की घोषणा करें कि हम तथाकथित प्रो-पीकिंग वामपन्थी कम्युनिस्टों की अराष्ट्रीय गतिविधियों का साथ नहीं देंगे और दूसरी पार्टियों की राष्ट्रीय गतिविधियों का हम साथ देंगे । अगर उन की तरफ से आज इस प्रकार की घोषणा होती है तो उस से अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी में दो ही विंग हैं और उन दोनों के सोचने के ढंग अलग अलग हैं । लेकिन आज दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट जिस तरह से यहां और इस सदन के बाहर वामपन्थी कम्युनिस्टों को समर्थन दे रहे हैं क्या उस के बाद भी सरकार वामपन्थी और दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टों को अब अलग अलग मान कर ही चलेगी और क्या उस के निर्णयों की स्थिति इसी प्रकार की रहेगी ?

जहां तक कम्युनिस्टों की अराष्ट्रीय गतिविधियों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सीमाओं पर पीछे जो आक्रमण हुआ था उस की भी भूमिका कोई नहीं थी बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास था । जिस समय मास्को में बैठ कर साम्यवाद को दुनिया में फैलाने का कार्यक्रम तैयार किया गया उस समय एक नारा लगाया गया था कि यूरोप में साम्यवाद का झंडा लगाने से पहले एशिया को विजय किया जाये । अंग्रेजी में शब्द ये थे : रोड टु पैरिस थ्रू शंघाई एंड कलकत्ता । इसी के अनुसार कम्युनिस्टों ने शंघाई को विजय करने के बाद कलकत्ता को निशाना बनाया था । मैं श्री नन्दा

से यहां पूछना चाहता हूं कि क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति इस प्रकार की नहीं रही कि उस ने भारत के पूर्वी भाग को, चाहे वह नेफा हो, चाहे नागालैंड हो या आसाम या पश्चिमी बंगाल हो, अपनी गतिविधियों का विशेष रूप से केन्द्र बनाया .

चीनी आक्रमण के समय साम्यवादियों की क्या तैयारियां थीं ? यह बात दूसरी रही कि देश कुछ सावधान था, देश की जनता सावधान थी । इस लिए साम्यवादी अपने स्वप्नों को साकार नहीं कर पाए, लेकिन श्वेतपत्र में जिस एक सर्कुलर की चर्चा की गई है, उस में कहा गया कि अक्तूबर, 1962 में जो गलती हम से हुई, उस को हम अब नहीं दोहरायेंगे । जिन देशद्रोही साम्यवादियों का यह इतिहास रहा है, सरकार कब तक उन को क्षमा करना चाहती है ?

मैं श्री नन्दा से यह बात भी स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास जो तथ्य हैं, उन को वह दबा कर क्यों रखना चाहती है । आज सरकार बताए कि नागालैंड और बर्मा के द्वारा पीकिंग के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की कम्यूनिकेशन लाइन थी या नहीं, वहां से कुछ हथियार आए या नहीं और आगे भी कुछ हथियार मंगाने की योजना थी या नहीं, जिस से देश में सशस्त्र विद्रोह होने वाला था । आखिर श्री नन्दा ये सब बातें देश को स्पष्ट भाषा में क्यों नहीं बताते ?

आज से दो साल पहले हांगकांग में हिन्दुस्तान की मुद्रा की जो कीमत थी, आज उस के ड्योढ़ा और दुगना होने के पीछे क्या रहस्य है, जब कि दुनिया में हिन्दुस्तान की करन्सी की कीमत सब जगह गिरी है ? पहले हांगकांग में हमारी करन्सी करीब तीन करोड़ के लगभग साल में खपती थी, लेकिन आज एक साल में ग्यारह, बारह करोड़ की करन्सी की मांग क्यों होने लगी है ? स्पष्ट बात यह है कि चीन हमारी करन्सी खरीद रहा है और अध्यक्ष महोदय, आप मुझ आज यह बात कहने की इजाजत दें कि हिन्दुस्तान में दो इस प्रकार के राजदूतावास हैं, जिन के द्वारा वह करोड़ों रुपया भारतवर्ष में कम्युनिस्टों के लिए आता है । क्या भारत सरकार के विजिलेंस डिपार्टमैंट, गुप्तचर विभाग, ने श्री नन्दा को इस प्रकार की जानकारी नहीं दी ? एम्बैसी के जिन बैग्ज को कोई नहीं खोल सकता, क्या इन राजदूतावासों के द्वारा उन यह रुपया आता रहा है ?

क्या गुप्तचर विभाग ने श्री नन्दा को यह जानकारी नहीं दी कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मन्दिर में इस प्रकार का बैग हैंड ओवर करने का पता चला है ? क्यों इन तथ्यों को छिपा कर रखना चाहिए ? मेरी मांग है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए यह करोड़ों रुपया जिन राजदूतावासों के द्वारा चीन से आ रहा है—मैं स्पष्ट शब्दों में उन राजदूतावासों का नाम किसी कारण नहीं लेना चाहता हूं—उन दोनों देशों से भारत सरकार को राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिए ।

मैं ने संसद् के पिछले अधिवेशन में भी चाइना बैंक की चर्चा को उठाया था । अब फिर मैं कहना चाहता हूं कि चाइना बैंक के साढ़े सात करोड़ रुपये के इतिहास को, उस की पूरी रिपोर्ट को, सरकार प्रकाशित करे । श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि उस में सूरजमल नागरमल का एकांउट पाया गया और दूसरों का एकाउंट पाया गया । मैं कहना चाहता हूं कि सूरजमल नागरमल ही नहीं, अगर प्रकाशवीर शास्त्री का भी एकाउंट चाइना बैंक में पाया गया और वह पैसा देशद्रोह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लगाया गया, तो उस को वही सजा देनी चाहिए, जो बड़े से बड़े देश-द्रोही को मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो । वह कोई व्यापारी हो या कोई दूसरा क्यों न हो । लेकिन क्या आज श्री हीरेन मुकर्जी अधिकार-पूर्वक इस बात को भी कह सकेंगे कि चाइना बैंक के एकाउंट्स में श्री ज्योति बसु और

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

श्री डांगे का नाम नहीं पाया गया? मैं चाहता हूं कि सरकार उस रिपोर्ट को सामने लाए। वित्त मंत्री, श्री कृष्णमाचारी, अपनी जेब में उस को क्यों छिपाए बैठे हैं ? कब तक इस रिपोर्ट को दबाए रखेंगे ?

दूसरी सब से बड़ी बात मैं कांग्रेस सरकार को और विशेषकर गृह मंत्री नन्दा जी और प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना चाहता हूं। अगर इस देश की स्वतंत्रता को बचाना है, पौने नौ सौ साल की लम्बी जद्दोजहद के बाद जो देश आजाद हो पाया है, उसको बचाना है जिस स्वराज्य भवन की भित्ति में, मूल में न जाने कितने अनगिनत बलिदान लगे हैं अगर उस स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो आज केवल कम्युनिस्ट पार्टी पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाना होगा बल्कि आपको अपने घर में भी झांक कर देखना होगा कि कम्युनिस्ट कहीं उधर भी तो नहीं है ? कम्युनिस्ट इधर ही नहीं बैठे हुए हैं आपके घर में भी बैठे हुए हैं। आपको अपनी गिरहबां में मुंह डाल कर देखना चाहिए।

अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए जहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भारतवर्ष में इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी को देश में काम करने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिये, इसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए वहां एक बात मैं श्री हीरेन मुखर्जी को भी कहना चाहता हूं। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि जो हमारे सिद्धान्त है, ये ऐसे ही जीवित रहेंगे, इसी तरह से विकसित होते रहेंगे जैसे कि सूर्य का उदय होता है। उनसे मुझे यह कहना है कि वर्तमान सरकार जो सामने की बैंचों पर बैठी हुई है उसकी दुर्बलता से हो सकता है कि अराष्ट्रीय काम करने वाले देश के अन्दर जीवित रहें लेकिन अब देश की जनता जाग कर खड़ी हो गई है और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी को वह देश की सुरक्षा को संकट में डालने का अवसर नहीं दे सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल कर आप सुन लें कि भारतवर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी की सी राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाली पार्टी का भविष्य सूर्योदय की तरह नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य अस्त होने वाले सूर्य की तरह से है (इंटरप्शंज)। भारतीय जनता कम्युनिस्ट पार्टी को उसी तरह से समाप्त कर चैन लेगी जिस तरह से सूर्य अस्त होने पर आराम के क्षण आते हैं (इंटरप्शंज)।

Shrimati Renu Chakravartty: Was he not opposing the arrest of Shri Golwalkar of the RSS under the D.I.R.?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शोर मचा कर जिस तरह का दूषित वातावरण कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य यहां बनाना चाहते हैं, इस तरह का वातावरण सफल नहीं हो सकेगा। इस पार्टी को उसी तरह से देश से समाप्त कर दिया जाएगा जैसे जीवन का अन्त होता है, सूर्योदय की तरह यह पार्टी राजनीतिक आकाश में अब नहीं रहेगी।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, नन्दा जी ने हमारे सामने यह किताब रखी है जोकि 45 सफे की है। पहाड़ खोद कर नन्दा जी ने उस में से क्या निकाला है ? एक चूहा निकाला है और वह भी मरा हुआ। मुझे हैरत होती है कि जिस सरकार के रहते हुए चीन के बारे में गलत नीतियां चलीं और दो ढाई साल पहले सारे भारतवर्ष को अपमानित होना पड़ा आज वही सरकार एक दूसरे दल के बारे में यह आरोप लगा रही है कि वह चीन के साथ मिला हुआ है और उनकी गतिविधियां देश-हित विरोधी हैं। मैं नन्दा जी से जानना चाहता हूं कि जिस दल के वह नेता है और मंत्री हैं और जिस दल के हाथ में मुल्क की बागडोर पिछले 17–18 साल से चली आ रही है,

उस दल की चीन सम्बन्धी नीति क्या रही है? श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और गोपालन के हाथ में कम से कम देश की बागडोर नहीं थी। अगर कोई इस देश में मुल्जिम है तो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी वह मुल्जिम हैं।

1950 या 1951 में जब तिब्बत की आजादी का हनन हुआ तो नन्दा जी उस वक्त बम्बई में मंत्री थे। अपने मंत्रीपद से वह हटे नहीं और जवाहरलाल नेहरू जी की हकूमत में मंत्री बनने के लिए दिल्ली आए। उसके बाद 1954 में कांग्रेस की सरकार ने पंचशील की संधि उसी चीन के साथ की जिस ने तिब्बत की आजादी का हनन करके भारत की उत्तरी सीमा पर संकट पैदा कर दिया था। क्या नन्दा जी ने उस वक्त इस नीति की आलोचना करते हुए इस्तीफा दिया था या वह अपने पद पर चिपक कर बैठे रहे?

उसी तरह से 1954 में जब यह पंचशील की संधि हुई और उसके ऊपर जो स्याही थी वह सूखने भी न पाई थी कि चीन के द्वारा लद्दाख में आक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त नन्दा जी और उनके दल ने और उनकी सरकार ने आक्रमण के इस तथ्य को इस सभा से छिपाये रखा। उस वक्त भी नन्दा जी ने इस बात को ले कर इस्तीफा नहीं दिया।

उसके बाद भी चीन ने आक्रमण किया। इस हमले को उन्होंने कभी कबूल नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने बरसों तक भारत के प्रतिनिधि यही कहा करते थे कि यह तो एक सीमा का झगड़ा है, सीमाई विवाद है। उसके बाद भी अगस्त, 1962 में इन लोगों ने घोषणा की थी कि भारत की भूमि पर से जब तक चीन नहीं हटता, उसके साथ कोई वार्तालाप या समझौता हम नहीं करेंगे। लेकिन अक्तूबर 1962 में जब रणभूमि पर हमारी हार हो गई, उसके बाद हमारी सरकार अपने वादे को भूल कर कोलम्बो प्रस्ताव लेकर समझौते के रास्ते पर चली।

मैं जानना चाहता हूं कि चीन को ले कर कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उस नीति में और वामपंथी कम्युनिस्टों की नीति में क्या फर्क है। वे भी राजनीतिक समझौता चाहते हैं और भूमि का सौदा करने के लिए शायद तैयार है और नन्दा जी और उनकी हकूमत भी चीन के साथ राजनीतिक समझौता चाहती है और अपनी भूमि का सौदा करने के लिए तैयार हैं।

चीन का जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस सरकार की नीति, नन्दा जी की नीति और वामपंथियों की नीति में कोई अन्तर नहीं है। आज वामपंथी कम्युनिस्टों के बारे में जो आरोप लगाये जाते हैं, उनका समावेश इस किताब में किया गया है। क्या इस में हमें मिला है? 45 सफे में कहीं दो पैरे ऐसे हैं जिन में वामपंथियों की कार्रवाइयों का जिक्र है। 43 सफे पर जो 26वां परिच्छेद है उस में 1948 और 1950 में जो उन्होंने काम किया था उसका जिक्र है। 49 सफे पर एक परिच्छेद 28 नम्बर का है। उस में उनके वर्तमान कार्यों के बारे में कुछ जिक्र है। यह कहा गया है कि वामपंथी कम्युनिस्ट नेता डलहौजी गये, मनाली गये, कुल्लू गये। कौन कहां जाता है या नहीं जाता है, इसकी एक लिस्ट दे कर आप इन आरोपों को साबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग बम्बई में जाते हों और अपनी भाग्य रेखा पंडितों और ज्योतिषियों को दिखा कर उन से पूछते हों कि क्या मैं प्रधान मंत्री बन सकता हूं। कोई कहां जाता है इससे कोई चीज साबित नहीं होती है। पूरी किताब में कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों के बारे में एक जुमला तक नहीं है। दो वाक्य मैं पाता हूं। एक उनका कार्यक्रम है कि किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों को संगठित करके एक जन आन्दोलन छेड़ा जाए। इस सदन में विरोधी दल के जो अधिकतर सदस्य

[श्री मधु लिमये]

हैं उन में से एक एक सदस्य इस काम को करता है और मैं भी करता हूं। अभिमान के साथ यह काम करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

वामपंथी कम्युनिस्टों के साथ मेरा मतभेद है। अगर इन में से कोई ऐसे हैं जोकि पेकिंग की ओर देखते हैं तो उनके साथ लड़ने के लिये मैं तैयार हूं और अपने दोस्तों से कहूंगा कि पेकिंग की ओर देख कर या मास्को की ओर देख कर या वाशिंगटन की ओर देख कर या लंदन की ओर देख कर हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। हमको अभिमुख होना है भारत के जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ, मजदूर और किसान जनता की तरफ, मध्यम श्रेणी की जनता की तरफ और उसकी ओर अभिमुख हो कर और उनको संगठित करके ही हमारे देश में समाजवाद स्थापित हो सकता है।

जहां मैं यह कहता हूं वहां साथ साथ सरकार का इस वक्त जो काम है उसकी भी कटु आलोचना करता हूं। संकटकालीन स्थिति की सरकार ने घोषणा की है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर युद्ध का खतरा हो, अगर कोई हमला होता है, फौजी चढ़ाई होती है या आन्तरिक विद्रोह की परिस्थिति है तो संकटकालीन कानून जारी किया जा सकता है। आज न जंग चल रही है, न फौजी लड़ाई हो रही है, न कोई हमारे देश में हिंसात्मक क्रान्ति होने जा रही है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि संकटकालीन स्थिति को बनाये रखते हुए और भारत सुरक्षा कानून को बनाये रख कर हजारों लोगों की जो स्वतंत्रता छीन ली गई है, उनके बारे में नन्दा जी क्या करना चाहते हैं। एक ही चीज वह करना चाहते हैं। वह जानते हैं कि जनता में असन्तोष है और जनता को अगर मौका दिया जाएगा तो उनकी सरकार एक दिन के अन्दर खत्म हो सकती है जैसे केरल में हो चुका है। नन्दा जी ने कहा कि लोगों को वोट देने का जो अधिकार दिया हुआ है, उसको नहीं रोक सकते थे, लोगों को इलेक्शन में खड़े होने से नहीं रोक सकते, कानन इसकी इजाजत नहीं देता है, तब मैं कहूंगा कि नजरबन्द कम्युनिस्टों को अगर आप रिहा नहीं करना चाहते हैं तो जो विधान सभा के सदस्य हैं उनको आप वोट देने की इजाजत दीजिये। जेल से नहीं छोड़ना चाहते तो न छोड़िये। अभी केरल में विरोधी दलों की हकूमत बन सकती है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है कल मेरे दल ने प्रस्ताव किया है कि जो सब से बड़ा केरल में दल है उसको राज्यपाल को न्यौता देना चाहिये कि सरकार बनाने के लिए और उस सरकार को बहुमत दिलाने के लिये ठोस और निश्चित कार्यक्रम के आधार पर हम सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वामपंथी कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके और नजरबन्द रखकर नन्दाजी राष्ट्रपति की गैर-जिम्मेदार और अप्रजातांत्रिक हकूमत को केरल में बनाये रखना चाहते हैं। केरल की जनता ने कांग्रेस को तो उखाड़ कर फेंक दिया है लेकिन राष्ट्रपति की हकमत की आड़ में छिप कर केरल की जनता पर वह अपनी नीतियां ठोंस देना चाहते हैं जिन्हें की केरल की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। तो हमारे सामने सवाल यह है कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा अब खत्म करनी चाहिए। अगर संकटकालीन स्थिति खत्म होती है, तो भारत रक्षा कानून की वे धाराएं जिनके अन्तर्गत इन को गिरफ्तार किया गया है समाप्त हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि इन धाराओं का संविधान के अन्दर जो बुनियादि अधिकार है उनके साथ टकराव है और ये धाराएं तभी खत्म हो जाएंगी जब संकटकालीन स्थिति खत्म हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, आज देश-हित के नाम पर ऐसे कानूनों, संविधान की ऐसी धाराओं का इस्तैमाल किया जा रहा है जिनका

इस्तेमाल केवल जंग, या फौजी चढ़ाई या हिंसात्मक विद्रोह का जब खतरा रहता है उसी समय किया जाना चाहिए। सरकार ने जो यह 45 सफों की किताब निकाली है इसको मैं गृह-मंत्रालय की बुद्धिहीनता का प्रतीक मानता हूं। अगर आप इसको ले कर अदालत में जाएंगे तो अदालत में यह किताब टिक नहीं सकेगी, इसको कोई सबूत नहीं कह सकता। अगर कम्युनिस्ट आन्दोलन में मतभेद हैं और उनके बारे में किताब लिखनी थी तो किताब लिखी जा सकती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो वाम पन्थ है यां दक्षिण पन्थ है उनके विचार क्या हैं, उनकी विचार प्रणाली क्या है, उसके बारे में चर्चा करना इस किताब का, इस पुस्तिका का, उद्देश्य नहीं हो सकता था। इसमें लिखा है "राष्ट्र विरोधी कार्यवाई" "राष्ट्र विरोधी काम"। हो सकता है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि प्रजातन्त्र खराब चीज है और जनाधिपत्य की जगह एकाधिपत्य आना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को आप जेल में बन्द करेंगे? जब तक वे इस सरकार को हिंसात्मक तरीके से उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं करते, तब तक ऐसे लोगों को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। इसलिए मैं एक जोरदार ढंग से आपकी मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार यह जो अपने हाथ में अधिकारों को केन्द्रित करने की नीति को चला रही है, उस नीति को वह छोड़ दे। इन कम्युनिस्ट नजरबन्दों के खिलाफ अदालतों के सामने मुकदमे चलाए। लेकिन अगर वह यह भी करने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया, उसी तरीके से ये जो 29 कम्युनिस्ट नजरबन्द केरल की जेलों में बन्द हैं, इन को विधान सभा में समय समय पर वोट देने के लिए भी कोई सुविधा दें। अगर यह हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि देश में प्रजातन्त्र पनप सकता है।

अन्त में मैं एक ही बात और कहूंगा।

मुझे बड़ा दुख होता है जब विरोधी दलों में से ही एक तबका इस तरह की मांग करता है कि फलां फलां दल के ऊपर पाबन्दी लगाओ। मुझे इस मांग से बड़ा सदमा होता है। दक्षिण-पन्थी कम्युनिस्टों ने हाल ही में अपनी कांग्रेस में मांग की थी कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ पर पाबन्दी लगायी जाय, और अब हमारे जन संघ के मित्र कहेंगे कि वामपन्थी कम्युनिस्टों पर या दक्षिणपन्थी कम्यनिस्टों के ऊपर पाबन्दी लगायी जाए। तो इससे न तो जनसंघ सत्ता में आएगा और न दक्षिण-पन्थी कम्युनिस्ट सत्ता में आवेंगे, यह जो नन्दा जी की जनता-विरोधी हुकूमत है वह वैसे ही कायम रहेगी। इसलिए मैं अपने मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि नागरिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की बुनियाद पकड़ो, सिद्धान्त की जड़ में जाओ और किसी दूसरे दल को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करने का और जनता की पीठ में छुरी भोंक देने का पाप न करो।

Mr. Speaker: Shri Venkatasubbaiah.

An hon. Member: Sir, how long are we going to sit?

Mr. Speaker: How long will the hon. Minister take?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): 45 minutes—I have to answer all the points that have been raised.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let us sit up to 7·30.

Shri P. K. Deo: Let us continue this tomorrow.

Mr. Speaker: That is not possible. I will call the hon. Minister at 6·15. We can sit up to 7·00.

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Mr. Speaker, Sir, I have been listening very attentively to the eloquent speech of Shri Mukerjee waxing eloquence over the misdeeds of this Government. My charge against this Gov-

[Shri P. Kenkatasubbaiah]

ernment is that it has been very late in arresting the Left Communists who are proving to be a danger to the security and sovereignty of this country. The other day when the question of installing a statue of Shri Subhas Chandra Bose was raised in this House. Shri Mukerjee worked himself up and chastised the Government for not installing his statue to perpetuate his name. Public memories are proverbially very short. But I would like to remind my hon. Communist friend that when Netaji was waging a war against British imperialism he was dubbed by the Communists as an agent of Tojo of Japan. Then, conveniently they changed their tactics and their plans also. Parliamentary democracy is only an expedient, not a matter of principle, for them.

If they believe in parliamentary democracy then I would straightaway ask my Communist friends one question. We in this country have adopted a Constitution which gives us the freedom of speech and expression, no matter to what community, caste or political party we belong to. The only condition is that the freedom of speech should not be misused for subversive and anti-national activities that will bring danger to this country.

Public memories are very short. Which of the national leaders the Communists have not criticised and dubbed as the agents of British imperialism. The father of the nation also did not escape their criticism. So, also Pandit Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose. People of hallowed memory and respect, people who were held in high esteem by the people of this country, people who were in the forefront of our freedom struggle, these were the people who were characterised by the Communists as agents of British imperialism. I know many instances where our Communist friends have acted during the Quit India Movement as paid agents of the British Government. At that time they were responsible for putting into jail and torturing many Congressmen who have sacrificed their very lives for the sake of the freedom of this country.

I was also very much amused to hear Professor Mukerjee speaking about the Kerala elections. I would like to ask of him only one question. Were the Kerala elections fought on this issue? What was the election manifesto of the Left Communists in the Kerala elections? Did they ask for a verdict or referendum of the Kerala people on the detention of these people by the Government? No, not at all. They have played on the innocence of the local people, as they have done earlier in Andhra and other places. Here I will narrate one instance. During 1952 general elections our Communist friends went about Andhra promising the voters five acres of land and one cow if they were returned to power. They always play on the innocence of the people to catch their votes. In Kerala also the same thing has happened. They have exploited the innocence of the people in the matter of food scarcity and they were able to secure some seats.

They say that they have got the majority of seats in Kerala elections. At the same time, they contradict or refute the right or claim of the Congress Party to rule the country because, according to the Communists, the Congress has got only a minority of votes. So, I would ask of them: how are you entitled to rule Kerala when you have got only a minority of votes? So, you have no right to speak on behalf of Kerala and your statement is incorrect.

Coming to the statement that has been laid on the Table of the House by Shri Nanda, I will quote only a few instances. A meeting was held in Tenali where they displayed the portrait of Mao Tse-tung, who is the aggressor, who has committed aggression on our country, who wants to put

this country under his heels, if he can. The portrait of such a person was displayed in Tenali. So, these people are masquerading themselves as patriots and they are really traitors. They have no faith in democracy.

At no time, even at the time of aggression, has the Communist Party made any statement about its line of action. It did not even say whether the Chinese have committed aggression or not. The Communist Party was unequivocal and it was very halting in coming forward and saying that the Chinese have committed aggression. Even today I was amazed to hear my hon. friend, Shri S. M. Banerjee, say that it is not an invasion but only aggression. I do not know the difference between aggression and invasion. They are accusing us as having some fellow-travellers in our midst. I do not know to which category Shri S. M. Banerjee belongs.

Shri S. M. Banerjee: I am a democrat.

An hon. Member: What is democracy?

Shri S. M. Banerjee: Don't teach me that. I am not going to learn patriotism from you.

Shri P. Venkatasubbaiah: I would like to ask of Shri Mukerjee one question. What led him to differ from the Left Communists? What was the difference of opinion? Was the difference of opinion this that China had not committed aggression? What led you to this difference of opinion because of which the party split into two parts? I may or may not agree but their own fellowmen, their own comrades, have denounced Dange saying that he has written a letter some 20 or 30 years back that he would act as an agent of the British. Without going into the merits of the case I will say that even the best people of their party have disbelieved Shri Dange. I would like to know if my statement is correct. I am afraid, Shri Hiren Mukerjee also holds the same view.

This is the history, this is the activity of the Communist Party in our country. Their flirtation with the Muslim League, of the communists with the communalists . . .

Shri Indrajit Gupta: What has that to do with the Muslim League?

Shri P. Venkatasubbaiah: . . . clearly shows the combination of Peking and Pindi. The inspiration comes from there. The flirtation between Peking and Pindi is very well reflected in the Kerala elections, in their flirtation with the Muslim League which is a rank communalist body. I will only plead that we must be very careful so far as these friends are concerned. Their history sheet is bad. Their activities are suspicious. They never claim this country as their motherland. They have got extra-territorial loyalties. Their inspiration is from somewhere. So, beware of these friends. I will only request the Home Minister to be more emphatic and bold enough to see that they are put in their proper place. As Shri Prakash Vir Shastri has very rightly pointed out, people are aware of these people's activities. I know, except some bungling or some debacle in Kerala or other places, nowhere, in no part of this country they are going to tolerate this party which has got a very suspicious history behind it and which has been trounced by the electorate. The electorate has given time and again its clear verdict against the anti-national activities of this party and I request Shri Nanda to deal very firmly so far as these Communist friends are concerned.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Mr. Speaker, Sir, I beg of this House to approach the problem in all seriousness, without passion and prejudice. To us India is first; India's security, India's independence—that is our primary concern. We will strike down anybody mercilessly if he goes against India's integrity or India's territorial sovereignty. We will not tolerate it. But I had the privilege to work with

[Shri N. C. Chatterjee]

Shri Gopalan in this House for many years and it is difficult for me to believe that Shri Gopalan is guilty of any treasonable or any traitorous activity. I do not believe it.

I looked for any real evidence to connect him with treachery or with treason. I have read this document with due care, but I find that it falls short of requisite proof. My first charge is that Shri Nanda has said in this document, on the first page, that on December 30, 1964 about 900 active members of the Communist Party of India had been detained in different cities under Rule 30 of the Defence of India Rules. This Parliament was sitting day after day up to the 24th December. Shri A. K. Gopalan was functioning in this Parliament. Why was this Parliament treated with scant courtesy? Why did the Home Minister not confront Shri Gopalan and take this Parliament into confidence and tell us what treasonable or anti-Indian or anti-national activities these Communists and these Members of Parliament were indulging in? Surely, it is only fair to them, fair to the Parliament that they should have been told. We should have been taken into confidence. This is a wonderful display of ministerial responsibility. Shri Nanda says that on the 1st January, 1965 he made a broadcast over the All India Radio announcing the aggression on the freedom and on the cherished human rights of 1,000 citizens. This is a serious matter and I honestly feel that they have not done their duty. Out of these 45 pages, if you scan them, you will find 32 pages which are devoted to quotations from all the ideological speeches and all sorts of thesis pointing out the split between the Right and the Left. We are not concerned with the split between the Right and the Left. We have nothing to do with that. We wanted facts. This was merely the Home Minister's political judgment which he pronounced on his political rivals and he threw it over to the electorate in Kerala asking them to accept it or reject it. They have rejected it. It is quite clear that the intelligent and educated electorate of Kerala has not accepted this fere *ipse dixit* of the Home Minister: Why? It is because you did not give facts. They wanted facts; they wanted concrete data; they wanted legal evidence. You have not given them.

Here are quotations spread over the period of 10 to 12 years. No new facts have been given. If you look at the last chapter—that chapter is the most serious chapter and I expected to get something there—that chapter is headed as "Preparations for subversion and violence". It starts on p. 32. You look at p. 32 and you will find that they have given quotations from a speech by a Bengal Member Mr. Jyoti Basu. What did Mr. Jyoti Basu say? Please remember that upto chapter IV, there is no real evidence of any subversive activity. Preparation for subversion and violence are given in chapter V. What is the first charge? What is the tangible evidence the Home Minister propounds? He has pointed out that Mr. Jyoti Basu had made a speech in Calcutta or somewhere else in Bengal. What is the speech? It is:

> "When a huge wave of anti-imperialist mass struggle swept through the land at the end of the Second World War, the big bourgeoisie leadership of the India National Congress betrayed the struggle instead of leading it, and assumed power through compromise with British imperialism . . . Bengal was partitioned. The land overflowed with blood, the dark blood of fratricidal strife, not the sacred blood that is shed in a liberation war".

What is wrong there? If Mr. Jyoti Basu said this that we have to pay the price of partition . . . .

An hon. Member: Is that all?

Shri N. C. Chatterjee: That is what is quoted here. If Netaji Subhash Chandra Bose had been here, if Dr. Shyama Prasad Mukerjee had been here, they would have talked in the same strain and possibly in a more severe language. Is there any justification for saying that there have been acts of subversion and violence?

Sir, you know, the Supreme Court of India has declared categorically, in the judgment of the Chief Justice of India, that this Defence of India Rule 30 is unconstitutional and illegal. You remember that I read out in this House that portion of the judgment where the Attorney General of India appearing for the Government of India clearly admitted that this is unconstitutional and that this is repugnant to articles 14, 21 and 22 of the Constitution. The Chief Justice pointed out that the Government should beware that they are guilty of unlawful and illegal confinement of citizens and that they will have to pay the penalty after the Emergency is over. In order to put it right, they sought to bring forward the Eighteenth Constitution Amendment Bill. We protested against that. Shri Jawaharlal Nehru was then the Prime Minister and he in his wisdom withdrew the Bill. That was the greatest tribute that could be paid to democracy and parliamentary form of Government. They withdrew it. Now, the situation is that here is the unconstituional law. Why have you resorted to that? Even when London was being bombed everyday, even when the Midlands were subjected to destruction, even when the whole British Empire was crumbling to pieces, the British Government did not take such power. Even then, the Home Minister, under the Defence of the Realm Act . . .

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): That is not correct. I would request my hon. friend to read the book "Lawless Laws" published by Late Shri Hem Chandra Nag, Editor of the Hindustan Standard.

Shri N. C. Chatterjee: I have read many books, and I have argued many cases including this particular case before the Supreme Court, and I ought to tell my hon. friend that there, even in the worst stage of the crisis facing the British Empire, they had an advisory board consisting of judges and jurists to whom the case of every detenu was sent.

Shri C. K. Bhattacharyya: They had Regulation III of 1818.

Shri N. C. Chatterjee: All that I am pointing out is this. Immediately this critical situation came, I wrote to the Home Minister Shri Nanda and I requested him "Will you at least consider the advisability of having a board of advisers, consisting of the Chief Justice of India, Mr. Justice Gajendragadkar, Mr. S. R. Das, the former Chief Justice of India who presided over the Commission of Inquiry on the late Sardar Pratap Singh Kairon, and also Mr. Mehr Chand Mahajan, another Chief Justice of India who has retired. He wrote to me that he would consider all that.

If you are satisfied that Shri A. K. Gopalan and these people are guilty of treason or guilty of violence or guilty of acts which are nothing short of treason, why do you not put them before a court of law and have them punished? We do not want that the taxpayers' money should be utilised for the purpose of keeping them behind the prison bars and they should enjoy the benefit of being State guests in this way. They should be subjected to condign punishment Why do you not do it? Why do you deprive them of the opportunity of defending themselves? Even for the Preventive Detention Act arrests, we have provided in article 22 of the Constitution that there must be a charge-sheet given within five days; otherwise, the detention becomes illegal. Why do you not give them a charge-sheet and give them a chance of defending themselves? Even a murderer is given that opportunity. What crime have these people committed? I think the Government are exaggerating the importance of some

[Shri N. C. Chatterjee]

statements made by men like Mr. Hare Krishna Konar or Shri Promode Das Gupta or by Mr. Ramamurti. We in India are pledged to non-violence. This Government should not be so feeble, and our people should not be so chicken-hearted as to think that just because some Member somewhere has spoken about violence, therefore, the country is going to pieces. The country will go to pieces not because of such statements but because of poverty and mass hunger which this Government is tolerating and is conniving at. That is the real problem. I would beg of the Home Minister to consider even now that the judicial process should be allowed to operate. Otherwise, these people should not be kept behind the prison-bars without trial, without an opportunity for defence, and without the formulation of any kind of charge-sheet against them.

Shri Kappen (Muvattupuzha): I was surprised and taken aback . . .

Shri S. M. Banerjee: At the Kerala election results.

Shri Kappen: . . . . at hearing Shri H. N. Mukerjee waxing eloquent on the injustice of arresting and keeping in prison the Left Communists. He was saying that the Home Minister had arrested them on the ground that they were pro-Peking. May I kindly ask one question of Shri H. N. Mukerjee? Was it the Home Minister who said first that they were pro-Peking? Was it we who said on this side first that the Left Communists were pro-Peking? Will my hon. friend kindly search his heart and see whether it was not he himself and his leader Shri S. A. Dange who had said that the Left-Communists were pro-Peking? Now, my hon. friend comes forward and says that the Home Minister has arrested them on the ground that they were pro-Peking. When my hon. friend said this, was he honest in his heart or was he lying in his throat when he said that they were pro-Peking? It is really surprising that people should change their attitudes and come and argue and wax eloquent on matters like that.

Much has been said about the Kerala election. My hon. friend Shri H. N. Mukerjee said that there was the verdict of the people. May I ask my hon. friend whether he is prepared to abide by the verdict of the people with regard to his party and liquidate it?

An hon. Member: Why not?

Shri Kappen: His party has secured only three seats in the legislature. Probably, after the Kerala election results, my hon. friend is trying to hug the legs of Shri A. K. Gopalan. Probably you want to join the Left communists now because you have found that you have place in the country. I cannot understand your argument except in this light.

Shri Indrajit Gupta: What a wonderful logic!

Shri Kappen: This is really wonderful.

Coming to the question of their arrest and detention, I have only one question to ask Government. Why is it that EMS Namboodiripad is allowed to roam about freely? Why not put him in prison at the earliest opportunity? Do not allow him to roam about. That is what I would advise Government to do.

Now there is no party in Kerala except probably the Left Communist who want the Left Communists to be released. What happened in Kerala in the elections? I would ask this of Shri Hiren Mukerjee. His party tried to form a united front with the Left communists, but were unable to do it. Why? They said because the Left Communists had joined with the Muslim League in an alliance, an alliance with a communal party. The Right

communists were not prepared to join them on that ground.

Shrimati Renu Chakravartty: Is that a charge to put them into jail?

Shri Kappen: I am speaking about the Kerala elections and its results. What are we to read from this? Mr. Mukerjee's Rightist party refused to join the united front because the Leftists had gone and joined a communal party. I would tell Shri Mukerjee that had it not been for this alliance they would not have got even one seat in Malabar. It is simply because of the communal alliance of the Left communists that they got what they got.

Shri Indrajit Gupta: You did the same thing before.

Shri Kappen: Let us analyse things as they are, seat by seat. Take, for example, Poonjar. Take my own constituency, Palai. Was there not an understanding between the Right and Left communists in the election? Why did you withdraw your Right communist candidate from Poonjar in favour of the Left communist candidate?

Shrimati Renu Chakravartty: Is this an argument to be used in this discussion?

Shri Indrajit Gupta: What is it that we are discussing?

Shri Kappen: I do not know what noise they are making.

Mr. Speaker: He will please address the Chair.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास): सच्ची बात सबको कड़वी लगती है।

Shri Kappen: I know truth is not palatable to many people. I am really sorry I have to say unpalatable things.

Mr. Speaker: He might say all that to me.

Shri Kappen: I was speaking about the Kerala elections. If I remember aright, Shri M. N. Govindan Nair, leader of the Right communist party said that the election manifesto prepared by them when they were together contained a clause to the effect that the integrity of the frontier will be maintained. Shri Nair said that when the Left communists alone wrote their mainfesto, they omitted that portion. What does it show? I shall quote not from the Home Minister's statement but from what Shri Hiren Mukerjee and Shri M. N. Govindan Nair and all their leaders said about what these Left communists are. If they are pro-Peking, if they are Chinese agents, should they be allowed to roam about freely and do harm to the country?

श्री मधु लिमये : सब से बड़े एजेन्ट तो आप हैं।

Shri Kappen: Therefore, I feel the Government are perfectly justified in the action they have taken. I would urge them to take stronger action, if necessary keep them in prison all the time they are found to be treasonable. No country will allow any other action. Is there any country which can be pointed out where it has allowed traitors to roam about freely in that country?

I am really happy about Shri N. C. Chatterjee's speech, because gratitude is a quality which man must have. He has been returned to this Parliament because of the help rendered by the Communists.

18 hrs.

Shri N. C. Chatterjee: No, Sir. Also PSP and also other opposition parties.

Shri Kappen: Therefore, I congratulate him for his splendid speech, because he is a grateful man. I must congratulate him for that.

I strongly maintain, and I would challenge Shri H. N. Mukerjee or

[Shri Kappen]

anybody to again fight the elections in Kerala on the question whether the Left Communists are to be freed from prison, and I can assure them that if that issue is placed before the electorate and the election is contested, not one seat will be given to the Left Communists. If the Left Communists have gained certain seats in Kerala, it is simply because democratic votes have been split, because of the Kerala Congress which has been formed. Therefore, I can say that the Left Communists have got 20 or 25 seats merely because democratic votes have been split. My submission is that the Kerala election is no index for deciding whether the Left Communists ought to be kept in prison or released. On the other hand, I maintain that the Kerala election definitely shows that these people, traitors, have to be kept in prison, as long as they continue to be traitors.

Shri Indrajit Gupta: What about the Palai Central Bank (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Shall we have a debate or fight here? When he is making a speech, he should be allowed to have his say. We are having a debate in Parliament.

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिसको नीति झगड़ा करने का हो तो क्या करें।

Shri Hari Vishnu Kamath: My hon. friend Shri Nanda, the Minister for Home Affairs, a former Prime Minister, a former Minister of Planning and Labour, the President of the Bharat Sevak Samaj, the President of the Bharat Sadhu Samaj, the *sadguru* of *Anugata Andolan* and *Sadachar Samiti*, the gallant Knight Errant who has vowed to exterminate corruption from the country by the end of this year, a Minister so conscientious and honourable that he righteously shrinks for commiting the ocular sin of looking at a secret document laid on the Table by a private Member with the permission of the Speaker, has given us this White, but not a bright, Paper, this little, incomplete brochure.

What does this brochure, this so-called White Paper, contain? What is the charge sheet, what is the indictment of the Left or pro-Peking Communists as they are called? I have not much time to read *in extenso* from the document, but on page 2 we have got a reference to the Left Communists. I wonder if in 1959 there were any Left Communists. There was one Communist Party, neither right nor left, but one upright or downright or whatever it was, Communist Party at that time. But one charge is that Communists of those days, 1959, Left Communists as Shri Nanda says, did not agree with the rest of the nation as regards the charges against China with regard to the "liberation" of Tibet. Is the ruling party, the Government, itself free from blame in this matter? I remember that day when the Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, in 1950, after having wondered what this "liberation" of Tibet was about, suddenly committed a *volte face,* and in the United Nations when El Salvador brought up a motion on Tibet, our representative Shri Gopalaswamy Ayyangar quietly backed out of the promise that had been given.

The Government of those days, so far as China was concerned a pusillanimous, invertebrate, myopic Government, a boneless wonder of a Government of those days, a Government which President Radhakrishnan himself rightly chastised as wilfully negligent and credulous, the Government of those days had enjoyed the blissful honeymoon with China which made them oblivious of realities. Those were the days when that lullaby, the opiate of *Hindi-Chini bhai bhai* reverberated from Shangai to Madurai. Those were the days when the Congress and the Communist

Party were supposed to be so friendly, regarded as so friendly in China itself that I heard from a very reliable source, a friend of mine who visited China, in those days the slogan raised in China was "Nehru ke baad Namboodiripad". Those were the days when the Government financed the India-China friendship society in India it was headed by an eminent Congressman, even after China had committed aggression in this country. How can this Government, with what face, indict the Left Communists when these Congress people themselves were toeing the same line as the Communist Party in those days? Here is an indictment of the communists. May I ask the Home Minister, why it is that up to this date, till now, why it is that they have kept the report on the accounts of the Bank of China a secret document, as secret as the CBI report? Is the obvious motive not to disclose the names of Congressmen? My hon. friend and colleague, Shri Dwivedy asked a pointed question on this matter in regard to their activities and the funds that the Communist Party got through the Bank of China and the other sources. My colleague Shri Dwivedy mentioned the name of a Member of the Cabinet. I shall quote from the proceedings of the Rajya Sabha, in the other place. The name of Mr. Biren Roy was mentioned. I shall quote from the records. The Finance Minister, Shri T. T. Krishnamachari refused to say anything in the matter and claimed secrecy for the document and then—what did he say?—he went on to say in his reply—it is rather amusing—"the House should trust the Government in these matters to take appropriate action". After their performance with regard to the Orissa affair, after the Orissa skeleton rattling so noisily in their cupboard, how can we trust this Government? They call the left communists as agents of China. Maybe, they are agents of China. But is it not the pot calling the kettle black? That is what they themselves were doing. They cannot hunt with the hounds and run with the hare. They were toeing more or less the same policy as the communists with regard to China, till August 1962 My party had the honour, had the privilege of drawing the attention of the Government, since 1954, or even earlier, against the menace that China was to this country, to the peace of Asia and to the peace of the world. My party was dubbed as war mongers even as late as August, 1962 in this House, when the then Defence Minister, after a brief interlude in London where he said that there was no danger from China—in October, it was before the invasion, when he was toasting Marshal Chen Yi in salubrious Switzerland mouthing *Hindi—Chini bhai bhai*, we here this House had to face this abuse and invective which came from the Treasury Benches, that we were war mongers. And these peace mongers! It is these peace mongers who brought war to our doors. That is the record of the Government. Now, we are asked to believe this document which has been circulated to Members. My hon. friend, Shri Mukerjee, has tried his very best to defend the left communists. But may I read from this document? I do not know whether it is correctly reported in this booklet or brochure. His own party leader, Shri Dange, according to this report, on page 31, referred to the left communists in a meeting in Bombay on 20th June 1964 that the left communists were Chinese agents. Shri Dange says that—I do not know whether he was correctly reported. (*An hon. Member*: Mr. Mukerjee accepts that) they were left communists in the sense that they subscribed to the Chinese views on the analysis of the Indian political situation and on the methods to be pursued in bringing about a political revolution.

Now, I charge the Government that it was their credulity and criminal negligence led to the debacle in NEFA and was national humiliation, and India's prestige in Asia had suffered, and that gave a fillip to the

[Shri Hari Vishnu Kamath]

pro-Chinese elements in our country. That is the charge against this Government, this pusillanimous and boneless wonder of a Government, which I condemn. (*Interruption*).

May I ask this Government why they did not answer the question of mine on the floor of this House as regards the money that passed from China to the leftist faction of the Communist party of India? They said that it could not be disclosed in the public interest: let alone discussion of the matter, it could not even be disclosed. My charge against the Government is that the plea of public interest—as you have rightly referred to it in another connection—is to my mind,—for this Government—a cloak or rather, may I say a quilt for this somnolent or at best a somnambulist Government, to hide, to cover a multitude of bungles and blunders which have brought the country to this pass, this national humiliation.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Hari Vishnu Kamath: I shall finish in a minute or two. Before I conclude, may I say that in this document which is placed before us by the Government, they have charged the left Communists with certain crimes, with certain preparations for violence and subversion. Now, the left Communists have a certain philosophy and they perhaps want to implement their philosophy. According to me, the only way to counter, to fight that philosophy is with a more potent philosophy, with a more potent ideology—political ideology or political philosophy—and with an active, firm, determined, socio—economic policy and programme. Let the Government come out with it.

Shri Indrajit Gupta: They cannot do that. They have not got the guts.

Shri Hari Vishnu Kamath: If that is not done, I am afraid the Government has no face, no clean face to show before the public. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member's time is up.

Shri Hari Vishnu Kamath: I shall finish now. I have learnt from authentic sources that the Government has in its possession sufficient material. It is also said in this brochure—there is an indication of it—that it is not complete, and that there is more material. I have learnt from reliable sources that the Government has in its possession sufficient material to bring these left Communists to trial. Let them bring them to trial: why hide these facts? They have done so before; let them bring them to trial, lest there should be disaster. (*Interruption*). If they do not bring these left Communists to trial, what will the judgment of the country be? I have learnt today, this morning, that the Home Ministry has supplied some Members of the Congress party with a brief, a note, containing more material than has been given to us.

Some hon. Members: No, no. (*Interruption*).

Shri Hari Vishnu Kamath: I have heard; I have seen it myself; I have seen the brief myself. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member should conclude now.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am finishing, Sir.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): If my party briefs me, what is wrong? (*Interruption*).

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it proper, Sir,—while Members of the House are not supplied that material in the national interest, perhaps, the Congress party has got it supplied by the Government, by the Home Minister, but which has been denied to us? I ask the Government to bring those left Communists to trial because

the Government have the requisite material with them. Otherwise, the Government will be dubbed as a pusillanimous Government, a boneless wonder of a Government.

Shrimati Renu Chakravartty: Reference was made to the document and to what Shri Dange has said. Shri Dange had given a statement to the National Council refuting this. It was stated in the newspapers that in a private meeting he had called them agents of China. This whole matter was discussed and it was clearly stated by Com. Dange that he had spoken only about ideological differences. Everybody knows that there are differences in the ideological field between China and Soviet Union and other communist countries of the world. This was what was said and that is the statement which he has made.

Shri Dinen Bhattacharya: Mr. Speaker Sir, at the very outset of the discussion of this motion, you kindly reminded us, the Members of the House, that we in India have a democratic principle and tradition and we have to maintain it. I put a simple question to you Sir which was tried to be raised by my hon. friend Shri S. M. Banerjee. What is this type of parliamentary democracy when a Member of Parliament, not of this Lok Sabha only but who has been a Member of the Lok Sabha for the last 10 years,—Shri Gopalan—is under detention? He was in the first Lok Sabha. He was the leader of the Communist Group. Still he is the leader of the party. Behind his back Shri Nanda has made derogatory remarks against him. What is this sort of democracy? Where are we being led to by this Government?

Shri Nanda has come out with a statement containing 45 pages. The issue is not between the Left CPI and the Government of India, it is a question of democracy and the democratic principles that are in danger. An eminent jurist, Shri Chatterjee, has amply described how illegal it is at this stage to detain persons without trial. The people of India expected that at least after the Kerala elections some good sense will prevail on the Government and they will invite Shri E. M. S. Namboodiripad, who is the leader of the majority party, to form a government. But, Sir, the Government is now conniving, is now trying to make hotch-potch arrangements with the Kerala Congress, and trying to form a Government putting the elected members inside the prison. Is this justice? Is this democracy? Is this parliamentary democracy?

Shri Bhagwat Jha Azad: Sure.

Shri Dinen Bhattacharya: Certainly not. One hon. Member from that side spoke. I do not know whether he belongs to the Congress or the Kerala Congress. From his remarks I understood that he was pleading for the Kerala Congress getting into power.

Shri Bhagwat Jha Azad: What are you, Left or Right?

Shri Dinen Bhattacharya: The statement that is there is absurd. It is full of false statements that I do not want to go into the details. Shri Jyoti Basu, the leader of the Left CPI has come out with two Press statements. The Government had not the guts to reply to them.

The Left CPI members are accused as being pro-China. I say it is a false statement, it is a lie, it has got no foundation. Shri Jyoti Basu has said:

> "We did not take the advice of any party, whether CPC or CPSU with regard to our party activities. We acted on our own considering the situation in India and our party."

If anything contrary to this is there, why is the Government afraid of bringing those persons before a court of law where everything can be

[Shri Dinen Bhattacharya]

settled? I know this Government has the least respect for the verdict of a court of law or the rule of law. One Shri Biren Dutt, a Member of this House, was released by the Supreme Court of India. The other six persons arrested were also released by the Supreme Court. But within a month they were re-arrested and detained without trial. Where is justice in this country? The people are losing all faith in this Government and in their activities.

I again challenge this Government. If they have got any material, any evidence against anybody who has been arrested or are detained, let them be put before a court. If they are proved to be traitors, pro-Chinese or Chinese agents, or that they were contemplating some subversive activities, let them be given the proper punishment by the court. Then the whole country will be behind the Government in their action. Until the Government does it, the history will show that only to keep the ruling party in power, only to hoodwink the people, to be-fool the people such a statement was made. Before that statement was made, people were told that it will be a white paper. Now it has come as a statement and it will go down in history as a black paper; not a statement. It does not contain even an iota of truth; only some ideological questions have been raised.

In Murat conspiracy case Justice Sulaiman has said in his judgment that you cannot impeach, you cannot punish, a person for his thought. If a person has some ideological view, you cannot punish him for that. You can punish a person only for his activities. Where is the proof of the pro-china activities of the people who have been detained Professor Mukherjee has said it; and I also repeat it, that supporters and financiers of Congress took overdraft from the Bank of China and it has been categorically stated in the West Bengal Legislative Council by Shri Jyoti Chakraverti. Not a single member of the Communist Party, either of the Right or of the Left, has got a single farthing as overdraft from the Bank of China. If the Government have got the guts, let them deny it and say what the truth is. If anybody has taken money from the Bank of China, it is the agents of the Congress and people who wanted to exploit the situation.

Before concluding my speech, I would again ask the whole House to consider this point. It is not a question of Shri Gopalan being released or not. In 1962 you had given reference to 1959. I say that all the members who were arrested, they were elected in 1962 in spite of your this type of propaganda.

This time Shri Nanda's speech, in which the Left Communists were dubbed as pro-Chinese was circulated by thousands in Kerala. Yet, the people refused to believe that cock and bull story of Shri Nanda and has elected the Communists in large numbers Shri Namboodiripad has come out with a statement, contradicting the illusion that was sought to be created by Shri Nanda by saying that the Congress has got the majority of votes. I say that it is not the Congress but the Opposition, including Rightists and Leftists and their supporters, that has got more than 47 per cent of the votes, which is more than what they obtained in the 1960 elections.

So, I would submit that Government should immediately realease all the detained memebrs. Let the elected Members of Kerala come out of detention and let Shri Namboodiripad form the Ministry. Let there be competition between the parties. Let the Communist Ministry function for some time. The Central Government have got ample powers to impose President's rule at any time by dismissing the Ministry, as they have done in 1959. It can be done again. but let there be a fair trial. Let the Government give a fair chance to the electorate and their elected represen-

tatives to serve them by forming the Ministry.

I will conclude by saying that this is a dishonest attempt to get some petty advantage for the ruling party by saying that other parties are anti-national or pro-Peking. Take Shri Gopalan. Can anybody face him in an election in Kerala? I make a challenge. Let Shri Nanda resign his seat and go to Kerala. Let Shri Gopalan also resign. Let them stand for election from Kerala. The people of Kerala will show who is the beloved son of this land, who is a patriot and who is not a patriot.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : श्रीमन्, इस सदन् के माध्यम से श्री नन्दा जी ने सारे देश का ध्यान ऐसे संकट और ऐसे देश द्रोहियों के कार्यों की ओर आकर्षित किया है कि देश उस के लिए उनका अनुगृहीत होगा। वैसे तो श्रीमन्, साम्यवादियों का एक अपना इतिहास है। संसार भर में यह प्रसिद्ध है है कि उन का एक अपना इतिहास है। वह इतिहास लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ है। इन का इतिहास तोड़ फोड़, सशस्त्र क्रान्ति, विस्तारवादी प्रवृत्तियां और जनता को भुलावे में रख कर अपना उल्लू सीधा करना है। इन का देशप्रेम यदि किसी तुला पर रख कर तोला जाय तो तराजू टूट जायगा और अगर किसी फीते से उन की भावनाओं को आंका जाय तो वह फीता भी टूट जायगा। इन की विचार संगति की यदि खोज की जाय तो एक बड़ी भारी क्रान्ति के संदेश की सर्वहारा का प्रतिनिधत्व करने का नारा लगाते हैं लेकिन वह अपने देश के लिए नहीं वरन् चीन के लिए है। इन की भावनाएं, इन की क्रान्ति, इन का सर्वहारा जन प्रतिनिधित्व का सुन्दर चित्र मास्को और रूस के लिए है, पेकिंग के लिए है। इन के दो रूप हैं। पश्चिमी साहित्यकार के एक नायक डा० जयकल का स्मरण आता है। उस ने कहा है कि एक डा० जयकल थे जिन्होंने कि सर्वहारा के माध्यम से बड़ी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त कर ली थी, रात को वह डाक्टर जयकल मिस्टर हाइड हो जाते थे और वह फिर भी नशे में मस्त हो कर ऐसे जघन्य और अवांछनीय कार्य करते यहां तक कि डाका भी वह डालते थे। मुझे स्मरण होता है कि मास्को के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि श्री ख्रुश्चेव जब यहां आए तो कश्मीर संदंभ में यह कहा कि कश्मीर की घाटी में अगर कोई खतरा पाकिस्तान से हो तो इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ कर पार्वती मंदिर के निकट पुकार देना हम तुम्हारी रक्षा के लिए आ जायेंगे। हमने देखा कि ठीक उस के कुछ दिन के बाद उन्हीं के एक साथी, पेकिंग के अधिष्ठाता माओत्से तंग और चाऊ एन लाई ने हमारे पर्वतराज हिमालय पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम अपनी उस धरती को वापिस नहीं ले लेंगे तब तक वह खून के छींटे धोये नहीं जा सकते हैं।

श्रीमन्, एक बार चर्चिल ने इन कम्युनिस्टों और उन की विचारधाराओं का समन्वय करते हुए कहा था। कुछ समय चर्चिल भी उन का साथी था। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उस ने कहा था कि यह ऐसे लोग हैं कि यह ध्वंस की और वफादारी की प्रक्रियाओं को बड़े ढोंग के साथ एक गाड़ी में लाद कर चलते हैं। इन से सावधान रहना चाहिए। इतना ही नहीं हमारे राष्ट्रपिता बापू ने अपने 1942 के स्वाधीनता आन्दोलन की गतिविधि के संदर्भ में हरिजन में एक लेख लिख कर एक इंटरव्यू को शाया किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन की साम्यवादी विचारधारा और इन के आदर्श से हमारा कोई मतभेद नहीं है लेकिन इनकी जो अंडरग्राउन्ड या जो तोड़फोड़ की और सशस्त्र क्रान्ति की जनता को बरगलाने की जो प्रवृत्ति है हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध हैं। वह बापू का एक संदेश था। चर्चिल जो संसार का एक बड़ा भारी राजनीतिज्ञ और विशिष्ट प्रकार का जन नेता था उस का दूसरा कथन था। आज श्रीमन्, चाहे यह कहें कि कांग्रेस कम्युनिस्टों के विरुद्ध है लेकिन

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

हमारा इतिहास बतलाता है कि हम तो बिलकुल विरुद्ध नहीं है। अगर विरुद्ध होते तो हम ने अब तक इन को जो बर्दाश्त किया वह कभी नहीं करते। गांधी जी के आन्दोलन के इतिहास के साथ इन का एक इतिहास जब बना तब मालूम पड़ा कि यह हमारे देश में देशद्रोह कर सकते हैं। उस 1951 के परिपत्र में जो सशस्त्र क्रान्ति का आवाहन किया तो पता चला कि घर का भेदी लंका ढा सकता है। यह हमारे ही आस्तीन के सांप हो सकते हैं जो हमारा दूध पीकर हम को डस सकते हैं।

जब इस प्रकार की स्थिति आई तब हम को थोड़ी आंख रखनी पड़ी। श्री नन्दा ने उनको गिरिफ्तार करके बड़ी सुरक्षा के साथ अन्दर रख दिया है। वहां कोई खतरा नहीं है। माननीय सदस्य क्यों परेशान होते हैं? मैं समझता हूं कि वहां उनके लिए अच्छी खुराक और पानी का इन्तजाम है।

जैसा मैंने कहा इन साम्यवादियों का हमारे देश में अपना एक इतिहास बन गया है। ऐसा लगता है कि उनका एक ही सिद्धान्त है—यह उनका बड़ा सिद्धान्त है—कि कोई सिद्धान्त नहीं है। अनेक विचार-धारायें हैं उनकी और उन विचार-धाराओं के पीछे पीकिंग की तानाशाही की छाया है। उनके विचार के कुछ देश भी हैं जिन में जनता का कोई अधिकार नहीं है। उनके कुछ दिमाग भी हैं जो लाल रंग के भूसे से भरे हुए हैं—वह भूसा भी रंगा हुआ है, शुद्ध भूसा नहीं है। ठीक ठीक सीधे सीधे और अच्छी व्यवस्था के साथ वे किसी देश में नहीं रह सकते। जो माननीय सदस्य मास्को गुट से लगे हुए हैं वे खुद फैसला करें कि पीकिंग के पिटठुओं के सम्बन्ध में उनकी विचार-धारा क्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मास्को ने ही आपको बचा कर रखा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्रीमन्, मास्को गुट ने कम्यूनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कंट्रोल कमीशन के द्वारा पीकिंग गुट के सम्बन्ध में जो जांच कराई मैं आप का ध्यान उसकी रिपोर्ट के एक अंश की ओर खींचना चाहता हूं। आप देखिए कि वे स्वयं साम्यवादियों के चीनी-पीकिंग गुट के सम्बन्ध में क्या कहते हैं:

> "इस प्रतिक्रियावादी गुट ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रालिटेरियटवाद का मार्ग त्याग दिया है और अंधे राष्ट्रवाद और क्रान्तिकारी जनता तथा श्रमिक वर्ग के प्रति सन्देह का मार्ग अपनाया है।"

यह कांग्रेस नहीं कहती, यह श्री नन्दा नहीं कहते, यह कहती है श्री हीरेन मुकर्जी की पार्टी जो मास्को के साथ लगी हुई है।

इस श्वेतपत्र के पृष्ठ 29 पर यह बताया गया है कि स्वयं कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं ने वामपन्थी गुट के सम्बन्ध में क्या राय दी। उन्होंने कहा :

> "विश्व साम्यवादी आन्दोलन के अन्तर्गत सैद्धांतिक वाद-विवाद की उग्रता के साथ अधिकांश कामरेडों (वामपक्षी) ने अपने विचारों तथा कामकाज का चीनी साम्यवादी दल की स्थिति के साथ गठबंधन कर दिया है।"

यह श्री नन्दा नहीं कहते, यह श्री हीरेन मुकर्जी की पार्टी कहती है, जो अभी बहुत जोरों से बोल रहे थे।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : माननीय सदस्य के पास क्या सबूत है? वह तो हमारी ही बात कह रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): मियां की जूती मियां के सिर ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्वेतपत्र के पृष्ठ 31 पर कहा गया है :

> "चीन समर्थक नेताओं ने चीनी साम्यवादी दल की सेंट्रल कमेटी के वैकल्पिक सदस्य चू-यांग द्वारा 26 अक्तूबर 1963 को चीनी विज्ञान अकादमी के समक्ष दिये गये भाषण को प्रसारित किया । इस भाषण में दुनिया के साम्यवादी दलों में फूट डालने के सैद्धान्तिक औचित्य के बारे में कहा गया था ।"

साम्यवादी दल की ओर से कहा गया है कि वह पार्लियामेंटरी प्रथाओं और प्रणालियों में विश्वास करता है लेकिन उसकी ओर से 1951 में एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसमें यह कहा गया:

> "हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहां की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है और यहां के 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इस तरह के देश में, जैसे कि चीन के अनुभव से मालूम हुआ गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसी भी क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिये बहुत ही असरदार हथियार है और राष्ट्रीय आजादी के युद्ध में कम्यूनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल को इस हथियार को काम में लाना पड़ेगा । ...... चीन के मुकाबले में हिन्दुस्तान में यातायात की बड़ी तरक्की हो गई है और इस तरह हमारे गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ सरकार तेजी के साथ बहुत बड़ी सेना हमारे सामने उपस्थित कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हम लोगों के पास दूसरे पड़ौसी दोस्त ऐसे राज्य नहीं हैं जो पीछे से पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ हमारी मदद कर सकें।"

ये शब्द उस पत्रिका, पैम्फलेट के हैं, जिसको चुपके चुपके बांटा गया और जो अब भी साम्यवादी दल के अपने रिकार्ड में मिलेगा । इस से सिद्ध होता है कि इन लोगों का सशस्त्र क्रान्ति में पूरा विश्वास है, यह पीछे से चाकू घोंप कर आगे जाना चाहते हैं, चीन के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये ऐसे देशद्रोही हैं, जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने उनके साथ बहुत रियायत की है। आखिर गिरफ्तार करने से क्या होता है? हमारा देश एक प्रजातंत्र है। इस में नन्दा जी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? जेल में रख सकते हैं, जहां अच्छा खाना दिया जाता है। यहां पर श्री हीरेन मुकर्जी तड़क तड़क कर बोल सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं, पायंट आफ आर्डर उठा सकते हैं और सदन की कार्यवाही को भंग करने की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये लोग चीन में होते--अगर रूस में भी होते--और वहां पर उस देश के विरुद्ध कोई आवाज उठाते तो जेल नहीं होती, ---

एक माननीय सदस्य: गोली से मार दिया जाता ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : ....बल्कि किसी चौराहे पर कुछ फैसला होता और वह फैसला क्या होता, माननीय सदस्य वहां जा कर देख लें, उन को पता चल जायेगा । (*Interruption*) मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय न करती और सजा न देती, तो फिर जनता स्वयं अपने भाग्य का फैसला करती,

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

वह स्वयं इन्तज़ाम करती और डट कर अच्छी सेवा करती ।

जहां तक रूस का सम्बन्ध है, जब ख्रुश्चेव यहां आए, तो वह पहला अवसर था कि रूस का कोई अधिष्ठाता यहां आए । लाखों की भीड़ ने उस का स्वागत किया और उस की आंखें खुल गई । बाद में पंडित जी का वहां पर स्वागत किया गया । तब उस ने समझा कि संसार में सह-अस्तित्व, जनता की प्रतिष्ठा और गरिमा को स्वीकार करना पड़ेगा और थोड़ा स्वच्छन्दता का वातावरण देना होगा । ख्रुश्चेव को भी हटा दिया इन लोगों ने । (*Interruption*)

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, वहां एक पार्लियामेंट है, जिसकी प्रोसीडिंग्ज़ हम ने अभी पढ़ीं । 3532 लोग एक पार्क में खड़े होकर दो रोज़ सैशन करते हैं । यह वहां का प्रजातन्त्र है, यह वहां की विस्तारवादी मनोवृत्ति है ।

श्री नन्दा घबरायें नहीं, ज़रा डट कर इन का मुकाबला करें । सारी जनता और कांग्रेस दल उन के साथ है । आप कस्टोडियन आफ़ डेमोक्रेसी हैं । अगर आप अपना हित चाहते हैं, तो कम्यूनिस्टों की भर्त्सना में आप भी साथ दीजिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से गृह मंत्री का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया । दुर्भाग्य इस बात का है कि नींद तो खुली, लेकिन काफी समय बाद खुली । यह कार्यवाही काफ़ी समय पहले होनी चाहिए थी, परन्तु वह काफी लेट की गई । इस पुस्तक में जो विवरण दिया गया है, यह हम ने अनेकों बार समाचार-पत्रों में पढ़ा है और रेडियो से सुना है । लेकिन इस में बहुत अच्छी बातें हैं, जिन को ले कर हम सारे देश में जनता को बता सकते हैं कि वामपन्थी कम्यूनिस्टों की गतिविधियां क्या हैं ।

इतनी अच्छी पुस्तक के बारे में हमारे एक मित्र कहते हैं कि इस में कुछ भी नहीं है । उन का कहना ठीक है । चूंकि उन के दिमाग में कुछ नहीं है, इस लिए वह इस पुस्तक से कुछ नहीं समझते । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपराधी को सहारा देता है, सहयोग देता है या उसकी वकालत करता है, वह भी उतना ही अपराधी है ।

आज हमारे देश में कम्यूनिस्टों की जो गतिविधियां चल रहीं हैं, उन के सम्बन्ध में सरकार को और कठोर कदम उठाना चाहिए । आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, वह तो पहले ही समाप्त हो जाती । जिस समय देश पर आक्रमण हुआ, तब हमारे भूतपूर्व गृह-मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ कम्यूनिस्टों को एरेस्ट किया । मैं चाहता था कि उन को एरेस्ट न किया जाता ताकि देश की जनता यह बताती कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है । इस देश में देशभक्तों का भंडार भरा हुआ है, कन्या कुमारी से ले कर काश्मीर तक, दक्षिण से ले कर उत्तर तक, देशभक्तों का जाल बिछा हुआ है । वे इन से निपटने की ताकत रखते हैं । वे इन को पिस्सू की तरह मसल दें, परन्तु हमारी सरकार के द्वारा इन लोगों को बढ़ावा दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं हम यह बात जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जब घर के अन्दर खटमल, मच्छर, पिस्सू इत्यादि, बढ़ जाते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनका नाश करने के लिए कौन सी दवाई

की जरूरत पड़ती है। उनको खत्म करने के लिए डी० डी० टी० के पाउडर की जरूरत होती है। ये जो खटमल, मच्छर इत्यादि हैं ये बढ़ रहे हैं और इनको मारने के लिए इस पाउडर का ही इस्तेमाल करना होगा। आप निगाह डालें, आपको देश भक्तों की टोलियां मिल जायेंगी और वे ही इन का नाश कर सकती हैं। आप उन पर कोई अंकुश न लगायें वे अपने आप इन से निपट लेंगी। आपको भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जो यहां चीनी दूतावास है, उससे आपको चाहिए कि आप सम्बन्ध तोड़ लें। आज आप उससे सम्बन्ध बनाये हुए हैं। दूतावासों में होता क्या है? इन्हीं दूतावासों में देश के विरुद्ध काम करने की सारी योजनायें पाकिस्तान द्वारा और चीन द्वारा अनेक प्रकार की बनाई जाती हैं, देशद्रोही योजनाएं बनाई जाती हैं। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध है, उसको नाजायज ठहराया जाना चाहिए, पूरी पार्टी को समाप्त आपको करना चाहिए। मैं यह बात अपने दल की ओर से आपके सामने रख रहा हूं।

सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जिन लोगों को बन्द गिया गया है उनको इस तरह से आपको बन्द नहीं करना चाहिए, उन पर आपको मुकदमे चलाने चाहिएं। आपने उनको इस तरह से बन्द करके हीरो बना दिया है, नेता बना दिया है, उनको चमका दिया है। उन पर आप मुकदमा चलाओ। देश द्रोही के साथ जो व्यवहार होता है, वह व्यवहार आप इनके साथ करो। जिस तरह से किसी देश द्रोही पर मुकदमा चलता है, उस तरह से इन पर भी आप मुकदमा चलायें। तब जो सरकार ने कदम उठाया है, उसको ठीक कदम समझा जायगा।

इस पुस्तक में बहुत से तथ्य नहीं दिये गये हैं। सरकार को सभी तथ्य देने चाहिए। क्यों उनको छिपा कर आपने रख छोड़ा है। पूरी बात बताई जानी चाहिए, कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। चाइना बैंक का जहां तक सम्बन्ध है, उससे सम्बन्धित जितने भी नाम हैं, वे सब सदन के सामने आने चाहिएं। उन सब नामों की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि वास्तव में उनकी गतिविधियां क्या हैं।

चुनावों से पहले जिन को पकड़ा गया है और अब चुनाव के बाद उनको न छोड़ने की जो नीति अपनाई गई है उसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, उनके ऊपर जो लांछन लगाये गये हैं उनके ऊपर सरकार को गम्भीरता से सोच विचार करके जितना कड़ा से कड़ा उनको दण्ड दिया जा सकता हो देना चाहिये। जो व्यवहार देश द्रोहियों के साथ होता है, वही उनके साथ भी होना चाहिये।

यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई? कृष्ण मेनन साहब हमारे प्रतिरक्षा मंत्री थे अगर वह सजग होते तो यह स्थिति पैदा न होती। उन्होंने सदन को बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने सदन को धोखे में रखा, सरकार को धोखे में रखा देश की जनता को धोखे में रखा। आज हमारे चव्हाण साहब सजग हैं। उनकी तरह से उनको भी सजग होना चाहिये था। उनकी तरह से उनको भी सतर्क रहना चाहिये था। इतना बड़ा अपराध करने के बाद उन्होंने केवल हटा दिया गया और कुछ दंड नहीं दिया गया। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया कि हजारों सैनिकों को मरवा दिया लेकिन फिर भी उनको बेदाग छोड़ दिया गया। यह कहां का न्याय था। प्रजातंत्र में जो अपराध करे उसको दण्ड न मिले यह कहां का न्याय है? इस तरह से क्या प्रजातंत्र टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। अब भी समय है कि भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री पर मुकदमा चलाया जाए। उनके ऊपर भी देश द्रोह के लांछन लगे हुए हैं। तब आने वाली जनता को हम बता सकेंगे कि प्रजातंत्र

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

में क्या क्या हो सकता है। तब हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे देश में जो अपराध करता है वह दण्ड भी भोगता है।

वामपंथी और दक्षिणपंथी की भाषा बोलनी किस ने शुरू की? यह नारा किस ने लगाया। यह नारा हमारी सरकार द्वारा ही तो लगाया गया है। इसी कांग्रेस द्वारा ही तो लगाया गया है। कुछ कम्मुनिस्ट ऐसे हैं जो उपद्रव करना नहीं चाहते हैं, जो चीन का साथ नहीं देना चाहते, जो चीन का समर्थन नहीं करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं, यह बात हमारी सरकार द्वारा ही तो बताई गई है। मैं दक्षिण पंथी कम्युनिस्टों से कहना चाहता हूं कि वे मजदूरों की बड़ी दुहाई देते हैं तो क्या कारण है कि यहां देश के अन्दर बहुत से मजदूर संगठन है, मजदूर यूनियन हैं, उन में शामिल हो जाते, क्यों नहीं वे उनके साथ मिल कर काम करते, क्यों नहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करते? आपके मन में तो यही है कि तोड़ो, फोड़ो, और उपद्रव कराओ मजदूरों को भड़काओ, उनको पेट भर अगर नहीं मिलेगा तो हमारी दूकान चलती रहेगी यह इनका नारा है?

देश के अन्दर ऐसी और भी पार्टियां हैं जो देश द्रोह का काम करती हैं। स्वतंत्र पार्टी भी उन में से एक है। क्या स्वतन्त्र पार्टी यह नहीं चाहती कि काश्मीर अलग रहे? क्या शेख अब्दुल्ला को उन्होंने छुड़वाने के प्रयत्न नहीं किए? क्या उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जो एक विदेशी भाषा है, बनाये रखने को नहीं कहा है और यह नहीं कहा है कि अंग्रेजी देश की भाषा होनी चाहिये। क्या जयप्रकाश नारायण जी के भाषणों का उन्होंने समर्थन नहीं किया है? मैं यह नहीं कहता हूं कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसी है। उस पार्टी में कुछ लोग अच्छे भी हैं। लेकिन उन में से भी जो ऐसी भाषा बोलें, जो काश्मीर को अलग करने की बात करें, उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

नन्दा जी से मैं कहना चाहता हूं कि वह इस बात को न भूलें कि देश के अन्दर जो देशभक्त हैं, उनको भी आपने सुरक्षा नियमों का इस्तेमाल करके अन्दर कर दिया है। कई स्थानों पर खास करके महाराष्ट्र के अन्दर हमारे कार्यकर्त्ताओं को इन्होंने पकड़ा है। क्या कारण था उनको पकड़ने का? कोई कारण नहीं था। उनको छोड़ा जाना चाहिये, बिना शर्त रिहा करना चाहिए। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जो अपराध करते हैं वे तो बाहर रहते हैं और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है उनको अन्दर कर दिया जाता है। यह जो गलत ढंग से इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बन्द होना चाहिये। उन पर मुकदमे चलने चाहिये अगर उन्होंने वास्तव में कोई अपराध किया है तो।

बड़ी हिम्मत के साथ नन्दा जी ने जो कदम उठाया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन पुस्तक में जो कमी है उसको पूरा किया जाए, यह मैं उन से प्रार्थना करता हूँ।

श्री सरजू पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के बारे में इस सदन में इस वक्त विचार हो रहा है उसके बारे में बहस इस बात की है कि जो आरोप लगाये गये हैं क्या वे इतने काफ़ी हैं, क्या वे ऐसे हैं कि इतने सारे लोगों को जेल में बन्द कर दिया जाए और उन पर मुकदमा भी न चलाया जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने और खास तौर पर प्रकाशवीर शास्त्री जी ने और दूसरों ने भी कम्युनिस्ट पार्टी पर इस बात का आरोप लगाया है और जहां तक हो सका है यह साबित करने की कोशिश की है कि ये देश भक्त नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि देशभक्ति इस बात से नहीं आंकी जाती है कि किस का विचार क्या है। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो लोग आज अपने आपको

देश भक्त बताते हैं, जो देश भक्ति की बात करते हैं लेकिन अगर उनका जो इतिहास रहा है उसको देखा जाए तो पता चलेगा कि ये कभी भी देश भक्त नहीं रहे हैं और न भविष्य में रहेंगे। गलत बात करने से और गलत आरोप लगाने से देश का और प्रजातंत्र का स्तर गिरता है।

हमारा कहना यह है कि अगर किसी के बारे में, किसी दल के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई ठोस आरोप है तो सरकार को उन आरोपों को सामने लाना चाहिये। गलत बातें कहना और गलत बातें पढ़ना और ऐसी बातें कर देना जिन में कोई तथ्य न हो, उससे देश के सामने भ्रम उत्पन्न होता है और लोगों का विधान और इस सदन में विश्वास उठता है। नन्दा जी को चाहिये कि था अगर उनके खिलाफ कोई आरोप थे, उनके पास कोई ठोस प्रमाण थे तो उनको हमारे सामने लाते। इनका सी० आई० डी० विभाग कहां था, कहां तक इनका वह सारा अमला जो इस तरह की हरकतें करने वालों का पीछा किया करता है, कहां है इनका सारा और कार्यकलाप जिससे पता लगता कि सही मानों में इन लोगों ने ऐसे कार्य किये हैं जिन की बदौलत इतने सारे लोगों को जेलों में बगैर मुकदमे चलाये बन्द करने की जरूरत पड़ गई। ये जो ठोस प्रमाण हैं, ये आने चाहिये थें। इस तरह का कोई भी प्रमाण हमारे सामने पेश नहीं किया गया है।

माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के आरोप कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाये हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे ऐसे भी सदस्य हैं जो आप से बीस गुना ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हैं। अगर इस तरह की कोई बात कही जाती है तो मैं भी यह कुर्बानियों की बात दावे के साथ कह सकता हूं।

जो भी आदमी देश के साथ गद्दारी करता है, जो सही मानों में देश में विश्वास नहीं रखता है, उस पर मुकदमा चलना चाहिये। यहां बहस यह भी हो रही है कि रूस में प्रजातंत्र नहीं है। एक कांग्रेस मिनिस्टर ने पूछा था जेलखाने में कि अगर आपके राज में ऐसा होता तो आप क्या करते? हम कहते हैं कि किसी भी आदमी को सजा देने के लिए सरकार को पवित्र होना पड़ेगा। जिस पार्टी के सारे मैम्बर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस पार्टी के मैम्बर चाइना बैंक के मैम्बर हैं, जिस पार्टी के सारे मैम्बर दूसरों से पैसा लेते हैं वह पार्टी कभी भी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती है। गोली मारने के लिए भी साहस चाहिये।

प्रजातंत्र का क्या अर्थ है अगर कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किये जा सकते हैं? सिर्फ गालियां देकर कम्युनिस्ट पार्टी को दबाया नहीं जा सकता है। यह सिद्ध करने की कोशिश करके कि हम ही देश भक्त हैं और दूसरी तरफ बैठने वाले लोग देश भक्त नहीं हैं, मैं, श्रीमान् कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई भी आदमी दबा नहीं सकता है।

हमारे हिरेन मुखर्जी साहब ने कहा कि सूरज की तरह कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्त सत्य हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कांग्रेस बैंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी तसलीम किया है कि बगैर समाजवादी अर्थव्यवस्था के देश का कल्याण नहीं हो सकता तब फिर बहस किस बात की है? आप भी तो समाजवाद चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप समाजवाद का बाना पहन करके देश को धोखा देना चाहते हैं और हम सच्चे समाजवादी हैं। हमारा चार्ज ही यह है कि आप देश में गलत बातों का प्रचार करना चाहते हैं। उद्धरण दिए जाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद हैं। लेकिन इसमें क्या बहस है। बहस तो इस बात की है कि उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है, उनका कौन सा ऐसा डाकूमेंट आपको मिला है जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे

[श्री सरजू पाण्डेय]

हैं कि वे गद्दार हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो उसे सामने लाना चाहिए। अगर इसी तरह के आरोप लगाकर आप लोगों को जेलों में डालेंगे तब तो आप उन सब लोगों को जेल में डाल देंगे जो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। आप उन लोगों को जेलों में डाल देंगे जो कि आप से गरीबों की मांगों के लिए लड़ते हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो लाजिमी तौर पर देश में प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नन्दा जी कुछ प्रमाणों के साथ देश के सामने आवें। लेकिन एक जनरल बात कही जाती है कि हम बिल्कुल सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं और इसी चीज को देश के सामने रखा जाता है। मुझे इस सिलसिले में सिकन्दर और डाकू की एक बात याद आती है। एक डाकू सिकन्दर के पास पकड़ कर लाया गया। सिकन्दर ने उससे पूछा कि तूने डाका क्यों डाला। उसने कहा मैंने तो एक डाका डाला है, तू तो रोज डाके डालता है। वही हालत सरकार की है। दूसरों को गालियां देते हैं और खुद गलत काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग जैसे शास्त्री जी हैं जो कि देश में देश भक्ति के नाम पर जातीयता का प्रचार करते हैं। ऐसे ही लोगों ने हिन्दी भाषा को बदनाम किया है और इन्हीं के कारण अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी का विरोध करने के लिए मजबूर हुए हैं। यही आदमी हैं जिन्होंने देश में हिन्दी को बदनाम किया है। इन्होंने ही जातीयता का प्रचार किया है। यही लोग हैं जिन्होंने देश में साम्प्रदायिकता फैलायी है। ऐसे लोगों को सरकार को जेलों में बन्द करना चाहिये। हम आपसे कहते हैं कि जनसंघ के लोग—जिनमें शास्त्री जी हैं यद्यपि अपने को निर्दलीय कहते हैं—प्रतिक्रियावादी हैं....

श्री बड़े (खारगोन) : क्या व्यक्तिगत बातें यहां लायी जा सकती हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : ऐसे ही लोग देश में जातीयता का प्रचार करते हैं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या व्यक्तिगत आक्षेप यहां किए जा सकते हैं ?

श्री सरजू पाण्डेय : हमको कोई ऐतराज नहीं है आप कम्युनिस्टों को बन्द कीजिए लेकिन प्रमाण तो उपस्थित कीजिए। लेकिन उनकी बात पूछिए जो देश भक्त बैठे हैं जो ऐसे पूंजीपतियों के पीछे हैं जो आज भी चीन को चावल बेच रहे हैं, और इस चीज को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी स्वीकार किया है। यही देश भक्त हैं जो हिन्दी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर देश में साम्प्रदायिकता फैलाते हैं। अगर आप हमको बन्द करते हैं तो इनको भी बन्द कीजिए।

Mr. Speaker: Mr. M. P. Mishra.... (*Interruptions.*) He is not here?

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: The hon. Minister. He may begin his speech.

Shri Nanda: Mr. Speaker, Sir, may I start on a personal note?

Mr. Speaker: If it is personal, we will have it tomorrow. He can continue tomorrow.

18.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, March 12, 1965/*Phalguna* 21, 1886 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—2406(Ai)LSD—3-4-65—1020